चिंतन

अब होगी नेताओं के दावों की परीक्षा

देश के पांच राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सत्ता की दौड़ तेज होगी। नेताओं के बड़े-बड़े दावे जनता की कसौटी पर परखे जाएंगे। करीब 17.4 करोड़ मतदाताओं और 824 विधानसभा सीटों पर होने वाला यह चुनाव केवल सरकार बदलने का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की परिपक्वता और जनता की उम्मीदों की भी बड़ी परीक्षा है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों ने अपने-अपने एजेंडे, वादों और रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। इन चुनावों की खास बात यह है कि यहां राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा तीखी रही है, जहां क्षेत्रीय दलों की मजबूत पकड़ है। ऐसे में राष्ट्रीय दल भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। चुनावों के दौरान अक्सर नेताओं द्वारा विकास, रोजगार, महंगाई और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। मुफ्त योजनाओं और जनहित के नाम पर नई-नई घोषणाएं मतदाताओं को प्रभावित करने का एक प्रमुख माध्यम बन जाती हैं, लेकिन समय के साथ मतदाताओं की समझ भी परिपक्व हुई है। अब मतदाता केवल वादों और नारों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे यह भी देखते हैं कि पिछले कार्यकाल में सरकारों ने वास्तव में क्या काम किया है और जनता के जीवन में कितना बदलाव आया है। यही वजह है कि यह चुनाव नेताओं के दावों की असली परीक्षा बनकर सामने आएगा। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि आचार संहिता लागू होने के बाद अब कोई भी सरकार नई योजनाओं या घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है। चुनाव केवल नेताओं या राजनीतिक दलों की परीक्षा नहीं होते, बल्कि यह मतदाताओं की जिम्मेदारी और जागरूकता की भी कसौटी होते हैं। जब मतदाता अपने अधिकार का ईमानदारी से प्रयोग करते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए जरूरी है कि हर मतदाता इस लोकतांत्रिक पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले और अपने वोट का प्रयोग जरूर करे। आखिरकार, चुनाव केवल सत्ता हासिल करने की दौड़ नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को जीतने की प्रक्रिया भी है। नेताओं के लिए यह अवसर है कि वे केवल वादे करने तक सीमित न रहें, बल्कि जनता के भरोसे को निभाने का संकल्प भी दिखाएं क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास ही होता है। मई में आने वाला जनादेश किसे सत्ता की जिम्मेदारी सौंपता है। जनता के लिए भी यह जिम्मेदारी के साथ चुनाव करने का मौका है। लोकतंत्र का यह उत्सव आखिर जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का आईना बनकर सामने आएगा।

डोनाल्ड ट्रंप के दावे और टूटता तिलिस्म

विश्लेषण
महेन्द्र तिवारी

ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और उनके आक्रामक व्यापारिक दृष्टिकोण ने वैश्विक भू-राजनीति में भारत और अमेरिका के संबंधों को एक जटिल धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के घटनाक्रम और ट्रंप के बयानों से यह आभास होता है कि वे भारत के आर्थिक उभार को एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, विशेषकर जब वे सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि वे भारत को 'अगला चीन' नहीं बनने देंगे। हालांकि, उनकी रणनीति का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के संदर्भ में अमेरिकी दबाव की सीमाएं बहुत संकीर्ण हैं। ट्रंप का यह सोचना कि प्रतिबंधों की धमकी से भारत की विकास यात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जमीनी हकीकत से परे नजर आता है।

डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और उनके आक्रामक व्यापारिक दृष्टिकोण ने वैश्विक भू-राजनीति में भारत और अमेरिका के संबंधों को एक जटिल धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के घटनाक्रम और ट्रंप के बयानों से यह आभास होता है कि वे भारत के आर्थिक उभार को एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, विशेषकर जब वे सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि वे भारत को 'अगला चीन' नहीं बनने देंगे। हालांकि, इस दावे और भारत पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के संदर्भ में अमेरिकी दबाव की सीमाएं बहुत संकीर्ण हैं।

ट्रंप का यह सोचना कि टैरिफ युद्ध या प्रतिबंधों की धमकी से भारत की विकास यात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जमीनी हकीकत से परे नजर आता है। भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा, चाहे वह व्यापारिक नीतियां हों या रूस जैसे देशों के साथ ऊर्जा संबंध। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर टैरिफ हमलों की श्रृंखला तब शुरू हुई, जब अमेरिका ने भारत को 'टैरिफ किंग' करार दिया और हार्ले-डेविडसन जैसी मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क को लेकर कड़ा रुख अपनाया। जवाब में, अमेरिका ने भारत को मिलने वाले 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस' (जीएसपी) के लाभ को समाप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को चोट पहुंचाना था, लेकिन इसके परिणाम ट्रंप की उम्मीदों के विपरीत रहे। भारत ने न केवल अमेरिकी कृषि उत्पादों और बादाम जैसे आयातों पर जवाबी शुल्क लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा की, बल्कि अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण भी शुरू कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बावजूद, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि देखी गई, जो यह दर्शाता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर इस कदर निर्भर हैं कि केवल टैरिफ के जरिए इन्हें अलग करना या भारत को दबाना संभव नहीं है।

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत एक अपरिहार्य बाजार और विनिर्माण केंद्र बना हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना खुद अमेरिका के लिए आर्थिक आत्मघात जैसा होगा। दबाव की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान देखने को मिला, जब अमेरिका ने भारत पर रूस से कच्चा तेल न खरीदने और प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भारी राजनयिक दबाव डाला। ट्रंप और उनके समर्थक गुट का मानना था कि भारत को अमेरिकी छत्रछाया में लाने के लिए यह सही समय है। हालांकि, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए न केवल रूस से तेल की खरीद जारी रखी, बल्कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक अवसर में बदल दिया।

अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और 'प्राइस कैप' जैसी नीतियों को दरकिनार करते हुए भारत ने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप फैसले लिए। यह अमेरिकी कूटनीति की एक बड़ी विफलता मानी जा सकती है क्योंकि वह एक प्रमुख लोकतांत्रिक साझेदार को अपनी मर्जी के अनुसार झुकने पर मजबूर नहीं कर सका। भारत के इस कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया कि नई दिल्ली की विदेश

नीति अब वाशिंगटन के निर्देशों पर नहीं, बल्कि अपने 140 करोड़ नागरिकों की जरूरतों और वैश्विक स्थिरता के अपने दृष्टिकोण पर आधारित है।

भारत की तुलना चीन से करना और उसे 'अगला चीन' न बनने देने की बात करना ट्रंप की एक रणनीतिक भूल को दर्शाता है। चीन का उदय एक सत्तावादी ढांचे के तहत हुआ, जिसने वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करती है। ट्रंप का यह डर कि भारत अमेरिकी विनिर्माण को निगल जाएगा, तथ्यात्मक रूप से कमजोर है क्योंकि भारत का विकास मॉडल निर्यात-आधारित होने के साथ-साथ उपभोग-आधारित भी है। भारत आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर रहा है, जिसे अमेरिका खुद 'फ्रेंड-शोरिंग' के नाम से बढ़ावा देता रहा है। ऐसे में एक तरफ भारत को विनिर्माण का विकल्प बनाना और दूसरी तरफ उसकी प्रगति को रोकने की बात करना ट्रंप की नीतियों में गहरे अंतर्विरोध को उजागर करता है। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यह भी देखा गया कि रक्षा सौदों के मामले में भी अमेरिका का दबाव काम नहीं आया। भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली का सौदा किया, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। भारत का अडिग रहना और अंततः अमेरिका का प्रतिबंधों से पीछे हटना यह साबित करता है कि वाशिंगटन को भारत की सैन्य और सामरिक महत्ता का भली-भांति आभास है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जितनी आवश्यकता है, उतनी भारत को अमेरिका की नहीं।

यह शक्ति संतुलन ट्रंप के उन दावों को खोखला कर देता है, जिनमें वे भारत को नियंत्रित करने की बात करते हैं। भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलें किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी क्षमता विस्तार के लिए हैं और ट्रंप के टैरिफ या धमकियां इसे रोकने में अक्षम साबित हुई हैं। अंततः ट्रंप की रणनीति में एक बुनियादी कमी यह है कि वे भारत को केवल एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं, जबकि भारत एक सभ्यतागत शक्ति और उभरता हुआ वैश्विक ध्रुव है। भारत की डिजिटल क्रांति, उसका विशाल युवा कार्यबल और उसकी रणनीतिक स्थिति उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर ले जा रही है। ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' के मुकाबले भारत का 'सबका साथ, सबका विकास' और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने का संकल्प अधिक समावेशी और प्रभावी है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप द्वारा भारत पर बनाए गए दबाव के हर प्रयास ने भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनने और अपने विकल्पों को तलाशने के लिए प्रेरित किया है। भारत को दबाव में रखकर सफल होने का सपना देखने वाले नेताओं को यह समझना होगा कि 21वीं सदी का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है और किसी भी महाशक्ति का कनिष्ठ भागीदार बनने के बजाय एक समान और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ट्रंप के दावे महज चुनावी बयानबाजी या दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक विश्व व्यवस्था में भारत की गति को रोकना अब किसी भी एक शक्ति के बस की बात नहीं रह गई है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष

श्वेता गोयल

मानवता का सबसे सशक्त सुरक्षा कवच है टीकाकरण

मानव सभ्यता के इतिहास में अदृश्य सूक्ष्मजीवों, वायरसों और जीवाणुओं ने समय-समय पर अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौतियां पेश की हैं। इन प्राणघातक संकटों के विरुद्ध मानवता के पास सबसे सशक्त और अचूक अस्त्र 'टीकाकरण' ही रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाने वाला 'राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस' सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक चेतना और लाखों जिंदगियों को अकाल मृत्यु से बचाने के संकल्प का उत्सव है। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि कैसे विज्ञान ने प्रकृति के प्रकोप को नियंत्रित कर एक स्वस्थ समाज की नींव रखी है। टीकाकरण की महत्ता को समझना आज इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि यह न केवल व्यक्ति विशेष की रक्षा करता है बल्कि एक अभेद्य सामुदायिक सुरक्षा तंत्र (हर्ड इम्युनिटी) का निर्माण भी करता है। टीकाकरण की प्रक्रिया वास्तव में शरीर की आंतरिक रक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने की एक कला है। हमारे वातावरण में अनगिनत रोगजनक तत्व विचरण करते हैं, जो किसी भी क्षण हमें अपनी चपेट में ले सकते हैं। वैक्सीन इन खतरों के विरुद्ध शरीर में एक कृत्रिम प्रतिरक्षा जागृत करती है, जिससे हमारा शरीर वास्तविक संक्रमण होने पर उससे लड़ने के लिए पहले ही तैयार रहता है। यह चिकित्सा विज्ञान की एक अद्भुत उपलब्धि है, जिसने चेचक जैसी भयावह बीमारियों का नामोनिशान मिटा दिया और पोलियो जैसे अभिशाप को इतिहास के पन्नों तक सीमित कर दिया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का मूल ध्येय समाज के हर वर्ग, विशेषकर नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस अभियान की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है। यह उन अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, डॉक्टरों और नर्सों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी क्षण है, जो दुर्गम क्षेत्रों में जाकर हर बच्चे तक 'सुरक्षा की खुराक' पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में टीकाकरण की ऐतिहासिक विजय गाथा का विश्लेषण करें तो 16 मार्च की तिथि स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी दिन वर्ष 1995 में देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, जो 'पल्स पोलियो अभियान' के व्यापक शंखनाद का प्रतीक बनी। 'दो बूंद जिंदगी की' का वह नारा केवल एक विज्ञापन नहीं बल्कि एक जन-आंदोलन बन गया, जिसने देश के कोने-कोने में चेतना जगाई। उस समय भारत पोलियो के मामलों का प्रमुख केंद्र माना जाता था लेकिन निरंतर प्रयासों और टीकाकरण की शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल में अंतिम मामला मिलने के बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया। यह उपलब्धि प्रमाणित करती है कि यदि इच्छाशक्ति और टीकाकरण का सही समन्वय हो तो किसी भी महामारी को परास्त किया जा सकता है। टीकाकरण की प्रासंगिकता केवल शिशुओं तक सीमित नहीं है। यद्यपि इसका आरंभ बाल्यकाल की सुरक्षा से होता है परंतु व्यस्क और वृद्धजनों के लिए भी यह उतना ही अनिवार्य है। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इस सत्य को वैश्विक स्तर पर पुनर्स्थापित किया है। 2020 के बाद भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर यह सिद्ध किया कि आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना केवल वैज्ञानिक नवाचार से ही संभव है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि टीकाकरण के लाभ केवल व्यक्तिगत आरोग्य तक सीमित नहीं रहते बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ कार्यबल राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति देता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में टीकाकरण की जड़ें बहुत गहरी हैं। दस्तावेजी प्रमाण बताते हैं कि 1802 में मुंबई की एक नन्ही बालिका को चेचक का टीका लगाकर इस आधुनिक सुरक्षा चक्र की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1896 में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम का आना और 20वीं सदी के प्रारंभ तक हैजा, प्लेग और टाइफाइड जैसी महामारियों के विरुद्ध टीकों की उपलब्धता ने भारतीय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान की। टीकाकरण केवल दवा की बूंद नहीं है बल्कि यह एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की पहली शर्त है। आज जब हम आधुनिक प्रौद्योगिकियों के युग में जी रहे हैं, तब हमारा यह दायित्व है कि हम भ्रांतियों और अफवाहों को दरकिनार कर टीकाकरण को एक नागरिक कर्तव्य के रूप में अपनाएं। यदि हम 'पूर्ण टीकाकरण' के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो भविष्य की पीढ़ियों को हम एक रोगमुक्त और निर्भय संसार उपहार में दे सकेंगे। हर साल लाखों जिंदगियां बचाने का यह संकल्प तभी फलीभूत होगा, जब 'सुरक्षा का यह चक्र' समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

(लेखिका शिक्षिका हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

ईश्वर की प्राप्ति

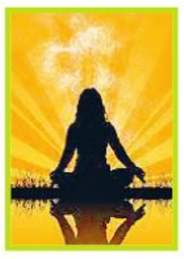

संकलित
दर्शन

जड़ जगत की रचना के लिए ईश्वर की जो शक्ति काम करती है, उसे प्रकृति कहते हैं और चैतन्य जगत की रचना करने वाली शक्ति को जीव कहते हैं। जिस प्रकार दोनों हाथ एक ही शरीर के दो भाग हैं, उसी प्रकार जीव और प्रकृति दोनों ही ईश्वरतत्व के दो अंश हैं। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, असल में वह अखिल आद्यशक्ति का सतोगुणी अंश है। मानवीय उन्नति तो सत्व गुणों को प्राप्त करने से ही हो सकती है। इसलिए उन उच्च गुणों की एक मानसिक प्रतिमा बनाकर उपासना करने का विधान किया गया है। ईश्वर का सत्व गुण अदृश्य रूप से हमारे निकट ही वर्तमान है। उसे अधिक मात्र में खींचकर अपने अंदर भर लेने के लिए प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और ध्यान अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन्हीं चारों के समन्वय को 'उपासना' कहा जाता है। उपासना जितनी ही प्रबल होगी, आकर्षण भी वैसा ही सशक्त होगा और उसी के अनुसार उपास्य देवतत्व की प्राप्ति होगी। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, त्याग, समता और न्याय आदि सद्गुणों का निष्ठापूर्वक जितना अधिक चिंतन किया जाता है, उतनी अधिक उनकी प्राप्ति होती है। उन्नति का क्रम तम से सत की ओर चलना है। जिसने जितना ही सत्गुण अपने में धारण कर लिया, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही उन्नतिशील कहा जाएगा। यदि एक भक्त सत तत्व की उपासना करता है तो कोई कारण नहीं कि उसे वह प्राप्त न हो। ईश्वर की उपासना का तात्पर्य उसके दिव्य सत तत्व की आराधना है।

दूसरों को कमजोर समझने की गलती न करें

संकलित
प्रेरणा

महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने-सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र-शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब-जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब-जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्रीकृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण ये रथ पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। यदि ये न होता तो पता नहीं तुम्हारे रथ की क्या स्थिति होती। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का अहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। यथा स्थिति का अच्छा से अवलोकन करे।

अंतर्मन

आज की पाती

बड़ा बोझ क्यों बन रही शादियां?

भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक आयोजन भी माना जाता है। यहां शादी में परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और पूरा समाज शामिल होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शादियों का स्वरूप बहुत बदल गया है। आजकल कई शादियां इतनी भव्य और महंगी हो गई हैं कि उनमें करोड़ों रुपए तक खर्च किए जाते हैं। बड़े-बड़े होटल, महंगे कपड़े, विदेशी सजावट, मशहूर कलाकारों के कार्यक्रम और कई दिनों तक चलने वाले समारोह अब आम बात हो गए हैं। ऐसी शादियों का सबसे बड़ा प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है। जब समाज में अमीर लोग बहुत महंगी शादियां करते हैं तो बाकी लोगों पर भी वैसी ही शादी करने का दबाव बनने लगता है। आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च बोझ बन जाता है।

- मनोज जोशी, बिलासपुर

X ट्रेंड f

जनता देगी जवाब

टीएमसी वालों को यह याद रखना होगा कि उन्होंने केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी का अपमान नहीं किया है, बल्कि देश के आदिवासी समाज के साथ-साथ करोड़ों महिलाओं के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। पश्चिम बंगाल की जनता-जनार्दन इसका भरपूर जवाब देगी।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कांशीराम को मिले भारत रत्न

सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कांशीराम के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक और आत्मसम्मान की राह दिखाई।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

ब्याज-मुक्त ऋण

युवा शक्ति ही सशक्त राजस्थान की असली पहचान है। उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज-मुक्त ऋण दिया जा रहा है।

- भजनलाल शर्मा, सीएम, राजस्थान

डबल इंजन सरकार

कुछ साल पहले किसने सोचा होगा कि असम के हर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल होगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और एम्स होंगे, एक पानी के नीचे सुरंग होगी और भी बहुत कुछ। डबल इंजन सरकार ने इन सभी को हकीकत बना दिया है।

-हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम, असम

करंट अफेयर

हमलों के बाद 'काली बारिश' से ईरान की जनता को खतरा

अमेरिका व इजराइल के ईरान के तेल भंडारों पर किये गये हवाई हमलों कारण उठे जहरीले धुएं के बादल धरती पर 'काली बारिश' हुई। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसके मद्देनजर जनता के लिए गंभीर खतरों की चेतावनी जारी की है।

पिछले हफ्ते ईरान के कई तेल डिपो और एक रिफाइनरी पर हमले के बाद तेहरान के पास काली और तैलीय बारिश हुई, जिससे राजधानी के निवासियों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। दो सप्ताह से जारी युद्ध के दौरान क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी काले धुएं के गुबार देखे गए। ईरान भी फारस की खाड़ी के पड़ोसी देशों के तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों पर ड्रोन व मिसाइलों से हमला कर अमेरिकी-इजराइली हवाई हमलों का जवाब दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, बारिश अपेक्षाकृत कम समय में वायुमंडल से खतरनाक रसायनों को साफ कर देती है लेकिन काली बारिश के संपर्क में आने वाले लोगों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यह तब होता है, जब राख और जहरीले रसायन वायुमंडल में पानी की बूंदों के साथ मिलकर बारिश के दौरान वापस पृथ्वी पर गिरते हैं। तेल रिफाइनरियों या तेल क्षेत्रों में आग लगने के बाद यह आम बात है।

ऑफ बीट

ब्रह्माण्ड स्वयं को क्यों खंडित कर रहा है?

ब्रह्मांड किससे बना है? यह प्रश्न सैकड़ों वर्षों से खगोलविदों को उद्वेलित करता रहा है। पिछली एक चौथाई सदी से, वैज्ञानिकों का मानना है कि परमाणु और अणु जैसी 'सामान्य' चीजें जो आपको, मुझे, पृथ्वी और लगभग हर चीज को बनाती हैं जिसे हम देख सकते हैं, ब्रह्मांड का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा है। अन्य 25 प्रतिशत 'डार्क मैटर' है, एक अज्ञात पदार्थ जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम यह पता लगा सकते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सामान्य पदार्थ को कैसे प्रभावित करता है। ब्रह्मांड का शेष 70 प्रतिशत भाग 'डार्क एनर्जी' से बना है। 1998 में खोजा गया, यह ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का लगातार बढ़ती दर से विस्तार कर रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में जल्द ही प्रकाशित होने वाले एक नए अध्ययन में, हमने डार्क एनर्जी के गुणों को पहले से कहीं अधिक विस्तार से मापा है। हमारे नतीजे दिखाते हैं कि यह एक काल्पनिक वैक्यूम ऊर्जा हो सकती है जिसके बारे में सबसे पहले आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया था – या यह कुछ अजीब और अधिक जटिल हो सकता है जो समय के साथ बदलता रहता है। एक सदी पहले जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत विकसित किया।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

विरोधकांवर आसूड उगारण्यापूर्वी...

‘सोनम वांगचुक यांची सुटका’ झाल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १५ मार्च) वाचले. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करण्यात चूक झाल्याचा साक्षात्कार सरकारला होण्यास तब्बल सहा महिने जावे लागले. नुकतेच केजरीवाल प्रकरणीदेखील (सदर प्रकरणात न्यायालयाने सीबीआयची कानउघाडणी केली होती; पण मुळात याबाबत सरकारने सीबीआयला योग्य तो सल्ला दिला असता तर ही वेळ आली नसती) एक प्रकारे सरकारची नाचक्की झाली. वांगचुक व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मनात मात्र ‘भर दुपारच्या अंधारातून’ बाहेर पडल्याची भावना निर्माण झाल्यास वावगे नाही.

या प्रकरणी न्यायालयात हेबियस कॉर्पसअंतर्गत ऑक्टोबर महिन्यात अर्ज सादर करूनसुद्धा न्यायालयाकडून मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत ‘तारखांवर तारखां’चे वळसे उगाळले जात होते, ही बाब विशेष दखल घेण्यासारखी. झाल्या प्रकारांचे तात्पर्य इतकेच की, चवताळून विरोधकांवर कायद्याचा आसूड उगारण्यापूर्वीच सत्ताधाऱ्यांनी सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करून निर्णय घेतल्यास पुढील अनर्थ टाळता येईल.

■ **शैलेश न. पुरोहित**, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

कायदा होईस्तोवर ‘इच्छापत्र’ योग्य!

निखिल दातार यांचा ‘जुग जुग जिओ हरीश राणा...’ हा लेख (रविवार विशेष - १५ मार्च) वाचला. मरणासन्न अवस्थेत १२-१३ वर्षे राहिलेल्याला निष्क्रिय इच्छामरण द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देऊन, ‘जगण्याने छळले होते...’ या उक्तीप्रमाणे हरीश राणाच्या पालकांना दिलासा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवरील हा लेख वाचून फेब्रुवारी २०१५ च्या ‘लोकसत्ता’च्या चतुरंग पुरवणीत प्रसिद्ध झालेला ‘उरले जगणे... मरणासाठी’ हा लवाटे आजोबांच्या इच्छामरणाच्या ‘तगाद्या’वरचा लेख आठवला. अरुणा शानबागसारख्या जवळपास ४० वर्षे अंथरुणाला खिळून असणाऱ्या व्यक्तीचा सांभाळ केईएम रुग्णालयाच्या परिचारिकांनी केला. पण त्या निमित्ताने ऐरणीवर आलेला दयामरणाचा प्रश्न आता अशा तऱ्हेच्या निकालामुळे धसास लागू पाहात आहे हे स्वागतार्हच आहे.

मात्र असा सर्रास कायदा करता येणार नाही, तर प्रत्येक प्रकरण तारतम्याने अभ्यासून निर्णय घ्यावा लागेल, हेही या प्रकरणाने स्पष्ट झाले आहे. वयस्कर झालेल्या पण औषधपाण्यावर बराचसा खर्च करत जीवनाची इतिकर्तव्यता, ध्येय वगैरेचे अप्रूप न राहिलेल्या व्यक्तींना त्यांना अंथरुणावर व्याधीने खितपत पडण्यापूर्वीच इच्छामरण हवे असेल तर त्यासंबंधी कायद्यापेक्षासुद्धा, डॉ. दातार यांनी पूर्वीच शिफारस केलेल्या, इच्छापत्र करून ठेवण्याच्या अंमलबजावणीचा रास्त उपयोग होईल असे वाटते.

कारण इच्छामरण म्हणजे आत्महत्या आणि दयामरण म्हणजे एकप्रकारे हत्या हा विचार जाऊ शकत नाही तोपर्यंत, जरी कायदा करू घातला, तरी कायद्याची निःसंदिग्धता आणि सापेक्षता प्रश्नचिन्हांकितच राहील. म्हणूनच वृद्धावस्थेत कुणावर आर्थिक भार येऊ नये असे वाटत असेल तर मध्यंतरी लोकसत्ता- ‘चतुरंग’मध्येच मसुद्याचा नमुना वाचल्याप्रमाणे ‘इच्छापत्र’ नोंदणी करून आपली गात्रे शिथिल झाल्यावर आणि उपचारांना शरीर साथ न देऊ शकण्याची स्थिती निर्माण झाल्यावर अधिक उपचार न करता शांतपणे मरू द्यावे अशी इच्छा लिहून ठेवून सुवर्णमध्य गाठता येईल. जिवलगांपैकी एखाद्याच्या मरणाची वाट पाहणे हे एखाद्या कठोर शिक्षेपेक्षा कमी नाही. म्हणूनच अशा इच्छापत्राच्या अंमलबजावणीची प्रशासकीय उदासीनता कमी होणे ही काळाची गरज वाटते.

■ **श्रीपाद पु. कुलकर्णी**, पुणे

प्रशासनाशी भाषेची नाळ तुटेल...

‘यूपीएससीत एकही मराठी नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ मार्च) वाचली. मराठीची इथेही होणारी पीछेहाट चिंताजनक आहे. इंग्रजी, हिंदी वा अन्य एखादी मातृभाषा यांपैकी कुठल्याच भाषेतून धड व्यक्त होता येत नाही, ही समस्या तर सर्वच भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात दिसते आहे. मराठीची अडचण तर याहून पुढची आहे. जगाच्या पातळीवर इंग्रजी आणि देशाच्या पातळीवर हिंदी, अशा दोन भाषा मराठीला झाकोळून टाकतात. आपल्या सर्वपक्षीय नेत्यांना मुंबईत पत्रकार मंडळी हक्काने ‘सर, हिंदी में’ अशी गळ घालतात आणि नेतेही परत तोच सारा ‘बाइट’ हिंदीत देतात! मराठी वाहिन्यांवर मराठीत चर्चा करायला सर्रास अमराठी प्रवक्ते येतात आणि त्यांच्याशी प्रश्नोत्तरे चक्क हिंदीत केली जातात. असे अन्य कुठल्याही राज्यात संभवत नाही. भाषेचे ज्ञान स्थानिक संस्कृतीशी नाळ जोडत असते. प्रशासकीय सेवा हे तर सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा प्रभाव पाडणारे क्षेत्र आहे. त्याचीच नाळ स्थानिक संस्कृतीपासून तुटत चालली असेल, तर ही स्थिती काळजी करण्यासारखी आहे असे वाटते.

■ **प्रसाद दीक्षित**, ठाणे

आधी महाराष्ट्रात तरी प्रतिष्ठा द्या!

‘लंडनमध्ये मराठी भाषा वैश्विक केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय’ (लोकसत्ता- १२ मार्च) ही बातमी वाचली. अशीच, काश्मीरमध्ये मराठी पुस्तक गाव उभारण्याचा अचाट निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असल्याची बातमी काही महिन्यांपूर्वी वर्तमानपत्रात झळकली होती. महाराष्ट्रात सरकार, महापालिका मराठी शाळा बंद करण्याचा चंग बांधत आहेत, हिंदीची सक्ती केली जात आहे. अन्य प्रांतीय तर मराठीला जाहीररीत्या झिडकारत आहेत.

तेव्हा सरकारने सर्वप्रथम मराठीचा आदरसन्मान महाराष्ट्रात राहावा आणि टिकावा, यासाठी पावले उचलावीत. ते झाल्यावर जे काही करायचे ते करा. अन्य राज्यांत भाषिक अल्पसंख्याक नाहीत काय? ते कसे त्या राज्याची भाषा मुकाट्याने शिकतात, आत्मसात करतात? मग फक्त महाराष्टातच त्यांची दादागिरी का? महाराष्ट्रात अन्य राज्यांसारखे भाषिक धोरण राबवून मराठीला प्रतिष्ठा देण्याची नितांत गरज आहे.

■ **चंद्रशेखर सु. खारकर**, ठाणे

‘दर्जे’दार गैरप्रकारांची चौकशी हवी

‘‘अल्पसंख्याक’ आबादानी’ हे संपादकीय (१४ मार्च) वाचले. शैक्षणिक संस्था सुरू करताना स्थानिक शिक्षक व कर्मचारी ठेवायचे, त्यांचा वापर करून घ्यायचा व अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झाला की त्यांना काढून टाकायचे व आपल्या नातेवाईकांना नेमायचे, असाही बाजार या अल्पसंख्याक दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांनी सुरू केला आहे.

राखीव जागा नाहीत, आता तर विद्यार्थी अल्पसंख्याक असण्याची अटही नाही, त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या नावावर शाळा कॉलेज सुरू करून सुविधा लाटायच्या, अवाच्यासव्वा शुल्क आकारून धनदांडग्यांना प्रवेश द्यायचा, असे प्रकार सुरू आहेत. या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांची चौकशी झाली पाहिजे. मागील वर्षी अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्षांनी बरेच गैरप्रकार उघडकीस आणले. कारवाई काय झाली हे गुलदस्त्यात आहे.

■ **प्रवीण सूर्यराव**, भिवंडी (ठाणे)

प्रतिमा डागाळण्याच्या प्रयत्नाचा निषेध

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात घरगुती, व्यापारी गॅसचा साठा पुरेसा आहे असे अधिकृतपणे सांगितले आहे. संबंधित खात्याचे मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी गॅसची देशात टंचाई नाही असे संसदेत जाहीर केले आहे. भारत पेट्रोलियम या गॅस कंपनीनेही ग्राहकांना तसे कळवले आहे. अशी वस्तुस्थिती असेल तर देशातील विरोधी पक्ष आणि त्यांचे नेते यांनी हे खोटे नॅरेटिव्ह पसरविले असून यातून भाजपची जनमानसातील प्रतिमा डागाळली जावी असा प्रयत्न असल्यास त्याचा सर्वांनी निषेध करावा.

■ **ॲड. बळवंत रानडे**, पुणे

आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न!

देशात सध्या कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा असून, ऊर्जेची पुरेशी उपलब्धता आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी लोकसभेत दिली असूनही मुंबईसह ठिकठिकाणी सिलिंडरसाठी रांगा दिसत आहेत. काही उपाहागृहे आणि बेकऱ्या बंद झाल्या आहेत. उद्योजकही धास्तावले आहेत. सत्ताधारी अशा वेळी विरोधकांवर अफवा पसरवत असल्याचा आरोप करत आहेत. सरकारने सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी व शांतता राखण्याची विनंती करावी. सर्व आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करून सत्ताधाऱ्यांना काय साधायचे आहे?

■ **विवेक तवटे**, ठाणे

भिंतीच्या अल्याड आणि पल्याड

बिहारमधले पूर, पश्चिम बंगालमधल्या ‘चार’बेटांना जलसमाधी... ते अगदी बांगलादेशींचे स्थलांतर हे सारे प्रश्न फराक्का बांधाशी संबंधित कसे काय?

चित्ततोष खांडेकर
नदी विषयक संशोधक अभ्यासक
chittatoshresearch@gmail.com

नदीकारण

कोलकात्याचे हुगळी बंदर हे नदीवर उभे असलेले मोठे बंदर आहे. पूर्व आणि उत्तर भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार याच बंदराहून होतो. पण वाढते शहरीकरण आणि इतर कारणांमुळे हुगळीतील पाणी आणि तिचे पात्र कमी होऊ लागले. त्यामुळे, ‘जर नदीत पाणीच उरले नाही तर बंदर कुठे उभे राहणार? आणि जर बंदरच नाही, तर कोलकात्याच्या औद्योगिक बाजारेपेठेचे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्यांचे काय होणार?’ - हा प्रश्न विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात सरकारसमोर आ वासून उभा होता. तेव्हा याचे समाधान म्हणून गंगेचे पाणी वळवून हुगळी नदीत आणायचे असा निर्णय इंग्रजांनी घेतला. स्वातंत्र्यानंतर तो भारत सरकारने आमलात आणला. त्यासाठी पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादजवळ फराक्का येथे नदीवर मोठ्ठा बांध (बराज) १९७५मध्ये बांधण्यात आला. या बांधाच्या भिंतींमुळे गंगेच्या प्रवाहाचा मोठा भाग आधी अडवला गेला, आणि मग कालव्यामार्गे हुगळी नदीमध्ये वळवला गेला. प्रवाहाच्या उरलेल्या छोट्या भागातून, गंगेचे पाणी सागराकडे मार्गक्रमण करत राहिले. पण यामुळे फराक्काच्या भिंतीच्या अल्याड आणि पल्याड काय नदीकारण उभे राहिले आणि त्याचा परिणाम आजही आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय राजकारणावर कसा होतो आहे, हे आजच्या लेखात समजून घेऊ.

फराक्काच्या या बांधाचे वेगवेगळे परिणाम बिहार, पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशमध्ये दिसून आले. बिहार ही तर गंगेची नैसर्गिक पूर मैदाने. त्यामुळे नदीच्या प्रवाहात (रिव्हर बेड), आणि पुराच्या काळात गंगा जितकी रुंदावते तितक्या पात्रात (रिव्हर बेल्ट) कोणीही वस्ती, जंगलतोड किंवा कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये असे कौटिल्य चाणक्यांनी अर्थशास्त्रात लिहून ठेवले आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना चाणक्य गुन्हाच मानत असत, गंगेचे अभ्यासक डी. के. मिश्रा सांगतात. नदीच्या पाण्याला अडवले तर विनाशकारी पूर येतील हे त्या काळापासून माहीत होते. शिवाय पात्र ओलांडूनही नदीचे पाणी येऊ शकते हे जाणूनच पात्राच्या आसपास रस्ता थोडासा सखल केला जाई. जेणेकरून त्यावरून नदीचे पाणी आरामात वाहून जाईल. शेतांजवळ नदीला जोडणारे कालवे बांधून, या कालव्यातून पुराचे पाणी सिंचनासाठी शेतांत वळते केले जाई. दुष्काळ पडला तरी या कालव्यांत वर्षानुवर्षे जमा झालेले पाणी शेतीला उपयोगी पडे.

पण ही पूर व्यवस्थापनाची व्यवस्था समजून न घेता इंग्रजांनी गंगेला येऊन मिळणाऱ्या कोसीवर नेपाळमध्ये उंच धरणे बांधली, तर गंगेचा पूर अडवायला पात्रात दोन्ही बाजूला मोठ्या भिंतींचे बंधारे (एम्बॅन्कमेंट्स) बांधले. पाऊस जास्त झाला की धरणाचे दरवाजे उघडले जाऊन मोठ्या प्रमाणात कोसी आणि इतर उपनद्यांचे पाणी गंगेला येऊन मिळू लागले, आधीपेक्षा पाणी प्रचंड वाढले आणि नदीकाठचे उंच बंधारे फोडून गावांमध्ये शिरायला लागले. यामुळे शेतांचा, गावांचा भयंकर विनाश गंगा करू लागली. तेव्हा हे उंच बांध तोडून जुनीच पूर व्यवस्था अमलात आणावी यासाठी ‘गंगा बाढ मुक्ती आंदोलन’ बिहारमध्ये उभे राहिले. ते आजही सरकारशी चर्चा करून आणि बांधांचा निषेध करून लढते आहे. पण फराक्काच्या बांधाने ही पुराची समस्या अधिकच गडद केली.

फराक्कामुळे काय झाले?

कारण कितीही पूर आला तरी पूर्वी हे पाणी समुद्रात वाहून जाई. पण फराक्काच्या भिंतीमुळे हे पाणी अडते. खूपच जास्त प्रवाह असेल, तर भिंतींना धडकन उलटून येते. याचाच अर्थ बिहारमध्ये पाऊस झाला नाही तरी, बंगालमधील पावसामुळे बिहारमध्ये गंगेकाठी पूर येतो. भिंतींमुळे नदीचा गाळ आता समुद्रात जात नाही तर नदीपात्रात जमा होतो आणि या गाळामुळे नदीची उंची प्रचंड वाढली आहे. त्यात पूर आला की पाहायलाच नको. बिहारमधील शहरे पुरात पाण्याखाली जायची कारणे या फराक्काच्या भिंतींत दडली आहेत. या सगळ्याच प्रश्नांविरोधात ‘गंगा बाढ मुक्ती आंदोलन’ गेली ४० वर्षे लढा देते आहे.

बिहारमधील हेच प्रश्न पश्चिम बंगालमध्येही मुर्शिदाबादच्या अलीकडे दिसतात. पण त्याला जोड आहे ‘चार’ भूप्रदेशांची. हिमालयापासून आणलेला सगळा गाळ नदीच्या प्रवाहात फराक्काच्या अलीकडे जमा होतो. या गाळाची माती खूप मोठ्या प्रमाणात एका ठिकाणी साचली की नदीत बेटं तयार होतात. या बेटांना गंगेच्या खोऱ्यात ‘चार’ (चारलॅण्ड्स) म्हणतात. येथील सुपीक माती शेतीसाठी वरदान असते. हे बेट तयार झाले की बंगालमधील शेतकरी त्यांच्यावर जाऊन शेती सुरू करतात. जमिनीचे सातबारे मिळवतात. पण जी नदी गाळ जमा (डिपॉझिशन) करते, तीच नदी माती वाहूनसुद्धा नेत असते (इरोजन). दशकभरात एखादा जोरदार पूर येतो आणि गंगा हेच बेट वाहून नेते. त्या बेटाची उरलेली माती पुन्हा नदीखाली जाऊन नदीची उंची वाढते. आता यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, त्यांच्या जमिनी तर जातातच पण कोणतीच नुकसान भरपाईही मिळत नाही. ती नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या संघटना सरकारशी बोलत आहेत आणि लढतही आहेत.

बांगलादेशावर परिणाम

भिंतीच्या अल्याड असे, तर भिंतीच्या पल्ल्याड नदीच्या प्रवाहातील पाणी आणि नदीसोबत वाहून येणारा गाळही प्रचंड कमी झाला. म्हणजेच, नदीकाठची सुपीक माती सागरात वाहून जात राहिली पण गाळाची माती येणे बंद झाले. प्रवाहातील पाणी कमी झाले, आणि सुपीक मातीही नाहीशी झाली, यामुळे बांगलादेशमधील गंगेकाठच्या सात ते आठ जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणची शेतीच नष्ट झाली. शिवाय बांगलादेशमध्ये गंगेचे मुख आहे. मुखाजवळ गंगा अनेक वितरक नद्या (डिस्ट्रिब्यूटरीज) तयार करते. या नद्याच गंगेला सागराशी जोडतात. त्यामुळे गंगेचे गोडे आणि सागराचे खारे पाणी या नद्यांमध्ये असते. पण गंगेतलेच पाणी कमी झाल्यामुळे या वितरक नद्यांना मिळणारे गोड पाणी कमी झाले. त्यांच्यातील सागरातून येणाऱ्या खाऱ्या पाण्यात प्रचंड वाढ झाली. पर्यायाने पद्मा आणि इतर वितरक नद्यांच्या खोऱ्यातील शेती, सिंचन, मासेमारी साऱ्यातच विलक्षण घट झाली. कृषिप्रधान बांगलादेशमध्ये बऱ्याच ठिकाणी शेतीच उरली नाही. शिवाय नदीच्या पाण्यावरच बांगलादेशमधील वस्त्रोद्योग उभे आहेत. त्यांनाही याचा फटका बसला. नदीचे पाणी कमी झाल्यामुळे बांगलादेशमध्ये लोक भूजलाचा वापर करू लागले. पण बांगलादेशच्या भूजलात नैसर्गिकरीत्या आर्सेनिकसारख्या विषारी धातूचे क्षार आहेत. भूजलाचा वापर प्रचंड वाढल्याने पाण्यातून विषबाधा होऊन पिके मेली, तर अनेक ठिकाणी शेकडोंना कर्करोग जडले. थोडक्यात बांगलादेशची गंगा खोऱ्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच कोलमडली. एवढा अनर्थ भारताच्या फराक्काच्या बांधाने झाला, असे म्हणतच बांगलादेशमधील भारतविरोधी भावना प्रचंड दृढ झाली. आजही भारताचा जो राग बांगलादेश करतो त्याच्या कारणांपैकी एक ठळक कारण फराक्काच आहे.

या सगळ्या विनाशाची चाहूल १९७०च्या दशकात बांगलादेशातील नेत्यांना लागली होती. त्यामुळे ‘फराक्काहून जास्त पाणी बांगलादेशात सोडण्यात यावे अन्यथा तो बांध फोडून गंगेला पूर्ववत करावे’- अशी मागणी गांधीवादी नेते मौलाना भसानी यांनी केली. तसे पत्रच त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानांना लिहिले. त्यावर काही उत्तर न आल्याने हजारोंच्या संख्येने निषेध मोर्चा भसानींनी काढला. हा मोर्चा फराक्काचा बांध उद्ध्वस्त करायला मुर्शिदाबादच्या दिशेने चालू लागला. हे आंदोलन इतके मोठे झाले की दोन्ही देशांना आपापल्या सैन्याच्या साहाय्याने ते थांबवावे लागले. जनभावना पाहता बांगलादेश सरकारने फराक्का बांधाविरोधात संयुक्त राष्ट्रांत धाव घेतली. पण भारताच्या मुत्सद्देगिरीमुळे संयुक्त राष्ट्रांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हा प्रश्न भारताशी चर्चा करून सोडवा असे सांगण्यात आले.

इथून पुढली २० वर्षे हा प्रश्न धगधगत राहिला आणि १९९६ मध्ये गंगा करारावर भारत-बांगलादेशने स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानुसार बांगलादेशला वाढीव पाणी फराक्कातून सोडण्यात यावे या मागणीस भारताने ३० वर्षांकरिता मान्यता दिली. काही प्रमाणात बांगलादेशात होणारे नुकसान कमी झाले. हा ३० वर्षे मुदतीचा करार या वर्षी संपतो आहे. त्यामुळे भारत आता हे वाढीव पाणी सोडणे कमी करेल? पुढे काय? हा प्रश्न बांगलादेशसमोर ‘आ’वासून उभा आहे.

या सगळ्याचा भारताच्या राजकारणावरही परिणाम झाला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच कोसळल्यामुळे बांगलादेशातून मजुरांनी पोटा-पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भारतात स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली. आज भारतामध्ये उभ्या राहिलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या राजकारणाची पाळेमुळे या फराक्काच्या भिंतीमध्येच आहेत. भिंतीच्या अल्ल्याड आणि पल्ल्याड आज गंगेचे नदीकारण हे असे आहे. पण या साऱ्याच समस्या सोडवायला सरकारने काय केले? हे पुढच्या लेखात समजून घेऊ.

कुतूहल

सापांमध्ये विष कुठून येतं?

सापाची म्हणजेच त्याच्या विषाची आणि त्यामुळे येणाऱ्या मृत्यूची भीती आपल्या मनात खोलवर रुजलेली असते. याचं कारण म्हणजे विषारी साप चावला की थेट मरणाच्या दारात रवानगी, असा आपला समज असतो. नाग, मण्यार, घोणस, फुरसं यापैकी एका जातीच्या सापानं दंश केल्यास आणि वेळेत योग्य उपचार न मिळाल्यास तसं घडू शकतं. साप आणि त्याचं विष याची घट्ट सांगड आपल्या मनात असते. अशा वेळी प्रश्न पडतो, सापांमध्ये विष येतं कुठून?

सापाचं विष म्हणजे त्याची विषारी लाळ! सापाचं विष फक्त त्याच्या लाळ-ग्रंथीत तयार होत असतं. ते कधीही सापाच्या रक्त प्रवाहात जात नाही. त्यामुळे त्याला स्वतःला त्याचा अपाय होत नाही. या ग्रंथी सापाच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूला, थोड्याशा खाली आणि डोळ्याच्या पाठीमागच्या बाजूला असतात. सापाच्या तोंडात वरच्या जबड्यात सुळ्यासारखे लांब, दोन अणकुचीदार दात असतात. विशेष म्हणजे ते पोकळ असतात, कारण सापाच्या दृष्टीने ती विषाच्या इंजेक्शनची सुई आहे. विषग्रंथीपासून निघालेली नलिका या दातांच्या पाठीमागच्या बाजूला जोडली जाते. विषाची पिशवी म्हणजे विषग्रंथी आणि ते टोचण्यासाठी टोकदार, पोकळ दाताची सुई असे दोन्ही सज्ज असतात. साप भक्ष्याला चावतो त्या वेळी त्याच्या डोक्यातील स्नायू विषग्रंथीच्या पिशवीला दाबतात. त्यामुळे त्यातील विष पोकळ टोकदार सुळ्यांमधून भक्ष्यांमध्ये टोचलं जातं.

साप भक्ष्याला चावतो आणि विष टोचतो. याचा नेमका उद्देश काय? शत्रूपासून आपलं संरक्षण करणं हा उद्देश तर आहेच. जमलं तर भक्ष्याला ठार मारणं किंवा किमान त्याची हालचाल मंद करणं, थांबवणं. त्यामुळे भक्ष्य गिळायला सोपं पडतं! असं विषयुक्त भक्ष्य ज्या वेळी साप गिळतो त्या वेळी भक्ष्याबरोबर त्यातल्या विषारी प्रथिनांचंही पचन होऊन जातं. सापाच्या पचनसंस्थेतून जाणाऱ्या या भक्ष्याचा थेट संबंध त्या सापाच्या रक्तप्रवाहाशी येत नसल्यामुळे, सापाला ते विषमय भक्ष्य बाधत नाही.

विषारी सर्पदंशामुळे जगभरात दरवर्षी जवळजवळ लाखभर माणसांचा मृत्यू होतो. एका अतिविषारी सापाच्या विषाच्या एका थेंबाने अडीच लाख उंदीर मरू शकतात इतकं ते जहाल असतं. एवढं त्यात असतं तरी काय? सापाच्या विषातले ९० ते ९५ टक्के घटक विषारी प्रथिनांनी बनलेले असतात. यात काही विकर म्हणजे ‘एन्झाइम्स’ असतात. हे विषारी पदार्थ मज्जासंस्थेवर परिणाम करणारे, काही स्नायूंवर; तर काही तांबड्या पेशींवर किंवा इतर पेशींवर परिणाम करणारे असतात. अशा एक वा अनेक दुष्परिणामांमुळे माणसाचा मृत्यू ओढवतो.

एखाद्या प्राण्याची लाळ एवढी विषारी असेल असं वाटलं होतं?

– बिपीन भालचंद्र देशमाने
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

‘सर्वांत उंच, सर्वांत भव्य, लोकांना दिपवून टाकणारे असे एखादे श्रद्धास्थान उभे करायचे आणि त्यातून आपल्या सत्तेला- आपल्या राजवटीला अधिकृतता मिळवायची,’ - हे शब्द हेर्मान कुल्के यांनी भारतातल्या ज्या राजवटीबद्दल वापरले, ती आजची नव्हे. मूळचे जर्मन असले तरी कुल्के हे भारतात दहा वर्षे राहिलेले होते, २०१० मध्ये त्यांना भारत सरकारने ‘पद्मश्री’ दिली होती हे खरे, पण प्रा. कुल्के यांचे हे भाष्य भारताच्या विद्यमान राजकारणाबद्दल नव्हते. उलट, १९६० च्या दशकापासून भारताविषयी केलेल्या अभ्यासाचा परिपाक म्हणून त्यांनी हे विधान केले, ते इसवी तेराव्या ते सतराव्या शतकातल्या भारतीय राजवटींबद्दल!

हेर्मान कुल्के

‘इंडॉलॉजी’ - भारतविद्या - हा हेर्मान कुल्के यांचा अभ्यासविषय. जर्मनीच्या फ्रायबर्ग विद्यापीठातून, डॉ. या विषयात संशोधनासाठी ते भारतात पहिल्यांदा आले. चिदम्बरम नटराज मंदिरावर त्यांचे ते संशोधन केंद्रित होते. जर्मनीत भारतविद्येच्या अभ्यासाची परंपरा श्लेगेल व मॅक्समुल्लरपासून, म्हणजे सन १८४० च्याही आधी सुरू झालेली. सुरुवातीला वेद/ पुराणे वा महाकाव्यांची भाषांतरे, मिथकांचा. मग लोकपरंपरांचा अभ्यास अशा मार्गाने पुढे गेलेल्या या अभ्यासपरंपरेत १९६५ मध्ये गुंथर सोन्थायमर यांच्यामुळे, ‘लोकदैवत व आज जिवंत राहिलेली लोकधाटी’ या अभ्यासाचे वळण आले. हाइन्रिख स्टाइनक्रॉन यांनी स्वातंत्र्योत्तर भारताची राष्ट्रीय प्रतीके वा अभिमानबिंदू आणि हिंदू परंपरा यांच्या संबंधांचा अभ्यास केला. हे स्टाइनक्रॉन २००४ मध्ये ‘पद्मश्री’ मिळवणारे पहिले जर्मन इंडॉलॉजिस्ट. त्यांच्यानंतर कुल्केच. आणि दोघेही हायडेलबर्ग विद्यापीठात काही काळ एकमेकांचे सहकारी. कुल्के यांनी मध्ययुगीन राजसत्ता कशा उभ्या राहिल्या, याचा अभ्यास केला. तो विषय शिकवला आणि पुस्तकेही लिहिली. ते काम मोठेच. पण कुल्के यांनी या अभ्यासशाखेत आणलेले नवेपण म्हणजे, एखाद्या भूभागाचे आराध्यदैवत आणि त्या भागातली राजकीय अधिसत्ता यांच्या सोळाव्या शतकापूर्वीच्या संबंधांचा त्यांनी केलेला अभ्यास. ओडिशातला ‘जगन्नाथ’ आणि तेथील मध्ययुगीन राजसत्ता यांच्या संबंधांचा कुल्के यांनी केलेला अभ्यास हे त्यांचे भारतविद्येला मोठेच योगदान मानले जाते. विष्णूचा अवतार मानला जाणारा, बलभद्र आणि सुभद्रा यांच्या सोबतीनेच दिसणारा जगन्नाथ हा बांधीव देवस्थानातला लाकडी मूर्तीचा देव! ही मूर्ती बदलली जाते, हेच त्याचे वैशिष्ट्य (‘नव कलेवर’ हा इरावती कर्वेंचा लेख त्या वैशिष्ट्यावरच आहे). पण हे असे लाकडी देव तर आदिवासींचे... मग तो इथे एवढ्या मोठ्या देवस्थानात आला कसा, राजमान्य झाला कसा आणि आजतागायत ओडियाभाषकांचे आराध्यदैवत ठरला कसा, हे सारे प्रश्न धसाला लावले ते कुल्के यांनी! त्यातून मिळालेले तपशील बरेच; पण अभ्यासाची दिशा त्याहून महत्त्वाची. ही दिशा राजेरजवाड्यांच्या आक्रमणांमुळे आदिवासी समाजांच्या झालेल्या नागरीकरणाची, त्यातून अपरिहार्यपणे झालेल्या घर्षण आणि संस्कृतिसंकराची, लोकदैवतांचे परमभक्त आपणच असे लोकांना वाटले तर लोक आपलेही अनुयायी होतील हे ओळखणाऱ्या तत्कालीन राजकीय चातुर्याची आणि म्हणून, त्यातून आजवर रुळलेल्या लोकधाटीची. समाजविज्ञान (विशेषतः राज्यशास्त्र) आणि भारतविद्या यांची सांगड घालता येते, हा संदेश हयातभरच्या अभ्यासातून देणारे प्रा. कुल्के १० मार्च रोजी निवर्तले.

राजवाडे विचारविश्व

‘ग्रामबंधूं’नी केलेला विश्वासघात

मेणवलीतले नाना फडणीस यांचे दप्तर अधिक अभ्यासासाठी आणि नंतर प्रकाशनासाठी आपल्याला उपलब्ध व्हावे म्हणून बाळ गंगाधर टिळकांमार्फत प्रयत्न करावेत, असा विचार वि. का. राजवाडे यांच्या मनात बळावला. मेणवलीकरांशी वादावादी झाल्यामुळे जरी त्या कामामध्ये व्यत्यय आला असला, तरी राजवाड्यांचे मन त्या दप्तरात गुंतले होते. त्या दप्तरातले रुमाल पाहून साधनसामग्रीचे वर्गीकरण करण्यासाठी त्यांनी काही दिवस मेहनत घेतली होती, पैसेही खर्च केले होते. ते आपल्या हातून निसटू नये, असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक होते.

पुण्याला जाऊन टिळकांना भेटण्यापूर्वी राजवाड्यांनी आपल्या मनातला विचार सातारचे प्रसिद्ध वकील दादासाहेब करंदीकर यांना सांगितला. ते टिळकांचे अनुयायी होते. त्यांनीही आपल्यासाठी टिळकांकडे शब्द टाकला, तर आपले काम अधिक सुकर होईल, असा त्यांचा कयास होता. दादासाहेबांनी राजवाड्यांकडून मेणवली दप्तराबद्दलची सगळी माहिती नीट ऐकून घेतली खरी; पण मदतीचे कसलेही आश्वासन मात्र दिले नाही. त्या बाबतीतली त्यांची टाळाटाळ लक्षात घेऊन राजवाड्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकायला हवी होती आणि दादासाहेबांवर विसंबून न राहता त्यांनी थेट टिळकांशी संपर्क साधायला हवा होता; पण त्यांना तसे काही सुचलेच नाही.

दादासाहेब करंदीकरांना जेव्हा ती माहिती राजवाड्यांकडून समजली, तेव्हाच त्यांच्या मनात मेणवलीचे ‘ते’ दप्तर सातारच्याच दुसऱ्या एका तरुण, उमद्या, उदयोन्मुख इतिहासकाराला मिळवून द्यावे, असा विचार पक्का झाला. त्या इतिहासकाराचे नाव होते, दत्तात्रय बळवंत पारसनीस. आपल्या रंजक लेखनशैलीमुळे तरुणपणातच ते प्रकाशझोतात आले होते. सातव्या इयत्तेतच शालेय शिक्षणाला रामराम ठोकणारे आणि ‘महाराष्ट्र कोकिळ’ हे मासिक काढून ते पाच वर्षे यशस्वीपणे चालवून दाखवणारे संपादक म्हणून पारसनीस गाजले होते, तसेच खुद्द टिळकांनी आग्रह केल्यामुळे राणी लक्ष्मीबाईंची माहिती शोधून काढून तिचे साधार व अत्यंत प्रभावी चरित्र प्रसिद्ध केल्यामुळेही ते अनेक मान्यवरांचे लाडके लेखक ठरले होते. न्या. म. गो. रानडे यांनी ‘दि राइज ऑफ दि मराठा पॉवर’ या इतिहासग्रंथाचे लेखन त्या वेळी सुरू केले होते, त्या कामात आणि पुण्यातल्या ‘पेशवे दप्तरा’तल्या ३४९७२ रुमालांमधल्या सुमारे दोन कोटी कागदपत्रांच्या अध्ययनात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी पारसनीसांना मुद्दाम आमंत्रित केले होते. पारसनीसांनी ती संधी साधली आणि जुन्या ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या नियमित प्रकाशनासाठी पुण्याच्या ‘डेक्कन व्हर्नाक्युलर ट्रान्सलेशन सोसायटी’च्या वतीने ‘भारतवर्ष’ नावाचे मासिक १८९६ पासून सुरू केले होते. (त्या ६४ ते ८० पानी अंकाची वार्षिक वर्गणी फक्त ४ रुपये होती.) त्या मासिकाच्या पहिल्याच अंकात हरिभाऊ आपटे यांच्या मदतीने पारसनीसांनी ‘मराठ्यांच्या इतिहासाची सामग्री’ हा ४० पानी निबंध प्रसिद्ध केला होता, त्याचे टिळकांनी ‘केसरी’त अग्रलेख लिहून कौतुक केले होते.करंदीकरांना हे सारे ठाऊक होते. म्हणूनच राजवाड्यांनी मेणवली दप्तराबद्दलची माहिती सांगितल्यावर त्यांना वाटले की, हे काम पारसनीस यांनीच केले, तर त्यांचा नावलौकिक आणखी वाढेल. त्यांची ही भावना स्वाभाविक असली, तरी सरळ साधी नव्हती. त्यांनी तसे राजवाड्यांना स्पष्ट सांगायचे धाडस दाखवले नाही. राजवाड्यांना अंधारात ठेवून त्यांनी ही माहिती पारसनीसांना कळवली. त्यांनी तातडीने हालचाली करून ‘ते’ दप्तर हस्तगत केले.

द.ब.पारसनीस यांच्याबद्दलचे यानंतरही अनेकदा उल्लेख करावे लागणार आहेतच; मराठ्यांच्या इतिहासाच्या संदर्भातल्या त्यांच्या योगदानाची महती कमी लेखण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळेच इथे ही अगदी संक्षिप्त माहिती एवढ्यासाठी दिली आहे की, करंदीकर वकील आणि खुद्द पारसनीस या दोन सातारकर ‘ग्रामबंधूं’नी राजवाड्यांचा केलेला विश्वासघात पुरेसा स्पष्ट व्हावा. करंदीकरांनी १८९७मध्ये राजवाड्यांना गाफील ठेवून त्यांचा अवसानघात केला आणि पारसनीसांनी पुढे १९०८मध्ये सुरू केलेल्या ‘इतिहाससंग्रह’ या मासिकातून क्रमाक्रमाने ‘ते’ दप्तर प्रसिद्ध करताना ते उजेडात आणण्याचे सारे श्रेय स्वतःकडे घेतले, राजवाड्यांचा कृतज्ञतापूर्वक नामोल्लेखही त्यात नव्हता.

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

नवोदित नेपाळची नवचेतना

चीन वा भारत, दोघांवरही अवलंबित्व नको, हीच आता नेपाळची भूमिका असणार, हे ओळखून भारताने 'थोरल्या भावा'पेक्षा हितचिंतकाच्या भूमिकेत राहणे बरे...

नेपाळच्या जनतेने नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तेथील तीन प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या जरठ वयाच्या नि जुनाट वृत्तीच्या नेत्यांना अभूतपूर्व धडा शिकवून नवा पक्ष आणि नव्या नेत्याच्या बाजूने घसघशीत कौल दिला. प्रस्तुत सार्वत्रिक निवडणूक नित्यनेमाने अवतरली नव्हती. ती घ्यावी लागली कारण गतवर्षी तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारला विद्यार्थी आणि बेरोजगारांच्या उठावासमोर नमते घ्यावे लागले नि सत्ता सोडावी लागली. आंदोलक पक्ष आणि त्यांचे नेते तेवढ्यावर थांबले नाहीत. ते त्या वेळी सत्तास्थानाचा ताबा घेते, तर सरकारविरोधी असंतोषाचे जनक म्हणून त्यांना मिरवता आले असतेही. मात्र निवडणुकीच्या लोकशाही मार्गाने सत्ताग्रहणाचे नैतिक अधिष्ठान त्या उठावाला लाभले नसते. उठावाचे असे अपूर्णांक जगातील कैक देशांत याआधीही दिसून आले आहेत. पण यांतील काहींची वाटचाल मातीतून मातेऱ्याकडेच झाली. नेपाळमध्ये हे घडले नाही. विद्यार्थी उठावाच्या केंद्रस्थानी असलेला राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) हा पक्ष नेपाळमध्ये सर्वार्थाने नवीनतम. त्या पक्षाचे नेते रबी लमिछने आणि बलेंद्र 'बलेन' शहा यांनी निवडणुका लढवण्याचा परिपक्व मार्ग निवडला. आरएसपीला निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाले आणि आता आज त्या पक्षाचे तरुणतुर्क नेते बलेन शहा नेपाळच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान होत आहेत. नेपाळच्या प्राधान्याने युवा मतदारांनी केवळ प्रस्थापित पक्षांना अद्दल घडवली नाही. त्यांनी मतदारांना गृहीत धरणाऱ्या आणि सत्तास्थापनेसाठी वाट्टेल त्या तडजोडी करणाऱ्या बेलगाम, बेमुर्वत नेपाळी नेत्यांना कायमस्वरूपी लक्षात राहील अशी अद्दल घडवली. बलेन शहा हे नवथर नाहीत. निवडणूक लढवण्याआधी ते काठमांडूचे महापौर होते. तेथे त्यांनी अनेक प्रयोग केले. रस्त्यावरील रहदारीचे नियोजन, अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमा राबवून काठमांडूतील दैनंदिन रहदारी काही प्रमाणात सुसह्य केली. ते ३५ वर्षांचे आहेत आणि त्यांच्या आधीच्या अनेक पंतप्रधानांपेक्षा वयाने लहान आहेत. पण मतदारांच्या दृष्टीने तेच त्यांचे बलस्थान ठरते. साचेबद्ध आणि स्वार्थी भूमिकेतून नेपाळचे वाटोळे करणाऱ्या आणि वर्षानुवर्षे पंतप्रधानपदाची संगीत खुर्ची खेळलेल्या नेत्यांपेक्षा नेपाळच्या मतदारांनी बलेन शहा यांच्यावर भरवसा दाखवला.

हा विश्वास अभूतपूर्व ठरतो. कारण २००८मध्ये नेपाळच्या राजेशाहीचा रक्तलांच्छित निःपात केल्यानंतर कोणत्याच पक्षाला आरएसपीइतके घसघशीत बहुमत मिळालेले नाही. या पक्षाने नेपाळच्या कायदेमंडळात १६५ जागांवर झालेल्या थेट निवडणुकीत १२५ जागा जिंकल्या. उर्वरित ११० जागा तेथे राजकीय पक्षांना त्यांनी जिंकलेल्या मतांच्या प्रमाणात वाटल्या जातात. त्यापैकीही ५७ जागा - म्हणजे एकंदर १८२ जागा- मिळवून आरएसपीने २७५ सदस्यांच्या सभागृहात निर्विवाद बहुमत मिळवले. येथून पुढे नेपाळमध्ये काही काळ तरी संधिसाधू आघाड्यांचे राजकारण चालणार नाही किंवा चालू दिले जाणार नाही हे नेपाळच्या मतदारांनी सुनिश्चित केले. आरएसपीची स्थापना २०२२मधली. पण या नवीन पक्षाला मोठे बहुमत मिळत असताना, नेपाळमधील इतर तीन मोठ्या पक्षांना मतदारांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. नेपाळी काँग्रेसला अवघ्या ३८ जागा मिळाल्या. तर दोन कम्युनिस्ट पक्षांची अनुक्रमे २५ आणि १७ जागांवर बोळवण झाली. यांतील पहिले लालभाई म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनिफाइड मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लेनिनिस्ट) काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत नेपाळच्या सत्तास्थानी होते. त्या पक्षाचे नेते के. पी. शर्मा ओली हे पंतप्रधान होते. त्यांच्याच कारभाराला कंटाळून नेपाळमध्ये सप्टेंबर महिन्यात उग्र आंदोलने झाली आणि ओली यांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान सोडून पळ काढावा लागला. बलेन शहा यांनी ओली यांचा त्यांच्याच मतदारसंघात प्रचंड मताधिक्याने दारुण पराभव केला आणि दोन नेत्यांना असलेल्या जनाधारातील तफावत दर्शवून

पाकिस्तानची सार्वत्रिक ओळख अनैतिक घुसखोरीची; तर चीनची ओळख कपटी प्रभावनिर्मितीची आहे. या दोहोंपेक्षा भारत वेगळा नि अधिक जबाबदार आहे हे आपल्या दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांना कृतीतून दाखवावे लागेल...

दिली. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांची झालेली वाताहत चीनसाठी नामुष्कीजनक ठरते असे आपल्याकडील काही विश्लेषकांचे मत. त्या न्यायाने नेपाळी काँग्रेसच्या दारुण पराभवाचाही श्लेष काढावा लागेल. त्यास भारतासाठी नामुष्की असेही संबोधावे लागेल. गेल्या १८ वर्षांत नेपाळमध्ये १४ आघाडी सरकारे आली. कोणतेही सरकार एक ते दीड वर्षापेक्षा अधिक काळ टिकू शकले नाही. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष परस्परांशी कधीही काडीमोड घेत नि नेपाळी काँग्रेस किंवा इतर छोट्या पक्षांसोबत सत्तेचा संसार मांडत. हीच बाब नेपाळी काँग्रेसची. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष या पक्षाचे खरे तर वैचारिक विरोधक. तरी दोन्ही पक्षांशी सत्तास्थापनेची चर्चा करण्यासाठी पक्षाचे नेते केव्हाही तयार! या बदफैली राजकीय 'लिव्ह-इन' व्यवस्थेला नेपाळी जनता विटली होती. त्यांना चेहरा हवा होता, पर्याय हवा होता. हे दोन्ही ज्या दिवशी प्राप्त झाले, त्या दिवशी त्यांच्या असंतोषाचा स्फोट झाला आणि त्या वावटळीत प्रस्थापित पक्ष नि नेते भुईसपाट झाले.

बलेन शहा यांनी काठमांडूचे महापौर असताना काही रोखठोक विधाने भारत, चीन आणि अमेरिका या 'महासत्तां'विरोधात केली होती. नेपाळचे अस्तित्व भारत आणि चीन यांच्या कृपाशीर्वादांस बांधले जाणे अजिबात योग्य नाही असा सूर लावणारे ते पहिलेच राजकारणी. यापूर्वी नेपाळमध्ये भारतधार्जिणे किंवा चीनधार्जिणे याच चष्म्यातून तेथील सरकारांकडे पाहिले जायचे. बलेन शहा यांचे अभियांत्रिकी शिक्षण कर्नाटकातले. ते स्थापत्य अभियंता आहेत आणि स्वतःच्या भावनांना वाट मोकळी करून देण्यासाठी रॅपसुलभ कवने रचतात. त्यांतील संताप आणि वेदना तरुणांना भावते. काठमांडूची महापौरपदाची निवडणूक लढवतानाही त्यांनी प्रस्थापित पक्षांना मात दिली होती. नेपाळचे भवितव्य हेच नेपाळी नेत्यांच्या आचार- विचार- संचाराच्या केंद्रस्थानी हवे. नेपाळची ओळख ही निव्वळ भारताचा किंवा चीनचा शेजारी देश किंवा या दोन्ही देशांच्या प्रभावाकडे आलटूनपालटून हेलकावे खाणारा देश इतपत राहू नये ही बलेन शहा यांची मनोमन इच्छा असते. यासाठीच प्रसंगी ते भारताशी नेपाळच्या नकाशावरून वाद घालतात. पण असे करताना किंवा भारताला खिजवण्यासाठी ते चीनच्या कच्छपी जात नाहीत. रोजगारार्थींचे लोंढे भारतात आणखी किती काळ जाणार, त्याऐवजी नेपाळमध्येच रोजगारनिर्मितीसाठी पावले उचलायला पाहिजेत, हे त्यांचे म्हणणे असंख्य बेरोजगारांच्या मनाची तार छेडून जातेच.

तेव्हा हे रसायन वेगळे आहे हे भारताने योग्य वेळी ताडले ते योग्यच. त्यांनी निर्णायक आघाडी घेताक्षणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला आणि अभिनंदन केले. बलेन शहा यांना याची जाणीव आहे. भारताच्या दृष्टीने उपखंडातली परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे नि त्यानुसार आपल्या धोरणातही लवचीकता दिसली पाहिजे. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ येथील प्रस्थापित सरकारांना तेथील नागरिकांच्या रेट्यापुढे पळता भुई थोडी झाली. तिन्ही देशांत पूर्ण बहुमताची सरकारे स्थापन झाली. अशा वेळी 'थोरल्या भावा'पेक्षा हितचिंतकाच्या भूमिकेत राहणे आपल्यासाठी केव्हाही फायद्याचे. या सर्व देशांमध्ये कधी चीन, कधी पाकिस्तान, तर कधी दोन्ही देशांनी भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी जंग जंग पछाडले. भारताच्या सुदैवाने हे प्रयत्न म्हणावे तितके यशस्वी झाले नाहीत. पण बांगलादेशाच्या आधीच्या सरकारच्या बाबतीत आपण 'चीन' बनण्याचा प्रयत्न केला नि सपशेल फसलो. यापासून बोध घेऊन येथून पुढे नेपाळच्या नवोदित सरकारशी संबंध प्रस्थापित करावे लागतील नि जोपासावे लागतील. पाकिस्तानची सार्वत्रिक ओळख अनैतिक घुसखोरीची आहे. चीनची ओळख कपटी प्रभावनिर्मितीची आहे. या दोहोंपेक्षा भारत वेगळा नि अधिक जबाबदार आहे हे कृतीतून दाखवावे लागेल. नेपाळमधील नवोदित नेतृत्वाकडे दोन देशांतील संबंधांची नवचेतना म्हणून पाहावे लागेल.

सत्ताधाऱ्यांची धांदल कशामुळे?

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar
@expressindia.com

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे लोकसभेतील चर्चेचा विषय गॅसपुरवठा हा असताना 'एपस्टीन फाइल्स'बद्दल बोलले, म्हणून अध्यक्षांनी त्यांना गप्प केले. पण अमेरिकाधार्जिण्या धोरणांना एपस्टीन फाइल्स जबाबदार असल्याची टीका संसदेबाहेरही करता येणार होती...

लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव संमत होणार नाही हे स्पष्टच होते. त्यामुळे सत्ताधारी 'एनडीए' आघाडी निश्चिंत होती. या प्रस्तावाकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतलेली होती. संपूर्ण चर्चेला शहा सभागृहात उपस्थित होते. चर्चेच्या पहिल्या दिवशी पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल यांनाच जास्त बोलायचे असल्याने आणि भाजपशी आपण किती एकनिष्ठ आहोत हे दाखवायचे असल्यामुळे वेळ खरे तर वाया गेला. काँग्रेसच्या गौरव गोगोईंना अडवण्यात आणि सल्ला देण्यात पाल यांना अधिक रुची असल्याचे दिसले. तोपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची वेळ झाली होती. मग, संदेश पाठवण्यात आला आणि लगेच सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले. शहांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जायचे असल्याने कदाचित असे झाले असावे. या प्रस्तावाला शहा उत्तर देणार असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याची गरज नव्हती. त्यांना उत्तरही द्यायचे नव्हते. एरवीही मोदी सभागृहातील चर्चांना क्वचितच उपस्थित राहतात. अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत त्यांचा सहभाग नव्हता. मोदी निवडणूकपूर्व प्रचारामध्ये गुंतलेले होते. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये त्यांचे दौरे होते. त्यामुळे लोकसभेतील चर्चा त्यांनी किती ऐकली असेल हे माहीत नाही. मोदींना तसेच बिर्ला यांना चिंता करण्याजोगे काहीही नव्हते. त्यामुळे हा प्रस्ताव आला, तो नामंजूर झाला आणि लोकसभेतील पुढील कामकाज सुरू झाले. तिथे मात्र केंद्र सरकारची कोंडी झाली.

खरे तर विरोधकांनी एलपीजी गॅसचा तुटवडा, इंधनपुरवठ्यातील समस्या या दोन मुद्द्यांवर चर्चा करायची होती. पहिल्या दिवशी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरलेही होते, पण हा मुद्दा अचानक विरोधकांनी सोडून देऊन बिर्लांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाला प्राधान्य दिले आणि चर्चेत भाग घेतला. केंद्र सरकारलाही 'एलपीजी'वरील चर्चा पुढे ढकलणे बरेच होते. अविश्वास प्रस्तावावर कोणीही कितीही टीका केली तरी त्यातून काही साध्य होणारे नव्हते, पण एलपीजी वगैरे मुद्दे अडचणीचे ठरतात. झालेही तसेच. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवून एलपीजी-इंधनपुरवठा वगैरे मुद्दे सभागृहात उपस्थित करण्याची परवानगी मागितली. बिर्लांनी राहुल गांधींना सभागृहात बोलण्याची परवानगी दिली. सभागृहात विशेष महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करता येतो. राहुल गांधींना मुद्दा मांडता येणार होता, कोणी हस्तक्षेप करण्याचे कारण नव्हते. राहुल गांधी पेट्रोलियमविषयक मुद्दा मांडणार असल्याने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांना सभागृहात उपस्थित राहावे लागले. त्यांनी निवेदन दिले. पण त्याआधीच राहुल

संग्रहित छायाचित्र

गांधींनी एलपीजी वगैरे मुद्दा मांडताना एपस्टीन फाइल्सचा जाणूनबुजून उल्लेख केला. हा जेफ्री एपस्टीन अव्वल दर्जाचा दलाल होता. त्याच्या अनेक भानगडी होत्या. त्यासंदर्भातील फाइल्समध्ये हरदीप पुरी यांच्या नावाचा उल्लेख झालेला आहे. त्यामुळे हे पुरी वादात सापडले आहेत. त्यांना केंद्र सरकारने अभय दिलेले आहे. या पुरींनी राजीनामा दिला पाहिजे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. राहुल गांधींनी एपस्टीन फाइल्सचा उल्लेख करताच त्यांना बिर्लांनी थांबवले. तुम्ही ज्या विषयावर बोलणार होतात तो हा विषय नाही. एपस्टीन फाइल्सचा आणि एलपीजी गॅसचा तुटवडा, इंधनपुरवठा वगैरे मुद्द्यांशी संबंध काय, असा प्रश्न बिर्लांनी केला. राहुल गांधी म्हणत होते की, या सगळ्याशी संबंध आहे म्हणून बोलतो आहे, पण बिर्लांनी ऐकले नाही. तातडीने सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. दोन दिवस अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करताना कसलीही चिंता न बाळगणारे सत्ताधारी 'एपस्टीन फाइल्स' असा उल्लेख ऐकल्यावर अस्वस्थ झाले. बिर्लांनीही तातडीने आक्षेप घेतला. राहुल गांधींचे बोलणे रोखण्यात आले. 'एपस्टीन' या एका शब्दाने सत्ताधारी, केंद्र सरकार, लोकसभाध्यक्ष असे सगळेच एकाचवेळी हडबडून गेले. राहुल गांधी लोकसभेतून बाहेर पडले आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. तिथे ते म्हणाले की, एपस्टीन हे नाव जरी ऐकले तरी सत्ताधाऱ्यांची तारांबळ उडते. माझे बोलणे थांबवले जाते. त्यांना या शब्दाची भीती वाटते... राहुल गांधींनी या कार्यक्रमातील भाषणातून 'एपस्टीन' ही सत्ताधाऱ्यांची दुखरी नस असल्याचा एकप्रकारे दावा केला. एपस्टीन या शब्दामुळे सत्ताधारी इतके अस्वस्थ का होतात, असा त्यांचा प्रश्न होता.

वास्तविक, राहुल गांधींनी 'एपस्टीन' शब्दाचा उल्लेख करून आरोपांची मोठी साखळी उभी केली असे दिसते. त्यातून केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये अडचणीत आल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केला आहे. पंतप्रधान 'कॉम्प्रोमाइज्ड' झालेले आहेत, असा आरोप काँग्रेसने वारंवार प्रचारात केला आहे. पंतप्रधान 'कॉम्प्रोमाइज्ड' झाले असतील तर त्यांच्यावर सर्वप्रकारचा आंतरराष्ट्रीय दबाव येणार. या दबावासमोर झुकण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. तसे झाले तर देशाचे हित कसे सांभाळले जाऊ शकेल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान 'कॉम्प्रोमाइज्ड' झाले असतील तर ते एपस्टीन फाइल्समुळे असू शकेल. आधीच देशातील एका केंद्रीय मंत्र्यांचा आणि एका मोठ्या उद्योजकाचा उल्लेख झालेला आहे. एपस्टीन फाइल्समधील आणखी काही लाख फाइल्स सार्वजनिक व्हायच्या आहेत. अमेरिकेने या फाइल्सच्या आधारे केंद्र सरकारवर सर्व प्रकाराचा दबाव आणला आहे, असा युक्तिवाद काँग्रेसच्या नेत्यांकडून केला जातो. एपस्टीन फाइल्सवरून लोकसभेत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली होती. त्याचा अर्थ विरोधकांनी एपस्टीन फाइल्सचा संबंध केंद्र सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय धोरण-निश्चितीशी असल्याचाही आरोप केलेला आहे.

सारे त्या 'फाइल्स'मुळेच?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव का आणला? अतिरिक्त आयातकर इतर देशांवरही लादले गेले हे खरे; पण ट्रम्प यांनी वारंवार भारताला लक्ष्य केले तसे इतर देशांना केलेले नाही. ट्रम्प सातत्याने भारत-पाकिस्तान युद्ध त्यांच्या मध्यस्थीने थांबल्याचे सांगत आहेत. या युद्धाचा संबंध त्यांनी भारताच्या व्यापाराशी जोडला होता. भारताला अमेरिकेचे म्हणणे मान्य करून, रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करावी लागली. अमेरिकेने 'परवानगी' दिली म्हणून आता संकटकाळात भारताने रशियाकडून कच्चे तेल पुन्हा घेतले. ट्रम्प भारताच्या आकांक्षा धुळीला मिळवत असताना केंद्र सरकार निमूट ऐकून घेत आहे. त्याचे कारण एपस्टीन फाइल्स हेच असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणविरोधी युद्धामध्ये भारताने अमेरिकेची बाजू घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले.

इराणशी भारताचे पारंपरिक संबंध होते, इराणकडून भारत कच्चे तेल विकत घेतो. इस्त्रायल-पॅलस्टिन संघर्ष वा इराण-अमेरिका संघर्ष असो, भारत आत्तापर्यंत तटस्थ राहिला. या वेळी मात्र भारताने अमेरिकेची बाजू घेतली. त्यामुळे भारत इराणविरोधात असल्याचे मानले गेले. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी इस्त्रायलच्या हल्ल्यात ठार झाल्यानंतर त्याबद्दल भारताने शोकही व्यक्त केला नाही. या घटनेच्या सहा दिवसांनंतर भारताकडून इराणच्या दूतावासात शोकसंदेश लिहिला गेला. या पक्षपाती भूमिकेचा फटका भारताला इंधनपुरवठ्याच्या राजकारणात बसला. एलपीजीचा तुटवडा वाढला, त्याचे परिणाम देशभर दिसू लागले. देशात रोष वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली. तेव्हा मात्र भारताने इराणशी संवाद सुरू केला, ताणलेले संबंध पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. एपस्टीन फाइल्स नसत्या तर केंद्र सरकार अशा कुठल्याही विषयावर दबावाखाली आले नसते, भारताला आंतरराष्ट्रीय धोरणामध्ये तडजोडच करावी लागली नसती. तसे झाले नसते तर इराणने भारताच्या इंधननौका मुळात अडवल्याच नसत्या. रशिया व चीन यांची इंधनपुरवठा जहाजे इराणने जाऊ दिली. भारताला मात्र तारेवरची कसरत करावी लागली, असा युक्तिवाद काँग्रेसने केला. एपस्टीन फाइल्सचा उल्लेख राहुल गांधींनी एलपीजी आणि इंधनाच्या मुद्द्यावर करण्यामागील हेच कारण असल्याचे दिसते. राहुल गांधी यांनी एपस्टीन एवढाच शब्द उच्चारला होता. बिर्ला म्हणत होते की, एलपीजीच्या विषयाशी एपस्टीनचा संबंध काय आणि संदर्भाबाहेरचे मुद्दे का मांडले जात आहेत. पण राहुल गांधी यांनी एपस्टीन या एका शब्दामधून सगळे धागे उलगडून दाखवले. राहुल गांधींना नेमके काय म्हणायचे आहे आणि ते काय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे केंद्र सरकारमधील चाणाक्षांनी ओळखले नसेल असे मानणे चुकीचे ठरेल. म्हणूनच एपस्टीन हा शब्द केंद्र सत्ताधाऱ्यांसाठी घातक ठरू लागला आहे. त्यातूनच त्यांची धांदल होऊ लागल्याचे दिसते.

अन्वयार्थ

रजा नको; पण...

मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना पगारी रजा देण्यासंदर्भातील गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच केलेल्या टिप्पणीमुळे सध्या तरी वेगळे वळण मिळाले आहे. देशभरातील महिलांना मासिक पाळीदरम्यान पगारी रजा द्यावी या मागणीसाठी शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी जनहित याचिका सादर केली होती. ही त्यांची या विषयावरची तिसरी याचिका होती. कायदा करून मासिक पाळीची रजा सक्तीची केली तर लोक स्त्रियांना नोकरी द्यायला कचरतील, त्यांच्यावर जबाबदारीची कामे टाकली जाणार नाहीत. यातून त्यांच्या करिअरचे नुकसान होऊ शकते अशी टिप्पणी करून सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेणेच नाकारले. लेखी निर्णयात आधीच्या याचिकांवरील निकाल कायम असल्याची

आठवण न्यायमूर्तींनी दिली असली, तरी तोंडी टिप्पणीचे गांभीर्य कमी होत नाही.

मासिक पाळी हे स्त्रीच्या आयुष्यातले अपरिहार्य असे जैविक चक्र. वयाच्या १२-१३ व्या वर्षी सुरू होऊन ते ४५-५० दरम्यान थांबते. या दरम्यान दर महिन्याला तीन ते चार दिवस होणारा रक्तस्राव ही नैसर्गिक गोष्ट असली तरी त्याचे स्वरूप, परिणाम प्रत्येक स्त्रीनुसार वेगवेगळे असतात. काही स्त्रियांना या दिवसात विशेषतः पहिल्या दोन दिवसांत अतोनात त्रास होतो, काही स्त्रियांना तो सहन करण्याइतपत असतो, तर काही स्त्रियांना फारसा त्रास होत नाही. पूर्वीच्या काळी मासिक पाळीच्या काळात विश्रांती मिळावी म्हणून स्त्रियांना ते चार दिवस बाजूला बसवले जाई. आता ती प्रथा मागे पडली असली तरी या काळात स्त्रियांना विश्रांती मिळावी म्हणून त्यांना पगारी रजा द्यावी ही मागणी गेली काही वर्षे लावून धरली गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये 'असे धोरण ठरवणे सरकारच्या हाती' असल्याचा निकाल दिला. बिहारमध्ये १९९२ पासून सरकारी कर्मचारी असलेल्या स्त्रियांना दरमहा दोन दिवस अशी रजा मिळते. कर्नाटकमध्ये गेल्या वर्षापासून सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये दरमहा या कारणासाठी एक रजा दिली जाते. याशिवाय ओडिशामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि केरळमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमधील स्त्रियांना दरमहा एक रजा दिली जाते. काही खासगी कंपन्यांनीही स्वतःहून स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान एक दिवस रजा दिली आहे. स्पेन, जपान यांच्यासह काही देशांनीही या रजेसंदर्भात कायदेशीर पावले उचलली आहेत.

असे असताना सरन्यायाधीशांनी ताजी याचिका का फेटाळली, हे समजून घेतले पाहिजे. साधारण दहा टक्के स्त्रियांनाच या काळात अतीव शारीरिक वेदना होतात, बाकीच्यांना थकवा, चिडचिडेपणा असतो. त्यांना मिळाली तर थोडी विश्रांती हवी असते. पण त्यासाठी रजेपेक्षाही घराबाहेर पडल्यावर भरपूर पाण्याची सोय असलेली स्वच्छतागृहे, सॅनिटरी नॅपकिन बदलण्याची व त्यांची विल्हेवाट लावण्याची सोय, कामाच्या ठिकाणी वाटलेच तर १०-१५ मिनिटे विश्रांती घेण्यासाठी सुविधा, कामाच्या ठिकाणी जाणेयेणे सुलभ असणे एवढे असेल तरी अनेकींना ते पुरेसे असते. पण तेवढ्याही सुविधा कार्यालयीन काम करणाऱ्या स्त्रियांना मिळत नाहीत. असंघटित क्षेत्रात, तसेच शारीरिक कष्टाची कामे करणाऱ्या स्त्रियांची तर आणखी वेगळी गोष्ट.

आपल्या देशात श्रमशक्ती (लेबर फोर्स)मध्ये आधीच स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी. स्त्रियांना रोजगार मिळवण्यासाठी आणि तो टिकवण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागते. त्यांच्या बाळंतपणाची रजादेखील अनेकदा त्यांच्या नोकरीमधला अडसर ठरते. अशा वेळी मासिक पाळीदरम्यान रजा सक्तीची झाली तर अनेक ठिकाणी स्त्रियांना नोकरी मिळणे अडचणीचे ठरू शकते. आधीच आपल्याकडे मासिक पाळीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन निरोगी नाही. त्यात अशा रजेमुळे तो आणखी बिघडू शकतो. तुम्हाला समानता हवी आहे, तर ही रजा का मागता, असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट रजेपेक्षाही मासिक ऋतुचक्र या स्त्रीच्या शारीर घटकाकडे संवेदनशीलतेने बघितले जावे, स्त्रीला त्या काळातील दैनंदिन जीवनात सहकार्य मिळावे यासाठी जाणीवजागृतीच नसेल तर न्यायालयीन सुनावण्या, निकाल वा सरकारी धोरणेही हतबल ठरतील.

इस्त्रायल-इराण युद्धामुळे खतपुरवठ्यावर परिणाम किती आणि कधी?

विश्लेषण

मोहन अटाळकर
mohan.atalkar@expressindia.com

इस्त्रायल/ अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायुपुरवठ्यासाठी जाहीर केलेल्या नवीन नियमावलीत खतनिर्मिती क्षेत्राला 'प्राधान्य क्षेत्र-२'चा दर्जा मिळाला असला, तरी खत प्रकल्पांना सरासरी वापराच्या ७० टक्केच नैसर्गिक वायुपुरवठा होऊ शकतो...

देशातील खतपुरवठ्याची स्थिती काय?

भारत हा जागतिक स्तरावर खतांचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आणि तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. भारताला दरवर्षी सुमारे सहा कोटी टन खताची गरज भासते. यापैकी बहुतांश खतांची आयात होते. भारतातील कृषी व्यवस्था ही प्रामुख्याने अवर्षण, जमिनीचा दर्जा, पिकांचे धोरण आणि रासायनिक खते यांच्या आधारावर अवलंबून आहे. यामध्येही युरिया हे सर्वात जास्त प्रमाणात वापरले जाणारे खत असून त्याच्या नियमित उपलब्धतेवर शेतमालाचे उत्पादन अवलंबून राहते. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये भारताने ३१४ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक देशांतर्गत युरिया उत्पादनाची नोंद केली आहे. आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशातील खतसाठ्याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात खतटंचाई भासणार नाही इतका पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात सध्या युरिया, डीएपी आणि इतर रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा (सुमारे १८० लाख मेट्रिक टन) उपलब्ध आहे. त्यामुळे खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना खत मिळण्यात अडचण येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप आणि रब्बी हंगामात सुमारे ७६ लाख मेट्रिक टन खतांचा वापर होतो. खतांचा वापर दरवर्षी वाढतच असून तो प्रतिहेक्टरी १४१ किलोपर्यंत पोहोचला आहे.

इस्त्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम काय?

भारताच्या एकूण युरिया आयातीत आखातातील ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीनचा वाटा सुमारे ७५ टक्के आहे. डीएपीची आयात प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, मोरोक्को, चीन, रशिया या देशांमधून होते. युद्धामुळे पश्चिम आशियातून होणाऱ्या आयातीवर परिणाम होत आहे. वाहतूक, विम्याचा खर्च वाढल्याने इतर देशांमधून आयात महाग होण्याची चिन्हे आहेत.

खत प्रकल्पांपुढील अडचणी कोणत्या?

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' (एस्मा) मधील अधिकारांचा वापर करून १० मार्च रोजी 'नैसर्गिक वायू (पुरवठा नियमन) आदेश २०२६' अधिसूचित केला आहे. त्यानुसार 'गेल्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ७० टक्के' गॅस मिळणे ही खत प्रकल्पांसाठी तात्पुरती दिलासादायक बाब असली, तरी प्रत्यक्षात ३० टक्के कपात ही उत्पादनावर परिणाम करणारी ठरेल. खत कंपन्यांना मिळणारा हा ७० टक्के गॅस केवळ खतनिर्मितीसाठीच वापरणे बंधनकारक असेल. यासाठी कंपन्यांना 'पेट्रोलियम प्लॅनिंग ॲण्ड ॲनालिसिस सेल'कडे वापराचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. गॅस कपातीमुळे उत्पादनाला फटका बसला, तर चिंताजनक स्थिती निर्माण होऊ शकते. जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे दीर्घकाळ लांबले, तर खत प्रकल्पांसमोरील संकटे वाढतील. अनेक कंपन्यांना उत्पादन बंद करावे लागेल.

कृषी उत्पादनावर परिणाम कसा?

सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, यूएई हे जगाला युरिया पुरवठा करणारे प्रमुख देश आहेत. युरिया, सल्फर आणि

अमोनिया यांचा सर्वाधिक पुरवठा या देशांमधून होतो. तर इराण हा अमोनियाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे. जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी या घटकांची आवश्यकता असते. मात्र, हे सर्वच देश युद्धात अडकले आहेत. त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा खतांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. सुमारे ४० टक्के खतांची वाहतूक या मार्गातून होते. खतपुरवठा ठप्प होणे हे शेतीसाठी धोकादायक संकेत आहेत. भारत खतांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. दरमहा सुमारे २० लाख टन एवढी खतांची आयात होते. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने खत अनुदानावर १.०९ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते.

पुढे काय होणार?

खत उद्योगांचा गॅसचा कोटा ७० टक्क्यांवर मर्यादित केल्यामुळे भविष्यात खतांच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आयात महागली, तर त्याचे ओझे सरकारी तिजोरीवर अनुदानाच्या रूपाने पडेल किंवा शेतकऱ्यांना त्याचा भार सहन करावा लागेल. खतपुरवठा कमी झाल्यास शेतमालाच्या उत्पादनावर पुढल्या हंगामात दुष्परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आयुष्यात सुख-समृद्धी, आर्थिक स्थैर्य आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी योग्य ‘अर्थभान’ अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे केवळ पैसे कमावणे नसून पैशांचे योग्य व्यवस्थापन, गुंतवणूक आणि बचतीचे नियोजन करणे आहे. हीच सध्याच्या काळाची गरज लक्षात घेऊन Loksatta.com या संकेतस्थळावर ‘लोकसत्ता अर्थभान’ हे आर्थिक माहिती देणारे सूक्ष्म संकेतस्थळ सुरु करण्यात आले आहे. याच्या नियमित वाचनाने आर्थिक आरोग्य उत्तम राखण्यास आणि सुरक्षित भविष्यासाठी नक्कीच मदत मिळेल.

‘लोकसत्ता अर्थभान’ ला भेट देण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा.

‘स्मॉल कॅप’मधील उत्तम दीर्घकालीन गुंतवणूक पर्याय

माझा पोर्टफोलिओ

अजय वाळिंबे

टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड (टाइम टेक) ही भारतीय कंपनी ही पॉलिमर उत्पादनांची आघाडीची उत्पादक असून ती बहरीन, इजिप्त, इंडोनेशिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, तैवान, थायलंड, व्हिएतनाम, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका येथे कार्यरत असलेली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या प्रेरित नावीन्यपूर्ण उत्पादने आहेत, जी औद्योगिक पॅकेजिंग सोल्युशन्स, जीवनशैली उत्पादने, ऑटोमोटिव्ह घटक, पायाभूत सुविधा / बांधकाम संबंधित उत्पादने, मटेरियल हँडलिंग सोल्यूशन आणि कंपोझिट सिलिंडर यासारख्या वाढत्या उद्योग विभागांना सेवा देतात.

टाइम टेक समूहाच्या जगभरात चाळीसहून अधिक उत्पादन सुविधा असून कंपनी नावीन्यपूर्ण प्लास्टिक उत्पादनांसाठी ओळखली जाते. वर्ष १९९२ मध्ये स्थापन झालेल्या, टाइम टेकने भारतीय ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि जागतिक ग्राहकांच्या गरजेतील तफावत भरून काढण्यासाठी २० उत्पादन प्रकल्प आणि ६ प्रादेशिक आणि विपणन कार्यालये स्थापन करून संशोधन आणि विकास, भविष्यकालीन उत्पादन डिझाइनिंग, उत्कृष्ट ग्राहक सेवेवर लक्ष केंद्रित करून स्वतःला वेगळे सिद्ध केले आहे.

बाजारपेठेतील नेतृत्व

देशांतर्गत औद्योगिक पॅकेजिंग विभागात कंपनीचा ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त बाजारहिस्सा आहे. ती मोठ्या आकाराच्या प्लास्टिक ड्रमची सर्वात मोठी उत्पादक, कंपोझिट सिलिंडरची दुसरी सर्वात मोठी उत्पादक आणि जागतिक स्तरावर इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्सची तिसरी सर्वात मोठी उत्पादक आहे. याव्यतिरिक्त, ती भारतातील मोक्स फिल्मची दुसरी सर्वात मोठी उत्पादक आहे आणि ती कार्यरत असलेल्या ११ देशांपैकी ९ देशांमध्ये बाजारपेठेतील आघाडीची आहे.

व्यवसाय विभाग

- **पॉलिमर उत्पादने :** एचएम-एचडीपीई प्लास्टिक ड्रम/जेरी कॅन आणि पेल्स, पॉलिथिलीन (पीई) पाईप, टर्फ आणि मॅटिंग्ज, डिस्पोजेबल बिन आणि एमओएक्स फिल्म्स
- **कंपोझिट उत्पादने:** इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (आयबीसी), कंपोझिट सिलिंडर (एलपीजी, ऑक्सिजन आणि सीएनजी), ऊर्जा साठवण उपकरणे, ऑटो उत्पादने आणि स्टील ड्रम.
- **स्थापित उत्पादने:** एचएम-एचडीपीई प्लास्टिक ड्रम/जेरी कॅन आणि पेल्स, पॉलिथिलीन (पीई) पाईप्स, टर्फ आणि मॅटिंग्ज, डिस्पोजेबल बिन, ऊर्जा साठवण उपकरणे, ऑटो उत्पादने आणि स्टील ड्रम.
- **मूल्यवर्धित उत्पादने :** इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (आयबीसी), कंपोझिट सिलिंडर (एलपीजी, ऑक्सिजन आणि सीएनजी) आणि एमओएक्स फिल्म्स

प्रमुख उत्पादने आणि महसूल विभाजन

- **औद्योगिक पॅकेजिंग (६२ टक्के) :** यामध्ये ड्रम, कंटेनर, जेरी कॅन आणि कोनिपॅक पेल्सचा समावेश आहे, सर्व टेकपॅक म्हणून नाममुद्रित आहेत आणि प्रामुख्याने केमिकल आणि ग्राहकोपयोगी उद्योगांमध्ये वापरले जातात.
- **इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (१३ टक्के) :** हे जागतिक स्तरावर जीएनएक्स नाममुद्रेअंतर्गत विकले जातात.
- **कंपोझिट सिलिंडर (११ टक्के):** यामध्ये लाइटसेफ एलपीजी सिलिंडर, पुढच्या पिढीचे अर्थात ‘नेक्स्ट जेन’ सीएनजी कॅस्केड्स आणि हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनसाठी सिलिंडरचा समावेश आहे.
- **पायाभूत सुविधा उपाय (७ टक्के):** पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, सांडपाणी इत्यादींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मॅक्स एम ब्रँडेड एचडीपीई पाईप्स आणि रेल्वे आणि सौरऊर्जा यासारख्या उद्योगांना पुरवल्या जाणाऱ्या मॅक्सलाइफ ब्रँडेड व्हॉल्व्ह-रेग्युलेटेड लीड-ॲसिड बॅटरीजचा समावेश आहे.
- **तांत्रिक आणि जीवनशैली (४ टक्के):** ते मॅटिंगसाठी ड्युरो वाइप, ड्युरो सॉफ्ट, ड्युरो टर्फ, ड्युरो कम्फर्ट आणि मीडोज आणि डिस्पोजल बिनसाठी डम्पो बिन यासारख्या टर्फ ब्रँडसह उद्योगांमध्ये विविध पर्याय उपलब्ध करून देते.
- **मोक्स फिल्म्स (३ टक्के):** कंपनी टेकपॉलिन म्हणून ब्रँडेड मल्टीलेयर मल्टी-ॲक्सिस ओरिएंटेड एक्स-क्रॉस लॅमिनेटेड फिल्म (एमओएक्स) प्रदान करते. आर्थिक वर्ष २०२२ आणि आर्थिक वर्ष २०२४ दरम्यान विक्रीचे प्रमाण १४ टक्के वाढले.

भौगोलिक विभाजन आणि कार्यादेश (आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये)

- **देशांतर्गत:** ६४ टक्के, **निर्यात:** ३६ टक्के
- **कार्यादेश :** आर्थिक वर्ष २०२६च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये, कंपनीकडे पीई पाईप्ससाठी २७५ कोटी रुपये आणि सीएनजी कॅस्केड्स सिलिंडरसाठी १६५ कोटी रुपयांचा कार्यादेश आहे. तसेच ४२५ कोटी रुपयांचा पॅकेजिंग कार्यादेश मिळाला आहे. प्रमुख ग्राहकः गोदरेज, लार्सन अँड टुब्रो, इंडियन ऑइल, ज्युबिलंट लाईफसायन्सेस, कारगिल, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स, व्होल्वो, विप्रो, इत्यादी

संशोधन आणि विकास

उपकंपनी एनईडी एनर्जी लिमिटेड तिच्या विद्यमान युनिटमध्ये लीड ॲसिड आणि लिथियममध्ये तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत टीबीएस (पारदर्शक कंटेनर बॅटरी) आणि ई-रिक्षा बॅटरी विकसित करत आहे. कंपनी कंपोझिट उत्पादनांपासून कंपोझिट अग्निशामक यंत्र आणि कंपोझिट वॉटर हीटर देखील विकसित करत आहे.

कंपनीचे तिसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल उत्तम आहेत. डिसेंबर २०२५ अखेर संपलेल्या तिमाहीसाठी कंपनीने १५६७ कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर १२६ कोटी रुपयांचा नक्त नफा कमवला आहे. गेल्या वर्षाच्या तिमाहीच्या तुलनेत उलाढालीत १३ टक्के वाढ साध्य केली असून निव्वळ नफा २५ टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत कंपनीने कर्जफेड करून आपले कर्ज ६४७ कोटींवरून ३८० कोटींपर्यंत खाली आणले आहे. येत्या सहा महिन्यांत कंपनी संपूर्ण कर्जमुक्त होईल अशी अपेक्षा आहे. सध्या नीचांकाजवळ असलेली ही कंपनी एक उत्तम दीर्घकालीन गुंतवणूक ठरू शकेल.

Stocksandwealth@gmail.com

टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड (५३२८५६)

शुक्रवारचा बंद भाव : **रु. १६१/-**

वर्षभरातील उच्चांक/ नीचांक : **रु. २४९/१५३**

बाजार भांडवल : **रु. ७,९५१ कोटी**

भरणा झालेले भागभांडवल

४९.३६ कोटी

शेअर होल्डिंग पॅटर्न (%)

प्रवर्तक	४७.५१
परदेशी गुंतवणूकदार	११.६६
बँका/ म्यु. फंड/ सरकार	१६.७०
इतर/ जनता	२४.१३
डेट इक्विटी गुणोत्तर	०.२२%

वेबसाइट: www.timetechnoplast.com

संक्षिप्त विवरण

- शेअर गट : स्मॉल कॅप
- प्रवर्तक : अनिलकुमार जैन
- व्यवसाय क्षेत्र : प्लॅस्टिक- पॉलिमर/ पॅकेजिंग
- पुस्तकी मूल्य : रु. ६१.६
- दर्शनी मूल्य : रु. १/-
- गतवर्षीचा लाभांश : २५०%

शेअर शिफारशीचे निकष

- प्रति समभाग उत्पन्न : ९.६१रु.
- पी/ई गुणोत्तर : १७.८
- समग्र पी/ई गुणोत्तर : २२.१
- इंटरेस्ट कव्हरेज गुणोत्तर : ८.२१
- बीटा : १.४
- गुंतवणूक कालावधी : २४ महिने
- रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉइड : १७.४%

माझा पोर्टफोलियो अंतर्गत सुचवलेल्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये लेखकाची वा त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांची (उपलब्ध माहितीप्रमाणे) कुठलीही गुंतवणूक नाही किंवा असल्यास ती कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलाच्या १% पेक्षा कमी आहे. तसेच सुचवलेल्या कंपनीशी लेखकाचा कुठलाही संबंध नसून त्याने कंपनीकडून कुठलेही मानधन अथवा भेटवस्तू घेतलेली नाही.

अस्वस्थ जगात पोर्टफोलिओत सोन्याचे स्थान

फंड मॅनेजरच्या डायरीतून

प्रसन्न पाठक

शतकांपासून, जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत सोन्याचे एक अद्वितीय स्थान राहिले आहे. आधुनिक भांडवली बाजार अस्तित्वात येण्यापूर्वी, सोने हे मूल्याचे भांडार, विनिमयाचे माध्यम आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रतीक म्हणून काम करत होते. आजही युद्ध, करोनासारख्या जागतिक संकट प्रसंगी आर्थिक साधने आणि डिजिटल मालमत्ता उपलब्ध असूनही - पोर्टफोलिओमध्ये सोने महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी, सोन्याचे महत्त्व केवळ त्याच्या किंमत वाढीच्या क्षमतेत नाही. जेव्हा आपण मालमत्ता वाटपात त्याची भूमिका तपासतो तेव्हा त्याचे खरे महत्त्व समोर येते. सोने एक शक्तिशाली वैविध्यात प्रभावी साधन म्हणून काम करते. कारण ते इक्विटी आणि रोखे दोन्हीशी कमी सहसंबंध दर्शवते, ज्यामुळे ते अनिश्चित आर्थिक आणि बाजार परिस्थितीमध्ये सर्वात प्रभावी स्थैर्य देणारे म्हणून ओळखले जाते.

पोर्टफोलिओत वैविध्याची भूमिका

मालमत्ता वाटपाचे मुख्य तत्त्व सोपे आहेः आर्थिक आवर्तनांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने वागणाऱ्या मालमत्ता एकत्रित केल्याने एकूण पोर्टफोलिओ जोखीम कमी होते. इक्विटी बाजार सामान्यतः आर्थिक वाढ, कंपन्यांची कमाई आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांशी जोडलेले असतात. स्थिर उत्पन्न साधने व्याजदर आणि पत परिस्थितींद्वारे चालविली जातात.

मात्र, सोने अनेकदा वेगळ्या लयीत जाते. त्याची कामगिरी जागतिक रोकड सुलभता, चलन बाजार, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि वाढत्या महागाईच्या अपेक्षांमुळे प्रभावित होते. या विशिष्ट घटकांमुळे, सोन्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या पारंपरिक वित्तीय मालमत्तेशी कमी किंवा अगदी नकारात्मक सहसंबंध दर्शविला आहे. बाजारातील ताणतणावाच्या काळात हे वैशिष्ट्य विशेषतः मौल्यवान बनते. जेव्हा समभागांमध्ये अस्थिरता किंवा घसरण येते, तेव्हा सोने अनेकदा संतुलन म्हणून काम करते, ज्यामुळे पोर्टफोलिओ तोटा कमी होण्यास मदत होते. थोडक्यात, सोने परतावा तयार करण्यासाठी नव्हे तर पोर्टफोलिओच्या विम्यासारखे अधिक काम करते.

अस्थिरता आणि संकटाविरुद्ध बचाव

आज जग अनिश्चिततेचे वेढले आहे. भू-राजकीय तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अशा वातावरणात, गुंतवणूकदार स्वाभाविकपणे मूल्य जपणाऱ्या मालमत्तेकडे आकर्षित होतात. सोन्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या संकटाच्या काळात आणि वाढत्या अस्थिरतेच्या काळात चांगली कामगिरी केली आहे. जेव्हा वित्तीय बाजारपेठ अस्थिर होतात, तेव्हा गुंतवणूकदार अशा अमूर्त मालमत्तांकडून सोन्यासारख्या मूर्त मालमत्तेकडे वळतात. ज्या सरकार किंवा कंपन्या पतपात्रतेशी जोडलेल्या नाहीत. सोने त्या वर्णनात पूर्णपणे बसते. अलीकडील सोन्याच्या किंमतीतील वाढ या गतिमानतेचे द्योतक आहे. गेल्या वर्षी सोने प्रति औंस ५,१८० डॉलरच्या आसपास होते. जे लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरू असूनही, अमेरिकी डॉलरच्या अलीकडच्या मजबुतीमुळे सोन्याच्या किमतीतील वाढ काही प्रमाणात कमी झाली आहे. जागतिक स्तरावर सोन्याची किंमत डॉलरमध्ये असल्याने, मजबूत डॉलर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी धातू अधिक महाग करून नफा मर्यादित करतो.

हा लेख लिहीत असताना डॉलर निर्देशांक १००.३० च्या जवळ आहे, कारण सोन्याच्या किमती ५,६०० डॉलरच्या जवळच्या विक्रमी उच्चांक आणि ४,४०० डॉलरच्या आसपासच्या नीचांकी दरम्यान सतत चढ-उतार होत आहेत. डॉलरमधील निर्णायक ‘ब्रेकआउट’ सोन्याच्या हालचालीच्या पुढील टप्प्यावर परिणाम करू शकतो. तरीही व्यापक मुद्दा कायम आहे.

सोने महागाई रोखण्यासाठी कार्यरत

सोने महागाई रोखण्यासाठी एक उपाय म्हणून आणखी एक महत्त्वाची भूमिका बजावते. चलनवाढ कालांतराने पैशाची खरेदी शक्ती कमी करते. चलनवाढीच्या काळात अनेक वित्तीय मालमत्ता संघर्ष करू शकतात, परंतु सोन्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या मूल्य जपले आहे.

तर्क सरळ आहे. मध्यवर्ती बँकांद्वारे सोने छापले जाऊ शकत नाही आणि ते अमर्याद पुरवठ्यात तयार केले जाऊ शकत नाही. जेव्हा महागाई वाढते किंवा गुंतवणूकदारांना जास्त आर्थिक विस्ताराची भीती वाटते तेव्हा सोने मूल्याचा नैसर्गिक साठा बनते. यामुळेच सोने अनेकदा कमकुवत चलन धोरण, वाढत्या महागाईच्या अपेक्षा आणि नकारात्मक वास्तविक व्याजदरांच्या काळात चांगले प्रदर्शन का करते हे स्पष्ट होते

भारतीय गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीतून सोने

भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, सोने एक अतिरिक्त फायदा देते. ज्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, ते म्हणजे चलन संरक्षण. सोन्याची आंतरराष्ट्रीय किंमत अमेरिकी डॉलरमध्ये असल्याने, भारतीय रुपयाचे कोणतेही अवमूल्यन रुपयाच्या दृष्टीने सोन्याचे परतावे वाढवते. दुसऱ्या शब्दांत, जरी जागतिक स्तरावर सोन्याचे भाव स्थिर राहिले तरी, कमकुवत रुपयामुळे देशांतर्गत सोन्याच्या किमती वाढतात. ज्या काळात डॉलर जागतिक स्तरावर मजबूत होतो, त्या काळात उदयोन्मुख बाजारातील चलने - रुपयासह अनेकदा डॉलरच्या तुलनेत घसरतात. ही गतिमानता भारतीय पोर्टफोलिओसाठी एक नैसर्गिक ‘हेज’ प्रदान करते, ज्यामुळे सोने स्थिर मालमत्ता म्हणून आणखी मौल्यवान बनते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, या चलन परिणामाचा अर्थ असा आहे की, भारतातील सोन्याचा परतावा बहुतेकदा केवळ जागतिक डॉलरच्या किमतीपेक्षा जास्त मजबूत राहिला आहे.

सोन्याचे योग्य वाटप

पोर्टफोलिओ बांधताना, सोन्याला सट्टेबाजीचा व्यापार म्हणून नव्हे तर एक धोरणात्मक वाटप म्हणून पाहणे ही परतावा वाढविण्याची गुरुकिल्ली आहे. पोर्टफोलिओच्या एकूण आकारमानाच्या ५ टक्के ते १५ टक्के सोन्याचे त्यात प्रमाण असावे, असे बहुतेक जागतिक वित्तीय सल्लागार असे सुचवतात. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, अतिरिक्त चलन ‘हेज’ लाभ आणि धातूकडे दीर्घकालीन सांस्कृतिक ओढ लक्षात घेता, या श्रेणीच्या उच्च टोकाकडे - सुमारे १० टक्के ते २० टक्के वाटप करणे अर्थपूर्ण आहे. असे वाटप पोर्टफोलिओ अस्थिरता कमी करण्यास मदत करते आणि दीर्घकालीन जोखीम-समायोजित परतावा सुधारते.

ज्या गुंतवणूकदारांनी या आधी सोन्याकडे गुंतवणूक या दृष्टिकोनातून पाहिले नाही, त्यांच्यासाठी, पद्धतशीर गुंतवणुकीद्वारे (एसआयपी) पोर्टफोलिओत हळूहळू सोन्याचे प्रमाण वाढविणे हा एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोन असू शकतो. विशेषतः अशा वातावरणात जागतिक घडामोडींमुळे अल्पकालीन किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात.

सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा आधुनिक मार्ग

आज, गुंतवणूकदारांना त्याच्या पोर्टफोलिओत फायदा घेण्यासाठी सोने मूर्त रूपात खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. वित्तीय बाजारपेठा ‘गोल्ड ईटीएफ’सारखे कार्यक्षम आणि पारदर्शक मार्ग देतात, जे सोन्याच्या किमतीचा मागोवा घेतात आणि साठवणूक आणि शुद्धतेशी संबंधित चिंता दूर करतात. आणखी एक प्रभावी मार्ग म्हणजे ‘मल्टी ॲसेट ॲलोकेशन फंड्स’, जिथे निधी व्यवस्थापक बाजार आवर्तनांत संतुलित गुंतवणूक राखण्यासाठी ‘इक्विटी’, रोखे आणि सोन्यामध्ये गतिमानपणे वाटप करतात. ही साधने गुंतवणूकदारांना सोईस्कर आणि नियंत्रित गुंतवणूक चौकटीत सोन्याचे विविधीकरण फायदे मिळवण्यास अनुमती देतात.

निष्कर्ष

आर्थिक आवर्तने, भू-राजकीय बदल आणि वित्तीय बाजारातील अस्थिरतेद्वारे परिभाषित जगात, मालमत्ता वाटप ही यशस्वी गुंतवणुकीचा आधारस्तंभ आहे. इक्विटी आणि रोखे त्याचा कमी सहसंबंध, महागाईशी लढण्याची क्षमता, बाजारातील अस्थिरतेदरम्यान लवचीकता आणि चलन अवमूल्यनापासून संरक्षण यामुळे ते चांगल्या पोर्टफोलिओचा एक अपरिहार्य घटक बनते.

सोने नेहमीच दरवर्षी सर्वोत्तम कामगिरी करणारी मालमत्ता नसली तरी ते मौल्यवान आहे. त्याचा उद्देश इतर सर्व गोष्टींपेक्षा चांगली कामगिरी करणे नाही - जेव्हा इतर मालमत्ता संघर्ष करतात तेव्हा पोर्टफोलिओ स्थिर राखणे आवश्यक आहे. ‘गोल्ड ईटीएफ’ असो किंवा ‘मल्टी ॲसेट ॲलोकेशन फंड’ असो, सुमारे १०-२० टक्क्यांच्या शिस्तबद्ध पद्धतीने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

(लेखक द वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ही मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

जबाबदार निवृत्ती नियोजनासाठी जीवन विमा

चला विमा समजून घेऊ

केदार पत्की

संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात किरकोळ बचतीच्या माध्यमातून पेन्शन फंड जमा करण्याकडे भारतीयांचा कल वाढल्याचे दिसून आले. निवृत्ती नियोजनासाठी हे अतिशय महत्त्वाचे साधन आहे. हा बदल प्रामुख्याने बदलती कौटुंबिक व्यवस्था, वाढलेले आयुर्मान, आरोग्यावरील खर्च, तसेच वाढते दरडोई उत्पन्न आणि त्यानुसार बदलणारे राहणीमान यांचा एकत्रित परिणाम असण्याची शक्यता आहे.

या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे नागरिक आता पारंपरिक निवृत्ती साधनांचे - जसे की भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) आणि दीर्घकालीन म्युच्युअल फंड या पर्यायांचे पुनर्मूल्यांकन करत आहेत. त्यासोबत जीवन विमा उत्पादनांचाही विचार करत आहेत. या सगळ्या पर्यायांचा वापर करून अधिक सुरक्षित निवृत्ती निधी उभारता येऊ शकतो.

संरक्षणापलीकडेः जीवन विम्याची बदलती भूमिका

जीवन विम्याचा मूलभूत उद्देश म्हणजे विमाधारकाच्या आकस्मिक निधनाच्या प्रसंगी कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता देणे हा आहे. पण आज जीवन विम्याची भूमिका केवळ संरक्षणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.

निवडक जीवन विमा उत्पादने आता व्यक्तींना स्वतःसाठी आणि जोडीदारासाठी सन्मानजनक निवृत्त जीवनाचे नियोजन करण्यास मदत करतात. पुढील पिढ्यांसाठी संपत्ती हस्तांतरणासही या विमा उत्पादनांची मदत होते. गॅरंटीड सेव्हिंग स्कीम, पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी आणि ॲन्युइटी लिंक्ड प्रॉडक्ट यामधून शेअर बाजारातील अस्थिरतेच्या काळातही निश्चितता पुरवली जाते. उत्पन्नाचे हे स्थिर पर्याय अनेक भारतीय कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण भारतात जोखीम स्वीकारण्याची प्रवृत्ती तुलनेने कमी असते.

निवृत्तीमुळे निर्माण होणारी उत्पन्नातील तूट भरून काढणे

संयुक्त कुटुंब पद्धतीऐवजी विभक्त कुटुंब पद्धती वाढत असताना आणि सामाजिक सुरक्षेचे कवच मर्यादित असताना, निवृत्त व्यक्तींना स्थिर आणि निश्चित उत्पन्नाच्या हमीची गरज अधिक भासते.

या पार्श्वभूमीवर, ॲन्युइटी योजना भारतात अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. तात्काळ (इमिडिएट) ॲन्युइटी आणि विलंबित ॲन्युइटी योजना नागरिकांना त्यांनी साठवलेल्या रकमेचे नियमित उत्पन्नात रूपांतर करण्याची संधी देतात. ज्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, अशांसाठी या योजना अत्यावश्यक खर्च भागवण्यासाठी नियोजनबद्ध आणि विश्वासार्ह उपाय ठरतात.

करसवलतींचा धोरणात्मक लाभ

कर-कार्यक्षम निवृत्ती नियोजनात जीवन विम्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

प्राप्तिकर कायद्यानुसार, भरलेले प्रीमियम कलम ८० सी अंतर्गत दरवर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावटीस पॉलिसीधारक पात्र ठरतात. विमा कंपनीद्वारे चालविलेल्या पेन्शन किंवा वार्षिकी योजनांमध्ये केलेले योगदानही याच मर्यादेत समाविष्ट होते. तसेच, विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून पॉलिसीची मुदतपूर्ती रक्कम आणि मृत्यू लाभ हे कलम १० (१०डी) अंतर्गत करमुक्त असतात.

या सर्व करसवलती उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींना करानंतरचे निवृत्ती उत्पन्न अधिक परिणामकारकपणे नियोजित करण्यास मदत करतात, तसेच संरक्षण आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधण्यास साहाय्य करतात.

आरोग्य जोखमींपासून निवृत्ती बचतीचे संरक्षण

आरोग्यावरील खर्चाची तयारी आपल्याकडे निवृत्ती नियोजनाचा एक महत्त्वाचा घटक असतो. जीवन विम्यासोबत क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी आणि लॉन्ग टर्म केअर रायडर्सचा समावेश केल्यास अनपेक्षित वैद्यकीय खर्चामुळे निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नावर होणारा विपरीत परिणाम टाळता येणे शक्य आहे..

विशेषतः महानगरांतील उच्च उत्पन्न गटातील नोकरदारवर्ग मोठ्या प्रमाणात जास्त जीवन संरक्षण कवच निवडत आहेत आणि अपघाती मृत्यू लाभापेक्षा गंभीर आजारपणांत उपयुक्त ठरणाऱ्या रायडर्सना अधिक प्राधान्य देत आहेत.

दक्षिणेकडील शहरात प्रामुख्याने याबाबतची जागरुकता अधिक आहे. त्यात हैदराबादमध्ये १२ ते १३ टक्के, बंगळूरमध्ये १० ते १२ टक्के आणि कोचीमध्ये ९ ते १२ टक्के जीवन विमाधारकांनी वरील रायडर्स स्वीकारले आहेत. तर मुंबईकरांमध्ये हे प्रमाण ७ ते १० टक्के असल्याचे बघायला मिळते.

लवकर सुरुवात, नियमित पुनरावलोकन

निवृत्ती नियोजनाची सुरुवात जितकी लवकर केली जाईल तितके परिणाम अधिक चांगले मिळतात. गेल्या काही वर्षांत जीवन विम्याकडे आता केवळ करबचतीचे साधन म्हणून पाहणे कमी होते आहे. जीवन विमा आता संपत्तीचे संरक्षण आणि दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वततेचा एक महत्त्वाचा स्तंभ बनत चाललाय.

संरक्षण आणि नियमित उत्पन्न या दोन्ही बाबींचा समतोल साधणारा जीवन विमा नागरिकांना सन्मानाने आणि स्वावलंबीपणे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगण्यास मदत करतो. तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांचीही योग्य काळजी घेतो. बदलत्या आर्थिक आणि वैयक्तिक परिस्थितीनुसार विमा संरक्षण आणि निवृत्ती धोरणाचे नियमित पुनरावलोकन करणे अत्यावश्यक आहे.

(लेखक, इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी)

'लाइफ सायकल फंड': नाकापेक्षा मोती जड?

साधारण आराखडा खालीलप्रमाणे असेल:

'मॅच्युरिटी'साठी उर्वरित वर्षे	समभाग (शेअर्स)	कर्जरोखे (डेट)	जोखीम श्रेणी
१५-३० वर्षे	जास्त (वाढीवर भर)	कमी	आक्रमक
१०-१५ वर्षे	तुलनेने जास्त	मध्यम	वृद्धीक्षम
५-१० वर्षे	संतुलित	संतुलित	मध्यम
३-५ वर्षे	कमी	जास्त	कमी
१ वर्षापेक्षा कमी	अत्यल्प	प्रामुख्याने रोखे	भांडवल रक्षण

मर्यादा आणि गुंतवणूकदारांनी विचारात घ्याव्यात अशा गोष्टी

- प्रमाणीकरण विरुद्ध वैयक्तीकरण 'ग्लाइड पाथ' हे गृहीत धरतो की, गुंतवणुकीचा कालावधी हा मालमत्ता-वाटप ठरवणारा एकमेव घटक आहे. प्रत्यक्षात, एकाच वर्षी निवृत्त होणाऱ्या दोन व्यक्तींची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे भिन्न असू शकते (उदा. निवृत्ती निधी, मालमत्ता किंवा इतर उत्पन्न). एक सरसकट नियम सर्वांना लागू पडेलच असे नाही.
- नियोजनातला एकारलेपणा: आयुष्यात अनेकदा गोष्टी आपण ठरवतो तशाच घडतात असे नाही. निवृत्ती लवकर घ्यावी लागते किंवा नोकरीत मुदतवाढ मिळते. पाल्यांना शिक्षणासाठी प्रवेश पुढेमागे होऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये, एक निश्चित मार्ग गुंतवणूकदाराच्या बदलत्या परिस्थितीशी पूर्णपणे जुळेल असे नाही.
- पोर्टफोलिओ 'ओव्हरलॅप': ज्यांच्याकडे 'लाइफ सायकल फंडा'सोबत इतरही म्युच्युअल फंड असतील, त्यांना एकूण 'इक्विटी' प्रमाणावर लक्ष ठेवावे लागेल. सुरुवातीच्या काळात, जेव्हा 'लाइफ सायकल फंड' ७०-९० टक्के 'इक्विटी' गुंतवणूक करतात, त्या वेळी अनवधानाने एकूण पोर्टफोलिओमधील जोखीम गरजेपेक्षा जास्त वाढू शकेल.

'लाइफ सायकल फंड' कसे काम करतील?

१ **मूळ संरचना :** प्रत्येक 'लाइफ सायकल फंड' एका ठरावीक वर्षाशी जोडलेला असेल, ज्याचा उल्लेख फंडाच्या नावात असणे बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, 'लाइफ सायकल फंड २०४५' किंवा '२०५५'. हे केवळ नाव नसून, गुंतवणूकदार किती काळासाठी गुंतवणूक करण्यास बांधील आहे, याचा तो स्पष्ट संकेत असेल.

- भांडवली बाजार नियामक 'सेबी'च्या नियमानुसार, हे फंड ५ ते ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी, ५ वर्षांच्या फरकाने (उदा. २०२५, २०३०, २०३५) सादर केले जातील.
- स्पष्टता राखण्यासाठी, प्रत्येक फंड घराणे एकाच वेळी जास्तीत जास्त ६ 'लाइफ सायकल फंड' चालवू शकेल.

२ **'ग्लाइड पाथ':** काळानुसार मालमत्तेचे वाटप या फंड गटाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे 'ग्लाइड पाथ', म्हणजे एक पूर्वनिर्धारित वेळापत्रक, जे 'मॅच्युरिटी'चे वर्ष जवळ येईल तशी पोर्टफोलिओमधील जोखीम टप्प्याटप्प्याने कमी करेल.

- सुरुवातीच्या काळात, गुंतवणुकीचा कालावधी मोठा असल्याने 'इक्विटी'चे (समभाग) प्रमाण जास्त असेल.
- जसजशी मुदत जवळ येईल, तसतसे हे प्रमाण 'डेट' (कर्जरोखे) आणि कमी अस्थिरता असलेल्या साधनांकडे वळवले जाईल. शेवटच्या टप्प्यात मुद्दल सुरक्षित ठेवण्याला प्राधान्य दिले जाईल. **(कोष्टक पहा.)**

येथे महत्त्वाचा मुद्दा असा की, हा बदल पूर्वनियोजित असेल, तो निधी व्यवस्थापकाच्या मर्जीवर किंवा बाजार परिस्थितीवर अवलंबून नसेल.

३ **बहु-मालमत्ता गुंतवणूक (मल्टी-ॲसेट एक्सपोजर)**

समभाग आणि रोख्यांव्यतिरिक्त, 'लाइफ सायकल फंड' सोने आणि चांदी ईटीएफ, इन्व्हिट्स आणि मौल्यवान धातूंशी संबंधित 'कमॉडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज'मध्येही गुंतवणूक करू शकतील. या बहु-मालमत्ता रचनेमुळे वैविध्य मिळेल आणि दीर्घकाळात महागाईविरुद्ध संरक्षण मिळण्यास मदत होऊ शकेल.

रचनात्मक फायदे: हे उत्पादन काय उत्तम करते?

वर्तणूक स्वयंचलन (बिहेव्हियरल ऑटोमेशन): या फंड गटाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे फेर-संतुलनाच्या निर्णयातील मानवी हस्तक्षेप काढून टाकणे. गुंतवणूकदार सहसा बाजार तेजीत असताना समभाग गुंतवणूक वाढवतात आणि मंदीत कमी करतात, जे चुकीचे आहे. 'ग्लाइड पाथ' याच्या नेमके उलट, म्हणजे शिस्तबद्ध आणि टप्प्याटप्प्याने जोखीम कमी करण्याचे काम करेल.

कर-कार्यक्षम फेर-संतुलन : जर तुम्ही स्वत: पोर्टफोलिओ संतुलित केला आणि नफ्यात असलेले समभाग विकले, तर तुम्हाला भांडवली नफा कर अर्थात 'कॅपिटल गेन्स टॅक्स' भरावा लागतो. मात्र, 'लाइफ सायकल फंडा'मध्ये हे अंतर्गत पातळीवर होत असल्याने गुंतवणूकदाराला उलाढालीवर कर भरावा लागणार नाही. २०-३० वर्षांच्या कालावधीत ही करबचत परताव्यामध्ये मोठी भर टाकू शकेल.

सोईस्करपणा: ज्यांना पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन अवघड वाटते, त्यांच्यासाठी ही रचना अगदी सोईस्कर ठरेल: एक फंड, एक एसआयपी, एक कालमर्यादा. अनेक योजनांचे निरीक्षण, मालमत्ता-वाटपातील विसंगती शोधणे आणि वेळोवेळी पुनर्संतुलन करणे. हा संपूर्ण बोजा नाहीसा होईल.

बांधिलकीचा विरोधाभास आणि भारतीय वास्तव

'लाइफ सायकल फंड' संकल्पनेतला मोठा विरोधाभास वर्तणुकीशी संबंधित आहे. हे उत्पादन २० ते ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन बांधिलकीसाठी बनवले आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांचा आजवरचा इतिहास वेगळीच कहाणी सांगतो.

- 'ॲम्फी'च्या आकडेवारीनुसार, एका महिन्यात बंद होणाऱ्या 'एसआयपी'चे नव्या 'एसआयपी'शी प्रमाण जुलै २०२४ मधील सुमारे ५१ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०२४ मध्ये ८२.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आणि मार्च २०२५ मध्ये ते १२८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त 'रेशो' म्हणजे नव्याने सुरू होणाऱ्यापेक्षा जास्त 'एसआयपी' बंद होत आहेत.
- एसआयपीच्या सरासरी कालावधीबाबत 'ॲम्फी' थेट आकडेवारी प्रकाशित करत नाही, पण सरासरी 'एसआयपी' दोन ते तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकत नाहीत, असा अंदाज केला जातो. 'लाइफ सायकल फंड' पाच ते तीस वर्षांसाठी तयार केलेले असताना, हे अंतर काळजी करण्यासारखे आहे.

जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने '२०५५'चा फंड निवडला, पण बाजारातील चढ-उतार पाहून ४-५ वर्षांतच पैसे काढले, तर या उत्पादनाचा फायदा त्याला मिळणार नाही. गुंतवणूकदार जर शेवटपर्यंत टिकून राहिला तरच 'ग्लाइड पाथ' त्याच्यासाठी यशस्वी ठरू शकेल.

लाइफ सायकल फंडांचा कोणी विचार करावा आणि कोणी करण्याची गरज नाही

यांच्यासाठी योग्य:

- स्पष्ट दीर्घकालीन ध्येय असलेले तरुण गुंतवणूकदार, विशेषत: जे आर्थिक सल्लागाराशिवाय गुंतवणूक करतात.
- स्वयं-निर्देशित गुंतवणूकदार जे आपल्या स्वत:च्या वर्तणूक पूर्वग्रहांना ओळखतात आणि ज्यांना एक शिस्तबद्ध यंत्रणा हवी आहे.
- पहिल्यांदाच गुंतवणूक विश्वात प्रवेश करणारे गुंतवणूकदार जे साधेपणा आणि रचना शोधत आहेत.
- ज्यांना एकाच साधनात दीर्घकालीन, स्वयंचलित, कर-कार्यक्षम बहु-ॲसेट गुंतवणूक हवी आहे.

यांना टाळता येईल:

- जे आधीच सक्षम आर्थिक सल्लागारासोबत काम करत आहेत.
- ज्यांची अनेक आणि गुंतागुंतीची आर्थिक ध्येये आहेत.
- ज्यांचा पोर्टफोलिओ खूप मोठा आहे आणि ज्यांना एकात्मिक व्यवस्थापनाची गरज आहे.
- ज्यांचा कालावधी १० वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना यातील 'ग्लाइड पाथ'चा पूर्ण लाभ घेता येणार नाही.

लाइफ सायकल फंड हे 'गुंतवणूक करा आणि विसरून जा' या धोरणासाठी एक उत्तम साधन ठरू शकतात. पण अट एकच, तुमची विसरून जाण्याची तयारी आणि तशी गरज असायला हवी.

लेखक 'इक्विरस' समूहाचे मुख्य व्यवसायवृद्धी अधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.
sandeep. walunj@zohomail.in

'फिर हेरा फेरी'

वित्तरंजन

आशीष थत्ते

चित्रपटात वित्त कधी फक्त एखाद्या संवादात असते किंवा कधी अख्खा चित्रपट त्यावर बेतलेला असतो तर काही चित्रपटांत वित्तविषयक संकल्पना शोधाव्या लागतात. बाबुराव गणपतराव आपटे म्हणजे परेश रावल, अक्षय कुमार आणि सुनील शेट्टी यांचा बहुचर्चित आणि दूरचित्रवाणीवर बऱ्याच वेळेला लागणाऱ्या या चित्रपटात वित्तीय संकल्पना तशा ठळक असल्या तरीही इतर आशयांमुळे त्या झाकोळल्या जातात. या चित्रपटात माझ्या दृष्टीने दोन संकल्पना महत्त्वाच्या होत्या. पहिली म्हणजे सुरुवातीलाच अक्षय कुमार आपल्या दोन्ही मित्रांना एका 'चिट फंड'मध्ये गुंतवणूक करायला भाग पाडतो. चिट फंड त्यांना २१ दिवसांत पैसे दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवतो. चित्रपटात हे अगदी विनोदी पद्धतीने दाखवले असले तरी आपल्या आसपास अशा भूलथापांना बळी पडणारे काही कमी नाहीत. मागच्याच वर्षी 'टोरेस ज्वेलर्स'ने केलेला 'पॉन्झी स्कॅम' तुम्हाला आठवतच असेल. आजसुद्धा त्याच्या खऱ्या सूत्रधारांचा शोध संपलेला नाही आणि गुंतवणूकदारांचे पैसेसुद्धा परत मिळाले नाहीत. वर्ष २०२४ मध्ये वित्तरंजन सदरात मी अशा फसव्या योजनांची रचना कशी केली जाते आणि यांना 'पॉन्झी स्कीम' का म्हटले जाते, हे लिहिले होते. ठाण्यासारख्या छोट्या शहरातसुद्धा अलीकडेच एक 'पॉन्झी' घोटाळा उघडकीला आला, त्यात गुंतवणूकदारांचे तब्बल ५०० कोटी रुपये बुडवले गेल्याचा आरोप आहे. चित्रपटात जरी विनोदी पद्धतीने दाखवले गेले असले तरी सुज्ञ गुंतवणूकदारांना हा मोठा धडा आहे की, झटपट परतावा देणाऱ्या या योजनांपासून सावध राहिले पाहिजे. चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे या योजनांचा बुरखा फाटल्यावर त्या ठिकाणी गुंतवणूकदार जमा होतात आणि कंपनीच्या कार्यालयाला एक दिवस अचानक टाळे लागलेले त्यांना दिसते. प्रत्यक्षातसुद्धा असेच होते, हे टोरेसच्या अनुभवातून सिद्ध झाले.

पण याच चित्रपटात एक अजून महत्त्वाची शिकवण किंवा गुंतवणुकीचा एक रस्ता दाखवलेला आहे. सामान्य माणसे याचा विचारदेखील करत नाहीत. पण ज्यांना जुन्या वस्तूंमध्ये रस आहे, त्यांना मी काय म्हणतोय ते समजेल. चित्रपटात एक पारसी गृहस्थ आपल्या घरामध्ये सव्वासहा कोटी रुपयांच्या जुन्या बंदुका संग्रह म्हणून ठेवतो. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला बिनविरोध निवड झालेले अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आपल्याकडे २५ कोटी रुपयांचे 'आर्टवर्क' म्हणजे एखादे चित्र, शिल्प किंवा मूर्तीमध्ये गुंतवणूक असल्याचे जाहीर केले होते. ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेते अभिनव बिंद्रा यांनी आपली पदक विजेती बंदूक उद्योगपती हर्ष गोयंका यांना त्यांची खेळाची आवड बघून दिली आहे. थोडक्यात काय तर गुंतवणूकदारांनी अशा अपारंपरिक गुंतवणुकीचे मार्गदेखील निवडावेत आणि असे मार्ग निवडणारे फक्त चित्रपटात नसून प्रत्यक्षातसुद्धा आहेत. आपल्या देशामध्ये बंदुका किंवा लष्करी वस्तू बाळगण्यास बरीच बंधने आहेत. त्याला विशिष्ट परवाना घ्यावा लागतो आणि वरचेवर त्याची माहितीसुद्धा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये द्यावी लागते मग तुम्ही बंदूक स्वसंरक्षणासाठी घेतली आहे किंवा गुंतवणूक म्हणून घेतली आहे. त्याला काही अपवादसुद्धा आहेत पण बऱ्याच ठिकाणी परवाना असावाच लागतो. त्यात अजून म्हणजे तलवारी किंवा इतर शस्त्रांमध्ये गुंतवणूकसुद्धा करू शकतो पण पुन्हा कायद्याची काळजी घ्यावी लागतेच. काही हौशी लोकांकडे आजसुद्धा जुन्या काळातील तलवारी त्यांच्या म्यानी आणि इतर जुनी लष्करी साधने आहेत. अशा अपारंपरिक गुंतवणुकीमध्ये कमी काळात फायदे मिळतातच असे नाही आणि प्राप्तिकरामध्येसुद्धा काहीही सूट मिळत नाही, त्यामुळे त्याचा विचार करूनच गुंतवणूक करा. अजून एक म्हणजे त्यात फसवणूक होण्याचीसुद्धा शक्यता असते. जाणकार माणसांना खरी पुरातन काळातील बंदूक आणि त्याची प्रतिकृती यातील फरक समजतो. पण सामान्य गुंतवणूकदारांना तो समजेलच असे नाही. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार या वाटेला जाईलच असे नाही.

असो, चित्रपट इंटरनेटवर विनामूल्य उपलबध आहे. नीरज व्होरा यांनी दिग्दर्शित केलेला वर्ष २००६ चा हा चित्रपट हसवणारा असला तरी काही गुंतवणुकीचे सल्लेदेखील देऊन जातो फक्त तुमची बघण्याची दृष्टी हवी.

लेखक कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट म्हणून कार्यरत
ashishpthatte@gmail.com

आहे आभासी तरी

डॉ. अजित जोशी

आपल्या सर्वांना माहिती आहे की शेअर बाजारातल्या कंपन्यांचे भाव जे वर-खाली होत असतात त्यामागचं गणित समजून घेण्यासाठी आपण वेगवेगळी गुणोत्तरं पाहतो. ही गुणोत्तरं आपल्याला त्या कंपनीतील नफा, कर्ज आणि भागभांडवल यांचं प्रमाण, कंपनीतील रोखीची उपलब्धता किंवा लिक्विडिटी अशा वेगवेगळ्या घटकांची माहिती देतात. कंपनीची कामगिरी या सगळ्या घटकातून आपल्याला दिसत राहते आणि त्याच्या आधारावर आपण तिची किंमत ठरवण्याचा प्रयत्न करतो यालाच मूलभूत विश्लेषण किंवा फंडामेंटल ॲनालिसिस म्हणतात. याच न्यायाने एक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे की हे 'क्रिप्टो' नावाच्या गूढ आभासी चलनाची किंमत कशामुळे ठरते? त्याचा आधार असलेले मूलभूत किंवा फंडामेंटल घटक कोणते? तेही कंपन्यांप्रमाणेच गुणोत्तरांमधून (रेशो ॲनालिसिस) आपल्याला समजतात का? तर याचे उत्तर नाही असं आहे. मुळात या चलनाचं स्वरूप आणि कार्यपद्धती वेगळी असल्यामुळे तिच्या किमतींवर प्रभाव टाकणारे घटक आणि त्याची निर्देशकही वेगळे आहेत. तुम्हाला जर यात गुंतवणूक करायची असेल तर हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

पहिल्या लेखापासून आपण यावर भर दिलेला आहे की, आभासी चलनाची सर्वात जास्त ताकद म्हणजे किती अधिकाधिक लोक किती मोठ्या प्रमाणावर त्यात किती व्यवहार करू इच्छितात, ही आहे. यात काही चलनात होणारे व्यवहार हे खूप मोठ्या प्रमाणावर असतात. उदाहरणार्थ, सोलाना या चलनामध्ये सुमारे १५ लाख सक्रिय इंटरनेट ॲड्रेसवरून तीस कोटींच्या आसपास व्यवहार दिवसासाठी होतात. याउलट बिटकॉइनसाठी मात्र हीच आकडेवारी ९०,००० मधून साडेतीन लाख कोटींचे दैनंदिन व्यवहार होतात.

अर्थात बिटकॉइनची किंमत खूप जास्त असल्यामुळे व्यवहारांची संख्या कमी आहे हे उघडच आहे. म्हणून जर आपण वापरकर्त्यांचा आकडा बघितला तर बिटकॉइनच्या बाबतीत तो सर्वात जास्त म्हणजे पाच कोटी एवढा आहे. त्यामध्ये इथेरियममध्येच तीन कोटी आहे. आणि सोलानात फक्त दीड कोटी आहे. यापैकी चलनाच्या एकूण मूल्याच्या संदर्भात असलेले वापरकर्ते नेटवर्क ॲक्टिव्हिटी इंडेक्स (एनएआय) या गुणोत्तरात दिसतात, तर त्यावर एकूण होणारे व्यवहार यूजर पार्टिसिपेशन रेशो (यूपीआर) यातून समजतात. त्यातही या चलनाचं एकूण बाजार मूल्य आणि दिवसाकाठी त्यात होणारे व्यवहार याचं प्रमाणही महत्त्वाचं आहे. नेटवर्क व्हॅल्यू टू ट्रांझॅक्शन रेशो (एनव्हीटी) या प्रमाणाचा आकडा सांगतो. चलन विकत घेण्यासाठी ही तिन्ही गुणोत्तरं तपासणं फार महत्त्वाचं आहे.

गेल्या वेळेला आपण पाहिलं की हे चलन निव्वळ देवाण-घेवाणीसाठी न वापरता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातून असंख्य व्यवहारांचा चोख हिशोब ठेवण्यासाठीदेखील यातील काही चलनांचा उपयोग होतो. अशा चलनांचे मूल्य ठरवण्यासाठी त्यांची उपयुक्तता आणि त्यात होणाऱ्या व्यवहारांचं मूल्य या गोष्टी प्रोटोकॉल मॉनिटायझेशन एफिशियन्सी (पीएमई) किंवा तंत्रज्ञानातील आर्थिक व्यवहारांची कार्यक्षमता या गुणोत्तरात दिसते. आपल्याला हे माहीत आहे की या चलनाचा पुरवठा तंत्रज्ञानातून ठरतो, कोणत्याही सेंट्रल बँक किंवा सरकारसारख्या यंत्रणेच्या मर्जीतून नाही. आणि एकूण पुरवठा किती असणार आहे हे आधीच ठरलेलं असतं. आता बाजारात उपलब्ध असलेल्या चलनाचं एकूण ठरलेल्या पुरवठ्याशी असलेलं प्रमाण सप्लाय डायनामिक्स पॅरामीटर (एसडीपी) मधून निश्चित होतं.

युद्धाच्या आगीत क्रिप्टो होरपळणार की झळाळणार?

चलनाचा वापर अधिकाधिक होत असेल तर त्यात व्यवहार करणं सहज शक्य होतं. ही तरलता अर्थातच लिक्विडिटी रेशोच्या माध्यमातून आपल्याला कळू शकते. सर्वात शेवटचा पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या चलनावर किती तंत्रज्ञ काम करत आहेत? कारण जेवढे चलन लोकप्रिय तेवढे अधिकाधिक तंत्रज्ञ त्यात स्वत:ला गुंतवणार हे उघड आहे. हे प्रमाण डेव्हलपर ॲक्टिव्हिटी रेशो (डीएआर) मधून लक्षात येतं. जगभरात लोकप्रिय असलेल्या पाच महत्त्वाच्या चलनांच्या संदर्भात हे रेशो कुठे आहेत ते खाली दिलेल्या आकर्षक चित्रातून आपण पाहू शकतो. (सोयीसाठी म्हणून मुळातल्या गुणोत्तरांना एक ते दहा या मोजपट्टीवर रूपांतरित केलेलं आहे).

आज आपण फक्त या गुणोत्तरांशी तोंडओळख करून घेतली. येत्या काळात त्यावर आपण सविस्तर चर्चा करू शकतो. पण आता तुम्ही या गुणोत्तरांच्या आधारे वेगवेगळ्या चलनांच्या मूलभूत गुणवत्ता तपासून पाहू शकता.

कोणतीही गुंतवणूक करताना त्या मालमत्तेची स्वत:ची क्षमता म्हणजे फंडामेंटल हे जसे महत्त्वाचे असतात त्याचप्रमाणे एकूण जागतिक आर्थिक राजकीय स्थिती किंवा मायक्रो फॅक्टर्स हाही महत्त्वाचा घटक असतो. इराण युद्ध पेटल्यापासून एकूण सर्वच मालमत्तांच्या किमतींवर जो जबरदस्त परिणाम झालेला आहे त्यातून क्रिप्टो चलन वेगळे सुटू शकलेलं नाही. कोणत्याही युद्धात बाजारातली एकूण रोख ही किंमत वाढीच्या भयापोटी कमी होते. आणि त्याचा अपरिहार्य परिणाम क्रिप्टोसारख्या जास्त जोखमीच्या गुंतवणुकीवर होतो. शिवाय क्रिप्टो बाजारातले व्यवहार हे २४ तास सुरू असतात. त्यामुळे शेअर्स किंवा इतर बाजारांप्रमाणे व्यवहार सुरू होण्याची वाट क्रिप्टो बाजारात पाहावी लागत नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे अमेरिकेचा हल्ला झाल्यापासून ताबडतोबच या चलनांच्या किमती कोसळल्या. मात्र या चलनाच्या संदर्भात एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी. बाजारात मोठी घसरण झाल्यानंतर केवळ दोन आठवड्यांत बिटकॉइन ईटीएफमध्ये सुमारे १.४७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली.

याच काळात एका मोठ्या कॉर्पोरेट गुंतवणूकदाराने जवळपास १७,९९४ बिटकॉइन (सुमारे १.२८ अब्ज डॉलर मूल्य) खरेदी केले. आज ईटीएफच्या माध्यमातून संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडे सुमारे १.५१ दशलक्ष बिटकॉइन म्हणजे एकूण पुरवठ्याच्या जवळपास ७.२ टक्के हिस्सा आहे. या सगळ्याचा अर्थ कसा लावायचा?

हा अर्थ लावत असताना कोणत्याही संकटाच्या काळात संस्थात्मक आणि सामान्य म्हणजेच इन्स्टिट्युशनल आणि रिटेल या गुंतवणूकदारांच्या दोन वेगळ्या गटांच्या वागणुकीतला फरक समजून घ्यायला हवा. रिटेल गुंतवणूकदार अनेक वेळेला कमी रक्कम देऊन त्या मोबदल्यात जास्त रकमेचे व्यवहार करतात. सोपं उदाहरण म्हणजे समजा एखादी ५० लाख रुपये एकरची जमीन तुम्ही फक्त दहा लाख रुपये देऊन खरेदी केली. अपेक्षा ही की जेव्हा तिची किंमत ५४ लाख होईल तेव्हा तुम्ही विकून टाकाल आणि तुमच्या मूळ दहा लाखावर चार लाखांचा फायदा होईल. क्रिप्टोच्या बाबतीतही असे भरपूर व्यवहार होते ज्याला लिव्हरेज्ड पोझिशन म्हणतात. पण समजा किंमत पाच लाखाने घसरली आणि तुम्ही पूर्ण ५० लाख देऊन जर विकत घेतली असती तर तुम्ही ४५ लाखाच्या जमिनीवर बसून राहू शकला असतात. पण इथे मात्र तुम्हाला तुमच्या दहातले पाच लाख गमावून स्वत:ची पोझिशन शून्य करावी लागते. अस्थिरतेदरम्यान २४ तासांत अशा सुमारे ३०० दशलक्ष डॉलरच्या लीव्हरेज्ड पोझिशन्स लिक्विडेट झाल्या, तर काही अहवालांनुसार एका दिवसात ५१५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत व्यवहार जबरदस्तीने बंद झाले. बिटकॉइनची किंमत ७०,००० डॉलरच्या खाली गेल्यावर एका क्षणी ३२९ दशलक्ष डॉलरची पोझिशन्स लिक्विडेट झाली.

या सर्वांमधून सामान्य गुंतवणूकदारांच्या वागणुकीचा आपल्याला अंदाज येतो. दुसरीकडे, सुरुवातीच्या धक्क्यात आपला आकार आणि तंत्रज्ञान यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदार झपाट्याने विक्री करू शकतात. पण त्यानंतर तो महत्त्वाचा टप्पा येतो जिथे सामान्य गुंतवणूकदार भीतीपोटी किंवा लीव्हरेज्ड पोझिशन विकल्या गेल्यामुळे बाजाराबाहेर जात राहतात. पण संस्थात्मक गुंतवणूकदार मात्र भविष्यात वातावरण स्थिर झाल्यानंतर किमती चढतील हा हिशेब ठेवून अधिकाधिक खरेदी करतात. गेल्या काही काळात बिटकॉइनच्या संदर्भात नेमकं हेच घडताना दिसत आहे.

म्हणूनच सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न? आत्ताच्या परिस्थितीत सामान्य गुंतवणूकदारांनी काय करावं?

युद्ध सुरू राहिलं तर किमती खाली जाऊ शकतात. त्यामुळे मोठी गुंतवणूक टाळायला हवी. मात्र स्थैर्य आलं तर अत्यंत झपाट्याने इतर कोणत्याही बाजारांपेक्षा या बाजारातली किंमत वाढायची शक्यता आहे. आणि म्हणूनच वर वर्णन केलेली लीव्हरेज्ड पोझिशन न घेता, आपल्या एकूण निधींचा छोटा हिस्सा क्रिप्टो चलनात गुंतवायची जोखीम घेता येईल. आतापर्यंत तुम्ही या बाजारातून बाहेर राहिला असाल तर आत शिरायची ही योग्य वेळ आहे.

लेखक एका व्यवस्थापन संस्थेमध्ये वित्त विभागात सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत
ajitatresearch@gmail.com

संपादकीय

धर्मस्वातंत्र्य की धर्मनियंत्रण?

देशात विविध राज्यांना धर्मस्वातंत्र्याचा (की धर्मरक्षण?) कायदा करण्याची गरज भासू लागली आहे. ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरातसह अनेक राज्यांनी हा कायदा केला. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही हे विधेयक सादर झाले आहे. हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा लग्नाच्या आमिषाने केलेले धर्मांतर बेकायदा ठरेल. असे करणाऱ्यास सात वर्षे कारावास, लाखापर्यंत दंडाची तरतूद प्रस्तावित आहे. ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करावयाचे असेल त्याने/तिने साठ दिवस अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे कळवायचे. थोडक्यात, धर्माला नोटीस पाठवायची. प्रशासन तुमची ही इच्छा सार्वजनिक करेल. त्यावर हरकती मागवेल. धर्मांतर झाल्यावरही २१ दिवसांच्या आत पुन्हा तसे घोषणापत्र द्यायचे. या प्रक्रियेशिवाय जे होईल ते सर्व बेकायदा. विधेयकाचे नाव आहे 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयक'. पण, तरतुदी पाहता हे एकप्रकारचे 'धर्मनियंत्रण'च आहे. धर्मांतरबंदीच म्हणा हवे तर! लोक आपला धर्म सोडून जातील अशी भीती कुठल्या धर्माला वाटते हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. पूर्वी ओडिशासह अनेक राज्यांत आदिवासी भागात काही प्रलोभने दाखवून नागरिकांचे धर्मांतर घडवून आणल्याच्या घटना घडल्या. म्हणून ओडिशात सर्वप्रथम हा कायदा आला. पुढे अन्य राज्यातही. खरे तर लोक गरिबीने, अन्याय व विषमतेच्या भावनेने अथवा आमिषाने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जात असतील तर मूळ धर्मासाठी हा चिंतनाचा विषय आहे. पण, धर्माचे ठेकेदार याबाबत चिंता करत नाहीत. आज धर्मांतराचा प्रश्न नव्याच मार्गाने समोर आला आहे. ते म्हणजे आंतरधर्मीय विवाह! धर्माच्या ठेकेदारांना खरी भीती आहे ती ही. उदाहरण घ्यायचे झाले तर हिंदू धर्मात विविध जातीत आजही रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत. जेथे धर्मातील विविध जातींत समानता नाही तेथे आंतरधर्मीय विवाह कसे मान्य होणार? मुस्लीम धर्मातही ख्रिश्चन, यहुदी व हिंदूसोबत लग्न करण्यासाठी वेगवेगळे नियम आहेत. ख्रिश्चन धर्मातही धर्म स्वीकारल्याशिवाय चर्चची औपचारिक सदस्यता मिळत नाही आणि त्या व्यक्तीवर धार्मिक संस्कारही केले जात नाहीत. धर्मांमध्ये औपचारिकतेला महत्व दिलेले दिसते. राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचे पालन, प्रचार आणि प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. सज्ञान व्यक्तीने स्वेच्छेने कुठला धर्म स्वीकारला अथवा आपला जोडीदार निवडला तर त्यावरही बंधने घालता येत नाहीत. वेगवेगळ्या धर्मांतील व्यक्ती धर्म न बदलताही स्पेशल मॅरेज ॲक्टनुसार विवाह करू शकतात. केवळ ते सज्ञान हवेत. पण, जेव्हा विवाह धार्मिक विधीनुसार केला जातो तेव्हा प्रत्येक धर्माचे स्वतःचे नियम असतात. दुसरी बाब म्हणजे धर्मांतर जबरदस्तीने असेल तर ते घटनेलाही मान्य नाही. रेव्हरंड स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्तीचे धर्मांतर बेकायदा ठरविले. 'जबरदस्ती' या कारणाच्या आधारेच ही धर्मस्वातंत्र्याची विधेयके आणली जात आहेत. धर्मांतराचा मुद्दा भारताला नवीन नाही. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वत: लाखो अनुयायांसह जाहीरपणे बौद्ध धर्म स्वीकारला. 'मी हिंदू धर्मात अस्पृश्यतेचा कलंक घेऊन जन्मलो; पण हिंदू म्हणून मरणार नाही' अशी एकप्रकारची नोटीसच त्यांनी हिंदू धर्माला १९३५ साली दिली. परिस्थिती बदलत नाही हे पाहून १९५६ साली त्यांनी धर्मांतर केले. मधली २१ वर्षे धर्मसंस्था बदलली नाही. येथे नव्या विधेयकात तर साठ दिवसांची नोटीस आहे. या कालावधीत धर्मांतर करणाऱ्यास, आंतरधर्मीय विवाह करू पाहणाऱ्यास समाज मंडप थाटून, ढोलताशे वाजवून स्वीकारेल? या विधेयकात गंमत अशी आहे की हे धर्मांतर जबरदस्तीने केलेले नाही हे ज्याच्यावर आरोप आहे त्यानेच सिद्ध करायचे आहे. ज्याने आरोप केला त्याने नव्हे. त्यामुळे कायद्याने एखादा आंतरधर्मीय विवाह झाला व भविष्यात नातेवाइकांनी जबरदस्तीने धर्मांतर करून हा विवाह झाल्याची तक्रार केली तर आता विधेयकानुसार धर्मांतराची सर्व प्रक्रिया तपासली जाईल. त्यातून गुंता वाढू शकतो. त्यामुळे हा कायदा व्यक्तीला स्वातंत्र्य देणार की बंधने आणणार, हे त्याच्या अंमलबजावणीत दिसेल. धर्म शब्दाची व्युत्पत्ती लॅटिन भाषेतील 'रेलिगरे' या शब्दापासून झाली. रेलिगरे म्हणजे बांधणे, जोडून ठेवणे. आज असे दिसते की धर्म तुम्हाला सोडायला तयार नाही. खरे तर 'भेदाभेद अमंगळ' ही धर्मांची नीती हवी. पण, धर्म हे धर्मापलीकडे पाहू देत नाहीत. हा अधर्म केव्हा संपेल कोण जाणे !

युद्ध कुणीही जिंको, मरतो सामान्य माणूसच!

ना हार, ना जीत; युद्ध केवळ जखमा देते; परंतु बादशाहीची भूक मिरवत फिरणाऱ्या बेलगाम माथेफिरूंना ही गोष्ट कोण, कशी, कधी समजावणार?

डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

युद्धाच्या बाबतीत एक अतिशय जुनी म्हण आहे, 'युद्ध कोणीही जिंकू द्या, वास्तवात सामान्य माणूसच मरतो. अमेरिकी क्षेपणास्त्रांनी इराणमध्ये ज्या खामेनेईंना मारले, त्याच क्षेपणास्त्रांनी निरपराध मुलांचाही बळी घेतला. इराणने आपल्या शेजारच्या देशांवर ड्रोन हल्ले केले. त्यात मरणारे, जखमी होणारे बहुतेक लोक निरापराधच होते. जहाजावर काम करणाऱ्यांनी काय गुन्हा केला होता की त्यांना लक्ष्य केले जावे? युद्धाचा एकच हेतू असतो दहशत, विध्वंस आणि हत्या करणं.

तुम्ही-आम्ही किंवा आपला भारत देश युद्धाचा भाग नाही. परंतु, आपणही त्यात होरपळून निघत आहोत. हजारो भारतीय कुठे जहाजात, तर कुठे एखाद्या देशामध्ये अडकून पडले आहेत. आखाती देशात कोट्यवधी भारतीय राहतात, त्यांच्या सुरक्षेची चिंता आहे. भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई निर्माण झाली. तथापि त्याचेही राजकारण चालू आहे. मला वाटतं, सरकारनं परिस्थिती स्पष्ट करावी आणि जनतेकडून सहकार्य घ्यावं. रस्त्याच्या कडेला असलेले ढाबे जे सामान्य माणसाचं पोट भरतात, त्यांच्यासाठी गॅसचा पुरवठा सुनिश्चित करावा.

१९७९ मध्ये इस्लामिक क्रांती होऊन अमेरिकेच्या पसंतीचे शाह रजा पहलवी (शाह ऑफ इराण) यांची राजवट उलथवली गेली आणि अयातुल्ला खोमेनी शासक झाले. त्यांनी इराणवासीयांचे मानवाधिकार आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं. शाहच्या काळातील वैज्ञानिक, संरक्षण दलातील अधिकारी आणि इतर प्रमुख लोकांना ठार केलं गेलं, तर काही जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले.

पुढच्याच वर्षी अमेरिकेने इराकचे शासक सद्दाम हुसेन यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि सद्दाम यांनी इराणवर हल्ला केला. अमेरिकेने इराकला शस्त्रे दिली. पैसे पुरवले. आठ वर्षे हे युद्ध चालले; परंतु इराक इराणला हरवू शकला नाही. का? - कारण इस्रायल इराणच्या मागे होता. आणि इस्रायलच्या मागे?- अमेरिकाच होती. अमेरिकेने असे का केले? इराणबरोबरच इराकलाही कमजोर करणे हाच अमेरिकेचा हेतू होता. त्या युद्धात लाखो लोक मारले गेले. त्यात रासायनिक शस्त्रांचाही वापर झाल्याचा आरोप आहे. ज्या सद्दामला अमेरिकेने आपला मोहरा केले त्यालाही मृत्युदंड देण्यात आला. त्याने रासायनिक शस्त्रे तयार केली होती असा त्याच्यावर आरोप होता. प्रत्यक्षात मात्र इराककडे कणभरही रासायनिक शस्त्रे मिळाले नाहीत. इराकचे नागरिक मात्र उद्ध्वस्त झाले.

आता इराणविषयी बोलू. तेथे महाबॉम्ब टाकल्यानंतर ट्रम्प यांनी स्वतःच सांगितले की, इराणची परमाणुक्षमता नष्ट केली गेली आहे. मग बोलणी झाली. परंतु, इराणने आपल्याजवळ बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे ठेवू नयेत अशी अमेरिकेची इच्छा होती. कोणताही देश आपल्या सार्वभौमत्वाशी अशाप्रकारे तडजोड कशी करेल? - इराणने नकार दिला. त्यानंतर अमेरिका हल्ला करणार हे निश्चित झाले; परंतु इराण आपल्या आसपासच्या आखाती देशांतील अमेरिकेच्या सैन्यतळांवर हल्ला करून संपूर्ण प्रदेश युद्धाच्या खाईत लोटेल, याचा अंदाज अमेरिकेला हल्ला करण्यापूर्वी आला नाही. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही हल्ले झाले. दुबई निर्विवादपणे जगाचं आर्थिक केंद्र बनलेलं आहे. जगभरातून धन-दौलत इथे येते. त्याच दुबईवर झालेल्या हल्ल्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संकट निर्माण केलं आहे. हाही काही डाव आहे का?

आता काही झाले तरी हे युद्ध लवकरात लवकर थांबले पाहिजे असे दडपण संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरब, कुवेत, बहरीन, कतार आणि जॉर्डनसारखे देश अमेरिकेवर टाकत आहेत. परंतु, ट्रम्प त्यांचे ऐकतील? इराणच्या आक्रमक पवित्र्याने सर्वांमध्ये भयंकर भीती उत्पन्न केली आहे. इराणला त्याचा फायदाही मिळतो आहे. प्रश्न हादेखील आहे की अमेरिकेला याचा अंदाज होता का, की खामेनेई आणि केवळ इराणी नेत्यांच्या मृत्यूनंतरही इराण अशा प्रकारचा हल्ला करेल? सांगणं कठीण आहे, पण इराणच्या मागे चीन आणि रशिया उभा आहे यात शंका नाही. इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम वास्तवात चीनच्या मदतीवर चालतो. अशा स्थितीत चीनच्या ताकदीवर गुरगुरण्यात इराण मागे का राहील? अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर चीन शस्त्र हाती घेऊन इराणच्या मदतीला आलेला नाही; परंतु इराणला त्याची उघड मदत चालली आहे. चीनच्या सहकार्याने तयार झालेली इराणची स्वस्त क्षेपणास्त्रे निकामी करण्यासाठी अमेरिकेला आपली महागडी शस्त्रे वापरावी लागत आहेत. अमेरिकेचे आर्थिक नुकसान करणे हे चीनचे उद्दिष्ट आहे. अमेरिकेच्या तळांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांची उपग्रह छायाचित्रे चीननेच जगाला दाखवली. जेणेकरून अमेरिकेची नाचक्की होईल. चीन प्रत्यक्षात अमेरिकेची गंमत पाहत आहे. इकडे रशियाने तर तिसऱ्या विश्वयुद्धाचा धोका आधीच वर्तवला आहे. आता प्रश्न असा की या युद्धात पुढे काय होईल? इराणमधील राजवट बदलण्याचा अमेरिकेचा हेतू साध्य होईल? अमेरिका हवाई युद्धात पारंगत आहे. परंतु हवाई हल्ल्यांनी राजवट बदलत नाही असे इतिहास सांगतो. अमेरिकेचे सैन्य खूपच शक्तिमान आहे; परंतु अवघड भौगोलिक रचना हे बलस्थान असलेला इराण काही दशके लढत राहील. खामेनेईंच्या मृत्यूनंतरही इराणच्या रेव्होल्युशनरी गार्डची दहशत इतकी आहे, की लोकशाहीसाठी बंडाचा मार्ग सोपा नाही.. इराणचे लोक अजूनही उद्ध्वस्त स्थितीत आहेत. खाली खामेनेईंचे चेले गळा दाबत आहेत, तर वरून अमेरिकेची क्षेपणास्त्रे प्राण घेत आहेत. सामान्य माणसाने करावे तरी काय?

vijaydarda@lokmat.com
डॉ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन वाचण्यासाठी स्कॅन करा :

अन्वयार्थ

'लापता लेडीज'चा पत्ता कुणालाच कसा शोधता येत नाही?

लैंगिक शोषण, कामासाठी शोषण, प्रेमसंबंध, अपहरण, खोटी आमिषे, प्रलोभने.. महिला-मुलींच्या बेपत्ता होण्यामागे कारणे असंख्य ! पण त्यावर उपाय काय?

रवींद्र राऊळ
ज्येष्ठ पत्रकार

बेपत्ता व्यक्तीला जाण्यासाठी एकच वाट असते, तर तिला शोधणाऱ्यांसमोर हजार वाटा फुटलेल्या असतात. राज्यातील बेपत्ता महिला आणि मुलींचे वर्षागणिक वाढणारे प्रमाण पाहता 'त्यांना शोधायचे कसे?' हे मोठे आव्हान पोलिस यंत्रणेसमोर आहे. राज्यात गतवर्षात बेपत्ता मुली आणि महिलांचा आकडा ४८ हजारांच्या पलीकडे, तर अल्पवयीन मुलींची संख्या १३ हजारांवर पोहोचली आहे. गेल्या वीस वर्षांतील बेपत्ता मुलींची वाढती संख्या हादरवणारी आहे. त्यातील निम्म्या मुलींनी लग्न केले असे असावे असे गृहीत धरले तरी उरलेल्या हजारो मुली आणि महिला कुठे असतील आणि त्यांचे काय झाले असेल, याचे उत्तर तपास यंत्रणांकडे नाही.

साधारणत: मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या की त्या प्रेम प्रकरणातून पळून गेल्या असाव्यात असा निष्कर्ष काढला जातो. मात्र, घराचा उंबरठा ओलांडण्यामागच्या अन्य कारणांचा विचार कुणी करत नाही. प्रेम प्रकरण असो की अन्य कारण, त्यांना पुढे कोणकोणत्या भीषण संकटांना सामोरे जावे लागत असेल, याचाही अंदाज येत नाही. बेपत्ता होण्यामागे बालविवाह, लैंगिक शोषण, कामासाठी शोषण, प्रेमसंबंध, अपहरण, खोटी आमिषे, प्रलोभने अशा असंख्य कारणांपैकी कुठलेतरी कारण असल्याने समाजातील त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न कायमच ऐरणीवर असतो. काहींना फूस लावल्याने, तर काही स्वेच्छेने घर सोडून जातात. कधी चार भिंतींमधील कौटुंबिक हिंसाचार, गृहकलह, छळ, पिळवणुकीला कंटाळून पलायन करतात, तर अनेक प्रकरणांमागे हुंड्यासारख्या सामाजिक समस्याही चिकटलेल्या असतात. बिघडलेले नातेसंबंध त्यांना घराचा पराकोटीचा तिरस्कार करण्यास भाग पाडतात. अशा मुली आणि महिला समाजकंटकांच्या तावडीत सापडल्या की पुढे होणारे त्यांचे हाल अनन्वित असतात.

आधी प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून नंतर शरीरविक्रयच्या व्यवसायात ढकलल्या गेलेल्या मुलींचे प्रमाणही धक्कादायक आहे. पोलिसांच्या हाती लागू नये म्हणून या मुलींना वेगवेगळ्या शहरांमध्ये फिरवले जाते. सुटका करून बाहेर पडलो तरी कुटुंबीय आणि समाज आपल्याला स्वीकारेल याची खात्री नसलेल्या या 'बदनाम' मुली. परतीचे दोर कापले गेल्याची जाणीव झाल्याने कोणत्याही संकटाशी मुकाबला करण्याची त्यांची क्षमता संपुष्टात येते. काहींना घरकाम, मजुरीसाठी कोंडून ठेवल्याने त्यांच्या नशिबी गुलामीचे जिणे येते, तर काही महिलांना नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने आखाती देशांत पाठवून फसवणूक केली जाते. तेथील विमानतळावर उतरताच त्यांचे पासपोर्ट आणि मोबाइल ताब्यात घेऊन मोलमजुरीच्या कामाला जुंपणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटला आळा घालण्याचे काम सध्यातरी नियंत्रणाबाहेरचे आहे.

सर्वसाधारण तपासात ५० ते ६० टक्के बेपत्ता महिलांचा थांगपत्ता पहिल्या वर्षभरात लागतो. त्यातील काही घरी परततात, तर काही ठामपणे नकार देतात. इतर प्रकरणांत साधारण वर्षभरानंतर मुलींचे कुटुंबीय पाठपुरावा करणे सोडून देतात. पोलिस यंत्रणेवरील कामाचा प्रचंड ताण पाहता प्रत्येक प्रकरणाचा ते प्राधान्याने तपास करतीलच याची शाश्वती नाही. बेपत्ता महिला/मुलींचा शोध घेणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि आवश्यक असल्यास त्यांना सुरक्षित निवारा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

दुसऱ्या बाजूला भविष्यात मुली घराचा त्याग करणार नाहीत यासाठी प्रयत्न व्हावयास हवेत. आत्मघातकी निर्णय घेण्यापूर्वी मुलींना सल्ला देणारी अथवा त्यांचे समुपदेशन करणारी व्यवस्था अतिशय तोकडी आहे. घरातील पौगंडावस्थेत असलेल्या मुलांशी वाद घालण्यापेक्षा त्यांच्याशी मिळतेजुळते घेऊन आवश्यकता भासल्यास त्यांचे समुपदेशन व्हायला हवे. सोशल मीडियाचे तोटे, तिथले आभासी जग आणि खोट्या भूलथापांविषयी सतर्क राहण्याची समज निर्माण केल्यानेही काही प्रमाणात स्थिती बदलू शकते. यातील काहीएक उपायांची दखल समाजाने घेतली तर हे प्रमाण घटू शकेल. सार्वजनिक ठिकाणी, गर्दीच्या ठिकाणी भेदरलेल्या, भांबावलेल्या, नैराश्यग्रस्त मुली नजरेस पडल्यास प्राथमिक संवाद साधण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांना मदतीची गरज असल्यास संबंधित यंत्रणांना कळवले पाहिजे. मुली आणि महिला बेपत्ता होणे हे समाजाच्या अनास्थेचे प्रतीक आहेच, शिवाय व्यवस्थेचे, यंत्रणांचे आणि सरकारचेही अपयश आहे. अशा आकडेवारीची केवळ चर्चा करण्यापेक्षा ठोस उपाय योजले तरच भविष्यात हे आकडे कमी होऊ शकतील.

ravirawool66@gmail.com

जगभर

'चायना मॅक्सिंग'! त्यापाठी जेन-झी वेडी का?

चीन कुठल्या ना कुठल्या कारणानं कायमच संपूर्ण जगभरात चर्चेत असतो. कधी त्यांच्या टेक्नॉलॉजीमुळे, कधी त्यांच्या युद्धखोर नीतीमुळे, कधी जगावर प्रभुत्व गाजवण्याच्या त्यांच्या अहमहमिकेमुळे, कधी भारताची कुरापत काढण्यामुळे, कधी अंतराळात स्वत:चं नवं साम्राज्य उभं करण्याच्या ईर्षेमुळे, तर कधी जागतिक बाजारपेठेवरील त्यांच्या वर्चस्वामुळे.

सध्या मात्र चीन जगभरात, विशेषत: जेन-झी तरुणाईत गाजतो आहे ते 'चायना मॅक्सिंग'मुळे! अमेरिका आणि इतर देशांमध्येही हा ट्रेंड गारूड करतो आहे. टिकटॉक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत असलेला हा ट्रेंड अमेरिका आणि इतर पाश्चात्त्य देशांत चिनी गोष्टींचं उघडउघड अनुकरण आणि कौतुक करताना दिसतो. इतकं की हे तरुण स्वत:च चिनी आहेत की काय असं इतरांना वाटावं!

सोशल मीडियावर जणूकाही सगळीकडे चीनचा जलवा पसरलाय. टिकटॉक आणि Twitch सारख्या प्लॅटफॉर्मवर तरुण अमेरिकन 'चायना मॅक्सिंग'मध्ये पूर्णपणं गुंतलेत. अनेकजण उघडपणे सांगताहेत की ते 'चिनी बनले आहेत'. या ट्रेंडमध्ये जेन झी सकाळी गरम पाणी पिताहेत, स्वयंपाकघरात ताई-ची करताहेत आणि चॉपस्टिक वापरण्याच्या कलेत पारंगत होताहेत. बीजिंगमधील वयोवृद्धांसारखा लूक मिळवण्यासाठी ते ट्रॅकसूटही घालताहेत.

इतकंच नाही, तर अनेक जण 'तुम्ही मला माझ्या आयुष्यातील चिनी टप्प्यात भेटलात', इतकं चीनचं गुणगाण करताना दिसतात. हा डायलॉग १९९९ मधील 'फाइट क्लब' या चित्रपटातील प्रसिद्ध संवादापासून प्रेरित असल्याचं मानलं जातं. त्या चित्रपटात नायक म्हणतो, 'यू मेट मी ॲट अ व्हेरी स्ट्रेंज टाइम इन माय लाइफ!' काहीजण चिनी लाइफस्टाइलही स्वीकारताहेत- जसं की रूममध्ये जाण्यापूर्वी बूट काढणं किंवा हर्बल उपचार घेणं.

'चायना मॅक्सिंग'मुळे अलीकडच्या काळात चीनच्या 'सॉफ्ट पॉवर'ला अधिक चमक मिळतेय. या ट्रेंडशी जोडलेलं एक प्रभावी नाव म्हणजे शेरी झू. त्या चिनी-अमेरिकन टिकटॉक क्रिएटर आहेत आणि पारंपरिक वेलनेस टिप्स शेअर करतात. तरुणाईत त्या खूपच पॉप्युलर आहेत. त्यांचे साडेसात लाख फॉलोअर्स आहेत.

आपल्या या फॉलोअर्सना त्या म्हणतात, 'उद्यापासून तुम्ही चिनी बनताहात.. मला माहीत आहे, काही जणांना ते विचित्र वाटेल, पण हे नाकारण्यात आणि त्याविरुद्ध लढण्यात आता काही अर्थ नाही.'

हा एक नवा लाइफस्टाइल ट्रेंड आहे, ज्यात चीनच्या जीवनशैलीचं रोमॅन्टीकरण केलं जातंय. चीनबद्दल अमेरिकन जेन-झीमध्ये इतकं आकर्षण का वाढतंय, याबद्दल प्रसिद्ध पत्रकार टेलर लॉरेन्झ म्हणतात, अमेरिकन तरुणांना सध्या चीन 'स्वर्गासारखा' वाटतोय, तर स्वतःचा देश 'निराशाजनक'.. काही तज्ज्ञांच्या मते, तुम्ही जगात कुठंही राहा, पण चीनमध्ये बनलेल्या वस्तूंनी तुम्ही वेढलेले असता. तुमचा फोन असो किंवा जगातील सर्वाधिक विकली जाणारी इलेक्ट्रिक कार- सर्वत्र चीनचा प्रभाव आहे.

टीकाकारांचं म्हणणं आहे, 'चायना मॅक्सिंग' संपूर्ण चित्र दाखवत नाही. चीनमध्ये सरकारवर टीका केली तर तुमचं काही खरं नाही. देशाची अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांना सामोरी जातेय. तरुणांमधील बेकारीचा दर १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. काम करणाऱ्या लोकांमध्ये 'बर्नआउट'ची समस्या वाढते आहे.. यातून लोकांचं लक्ष दूर करण्यासाठी मुद्दाम हा ट्रेंड पसरवला जातोय!..

करनीती

प्रलंबित आरओसी फॉर्म भरण्याची संधी

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, गुढीपाडवा जवळ आला आहे. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने कंपन्यांसाठी कोणती 'गोड' बातमी दिली आहे?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, सरकारने 'कंपनी अनुपालन सुविधा' योजना, २०२६ (CCFS) सुरू केली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना एमसीए-२१ रजिस्ट्रिमधील जुने/प्रलंबित रेकॉर्ड कमी शुल्कात नियमित करण्याची संधी मिळते.

अर्जुन : अनेक छोट्या कंपन्या आणि एमएसएमईंना उशीरा दाखल केल्याबद्दल मोठा दंड भरावा लागतो. ही योजना त्यांना कशी मदत करते?

कृष्ण : कंपन्या एकूण अतिरिक्त शुल्काच्या केवळ १०% भरून त्यांचे प्रलंबित वार्षिक फाइलिंग पूर्ण करू शकतात. जर एखादी कंपनी इनॲक्टिव असेल परंतु रजिस्टरवर राहू इच्छित असेल तर ती सामान्य शुल्काच्या केवळ निम्मे पैसे भरून 'डॉर्मन्ट' स्थितीसाठी अर्ज करू शकते. जर त्यांना कंपनी बंद करायची असेल (स्ट्राइक ऑफ), तर त्यांना फाइलिंग फीच्या केवळ २५% भरणे आवश्यक आहे.

अर्जुन : कृष्णा, उद्योजकांसाठी ही बातमी'गोड गाठी'सारखी आहे! ही योजना केव्हा सुरू होते आणि त्याचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

कृष्ण : ही योजना १५ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि १५जुलै २०२६पर्यंत खुली राहील. हे जवळजवळ सर्व कंपन्यांना लागू होते ज्यांनी वार्षिक विवरणपत्र (एमजीटी-७) किंवा वित्तीय विवरण (एओसी -४) आणि इतर सारख्या वार्षिक कागदपत्रे भरण्यास चुकवले आहेत. सरकारने जुनी कागदपत्रे/फाइलिंग उशिरा केलेल्यांना मर्यादित काळासाठी दंडाशिवाय दुरुस्त करण्याची एकदाच संधी दिली आहे.

- उमेश शर्मा, सीए

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

जेन झी

अखंड अस्थिरता, सततचा ताण आणि रागामुळे धुमसत आहेत ही पोरं

भारतातील बहुसंख्य जेन-झी अस्थिर, तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये किंवा अल्परोजगारी आहेत. तो सहजपणे अतिरेकी शक्तींच्या कह्यात जाऊ शकतो.

राही श्रु. ग.
सीनिअर रिसर्च फेलो
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ

अघळपघळ ढगळ कपडे, बूट, टॅटू, कानात डूल, नाकात रिंग अशा अवतारात ऑफिसमध्ये येणारी मुलं-मुली म्हणून जेन-झी सोशल मीडियावर दाखवली जातात. कामाच्या ठिकाणी तिथल्या राहणीबद्दलचे नियम मोडणारे, कामाच्या पद्धतीत सर्जनशील, पण काहीसा मोकळाढाकळा स्वभाव असणारे असं जेन-झींचं चित्र सोशल मीडियावरील विनोद, रील्स आणि मीम्समध्ये दिसतं. अन्यायाच्या बाबतीत (जरा जास्तच) संवेदनशील, स्वतःचा वेळ, स्वतःचा आनंद आणि आरोग्य याला महत्त्व देणारे असं व्यावसायिक जगातल्या जेन-झींचं वर्णन होतं. यात तथ्य असलं तरी या चित्रात दिसणारे जेन-झी हे प्रत्यक्षात एकूण जेन-झी लोकसंख्येचा फारच छोटा घटक आहेत. बहुसंख्य जेन-झी हे बांधकामाची ठिकाणं, कारखाने, खाणी आणि शेतीतल्या अंगमेहनतीच्या कामांपासून ते स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिटचे 'डिलिव्हरी पार्ट्नर्स' म्हणून काम करतात. सर्व वर्गातले जेन-झी हे एकाचवेळी दोन किंवा तीन कामं, 'साइड हसल' करतात.

नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्था कामगारांचा एक नवा वर्ग तयार करते, असं ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ गाय स्टॅन्डिंग त्यांच्या २०११मधल्या 'द प्रिकॅरिएट : द न्यू डेंजरस क्लास' या पुस्तकात म्हणतात. या वर्गाला त्यांनी दिलेलं नाव आहे प्रिकॅरिएट. मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानात कामगारांच्या वर्गाला 'प्रोलिटेरिएट' म्हणतात. हा 'नाही रे' वर्ग नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये अस्थिर आणि हतबल झालेला आहे, त्यातून एक नवा प्रिकॅरिएट वर्ग तयार होतो आहे, अशी स्टॅन्डिंग यांची मांडणी. भारतातील बहुसंख्य जेन-झी या वर्गाचा भाग आहेत. हा वर्ग अस्थिर, तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये किंवा अल्परोजगार असलेला आहे. पारंपरिक अर्थाने ज्यांना आपण 'कामगारां'ना कायम नोकरीतलं स्थैर्य असणं अपेक्षित आहे. उदारीकरणापूर्वी कामगारांना पक्क्या नोकऱ्या, कामगार संघटनांचा काही प्रमाणात का होईना, आधार होता. प्रिकॅरिएट मात्र सुरुवातीपासून अस्थिर आणि तात्पुरत्या कंत्राटांवरच्या नोकऱ्यांमध्ये आहेत. कामाच्या बाबतीतली लवचीकता त्यांच्यावर लादली गेली आहे. त्यांच्या हक्कांचं सातत्याने हनन होतं. या अस्थिरतेमुळे मोठ्या प्रमाणात मानसिक ताणतणावांना ते तोंड देतात. स्टॅन्डिंग यांच्या मते, अंगमेहनतीपासून ते असंघटित क्षेत्रातल्या 'बौद्धिक' कामांपर्यंत सगळीकडे ही अस्थिरता पसरलेली आहे.

आजच्या या प्रिकॅरिएट कामगारांचा बराच वेळ सतत रोजगाराच्या संधी शोधत राहणं, कामाच्या वेळापलीकडेही फोन किंवा ई-मेलवर उपलब्ध राहणं अशा कामांमध्ये जातो, ज्याचा कसलाही मोबदला त्यांना मिळत नाही. आपल्या हक्कांसाठी संघटित होण्यात प्रिकॅरिएटसमोर अनेक अडथळे आहेत. गेल्या दशकभरात मोबाइल ॲप्सवरून होणाऱ्या किराणा, खाद्यपदार्थ पोहोचविण्याच्या, टॅक्सी, रिक्षा, ते घरगुती ब्यूटी ट्रीटमेंट्सपासून घरकामापर्यंतच्या उद्योगांमध्ये काम करणारे 'गिग वर्कर्स' या प्रिकॅरिएटचा मोठा हिस्सा आहेत.

नवउदारमतवादातल्या तीव्र स्पर्धात्मकतेने समाजातल्या जात, धर्म आणि लिंगभावाच्या भेदरेषा गडद केल्या आहेत. अखंड अस्थिरतेतून येणारा ताण, राग आणि अनारोग्यातून हा वर्ग सहजपणे अतिरेकी उजव्या शक्तींच्या कह्यात जाऊ शकतो, असा इशारा देत स्टॅन्डिंग म्हणतात, 'त्यांना मूलभूत हक्क, आर्थिक स्थैर्य मिळेल, याची खात्री केली, तर समाजाला पुढे नेण्याची मोठी क्षमता या वर्गात आहे.'

raheeshrutiganesh@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

ऐन उकाड्यात लोडशेडिंग; चार तास बत्तीगुल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून वीजपुरवठ्याबाबत मोठमोठे दावे केले जात होते, मात्र अनेक वर्षांनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा लोडशेडिंग सुरू झाले आहे.

महावितरणच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, कंपनीला शुक्रवारी सायंकाळपासून लोडशेडिंग सुरू करावे लागले. शनिवारी सायंकाळीही अशीच परिस्थिती कायम होती. शनिवार, १४ मार्चसाठी महावितरणच्या दैनंदिन सिस्टम रिपोर्टनुसार, कंपनी सकाळी ११ ते दुपारी ४ आणि पहाटे ४ वाजता विजेची मागणी पूर्ण करण्यात सक्षम होती. मात्र, रात्री ८ वाजता १,००० मेगावॉट पेक्षा अधिक लोडशेडिंग करावी लागली.

महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर सांगितले की, महाराष्ट्रात तापमान वाढत असल्यामुळे विजेची मागणीही वाढत आहे. सायंकाळच्या वेळी वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यात कंपनी असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून दररोज तीन ते चार तास जास्त लाइन लॉस असलेल्या गावांमध्ये लोडशेडिंग केली जात आहे. रात्री सौर ऊर्जेचे उत्पादन शून्यावर येते, त्यामुळे अडचण निर्माण होते.

राज्यात गर्भपाताचा 'पोर्टेबल' उद्योग

सर्रास अवैध गर्भलिंग निदान; सोनोग्राफी मशिनची ऑनलाइन खरेदी; यंत्रणा करतेय काय?

लोकमत विशेष

संतोष हिरेमठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

एआय इमेज

छत्रपती संभाजीनगर : सोनोग्राफी मशीनचा स्थिर वापर करण्यास परवानगी आहे. मात्र, राज्यात सर्रास पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनचा वापर करून अवैध गर्भलिंग निदान, गर्भपाताचा उद्योग सुरू आहे. शासनाने अशा मशीनच्या वापरावर बंदी घातलेली असतानाही ऑनलाइन खरेदी करून गुप्तपणे त्याचा वापर केल्याच्या घटना पुढे होत आहेत. त्यामुळे यंत्रणा काय करतेय, असा सवाल सर्वसामान्यांतून उपस्थित केला जात आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी उघडकीस आलेल्या रॅकेटकडून पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनद्वारे गर्भलिंग निदान सुरू होते. गेल्या काही वर्षांत विविध जिल्ह्यांत पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनद्वारे गर्भलिंग निदान, अवैध गर्भपात करणाऱ्या टोळ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. ग्रामीण भागात घर, गोठे, वाहनांमध्ये या मशीनचा वापर होत असल्याचे आढळले. काही प्रकरणांमध्ये वायरलेस, ब्लूटूथ तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या सोनोग्राफी मशीनचा वापर करण्यात आल्याने चिंता वाढली आहे.

आठ दिवसांत घरी

पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन, प्रोब अक्षरशः मोबाइल, स्मार्ट टीव्हीप्रमाणे ऑनलाइन बाजारात सहज मिळत आहेत. ऑर्डर दिल्यानंतर आठ ते दहा दिवसांत डिलिव्हरी देण्याचे आश्वासनही ऑनलाइनवरील यंत्रणा देते.

ट्रॅकिंग सीस्टम हवी

पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन यंत्रणा, प्रोब, सॉफ्टवेअर यासह महत्त्वाचे भाग ट्रॅक करता येतील, अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

मोबाइलप्रमाणे पोर्टेबल : सोनोग्राफी मशीन ट्रॅकिंग सिस्टम असणे आवश्यक आहे. मशीन कोण चालू केले, कुठे वापरले यावर लक्ष ठेवले पाहिजे.

पोर्टेबल वापरावर बंदी

अवैध गर्भलिंगनिदान प्रकरणातील आरोपी सुटल्यावर पुन्हा तोच धंदा करीत असल्याचे समोर आले आहे. पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन वापरण्यावर शासनाकडून बंदी आहे. राज्यासह देशभरात त्यावर बंदी आहे. हे मशीन कोणालाही मिळाली नाही पाहिजे. परंतु त्याची ऑनलाइन खरेदी केली जाते.

डॉ. पारस मंडलेचा, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, मनपा

वेळावेळी तपासणी

मशीनवर बंदी आहे. अवैध गर्भलिंगनिदान होऊ नये, यादृष्टीने आमच्याकडून नियमितपणे तपासणी केली जाते.

डॉ. कमलाकर मुदखेडकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक

गेल्या चार वर्षांमध्ये बीड, छत्रपती संभाजी नगर, जालना, नाशिक जिल्ह्यांमध्ये उघडकीस आलेले गुन्हे

जून २०२२ मध्ये बीड जिल्ह्यातील बक्करवाडी येथे अवैध गर्भपात करताना ३० वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातही असेच पोर्टेबल मशीन वापरले होते .

मे २०२४ मध्ये छत्रपती संभाजी नगर शहरातील गारखेडा परिसरात महापालिकेने छापा मारून अवैध गर्भपात केंद्राचा भांडाफोड केला होता. यातील आरोपींनी पाच लाख रुपयांत तीन सोनोग्राफी टॅब, प्रोब खरेदी केल्याचे उघडकीस आले होते.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये भोकरदन (जि. जालना) येथे सरकारी योजनेतून बांधलेल्या जनावरांच्या गोठ्यात सुरू असलेल्या अवैध गर्भलिंगनिदान केंद्राचा स्थानिक गुन्हे शाखा, आरोग्य विभागाच्या पथकाने पर्दाफाश केला. यात अवैध गर्भलिंगनिदानासाठी प्रथमच वायरलेस ब्लूटूथ सोनोग्राफी मशीनचा वापर झाल्याचे समोर आले.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नाशिकमध्ये अवैध गर्भलिंग निदान करणारे रॅकेट उघड करण्यात पोलिसांना यश आले.

श्रीनिवास नाडगौडा : सेवा, प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यनिष्ठेची अखंड वाटचाल

LOKMAT ONE WORLD SUMMIT & AWARDS Egypt 2026

Powered by NYATI

श्रीनिवास नाडगौडा

संचालक : वायुपुत्र बिल्डर्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि., एक्सलन्स इन क्वालिटी कन्स्ट्रक्शन अँड प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन पुरस्कार

श्रीनिवास नाडगौडा यांचा जीवनप्रवास शिकवतो की पद, पैसा किंवा प्रतिष्ठेपेक्षा सेवा मोठी असते. राष्ट्रसेवा, सामाजिक बांधिलकी, अध्यात्मिक समतोल आणि अखंड कार्यशीलता यांचा संगम म्हणजेच श्रीनिवास नाडगौडा-खऱ्या अर्थाने एका अनोख्या विश्वाची सफर.

श्रीनिवास नाडगौडा यांचा जीवनप्रवास म्हणजे केवळ यशाची कहाणी नाही, तर तो सेवेला जीवनमंत्र मानून जगलेल्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रवास आहे. दादर येथील राजाशिवाजी विद्यालयातून मराठी माध्यमात शिक्षण घेतलेल्या श्रीनिवास यांनी पुढे गुरुनानक खालसा कॉलेज, माटुंगा येथून रसायनशास्त्रात पदवी आणि मुंबई विद्यापीठातून रसायनशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. नियतीने त्यांच्यासाठी राष्ट्रसेवेचा मार्ग निवडला. त्यांनी कस्टम्स व सेंट्रल एक्साईज विभागात प्रवेश केला आणि डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स (DRI) येथे कार्यरत झाले. तस्करीविरोधी मोहिमांमध्ये त्यांनी धाडस, प्रामाणिकपणा आणि अत्युच्च कर्तव्यभावनेचे दर्शन घडवले.

त्यांच्या या उल्लेखनीय सेवेसाठी २६ जानेवारी २००१ रोजी त्यांना राष्ट्रपतींचा विशिष्ट सेवा पुरस्कार बहाल करण्यात आला–हा त्यांच्या निष्ठावान राष्ट्रसेवेचा गौरव होता. दीर्घकाळची सरकारी सेवा पूर्ण केल्यानंतर, २००८ साली त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली, मात्र 'सेवा' हा धागा कधीच तुटू दिला नाही. त्यांनी रिअल इस्टेट व पुनर्विकास क्षेत्रात पाऊल टाकले, २० हून अधिक प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले.

२०१३ साली, त्यांनी "वायुपुत्र बिल्डर्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि." या कंपनीची स्थापना केली. आझाद नगर जेम CHSL हा दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला पुनर्विकास प्रकल्प त्यांनी यशस्वीरीत्या मार्गी लावला–जो केवळ एक प्रकल्प नव्हता, तर अनेक कुटुंबांच्या स्वप्नांना मिळालेले नवे आयाम होते. त्यानंतर त्यांनी खार येथील प्रकल्प पूर्ण केला असून, सध्या मुंबईत आणखी चार पुनर्विकास प्रकल्प उंबरठ्यावर आहेत.

त्यांच्या कार्यपद्धतीचा आत्मा आहे–पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि दिलेल्या शब्दाचे पालन. याच मूल्यांमुळे ते सभासदांचा विश्वास जिंकू शकले. परंतु यांची खरी ओळख केवळ यशस्वी अधिकारी किंवा विकासक म्हणून मर्यादित नाही. सेवा हेच त्यांचे खरे ध्येय आहे. गेल्या ८ वर्षांपासून ते विनामूल्य योगशिक्षक म्हणून सेवा देत आहेत. ते गेल्या १४ हून अधिक वर्षांपासून आपल्या गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव म्हणून मानद (Honorary) सेवा देत आहेत.

२०२४ साली, त्यांच्या जीवनानुभवांना शब्दरूप देत त्यांनी "सफर एका अनोख्या विश्वाची" हे मराठी पुस्तक प्रकाशित केले.

हे पुस्तक म्हणजे केवळ आत्मकथन नसून, तरुण पिढीसाठी प्रेरणादायी दीपस्तंभ आहे. ज्यात कर्तव्य, संघर्ष, सेवा आणि यश यांचा सुंदर समन्वय आढळतो.

बनावट मसाले बनवणाऱ्या कारखान्यावर 'पुष्प ब्रँड'चा छापा

धार : मसाले जगतातील अग्रगण्य नाव असलेल्या 'पुष्प ब्रँड इंडिया लिमिटेड'ने आपल्या ब्रँडची नक्कल करणाऱ्यांविरुद्ध मोठी कायदेशीर लढाई जिंकली आहे. धार जिल्ह्यातील मनावर तालुक्यातील सिंघाना येथे 'सिंघाना फार्मर्स ब्रँड' (कृष सर्जन किसान उत्पादक प्रोड्युसर कंपनी लि.)द्वारे सुरू असलेल्या बनावट उत्पादनांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार छापा टाकून मोठ्या प्रमाणात मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

'पुष्प' ब्रँडच्या नावाने व पॅकेजिंगशी साधर्म्य असलेल्या बनावट उत्पादनांची विक्री बाजारात होत असल्याची माहिती कंपनीला मिळाली होती. यामुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत होता. या विरोधात पुष्प ब्रँड इंडिया लिमिटेडने त्यांचे कायदेशीर सल्लागार 'किंशुक लीगल' यांच्यामार्फत इंदूरच्या न्यायालयात दाद मागितली होती.

न्यायालयाने मान्य केले की, प्रतिवादीने पुष्प ब्रँडच्या मूळ पॅकेजिंगची हुबेहूब नक्कल केली आहे. ग्राहकांची दिशाभूल टाळण्यासाठी न्यायालयाने तातडीने अंतरिम स्थगन आदेश पारित केला, तसेच अधिवक्ता मनीष नागर यांना तपासणी व जप्तीचे आदेश दिले.

ग्राहकांच्या विश्वासाशी खेळ करणाऱ्या आणि ब्रँडची नक्कल करणाऱ्यांविरुद्ध ही मोहीम सुरूच राहील. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून आमच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहोत, असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (वा.प्र)

जमीन नोंदी, मोजणी वेगवान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा अभूतपूर्व कायापालट होणार आहे. राज्यात भूमिअभिलेख विभागाची ४९ नवी कार्यालये स्थापित करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील भूमिअभिलेख विभागासाठी नवीन सुधारित आकृतिबंध जाहीर करण्यात आला आहे. भूमिअभिलेख विभागात यापूर्वी ९,६८९ पदे मंजूर होती. आता यामध्ये ९९४ नवीन पदांची वाढ करण्यात आली असून, विभागाचा एकूण आकृतिबंध आता १०,६८३ पदांचा झाला आहे. यामध्ये नियमित पदांसोबतच काही सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतर आता या सुधारित आकृतिबंधावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

विशेष उपअधीक्षकसह चौकशी कार्यालये स्थापन

नांदेड येथे एक उपसंचालक भूमिअभिलेख कार्यालय, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे, मुंबई उपनगर अशी ८ जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालये, पुणे, कोकण, नाशिक, अमरावती, नागपूरमध्ये २३ नवीन नगर भूमापन अधिकारी कार्यालये, ५ विशेष उपअधीक्षक कार्यालये, १२ नवीन चौकशी अधिकारी कार्यालये निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे.

शिक्षण, साहित्य आणि रंगभूमीचा अष्टपैलू मानबिंदू : प्रा. डॉ. प्रदीप ढवळ

प्रख्यात अभिनेते बोमन इराणी यांच्या हस्ते प्रा. डॉ. प्रदीप जनार्दन ढवळ यांचा सन्मान

LOKMAT ONE WORLD SUMMIT & AWARDS Egypt 2026

Powered by NYATI

डॉ, प्रदीप ढवळ

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि शिक्षणतज्ञ

ढवळ यांना वेगळे ठरवणारे त्यांचे गुण

प्रा. डॉ. प्रदीप ढवळ यांचे अष्टपैलू गुणच त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे ठरवतात. दीर्घ शैक्षणिक समर्पण, साहित्यसंपदा, रंगभूमीवरील विक्रमी कामगिरी, प्रभावी वक्तृत्व आणि प्रेरणादायी मार्गदर्शन अशा प्रकारे प्रा. डॉ. प्रदीप ढवळ यांचे ज्ञान, सर्जनशीलता, नेतृत्वगुण त्यांना अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व बनवतो.

शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घ सेवाकाळ, साहित्य-सर्जनाची समृद्ध परंपरा, रंगभूमीवरील विक्रमी प्रयोग आणि सामाजिक कार्यातील सक्रिय सहभाग या सर्वांचा संगम म्हणजे प्रा. डॉ. प्रदीप जनार्दन ढवळ. ठाण्यातील ज्ञानसाधना महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विभागात सलग ३२ वर्षे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत राहून त्यांनी हजारो विद्यार्थ्यांना घडवले. वरिष्ठ प्राध्यापक म्हणून सेवानिवृत्त होताना त्यांनी केवळ अध्यापनच नव्हे, तर व्यक्तिमत्त्व विकासाचाही ठसा उमटवला. "वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील आजारी उद्योग आणि व्यवस्थापनाची भूमिका" या विषयावर त्यांनी संशोधनप्रबंध सादर केला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्यांनी लंडनमधील एम्पायर कॉलेजमधून 'सीडीआर' पूर्ण करून आपली शैक्षणिक व्याप्ती विस्तारली.

डॉ. ढवळ यांनी २० हून अधिक पुस्तके आणि नाट्यकृती लिहिल्या आहेत. 'नरेंद्र ते विवेकानंद: एक झंझावात', 'जॉर्ज वॉशिंग्टन: एक ओऍसिस', 'संताजी घोरपडे का स्वस्त योद्धा', 'पराक्रमाची हिमशीकरे', 'योद्धा कर्मयोगी' (एकनाथ शिंदे यांचे चरित्र) आणि 'अभिमान' (सतीश प्रधान यांचे चरित्र) ही त्यांची उल्लेखनीय साहित्यकृती आहेत.

'संन्यस्त ज्वालामुखी', 'शिवबा', 'द्वंद्व' आणि 'फुंकार' यांसारख्या नाटकांनी रंगभूमी गाजवली. 'द्वंद्व'चे सलग १२ प्रयोग करून त्यांनी जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. 'संन्यस्त ज्वालामुखी' या नाटकाचे १५३ प्रयोग सादर होत त्याची नोंद 'लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये झाली. 'शिवबा' या ८० कलाकारांच्या महानाट्याचे महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, इंदूर आणि भोपाळ येथे ३५० हून अधिक प्रयोग झाले.

६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इजिप्तच्या कैरो येथे प्रदान करण्यात आलेला 'लोकमत वन वर्ल्ड' पुरस्कार हा त्यांच्या कार्याची जागतिक पातळीवरील दखल ठरला. शिक्षण, साहित्य आणि संस्कृती क्षेत्रातील त्यांचे योगदान ठाणे जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब ठरले आहे.

मुस्लीम दाम्पत्याकडून हिंदू मुलीचे कन्यादान

सामाजिक ऐक्य, बंधुभाव आणि मानवतेचा संदेश देणारा आगळावेगळा विवाहसोहळा रीतीरिवाजांनुसार संपन्न झाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

चांदूर बाजार (अमरावती) : अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील बेलोरा येथे सामाजिक ऐक्य, बंधुभाव आणि मानवतेचा संदेश देणारा आगळावेगळा विवाहसोहळा पार पडला. हिंदू नवदाम्पत्याच्या विवाहात मुस्लीम दाम्पत्याने कन्यादान करत समाजासमोर एकोप्याचा प्रेरणादायी आदर्श ठेवला. या अनोख्या सोहळ्याची परिसरात मोठी चर्चा होत असून, सर्व स्तरांतून त्याचे कौतुक केले जात आहे.

बेलोरा येथील नितीन याचा विवाह मध्य प्रदेशातील माजरी गावातील सुनीता हिच्यासोबत १४ मार्च रोजी हिंदू रीतीरिवाजांनुसार झाला. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल आदिवासी कुटुंबातील सुनीता हिच्या विवाहासाठी मदतीची आवश्यकता होती. ही बाब कळताच मोर्शी तालुक्यातील रिद्धपूर येथील अब्दुल राजिक आणि त्यांच्या पत्नी नाहीद अंजुम यांनी पुढाकार घेतला.

सामाजिक संदेश देणारा ठरला विवाहसोहळा

१ विवाहस्थळी हिंदू परंपरेनुसार सर्व धार्मिक विधी पार पडले. नववधूचे पूजन, मंगलाष्टक, कन्यादान आदी विधींमध्ये अब्दुल राजिक आणि नाहीद अंजुम यांनी श्रद्धेने सहभाग घेत नवदाम्पत्याला सुखी वैवाहिक आयुष्यासाठी आशीर्वाद दिले.

२ विवाह सोहळ्यात उपस्थितांमध्ये भावनिक वातावरण निर्माण झाले. धर्म, जात-पात यापलीकडे जाऊन माणुसकी आणि सामाजिक सलोखा जपण्याचा हा संदेश देणारा विवाहसोहळा प्रेरणादायी ठरला.

शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को स्वच्छ और मजबूत नहीं रख पाएंगे।

– महात्मा बुद्ध

जंग की आग

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू होने के बाद युद्ध में अब जो तौर-तरीके अपनाए जाने की खबरें आ रही हैं, उससे यह चिंता गहराने लगी है कि इसका असर किस रूप में सामने आएगा। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु या व्यापक विनाश के हथियारों और अन्य मसलों की अपनी सुविधा के मुताबिक व्याख्या करने वाला अमेरिका खुद कई बार सारे तकाजों के खिलाफ जाकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति भी उपेक्षा भाव प्रदर्शित करता है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर मिसाइल दागे जा रहे हैं और व्यापक पैमाने पर जानमाल की क्षति हो रही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के साझा हमले में कई ऐसे ठिकानों पर भी बमबारी की गई, जिसके पर्यावरणीय और मानवीयता पर असर को लेकर दुनिया भर में सवाल उठे हैं। मसलन, प्रतिद्वंद्विता के क्रम में या ईरान को झुकाने के लक्ष्य से वहां एक स्कूल पर हमले के अलावा कई शहरों में तेल ठिकानों पर मिसाइल दागे गए। उससे बाद वहां जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, उसका असर दीर्घकालिक होगा और इसकी मार सिर्फ आम लोगों को झेलनी होगी।

एक ओर विश्व भर में यह उम्मीद की जा रही है कि इस युद्ध की वजह से तेल और गैस के साथ-साथ अन्य कई मोर्चों पर व्यापक संकट गहराने के मद्देनजर शांति की राह खोजी जाएगी, दूसरी ओर खबर यह आई कि अमेरिका ने शनिवार को ईरान के खर्ग द्वीप पर हमला करके मसले को और जटिल स्वरूप दे दिया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया और तेल ढांचों को निशाना नहीं बनाया। मगर खर्ग द्वीप को जिस तरह ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार और नब्बे फीसद कच्चे तेल के निर्यात के केंद्र के रूप में जाना जाता है, उसमें कहना कठिन है कि हमलों का असर सीमित होगा। अगर हमलों की जद में तेल भंडार भी आए, तो उसके नतीजों की कल्पना की जा सकती है। फिर इस पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी, खाड़ी देशों में स्थित तेल रिफाइनरियों पर कैसा खतरा पैदा होगा, कहना मुश्किल है। इस क्रम में बड़े पैमाने पर तेल ठिकाने नष्ट होते हैं, तो आने वाले वक्त में दुनिया भर में संकट गहराएगा।

युद्ध की चरम अवस्था में भी यह उम्मीद की जाती है कि इसमें शामिल देश संघर्ष की स्थिति में तय किए गए नियम-कायदों और मानवीयता का खयाल रखेंगे। मगर हालत यह है कि इस संबंध में मानवीय प्रश्नों की तो दूर, युद्ध को लेकर बने अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बिना किसी हिचक के धता बताया जा रहा है। विश्व भर में इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले की निंदा कर चुके हैं। रूस भी कह चुका है कि हम जिस अंतरराष्ट्रीय कानून की बात करते हैं, वह लगभग खत्म हो चुका है। इसके अलावा, तेल ठिकानों पर हमले के बाद बहुत बड़े दायरे में जो पर्यावरणीय प्रभाव सामने आ रहे हैं, उसका खमियाजा आखिर कौन भुगतेगा? खबर यह भी आई कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान के आसमान से काली स्याही जैसा तरल बरस रहा है। अंधाधुंध हमलों के बाद युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों की जिंदगी जिस हालत में पहुंच गई है और मानवीयता के सभी तकाजे दरकिनार किए जा रहे हैं, वह सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

गंगा का जीवन

गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए वर्षों से प्रयास चल रहा है। इसके लिए भारी-भरकम बजट भी आबंटित किए गए। मगर सकारात्मक नतीजे कभी सामने नहीं आए। गंगा कार्ययोजना में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर करीब दशक भर पहले केंद्र सरकार ने बहुआयामी कार्यक्रम 'नमामि गंगे' की शुरुआत की थी। प्रारंभिक दौर में इसमें प्रगति भी दिखी थी और उम्मीद बंधी थी कि वर्षों से मैली हो रही गंगा धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अब स्वच्छ हो जाएगी। निराशा की बात है कि 'नमामि गंगे' भी सही दिशा में नहीं बढ़ पाई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रपट से उन सभी लोगों को मायूसी हुई है जो गंगा के निर्मल होने का इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड के बजट सत्र में पेश की गई कैग की रपट बताती है कि 'नमामि गंगे' कार्यक्रम क्रियान्वयन एजंसियों की विफलता के कारण वांछित नतीजे नहीं दे पाया। गौरतलब है कि इसके लिए केंद्र ने एक हजार करोड़ की राशि मुहैया कराई थी।

यह दुखद ही है कि गंगा कार्ययोजना की असफलता से नमामि गंगे से जुड़ी एजंसियों ने कोई सबक नहीं लिया। इस कार्यक्रम में खामियां ठीक वैसी ही थीं, जैसी पिछली योजना में थीं। 'नमामि गंगे' अपेक्षित परिणाम देने में क्यों विफल रही, इसे न केवल केंद्र को, बल्कि इस कार्यक्रम से जुड़े विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा। इस परियोजना में नाकामी न केवल बड़ा आर्थिक नुकसान है, बल्कि उन सभी संकल्पों पर भी आघात है, जिनमें लोगों की यह इच्छा शामिल थी कि गंगा स्वच्छ और अविरल हो। मगर ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई। हैरत की बात है कि गंगा की छोटी जलधाराओं के पास कूड़ा फेंके जाने से लेकर स्थानीय जरूरतों का आकलन किए बगैर कई तटों पर श्मशान घाट बना दिए गए। कैग ने जो खामियां उजागर की हैं, वह उन अधिकारियों को क्यों नहीं दिखा जो इस कार्यक्रम के अमल के लिए जिम्मेदार थे। अवजल शोधन संयंत्र के दोषपूर्ण डिजाइन में लापरवाही क्यों और किस स्तर पर हुई? मानदंडों का उल्लंघन करने वालों की अब जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

युद्ध से लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था

यह सोचा नहीं गया था कि इस युद्ध से वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा, जो पश्चिम एशिया में अन्य संघर्षों से कहीं अधिक गंभीर होगा। इस युद्ध ने यात्रा के तौर-तरीकों, ऊर्जा पर निर्भरता, जीवनयापन की लागत, व्यापार मार्गों और रणनीतिक साझेदारियों को बदल दिया है।

जयंतीलाल भंडारी

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और होर्मुज जलमार्ग बंद होने का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। जहां दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर घटने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं विभिन्न देशों में शेयर बाजार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध शुरू करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आक्रामक कदम के रूप में पेश किया था। अब इस युद्ध ने कुछ और ही रूप ले लिया है। यह सोचा नहीं गया था कि इससे वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा, जो पश्चिम एशिया में अन्य संघर्षों से कहीं अधिक गंभीर होगा। इस युद्ध ने यात्रा के तौर-तरीकों, ऊर्जा पर निर्भरता, जीवनयापन की लागत, व्यापार मार्गों और रणनीतिक साझेदारियों को बदल दिया है।

गौरतलब है कि अन्य कई क्षेत्रीय संघर्षों से आमतौर पर अछूते रहने वाले देशों को अमेरिकी सैन्य अड्डों के कारण भी ईरान की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे सैन्य टकराव ने बेहद कम समय में ही अमेरिकी खजाने पर बोझ डालना शुरू कर दिया है। अब पेंटागन का रोजाना युद्ध खर्च औसतन दो अरब डालर तक पहुंच चुका है। हर दिन अमेरिकी सैन्य अभियान पर अरबों डालर खर्च हो रहे हैं। इस संघर्ष ने केवल अमेरिकी बजट पर ही प्रभाव नहीं डाला, बल्कि कई महंगे सैन्य उपकरणों का नुकसान भी हुआ है। अगर यह युद्ध लंबा चला, तो इसके प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं। कच्चे तेल संकट के कारण मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के जोखिम की आशंका है। इससे विकास रुक सकता है।

गौरतलब है कि ईरान और इजराइल-अमेरिका के युद्ध के बीच ईरान ने जहाजों की आवाजाही का सबसे अहम होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है। इस मार्ग से बीस फीसद से अधिक वैश्विक कच्चे तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस जलमार्ग के बंद हो जाने से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। चूंकि कच्चे तेल के लिहाज से भारत का करीब चालीस फीसद कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर आता है। ऐसे में यह युद्ध भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों के लिए 85 फीसद से अधिक आयात पर निर्भर है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। युद्ध लंबा चलने पर इसकी कीमत बेतहाशा बढ़ सकती है। इससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होने लगेंगे और वहीं भारत से निर्यात घटने और व्यापार घाटा बढ़ने की चुनौती बढ़ती दिखाई देगी। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच हुई उच्च-स्तरीय वार्ता के बाद ईरान ने भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों को होर्मुज जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है।

इस युद्ध से सीधे तौर पर जुड़े अमेरिका, इजराइल और ईरान सहित युद्ध से प्रभावित पश्चिम एशियाई और यूरोपीय देश भी भारत के लिए निर्यात के प्रमुख बाजार हैं। ऐसे में निर्यातकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पश्चिम एशिया जाने वाला माल भारत के घरेलू बंदरगाहों पर जमा होने लगा है। जहाजों की सुरक्षा को देखते नए निर्यात आदेश नहीं लिए जा हैं। ऐसी स्थिति में खासतौर से पश्चिम एशिया के देशों में निर्यात घटने की आशंका है। भारत ने इस वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अप्रैल से दिसंबर की अवधि में पश्चिम एशिया के 13 देशों को करीब 50 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जो भारत के कुल निर्यात का करीब 15 फीसद है। विभिन्न देशों में भारत से खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, बासमती चावल, चाय, मशीनरी, दवाएं, रत्न-आभूषण, प्लास्टिक और रबड़ जैसे क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजंसी फिच की इकाई बीएमआइ ने एक रपट में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, माल ढुलाई महंगी होने और आपूर्ति श्रृंखला टूटने जैसे चिंताजनक हालात से भारत के निर्यात और निवेश पर असर पड़ेगा। रपट में यह भी कहा गया है कि यदि कच्चे तेल की कीमतों में दस फीसद की वृद्धि होती है, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 0.3 से 0.6 फीसद की कमी आ सकती है और इससे निर्यात मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ जाएंगी।

> इस युद्ध के बीच ईरान ने जहाजों की आवाजाही का सबसे अहम होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है। इस मार्ग से बीस फीसद से अधिक वैश्विक कच्चे तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस जलमार्ग के बंद हो जाने से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। चूंकि कच्चे तेल के लिहाज से भारत का करीब चालीस फीसद कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर आता है। ऐसे में यह युद्ध भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों के लिए 85 फीसद से अधिक आयात पर निर्भर है। ऐसे में तेल के दाम में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है।

सरकार और निर्यातकों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। इस बीच सरकार नागरिकों, निर्यातकों और अन्य प्रभावित वर्गों की मुश्किलों को कम करने के मद्देनजर रणनीतिक रूप से कदम उठा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का भी फैसला किया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद देश की सभी रिफाइनरियों और पेट्रो केमिकल इकाइयों को अपने अन्य उत्पादों की तुलना में एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देनी होगी। मगर सरकारी तंत्र को सतर्क रहना होगा, ताकि गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी न होने पाए। सरकार ने युद्ध से निर्मित हालात से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव पर सरकारी मंत्रालयों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक में विचार मंथन के बाद बहुमंत्रालयी सहायता डेस्क सहित निर्यातकों को हरसंभव सहयोग दिया जाना सुनिश्चित किया है।

इसमें दो मत नहीं कि भारत को द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का पूरा लाभ लेते हुए निर्यात को हरसंभव तरीके से बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए भारत के व्यापार समझौते अहम भूमिका निभा सकते हैं। हाल के महीनों में जिन देशों के साथ समझौते किए गए हैं, उन्हें क्रियान्वयन की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाना होगा। मगर ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध के बीच भारत से निर्यात बढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। ऐसे में निर्यात बढ़ाने के लिए चिह्नित किए गए करीब दो सौ देशों में निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं निर्यातकों की दिक्कतों को कम करना होगा। ये दिक्कतें केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं हैं, वरन निर्यात पर लगाए गए डंपिंग-रोधी शुल्क भी अड़चन हैं। अब घरेलू ढांचागत सुधारों के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता आवश्यक होगी। इसके लिए देश में नियमों और नियामक संस्थाओं के कामकाज में मूलभूत बदलाव की जरूरत है। कर सुधारों को और गहराई देने के साथ जीएसटी प्रणाली को प्रभावी बनाना जरूरी है।

उम्मीद करें कि सरकार ईरान और इजराइल-अमेरिका के युद्ध की वजह से निर्यात चुनौतियों से निपटने और निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापार समझौतों के अधिकतम लाभ के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और नए सुधारों की राह पर आगे बढ़ेगी। दूसरी ओर संकट के इस दौर में आवश्यक वस्तु अधिनियम को कारगर तरीके से लागू करना होगा, तभी देश में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जा सकेगी जिससे आम लोगों को राहत मिले। नागरिकों को आश्वस्त करना होगा फिलहाल गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और कच्चे तेल और गैस की नई आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भी अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं।

मानवीयता के मूल्य

संगीता कुमारी

समाज के सभी आयु वर्गों की रुचियों पर अगर हम नजर डालें, तो सभी में एक बात सामान्य दिखेगी और वह है संचार के साधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह सड़कें नहीं हैं, मगर रेडियो और मोबाइल की अच्छी सुविधा है। बच्चे और युवा मोबाइल के जरिए देश-विदेश की सैर करते हैं, तो कई बुजुर्ग अब भी रेडियो को अपने कानों से लगाए देश-विदेश की खबरों पर नजर रखते हैं। इन बुजुर्गों ने अपनी धंसी आंखों से न जाने कितनी पीढ़ियों को उसी रेडियो के माध्यम से बदलते हुए देखा है। दूसरी ओर, इन बुजुर्गों के सामने परिवार के युवा मोबाइल या स्मार्टफोन पर अनेक ऐप का उपयोग करते हैं और ताजा-ताजा घटनाओं, कहानियों और खबरों से लैस रहते हैं। इन सभी के बीच सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता है, तो वह है सकारात्मक दृष्टि से सामाजिक चिंतन में लगे लोगों का, जो हमेशा से भारत की पृष्ठभूमि को अपने उच्च विचारों से संचित करते रहे हैं। पत्रकार हों या साहित्यकार, देश की दिशा-दशा का आकलन करके समय-समय पर अपनी वाणी को लेखन के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाते रहते हैं।

सच यह है कि भारत की मिट्टी में एक खास खुशबू है, जो प्राचीन काल से विदेशियों को आकर्षित करती आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि समय में परिवर्तन के साथ भारतीय समाज विभिन्नताओं से भरपूर अतुल्य भारत बन गया है। समाहित कर लेना भी एक कला है, जो भारत की भूमि से लेकर गंगा जैसी अनेक नदियों को बखूबी आता है। मगर अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को खो देना बिल्कुल नहीं आता है। यह मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए साहित्य समाज, भूमि या नदियों को अनेक लोभी भ्रष्टाचारियों ने दूषित भी किया है, लेकिन यह भारत की किस्मत ही है कि देश के आम और साधारण लोग अब भी स्वच्छता को अपने जीवन-मूल्यों में सबसे ऊपर रखते हैं।

स्वच्छता केवल स्थान या बाहरी शरीर की ही नहीं होती है, बल्कि विचारों की भी होती है। विचार का संचार कई रूपों में होता है। आज इस इक्कीसवीं सदी में संचार के माध्यम अनेक हैं, मगर प्राचीन काल से आज तक संचार की जिस विधा को विचारों को प्रेषित करने के लिए उत्तम माना जाता है, वह है साहित्य। लेखक समाज का आकलन करता रहता है, तो लेखन उसके लिए एक सामान्य कार्य बन जाता है, क्योंकि उसे लिखना ही है। इस लिहाज से पत्रकार भी साहित्यकार ही होता है। भारत के लगभग प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए एक विभाग अवश्य होता है, कुछ संस्थाएं केवल हिंदी भाषा के विकास के लिए ही बनाई गई हैं और कुछ भारतीय भाषाओं के लिए। कुछ साहित्यकार बनाए जाते हैं, कुछ साहित्यिक गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं। आज समाज के बहुत सारे गुणी, पारखी नजर रखने वाले साहित्यकारों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उनकी चिंता विचारों की स्वच्छता को लेकर है। सामाजिक धरोहर को सच्चे विद्वानों के हाथों में देने का जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शीर्ष पर बैठे कुछ साहित्यकारों को केवल पूर्वाग्रहों से संचालित होने और पक्षपात की आदत हो गई हो। इसी वजह से साहित्य समाज की स्वच्छता की आवश्यकता है।

चिंतन के लिए पद क्या और पदहीन क्या? चिंतन वह विषय है, जो प्रत्येक संवेदनशील प्राणी के जेहन में पाया जाता है। साहित्य का संबंध ही संवेदनाओं से है। स्वच्छ लेखन को केवल पन्नों पर अक्षरों में उतार देना भर काफी नहीं है, उसे लोगों तक पहुंचाना भी अति आवश्यक है। कुछ लोग अपनी दूषित भावनाओं को चटपटे रूप देकर, अश्लीलता को मनोरंजन का नाम देकर, विवाद का तड़का लगाकर और अपने पदों का दुरुपयोग कर साहित्य को व्यवसाय बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि इस प्रवृत्ति को महत्त्व दिया जाएगा, तो समाज को स्वच्छ करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज भारतीय समाज वैसे ही पश्चिम की बेलगाम आधुनिकता के दलदल में फंस रहा है। टीवी हो या बड़ा पर्दा, जिस प्रकार महिलाओं के उत्थान के नाम पर कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी महिमामंडित किया जाता है, उससे मानवीयता और सामाजिकता के मूल्य भी प्रभावित होते हैं। इस पर भी मनन करने की जरूरत है और जिसका हमारे समाज का बौद्धिक और साहित्यकार तबका ध्यान रखता भी है। इस विपरीत समय में भी बहुत सारे अनुभवी पत्रकार और साहित्यकार समाज में मौजूद हैं, जिनकी लेखनी प्रेमी हृदय के समांतर किसी में सिर्फ अवांछित आकांक्षाएं नहीं देखते हैं, बल्कि अपने अपने कोमल शब्दों से हृदय स्पर्श कर लेते हैं। उन्हें इस बात की चिंता खाती रहती है कि भावी पीढ़ी के भीतर भारतीय साहित्यिक धरोहर को आगे ले जाने की ताकत कैसे बढ़े।

महान विभूतियां अपने पीछे महान कर्मों का इतिहास छोड़कर चली जाती हैं, पत्थर पर दूर भविष्य तक जीवित रहने वाली अमिट रेखाएं खींच जाते हैं। हम आज भी निगाह उठाकर देखें, तो समाज में बहुत सारे महान चिंतक और साहित्यकार अपने उच्च विचारों के जरिए अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में महान विभूतियां विचारों की स्वच्छता से समाज की सफाई में लगी हुई हैं। आज समय की मांग है कि केवल शब्द नहीं चाहिए, शब्दों से उच्च स्तर के वाक्य बने, वैसे शब्द और वाक्य की जरूरत है। वाक्य ऐसे हों, जो पढ़ने वाले के जेहन को झकझोर दे। सोती हुई सतह को ऐसी नींद से जगी हुई भोर चाहिए।

दुनिया मेरे आगे

> स्वच्छता केवल स्थान या बाहरी शरीर की ही नहीं होती है, बल्कि विचारों की भी होती है। विचार का संचार कई रूपों में होता है। आज इस इक्कीसवीं सदी में संचार के माध्यम अनेक हैं, मगर प्राचीन काल से आज तक संचार की जिस विधा को विचारों को प्रेषित करने के लिए उत्तम माना जाता है, वह है साहित्य और साहित्यकार।

संयम और जिम्मेदारी

केंद्र सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि देश में रसोई गैस की पर्याप्त व्यवस्था है, फिर भी कई राज्यों में अफवाहें और आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। देश के कई हिस्सों में इसका असर दिखाई देने लगा है। व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग ठप होने से उद्योग और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी गैस एजंसियों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। देहरादून में कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन को कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करनी पड़ी है। इस स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती अफवाहों और जमाखोरी से निपटना है। जब लोग डर के कारण जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने लगते हैं, तो बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। कालाबाजारी करने वालों को मौका मिल जाता है। इसलिए सरकार के साथ-साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे संयम बरतें और ऐसी गतिविधियों का विरोध करें। वर्तमान परिस्थिति हमें यह भी सिखाती है कि ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कितना आवश्यक है। यदि जनता संयम बरते, कालाबाजारी का विरोध करे और प्रशासन को सूचना दे, तो ऐसी आपात स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

विकास के सवाल

'कुप्रबंधन का पानी' (संपादकीय 11 मार्च) में जल प्रबंधन अव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। विज्ञान और तकनीक की प्रगति के दौर में भी यदि लोगों को स्वच्छ पेयजल न मिल पाए, तो यह विकास की दिशा पर सवाल खड़ा करता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन पानी के दूषित नमूनों में से अधिकांश पर उपचारात्मक कार्रवाई न होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। यह बेहद चिंता की बात है। इंदौर जैसी घटनाएं बताती हैं कि पेयजल की गुणवत्ता को लेकर ढिलाई कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इसी कारण कई लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए। भू-जल में बढ़ते आर्सेनिक और अन्य प्रदूषक भी चिंता बढ़ा रहे हैं। स्पष्ट है कि केवल योजनाएं घोषित करना पर्याप्त नहीं, बल्कि निगरानी, जवाबदेही और मजबूत जल प्रबंधन भी जरूरी है, ताकि स्वच्छ पेयजल वास्तव में हर नागरिक तक सुरक्षित रूप में पहुंच सके।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

नींद का महत्त्व

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलित आहार के साथ-साथ अच्छी और पर्याप्त नींद जरूरी है। वर्तमान समय में जीवनचर्या में बदलाव, तनाव, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग तथा कई दूसरी अनियमितताओं के कारण लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। नींद पूरी न होने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, थकान, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अवसाद जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। देर रात तक मोबाइल का उपयोग नींद की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इस गंभीरता को समझने की जरूरत है कि स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग सात से आठ घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसके लिए समय पर सोने की आदत, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सोने से पहले डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। अच्छी नींद लेने वाले व्यक्ति अपने कार्यों को अधिक सकारात्मकता और दायित्व के साथ पूरा करते हैं।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

मजदूरों की मुश्किल

सरकार के निर्देश पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों के वितरण पर रोक लगा दी है। इससे लाखों उपभोक्ताओं और हजारों एमएसएमई इकाइयों को आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह बाधा लंबे समय तक जारी रहती है, तो यह छोटे पैमाने के उद्योगों को अपनी इकाइयां बंद करने पर मजबूर कर सकती है। इससे आर्थिक नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। मजदूरों की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। उन्हें काम से निकाला जा सकता है। इसी तरह भोजनालयों, होटलों और सड़कों के किनारे खाना बेचने वालों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उपभोक्ताओं को काला बाजारियों को ज्यादा पैसे देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आपूर्ति और मांग के संतुलन में भारी अंतर के कारण, गैस कारोबारियों का एक वर्ग कालाबाजारी कर रहा है।

– युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

व्रत त्योहार

17 मार्च : मासिक शिवरात्रि। भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन।
18 मार्च : फाल्गुन अमावस्या। पितृ तर्पण और दान-पुण्य के लिए महत्त्वपूर्ण।
19 मार्च : चैत्र नवरात्रि प्रारंभ।
21 मार्च : गौरी पूजा/गणगौर।
22 मार्च : विनायक चतुर्थी। भगवान गणेश की आराधना का दिन।
24 मार्च : यमुना छठ।
26 मार्च : श्री दुर्गा महाअष्टमी।
27 मार्च : राम नवमी।
29 मार्च : कामदा एकादशी।
31 मार्च : प्रदोष व्रत - शुक्ल पक्ष।

देशभर में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है नवसंवत्सर

देवेंद्र सिंह

भारतीय संस्कृति में पर्व केवल उत्सव और उल्लास का अवसर नहीं होते, बल्कि वे जीवन के गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी अपने भीतर समेटे रहते हैं। प्रत्येक त्योहार हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य, परंपराओं के सम्मान और आत्मिक उन्नति की प्रेरणा देता है। ऐसा ही एक महत्त्वपूर्ण और पवित्र पर्व है नवसंवत्सर (हिंदू नववर्ष)। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इसे वर्ष प्रतिपदा या भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह पर्व अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश-कर्नाटक में उगादी या युगादि, कश्मीर नवरेह, सिंधी समुदाय में चेटीचंड व मणिपुर में साजिबू चेइराओबा प्रमुख हैं।

'युगादि' शब्द नए युग का प्रतीक

'युग' और 'आदि' शब्दों के मेल से बना 'युगादि' शब्द अपने आप में एक नए युग के आरंभ का प्रतीक है। यह केवल कैलेंडर का परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन में नवचेतना, नई आशा और नए संकल्पों का प्रारंभ भी है। भारतीय संस्कृति में समय को केवल दिनों और महीनों की गणना तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि उसे सृष्टि और प्रकृति के अनंत चक्र से जोड़ा गया है। यही कारण है कि नवसंवत्सर का प्रारंभ भी उस समय होता है जब प्रकृति स्वयं नवजीवन से भर उठती है।

तिथि सृष्टि के उद्भव का भी प्रतीक

पौराणिक मान्यता के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस जगत की रचना का प्रारंभ किया था। इसलिए यह तिथि केवल नए वर्ष का आरंभ ही नहीं, बल्कि सृष्टि के उद्भव का भी प्रतीक मानी जाती है। इस दिन ब्रह्मा जी के साथ-साथ उनके द्वारा रचित समस्त सृष्टि (देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु-पक्षियों और वनस्पतियों) का स्मरण और पूजन किया जाता है। भारतीय दर्शन की विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति के प्रत्येक तत्व को दिव्यता का स्वरूप माना गया है। यहां तक कि रोग और उनके उपचारों का भी स्मरण किया जाता है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय संस्कृति जीवन को समग्र दृष्टि से देखने की शिक्षा देती है।

शुक्ल पक्ष की शुरुआत

ज्योतिषीय दृष्टि से भी वर्ष प्रतिपदा का अत्यंत विशेष महत्त्व है। एक ज्योतिषाचार्य के अनुसार, भारतीय पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति के आधार पर निर्मित होता है, इसलिए इसे चंद्र-सौर पंचांग कहा जाता है। अमावस्या के बाद जब चंद्रमा की पहली कला प्रकट होती है, तब शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है और उसी का पहला दिन प्रतिपदा कहलाता है। चैत्र मास की यह प्रतिपदा ही नवसंवत्सर का प्रथम दिन मानी जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य ने भी इसी दिन से दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। ज्योतिष परंपरा में इस दिन से नए वर्ष के ग्रहाधिपत्य का विचार किया जाता है। इस दिन पंचांग सुनने की परंपरा भी प्रचलित है, जिसमें विद्वान ज्योतिषाचार्य आगामी वर्ष की संभावनाओं का वर्णन करते हैं।

चैत्र शुक्ल वर्षारंभ के लिए शुभ

चैत्र मास का महत्त्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत विशेष है। यह वह समय होता है, जब शीत ऋतु के बाद वसंत अपनी पूर्णता पर होता है और प्रकृति नए जीवन से भर उठती है। वृक्षों और लताओं में नई कोपलें फूटती हैं, फूल खिलते हैं और वातावरण में ताजगी का संचार होता है। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्षारंभ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घरों को सजाने-संवारने की भी विशेष परंपरा है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं। आम के पत्ते समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि यह तोरण घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है।

'गुड़ी' स्थापित करने की परंपरा

महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे वर्ष के साढ़े तीन शुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इसी दिन से शालिवाहन शक संवत की भी शुरुआत मानी जाती है। लोककथाओं के अनुसार, शालिवाहन नामक एक वीर युवक ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाकर उनमें प्राण फूंक दिए और शत्रुओं को पराजित किया। उसकी इस विजय की स्मृति में विजय ध्वज के रूप में 'गुड़ी' स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने दक्षिण भारत की प्रजा को अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई थी। इस विजय की खुशी में लोगों ने अपने घरों में ध्वज फहराए, जो आगे चलकर गुड़ी पड़वा की परंपरा बन गई।

हिंदू नव वर्ष (19 मार्च से शुरू)

प्रसाद जीवन के कड़वे व मीठे अनुभवों का प्रतीक

कर्नाटक में युगादि पर घरों में नीम की कोपल और गुड़ का प्रसाद खाया जाता है, जिसे 'बेवू-बेला' कहा जाता है। यह प्रसाद जीवन के कड़वे और मीठे अनुभवों का प्रतीक है और हमें यह संदेश देता है कि जीवन में आने वाले सुख-दुःख को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में पूरन पोली नामक पारंपरिक मीठा व्यंजन बनाकर पर्व की खुशियां साझा की जाती हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय इस दिन नवरेह के रूप में विशेष पूजा-अर्चना करता है, जबकि सिंधी समाज में यही पर्व चेटीचंड के रूप में मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा से आरंभ होने वाला यह उत्सव आगे चलकर चैत्र नवरात्र और रामनवमी के साथ अपने आध्यात्मिक चरम पर पहुंचता है। इन नौ दिनों में देवी शक्ति की आराधना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाता है।

लेने की अपेक्षा देने का अनुभव अद्भुत

योगेंद्र माथुर

किसी से कुछ प्राप्त करना सुखद व प्रसन्नतादायक हो सकता है लेकिन विश्वास कीजिए, किसी को कुछ देना लेने से कहीं अधिक सुखद व संतोषदायक है। लेने की अपेक्षा देने का अनुभव अद्भुत आंतरिक खुशी प्रदान करता है। अतः लेने के बजाय किसी को कुछ देना सीखिए!

किसी वृद्धाश्रम जाकर हम वहां असहाय, अक्षम व निराश्रित वृद्धजनों को उनके कार्य में सहयोग व सहायता प्रदान कर सकते हैं। उन्हें कुछ खाने को दे सकते हैं। जो दुआएं हमें मिलेंगी, वह हमारे प्रारब्ध के असंख्य पाप नष्ट करने वाली होंगी।

प्रश्न यह है कि क्या दें, किसे दें, कब दें और कहां दें? तो सीधा-सा उत्तर है, जब मन चाहे, जो मन चाहे, जिस किसी को देना चाहे, जहां चाहे, बिना विचार किए दे दीजिए! जो कुछ आपके पास आवश्यकता से अधिक है या अनावश्यक है, किसी को दे दीजिए! यदि आपके पास कुछ अधिक, अतिरिक्त या अनावश्यक नहीं है और देने का मन हो तो आप उसे अपने हिस्से में से कुछ अंश दे सकते हैं। हमारे यहां तो कहावत भी प्रचलित है, मिल बांट कर खाना, बैकुंठ में जाना! इस कहावत में देने के इस पुनीत कार्य को धर्म से संबद्ध किया गया है। अपरिग्रह का धार्मिक संदेश भी यहां जुड़ा हुआ है।

जीवन दर्शन

आवश्यक नहीं कि किसी को कोई वस्तु या धन ही दिया जाए, हम अपनी सामर्थ्य, क्षमता या शक्ति के अनुसार किसी को कुछ अन्य भी दे सकते हैं। हम किसी को शारीरिक या बौद्धिक सहयोग या सहायता भी दे सकते हैं। यदि हम सुशिक्षित हैं तो विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कला में हम सिद्धहस्त हैं तो अन्य लोगों को उस कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें उसमें पारंगत कर सकते हैं। इस तरह हम किसी को उसकी आजीविका का साधन भी उपलब्ध करा सकते हैं।

देने का मन हो तो किसी वृद्धाश्रम जाकर हम वहां असहाय, अक्षम व निराश्रित वृद्धजनों को उनके कार्य में सहयोग व सहायता प्रदान कर सकते हैं। उन्हें कुछ खाने को दे सकते हैं। बदले में उनकी जो दुआएं हमें मिलेंगी, वह हमारे प्रारब्ध के असंख्य पाप नष्ट करने वाली होंगी। किसी दुःखी व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कीजिए और उन्हें सांत्वना देकर उनके आंसू पोछिए। आत्मिक संतोष का अनुभव करेंगे।

पेड़-पौधे हमारे पर्यावरण के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। किसी बाग-बगीचे में जाकर वहां हम पेड़ पौधों को जल दे सकते हैं और उनके संरक्षण व संवर्द्धन में अपना योगदान दे सकते हैं। किसी धर्म स्थल या आराधना स्थल पर जाकर हम वहां व्यवस्था बनाने में अथवा साफ-सफाई में अपना श्रम व समय दे सकते हैं। कोई तीज-त्योहार हो तो किसी गरीब या श्रमिकों की बस्ती में जाइए। वहां बच्चों को नए कपड़े, मिठाई व खिलौने देकर हम उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

बच्चों के खिले चेहरे और उनकी निश्छल व मधुर मुस्कान हमारी चिंताओं, परेशानियों व श्रम की थकान या दर्द में अभूतपूर्व आराम देने वाली होती है। आपके यहां कोई वैवाहिक या अन्य कोई आयोजन संपन्न होने के बाद भोजन सामग्री बच गई है तो यहां-वहां सड़क पर फेंकने के बजाय किसी गरीब बस्ती में जाकर या मंदिरों आदि के आसपास भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को बांट दीजिए। अन्न व्यर्थ नहीं जाएगा। गाय, कुत्ते व कौवे को खाने को देने का कार्य तो हमारे यहां धर्म से संबद्ध किया गया है।

हिमपात

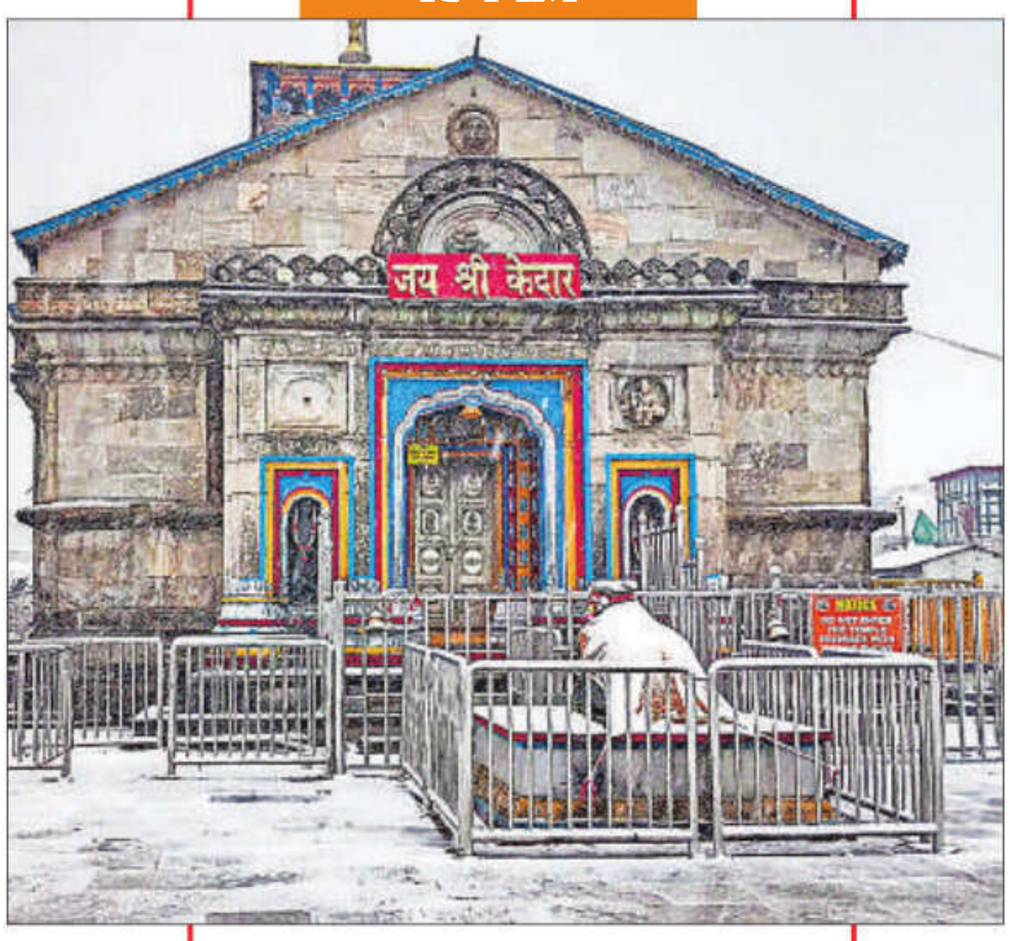

केदारनाथ मंदिर परिसर में हुई हल्की बर्फबारी का दृश्य।

स्वयं के बारे में हमारे भ्रम

रोहित कौशिक

हम अपनी जिंदगी में स्वयं के संबंध में अनेक तरह के भ्रम पाले रहते हैं। कभी-कभी तो लगता है कि हम अपनी सारी जिंदगी भ्रम में ही निकाल देते हैं। अनेक लोग तो इसी भ्रम में रहते हैं कि जिंदगी उन्हें नहीं बल्कि वे जिंदगी को चला रहे हैं। कई बार जिंदगी में भ्रम जरूरी होते हैं तो कभी-कभी हम कुछ ज्यादा ही भ्रम पाल लेते हैं। यह बात आपको अजीब लगेगी लेकिन सच्चाई यही है कि स्वयं के बारे में थोड़ा भ्रम होना जिंदगी को कुछ आसान बना देता है। दूसरी तरफ स्वयं के बारे में जरूरत से ज्यादा भ्रम होना हमें अहंकारी बना देता है और हमारा अहंकारी स्वभाव दूसरों के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा करता है।

सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में जानबूझकर भ्रम पैदा करते हैं या फिर स्वतः ही हमारी जिंदगी में भ्रम पैदा हो जाते हैं? वास्तविकता तो यह है कि कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी जिंदगी में भ्रम पैदा नहीं करता है। भ्रम स्वतः ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और ताउम्र हमारा साथ निभाते हैं। जब भ्रम हमारा साथ निभातें है तो हम भी भ्रमों का साथ निभाते हैं। हमारे और भ्रम के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से तो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से यह रिश्ता इतना मजबूत होता है कि किसी भी कीमत पर टूटता नहीं है।

स्वयं के बारे में हमें कई तरह के भ्रम क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है। किसी राजनेता को यह भ्रम रहता है कि अन्य राजनेताओं की अपेक्षा उसका जनता से ज्यादा जुड़ाव है। किसी प्राध्यापक को यह भ्रम रहता है कि अपने विषय पर जितनी पकड़ उसकी है, उस विषय पर उतनी पकड़ पूरे विश्वविद्यालय में किसी की नहीं है। कुछ लोगों को अपनी विद्वता का भ्रम रहता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी मूर्खता का भ्रम भी रहता है। आप कहेंगे कि भला मूर्खता का कैसा भ्रम? दरअसल मूर्खता का भी भ्रम होता है। कुछ लोगों को यह पता होता है कि वे मूर्खता का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यह भ्रम होता है कि जितनी मूर्खता का काम वे कर रहे हैं उतनी मूर्खता का काम कोई और नहीं कर सकता, जबकि वास्तविकता यह होती है इस समाज में उनसे भी बड़े मूर्ख मौजूद रहते हैं और वे अपनी मूर्खता पर गर्व भी करते हैं। कुछ लोगों को अपनी सुंदरता का भ्रम होता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह भ्रम रहता है कि उनका चेहरा अच्छा नहीं है। कुछ साहित्यकारों को यह भ्रम होता है कि उन जैसा और कोई नहीं लिख रहा तथा दूसरे साहित्यकार कूड़ा लिख रहे हैं। किसी को यह भ्रम होता है कि अपने मुहल्ले में मैंने अपनी बेटी या बेटे की शादी में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। किसी को यह भ्रम होता है कि अपने मुहल्ले में मैंने सबसे अच्छा घर बनाया है। यानी इस तरह के भ्रम अंतहीन हैं। ऐसे भ्रमों से कई पन्ने भरे जा सकते हैं।

स्वयं के बारे में भ्रम पैदा होना हमारी परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमारे चारो तरफ का माहौल कैसा है। हमारे चारो तरफ किस प्रकार के लोग रहते है। लोग हमसे किस तरह की बातें करते हैं। हम अपने चारो तरफ मौजूद लोगों की बातों पर कितनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमारे दोस्त और परिचित हमारी हर बात मानकर हां में हां तो नहीं मिलाते हैं। हमारे परिचित हमें बात-बात में चने के झाड़ पर तो नहीं चढ़ा देते हैं। हमारी जिंदगी में ये सारी परिस्थितियां मिलकर स्वयं के बारे में भ्रम पैदा करती हैं। जब हमें अपने बारे में कुछ भ्रम हो जाता है तो हम अन्य नए-नए भ्रम भी पालने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने चारो तरफ एक ऐसा आभासी वातावरण बना लेते हैं जो वास्तविक लगने लगता है और हमारी जिंदगी को कई तरह से प्रभावित करता है। हमें स्वयं के बारे में तो कई तरह के भ्रम रहते ही हैं लेकिन दूसरों को भी हमारे बारे में कई तरह के भ्रम रहते हैं। सवाल उठता है कि जब दुनिया में भ्रम ही भ्रम हैं तो फिर इस दुनिया में वास्तविक क्या है?

जीवन जगत

स्वयं के बारे में भ्रम पैदा होना हमारी परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमारे चारो तरफ का माहौल कैसा है। हमारे चारो तरफ किस प्रकार के लोग रहते है। लोग हमसे किस तरह की बातें करते हैं। हम अपने चारो तरफ मौजूद लोगों की बातों पर कितनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमारे दोस्त और परिचित हमारी हर बात मानकर हां में हां तो नहीं मिलाते हैं।

थाईलैंड से इंडोनेशिया तक विश्व संस्कृति के महानायक हैं राम

योगेश कुमार गोयल

रामनवमी केवल एक धार्मिक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की उस अमर परंपरा का उत्सव है, जिसके केंद्र में मर्यादा, धर्म, करुणा और आदर्श जीवन का संदेश निहित है। इस वर्ष रामनवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी। दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले भगवान राम के बिना हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति की कल्पना ही अधूरी है। विराट भारतीय संस्कृति के प्राणपुरुष श्रीराम वास्तव में केवल भारत ही नहीं, विश्व संस्कृति के भी महानायक हैं। राम हमारे सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन में इस प्रकार रचे-बसे हैं कि उनका नाम मात्र ही मन को दिव्य शांति और ब्रह्मानंद की अनुभूति कराता है। यही कारण है कि भगवान राम की महिमा भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है।

दुनिया के अनेक देशों में भगवान राम की पूजा की जाती है और रामायण को विभिन्न रूपों में पढ़ा और सुना जाता है। भारत के अतिरिक्त कम से कम नौ ऐसे देश हैं, जहां रामकथा की परंपरा जीवंत रूप में विद्यमान है। इंडोनेशिया में तो रामकथा के पांच अलग-अलग संस्करण प्रचलित हैं, जिनकी रचना नौवीं शताब्दी में हुई मानी जाती है। नेपाल में चार रामायणों की परंपरा मिलती है जबकि जापान में भी रामायण से संबंधित उल्लेख देखने को मिलते हैं। मारीशस, नेपाल, इजरायल और कई मुस्लिम देशों में भी रामभक्ति की परंपरा आज भी दिखाई देती है। इतिहास और पुरातत्व के स्तर पर भी इसके रोचक प्रमाण मिलते हैं। इराक के सिलेमानिया क्षेत्र में बैनुला बाईपास के पास हुई खुदाई में भगवान राम और हनुमान की दुर्लभ प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जिनके बारे में इराक सरकार ने भारत को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। इराक के पुरातत्व विभाग के अनुसार ये प्रतिमाएं लगभग चार हजार वर्ष पुरानी मानी जा रही हैं। ऐसे प्रमाण यह संकेत देते हैं कि भगवान राम का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि हजारों वर्षों से विश्व सभ्यता के व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य में भी उनकी उपस्थिति बनी हुई है।

मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की यात्रा भारत से लेकर मारीशस, नेपाल, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और श्रीलंका तक रही है। इन सभी देशों में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि भगवान राम के चरण इन सभी देशों में पड़े थे। थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भगवान राम की कथाओं का वर्णन और मंचन अक्सर होता है। बैंकाक में तो रामायण चित्रों की दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला भी है। वहां राजमहल के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति और अंदर तथा बाहरी दीवारों पर पूरी रामायण है। दीवारों पर ऐसे ही रामायण का अंकन कंबोडिया के राजमहल में भी मिलता है। थाईलैंड तो पूरी तरह से राममय है, जहां की सड़कों से लेकर पुलों के नाम भी भगवान श्रीराम के नाम पर ही रखे गए हैं।

थाईलैंड के लबबुरी में हनुमान जी संजीवनी बूटी हेतु गिर पर्वत उठाते हुए दिखते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग श्रीराम और उनके जीवन से सीख ले सकें, इसके लिए थाईलैंड में श्रीराम के जीवन पर आधारित चित्रकला की कार्यशाला भी आयोजित की जाती हैं। वहां भगवान राम की कहानी रामायण का स्थानीय स्वरूप मौजूद है, जिसे 'रामाकीन' या 'रामाकियेन' कहा जाता है, जिसका अर्थ है राम की कीर्ति। इस ग्रंथ में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और महाबली हनुमान का उल्लेख है। यह ग्रंथ काफी हद तक वाल्मीकि रामायण के जैसा ही है, केवल कुछ हिस्सों में इसका चित्रण अलग है, जिसे थाईलैंड की संस्कृति के प्रमुख ग्रंथ का दर्जा हासिल है। थाईलैंड की ही भांति कंबोडिया में भी रामायण का स्थानीय संस्करण है, जिसे 'रिएमकार' कहा जाता है। वहां भी बौद्ध और हिन्दू धर्म के मिले-जुले अंश पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी रामकथा का एक रूप 'काकाविन' रामायण ग्रंथ के रूप में मिलता है, जो कई सदियों से इस देश का अहम हिस्सा है, हालांकि स्थानीय देवी-देवताओं के अनुसार इसमें कुछ बदलाव भी हैं। इंडोनेशिया में रामायण का कई बार मंचन होता है, खासतौर से कठपुतलियों के जरिए रामायण का मंचन वहां बेहद सामान्य है और वहां की संस्कृति का हिस्सा है।

भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम को समर्पित राम मंदिर भी दुनिया के कोने-कोने में बने हैं, जो विश्वभर में बसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सर्वोच्च प्रतीक हैं और रामभक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। विदेशों में भी इन राम मंदिरों का बड़ा महत्व है। कई देशों में भव्य राम मंदिरों का निर्माण किया गया है, जहां भारत से जाने वाले हिंदू तीर्थ यात्री दर्शन के लिए जाते हैं।

विभिन्न देशों में बने ये राम मंदिर न केवल हिंदू धर्म के सबसे महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शामिल हैं बल्कि दुनियाभर में हिंदू धर्म की आस्था और संस्कृति के प्रतीक भी हैं। विदेशों में राम मंदिरों का निर्माण भारत की गौरवशाली सनातन संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देते हुए दुनियाभर के लोगों को हिंदू धर्म के बारे में जानने और समझने में मदद करता है।

रामनवमी (26 मार्च) पर विशेष

संकट में ऊर्जा

ऊर्जा संकट का आर्थिक प्रभाव भी कम गंभीर नहीं होता। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। परिवहन, उद्योग और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। इसलिए ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है। आज की दुनिया को अक्सर 'वैश्विक गांव' कहा जाता है। तकनीक, व्यापार और संचार के विस्तार ने देशों को इतना परस्पर जुड़ा हुआ बना दिया है कि विश्व के किसी भी हिस्से में घटित घटना का प्रभाव सीमाओं से परे जाकर अन्य देशों तक पहुंच जाता है। पश्चिम-एशिया में हाल ही में बढ़े सैन्य तनाव और युद्ध की स्थिति ने इस वास्तविकता को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और उसके बाद उत्पन्न भू-राजनीतिक संकट ने केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को ही नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित किया है। इसका असर भारत जैसे ऊर्जा-आयातक देशों पर विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया विश्व की ऊर्जा राजनीति का केंद्र माना जाता है। तेल और गैस के विशाल भंडार के कारण यह क्षेत्र दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है, लेकिन जब भी इस क्षेत्र में संघर्ष या अस्थिरता पैदा होती है, तो उसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। वर्तमान संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसका प्रभाव कई देशों के साथ-साथ भारत पर भी दिखाई देने लगा है। भारत में 'एलपीजी' (लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस) गैस-सिलेंडरों की आपूर्ति में देरी, बुकिंग की अवधि में वृद्धि और होटल-रेस्टोरेंट उद्योग में गैस की कमी जैसी समस्याएं इसी व्यापक संकट की ओर संकेत करती हैं। भारत की ऊर्जा संरचना को समझे बिना इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा जा सकता। भारत विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन उसकी घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता अभी भी सीमित है। 'एलपीजी' की मांग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है और इन आयातों का अधिकांश भाग पश्चिम एशियाई देशों से आता है। ऐसी स्थिति में यदि उस क्षेत्र में युद्ध या परिवहन मार्गों में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसका सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ना स्वाभाविक है। भारत में रसोई गैस केवल एक घरेलू ईंधन नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। पिछले दशक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों परिवारों को 'एलपीजी' कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हुई है, लेकिन इस बढ़ती सहूलियत के साथ-साथ आयात पर बढ़ती निर्भरता भी एक चुनौती बनकर सामने आई है। यदि वैश्विक संकट के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका असर केवल घरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि छोटे व्यापार, होटल-रेस्टोरेंट उद्योग और खाद्य क्षेत्र पर भी पड़ता है। ऊर्जा संकट का आर्थिक प्रभाव भी कम गंभीर नहीं होता। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। परिवहन, उद्योग और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। इसलिए ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसी परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और उसकी विदेश नीति परंपरागत रूप से संतुलन, संवाद और शांति के सिद्धांतों पर आधारित रही है। भारत के संबंध पश्चिम-एशिया के लगभग सभी प्रमुख देशों के साथ हैं - चाहे वह इज़राइल हो, ईरान हो या अरब देश। इसलिए भारत के सामने चुनौती यह है कि वह अपनी कूटनीतिक संतुलन क्षमता को बनाए रखते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाए। भारत की विदेश नीति का मूल आधार हमेशा से यह रहा है कि वह किसी भी संघर्ष में पक्ष लेने के बजाय संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान का समर्थन करे। आज भी यही दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत युद्ध के बजाय बातचीत, संघर्ष-विराम और बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन करता है। भारत की छवि एक जिम्मेदार और शांति-समर्थक राष्ट्र की रही है और इस संकट के समय भी उसे इसी दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि केवल कूटनीति ही पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। भारत को अपनी ऊर्जा नीति में दीर्घकालिक सुधार करने होंगे। इसके अंतर्गत ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण अत्यंत आवश्यक है, ताकि देश किसी एक क्षेत्र या देश पर अत्यधिक निर्भर न रहे। इसके साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा-जैसे सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार भी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

युद्ध की आंच में झुलसती वैश्विक अर्थव्यवस्था

|| कांतिलाल मांडोत ||

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब केवल दो देशों का सैन्य टकराव नहीं रह गया है बल्कि यह धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला संकट बनता जा रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहा यह संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजार व्यापारिक गतिविधियों और वित्तीय बाजारों पर गहरा असर डाल रहा है। युद्ध के दसवें दिन ही दुनिया ने इसका आर्थिक प्रभाव साफ तौर पर महसूस करना शुरू कर दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेज वृद्धि और शेयर बाजारों में आई गिरावट ने यह संकेत दे दिया है कि यदि यह संघर्ष लंबा चला तो इसका असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा।

तेल की कीमतों में तेजी इस संकट का सबसे बड़ा संकेत बनकर सामने आई है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं जो जुलाई 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। कुछ ही दिनों में तेल की कीमतों में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तेल की कीमतों में इतनी तेज वृद्धि का सीधा कारण पश्चिम एशिया में पैदा हुई अनिश्चितता और आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक और निर्यातक क्षेत्रों में से एक है इसलिए वहां होने वाला कोई भी सैन्य संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजार को तुरंत प्रभावित करता है। निवेशकों और व्यापारियों को डर है कि यदि युद्ध और फैलता है तो तेल की आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है जिससे कीमतों में और तेजी आ सकती है।

तेल की कीमतों में इस उछाल का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करते हैं। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में हर बढ़ोतरी सीधे देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसी आशंका के कारण भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। दो दिन के अवकाश के बाद जब बाजार खुला तो निवेशकों में डर और अनिश्चितता का माहौल था। परिणामस्वरूप बाजार खुलते ही भारी बिकवाली शुरू हो गई और सेंसेक्स लगभग 1800 अंक नीचे खुला। थोड़ी ही देर में गिरावट बढ़कर 2492 अंकों तक पहुंच गई जिसने निवेशकों को और चिंतित कर दिया।

दिन के अंत में बाजार में थोड़ी स्थिरता जरूर दिखाई दी लेकिन नुकसान काफी बड़ा रहा। सेंसेक्स अंततः 1352.74 अंकों की गिरावट के साथ 77566.16 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी भी 422 अंकों से अधिक गिरकर 24028 के आसपास बंद हुआ। लगातार गिरावट के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक लगभग ग्यारह महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बाजार में आई इस गिरावट का सबसे अधिक असर उन क्षेत्रों पर पड़ा जो सीधे तेल और परिवहन लागत से जुड़े हैं। तेल कंपनियां ऑटोमोबाइल उद्योग धातु उद्योग एविएशन और लॉजिस्टिक कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट

तेल की कीमतों में इस उछाल का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करते हैं। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में हर बढ़ोतरी सीधे देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसी आशंका के कारण भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। दो दिन के अवकाश के बाद जब बाजार खुला तो निवेशकों में डर और अनिश्चितता का माहौल था। परिणामस्वरूप बाजार खुलते ही भारी बिकवाली शुरू हो गई और सेंसेक्स लगभग 1800 अंक नीचे खुला। थोड़ी ही देर में गिरावट बढ़कर 2492 अंकों तक पहुंच गई जिसने निवेशकों को और चिंतित कर दिया।दिन के अंत में बाजार में थोड़ी स्थिरता जरूर दिखाई दी लेकिन नुकसान काफी बड़ा रहा। सेंसेक्स अंततः 1352.74 अंकों की गिरावट के साथ 77566.16 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी भी 422 अंकों से अधिक गिरकर 24028 के आसपास बंद हुआ।

देखी गई। बाजार में इस गिरावट से निवेशकों की लगभग आठ लाख करोड़ रुपये की पूंजी कम हो गई जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाती है।

सरकार का कहना है कि फिलहाल महंगाई पर इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि देश में मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत नियंत्रित स्तर पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले भारतीय तेल बास्केट की कीमतें गिरावट की ओर थीं और दो मार्च तक यह लगभग 69 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से बढ़कर 80 डॉलर के आसपास पहुंची थीं। उनका कहना है कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और यदि जरूरत पड़ी तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि आम लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतों में यह तेजी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर परिवहन लागत उत्पादन खर्च और अंततः उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर जरूर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि महंगाई बढ़ने का खतरा पूरी तरह टला नहीं है।

ऊर्जा बाजार के अलावा इस युद्ध ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। समुद्री मार्गों में बढ़ते जोखिम के कारण कई जहाजों को अपने रास्ते बदलने पड़ रहे हैं और कुछ जहाजों को यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ रही है। इसके कारण दुनिया भर के कई कंटेनर बंदरगाहों और समुद्री मार्गों में फंस गए हैं। भारत का लगभग 12000 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात माल भी इसी संकट में फंसा हुआ है। यह स्थिति भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गई है क्योंकि माल की डिलीवरी में देरी होने से व्यापारिक अनुबंध प्रभावित हो सकते हैं और कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

लॉजिस्टिक्स कंपनियों के अनुसार युद्ध के कारण शिपिंग कंपनियों ने कई नए आकस्मिक शुल्क लागू कर दिए हैं। सामान्य परिस्थितियों में जहां एक कंटेनर की ढुलाई लागत लगभग 800 से 1500 डॉलर के बीच होती थी वहीं अब यह लागत कई गुना बढ़ गई है। कई मामलों में प्रति कंटेनर लगभग 4000 डॉलर तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है। इन अतिरिक्त शुल्कों में युद्ध जोखिम अधिभार आपातकालीन लागत वसूली शुल्क और पीक सीजन शुल्क जैसे कई नए चार्ज शामिल हैं। इससे निर्यातकों की लागत अचानक बढ़ गई है और उनके मुनाफे पर गंभीर असर पड़ रहा है।इस संकट का सबसे अधिक असर उन वस्तुओं पर पड़ रहा है जो जल्दी खराब हो जाती हैं। बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में तरल माल निकासी की प्रतीक्षा कर रहा है जबकि लगभग 939 टन जल्दी खराब होने वाला माल भी फंसा हुआ है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इन वस्तुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा समुद्र में फंसे कंटेनरों में लगभग चार लाख टन बासमती चावल भी शामिल है जो भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में से एक है। बासमती चावल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है और यदि युद्ध के कारण वहां व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो भारतीय किसानों और निर्यातकों दोनों को नुकसान हो सकता है।

इसी तरह भारत का काबुली चना भी खाड़ी क्षेत्र के देशों में बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। पिछले दो वर्षों में इसका निर्यात लगभग दोगुना हो गया था और इसमें ईरान अरब देशों और तुर्किए की बड़ी हिस्सेदारी रही है। लेकिन वर्तमान युद्ध के कारण इन देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं जिससे इस निर्यात पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो भारतीय कृषि निर्यात को भी बड़ा झटका लग सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की कीमतों में आई वृद्धि को इस संघर्ष की परिस्थितियों मं उचित बताया है। उनका कहना है कि यदि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे को समाप्त करना है तो कुछ समय के लिए तेल की कीमतों में वृद्धि को स्वीकार करना पड़ेगा। उनका दावा है कि जब यह खतरा समाप्त हो जाएगा तब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी और बाजार फिर से स्थिर हो जाएगा। हालांकि फिलहाल वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और निवेशक आने वाले दिनों को लेकर सतर्क हैं।

स्पष्ट है कि युद्ध का प्रभाव केवल सीमा रेखाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह आर्थिक व्यवस्था के हर स्तर को प्रभावित करता है। तेल की कीमतों में तेजी शेयर बाजारों में गिरावट और वैश्विक व्यापार में बाधा इस बात का संकेत है कि यदि यह संघर्ष जल्द समाप्त नहीं हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे समय में सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे आर्थिक स्थिरता बनाए रखें और आम नागरिकों को महंगाई तथा आर्थिक अस्थिरता से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। यदि कूटनीतिक प्रयासों के जरिए जल्द समाधान नहीं निकला तो यह युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय तक चिंता का कारण बना रह सकता है।

महिला मुखिया बदल रहीं गाँवों की तस्वीर

आयुष कृष्ण त्रिपाठी

रायबरेली जिले के धर्मपुर गांव में काम का दिन आठ बजे से पहले शुरू हो जाता है। पंचायत बिल्डिंग से जुड़े एक छोटे से कमरे के अंदर, नौ महिलाएं पहले से ही एक सेमी-ऑटोमैटिक प्रेस के चारों ओर अपनी जगह पर बैठी होती हैं। कॉटन फाइबर एक सिरे से जाता है। दूसरे सिरे से साफ-सुथरे सीलबंद पैकेट निकलते हैं। जब तक सड़क के उस पार स्कूल की घंटी बजती है, तब तक कई सौ सैनिटरी पैड गिने जा चुके होते हैं, उन्हें ढेर लगाकर सुबह बांटने के लिए अलग रख दिया जाता है। यह यूनिट 2023 में ग्राम प्रधान सुशीला देवी ने एक सेल्फ-हेल्प ग्रुप की मीटिंग के बाद शुरू की थी, जिसने एक अचानक मोड़ ले लिया।नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में 15 से 24 साल की उम्र की सिर्फ़ 59 परसेंट औरतें ही पीरियड्स से बचाव के लिए कोई साफ़-सुथरा तरीका इस्तेमाल करती हैं। नेशनल एवरेज 78 परसेंट है। रायबरेली ज़िले में, धर्मपुर ग्राम पंचायत बिल्डिंग से जुड़े एक कमरे में, नौ औरतें हर सुबह आठ बजे से पहले एक सेमी-ऑटोमैटिक सैनिटरी पैड प्रेस चलाने आती हैं, जिसे ग्राम प्रधान सुशीला देवी ने पहली बार आठ महीने बाद, तीसरी बार अप्लाई करने पर मंजूरी दिलाई थी। मशीन की कीमत 11 लाख रुपये है। आठ पैड का एक पैकेट 20 रुपये में बिकता है। कमर्शियल ब्रांड रखने वाली सबसे पास की फार्मेसी छह किलोमीटर दूर है और उतने ही पैकेट के लिए 65 रुपये लेती है। यह यूनिट 2023 की शुरुआत से चल रही है। यह रोज़ाना लगभग 800 पैड बनाती है। एक महिला ने चलते-चलते बताया कि वह कपड़ा ढूंढ रही है क्योंकि उसे पीरियड्स हो रहे हैं। दूसरी महिलाएं भी बोलने लगीं। जब तक मीटिंग खत्म हुई, यह साफ हो गया था कि गांव की बहुत सी महिलाओं ने कभी सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं किया था कुछ कपड़े का इस्तेमाल कर रही थीं, कुछ राख मिला कपड़ा इस्तेमाल कर रही थीं क्योंकि पैड या तो आस-पास नहीं मिलते थे या बहुत महंगे थे। सुशीला देवी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस मीटिंग से जो निकला, वो होगा।₹ ₹ये वो औरतें थीं जिन्हें मैं सालों से जानती थी। मुझे नहीं पता था कि ये उनकी रोज़ की सच्चाई है।₹ उन्होंने वढ ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मशीनरी के लिए अप्लाई किया था। पहला एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। दूसरा सवालों के साथ वापस आया। तीसरा एप्लीकेशन मंजूर हुआ, पहला एप्लीकेशन फाइल करने के आठ महीने बाद। यूनिट अब रोज़ 700 से 800 पैड बनाती है, जो आठ के पैकेट के लिए 20 रुपये में बिकते हैं। लोकल स्कूल, आंगनवाड़ी और रल्ठ्ऋ ज़्यादातर स्टॉक लेते हैं। कविता सिंह, जो ग्यारह साल से गांव के अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही हैं, ने कहा कि क्लास 6 से 8 की लड़कियां हर महीने तीन या चार दिन अटेंडेंस रजिस्टर से गायब रहती थीं। उन्होंने कहा, ₹मुझे पता था क्यों, लेकिन मैं लंबे समय तक इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। जब से पैड आने शुरू हुए हैं, तब से यह बदल गया है। उनमें से ज़्यादातर अब रेगुलर आती हैं।₹ बांदाः जानवरों के बाड़े से कुकिंग गैस, बांदा ज़िले में, मीना प्रजापति 2015 से देवापुर पंचायत की ग्राम प्रधान हैं। वह आपको बताएंगी कि उनके पहले टर्म में कुछ खास नहीं हुआ। वह किसी की प्रॉक्सी नहीं थीं उनके पति साल के ज़्यादातर समय पुणे में काम करते हैं लेकिन उन्हें ब्लॉक ऑफ़िस में डर लगता था और जो भी फ़ाइल करने को कहा जाता था, वह बिना कारण पूछे फ़ाइल कर देती थीं। उन्होंने कहा, ₹मैं घर जाती थी और खाना बनाती थी और अगली बार जब वे मुझे बुलाते थे तो वापस आ जाती थी।₹ ₹वह मेरा पहला टर्म था।उनके दूसरे टर्म की शुरुआत अलग तरह से हुई। पंचायत की पुरानी फ़ाइलें देखने पर, उन्हें एक कम्युनिटी बायोगैस प्लांट के लिए 2019 का एक मंजूरी ऑर्डर मिला, जो कभी लागू ही नहीं हुआ था। असली जगह एक ऐसे गाँव में थी जिसे बाद में दूसरी पंचायत में मिला दिया गया था। मंजूरी को बस एक तरफ़ रख दिया गया था और भूल गए थे। वह इसे ब्लॉक ऑफ़िस ले गईं और अगले चार महीने यह पक्का करने में बिताए कि फ़ंड को दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ऐसा किया गया। यह प्लांट अब जानवरों के बाड़े की एक लाइन के पीछे है और आठ घरों के गोबर से चलता है। ग्यारह परिवारों को ढश्उ लाइनों के ज़रिए कुकिंग गैस मिलती है। बायो-स्लरी का बाय-प्रोडक्ट आठ किसान परिवारों को ऑर्गेनिक खाद के तौर पर जाता है। उन किसानों में से एक, रामखेलावन ने कहा कि उन्होंने पिछले रबी सीज़न में यूरिया पर लगभग फ₹ 1,800 कम खर्च किए। एक दूसरे किसान ने कहा कि उनके खेत में बचत कम हुई। एक तीसरे ने एक सीज़न के लिए इसे आज़माया और फिर से केमिकल फ़र्टिलाइज़र पर लौट आए क्योंकि उनके ऊबड़-खाबड़ खेत में स्लरी डालना मुश्किल था। प्रजापति ने कहा, ₹औरतें जलाने की लकड़ी के लिए चालीस मिनट पैदल चलती थीं।₹ ₹छढ्ऋसिलेंडर बहुत महंगे थे। गोबर वहीं पड़ा रहता था। अब गोबर फ्यूल है और स्लरी फ़र्टिलाइज़र है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता।₹

लखीमपुर खीरी में, ग्राम प्रधान पुष्पा रावत ने 2022 में गांव के स्कूल ग्राउंड पर रोज़ाना योग सेशन शुरू किए। सबसे पास का सब-सेंटर चार किलोमीटर दूर है। जब भी होता है, डॉक्टर हर हफ़्ते आते हैं। रावत ने कहा कि वह कुछ ऐसा ढूंढ रही थीं जिसमें कोई खर्च न हो और जो किसी सरकारी डिपार्टमेंट पर निर्भर हुए बिना हर दिन हो सके। पहली सुबह तीन औरतें आईं। दूसरे हफ़्ते के आखिर तक बारह औरतें आ गईं। अब ज़्यादातर दिनों में लगभग चालीस लोग आते हैं औरतें, बुज़ुर्ग लोग, टीनएज लड़कियां। एक लोकल आशा वर्कर और एक रिटायर्ड टीचर सेशन को लीड करते हैं। कुछ परिवारों ने शुरू में औरतों के सूरज उगने से पहले पब्लिक जगह पर इकट्ठा होने पर एतराज़ किया। रावत ने कहा कि उन्होंने बहस नहीं की। वह आती रहीं। ₹वे मेरे पति से बात करने के लिए कहते थे। वह उन्हें मेरे पास वापस भेज देते थे।₹ उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से लगभग आधी की हेड अभी राज्य के 50 परसेंट रिज़र्वेशन रूल के तहत औरतें हैं। तीनों मुखियाओं ने एक ही शुरुआती अनुभव बतायाः बिना किसी से बात किए मीटिंग में मौजूद रहना, गांव वालों का उनके घर आना और प्रधान के पति को बुलाना, पंचायत सेक्रेटरी को ऐसी फाइलें मैनेज करते देखना जो टेक्निकली उनकी थीं। सुशीला देवी ने कहा, ₹इसमें समय लगा।₹ ₹एक बार जब सड़क बन गई और लोगों ने उसे देखा, तो वे सीधे मेरे पास आने लगे। उससे पहले वे मेरी तरफ नहीं देखते थे और मेरे पीछे खड़े किसी को देखते थे।₹

तीनों ने कहा कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की वजह से वे कुछ भी कर पाए। हर मामले में, रल्ठ्ऋनेटवर्क चुनाव से पहले गांव में एक्टिव था और उसने प्रधान को महिलाओं का एक ग्रुप दिया जो ग्राम सभाओं में जाती थीं, पब्लिक मीटिंग्स में सवाल उठाती थीं और चुने हुए प्रधान को एक ऐसा वोट बैंक दिया जिसे आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता था। पुष्पा रावत, जिनके पति साल के ज़्यादातर समय दिल्ली में रहते हैं, ने वह कहा जो महिलाओं की पॉलिटिकल हिस्सेदारी के किसी भी ऑफिशियल अकाउंट में दर्ज नहीं होता है। ₹लोग सुबह कैंप और दोपहर में पंचायत मीटिंग देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि मैंने इन सबसे पहले सुबह चार बजे रोटियां बनाई हैं। उस हिस्से के लिए कोई स्कीम नहीं है।₹सुशीला देवी की रिज़र्व सीट अगले चुनाव में रोटेट होती है। वह जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पैड यूनिट की चिंता नहीं है। ₹इसे चलाने वाली महिलाएं अब इसे मुझसे बेहतर जानती हैं। हमेशा यही आइडिया था कि इसे मेरी ज़रूरत नहीं होगी।

यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट की 2022-23 की सालाना रिपोर्ट में राज्य की 58,195 ग्राम पंचायतों की लिस्ट है, जिनमें से 29,342 में अभी महिलाएं हेड हैं, जो 50 परसेंट रिजर्वेशन नियम के तहत हैं, जो 2010 में यूपी पंचायत राज एक्ट में हुए बदलाव के बाद लागू हुआ था। रिपोर्ट में इस्तेमाल हुए फंड और पूरे हुए कामों को मापा गया है। इसमें यह नहीं मापा गया है कि उन 29,342 महिलाओं में से कितनी ने अपने फैसले खुद लिए। ठ्ऋर-5 के डेटा से पता चलता है कि यूपी में, 57 परसेंट शादीशुदा महिलाएं बताती हैं कि उनके हेल्थकेयर के बारे में फैसले सिर्फ उनके पति ही लेते हैं। पंचायत घर से अलग संस्था है, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं है। सुशीला देवी की रिजर्व सीट अगले चुनाव में रोटेट होगी। वह जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पैड यूनिट उनके प्रधान होने पर निर्भर नहीं करती है रल्ठ्ऋफेडरेशन के पास मशीनरी होती है, पंचायत के पास नहीं। यह व्यवस्था नए प्रधान और नए सेक्रेटरी के बाद भी चलती है या नहीं, यह डेटा में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठ्ऋर अपना अगला सर्वे 2024-26 में करेगा। इसमें 15 से 24 साल की महिलाओं से पूछा जाएगा कि वे अपने पीरियड्स के दौरान क्या इस्तेमाल करती हैं। धर्मपुर में, उनमें से कुछ महिलाओं का जवाब पिछली बार दिए गए जवाब से अलग होगा। यहां हर नंबर का सोर्स ये हैः ठ्ऋर-5 वढ स्टेट फैक्टशीट (मेंस्टुअल हाइजीन 59%, नेशनल 78%, पति के हेल्थकेयर फैसले 57%), वढ पंचायत राज एक्ट 2010 अमेंडमेंट, वढ पंचायती राज डिपार्टमेंट ने पंचायतों की संख्या 58,195 बताई, ठ्ऋर-6 फील्डवर्क विंडो 2024-26। आखिर में यह लाइन इसलिए है क्योंकि यह एक असली सर्वे साइकिल से जुड़ी है यह कोई दिखावटी दिखावा नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है जिसके साथ एक तारीख जुड़ी है।

यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट की 2022-23 की सालाना रिपोर्ट में राज्य की 58,195 ग्राम पंचायतों की लिस्ट है, जिनमें से 29,342 में अभी महिलाएं हेड हैं, जो 50 परसेंट रिजर्वेशन नियम के तहत हैं, जो 2010 में यूपी पंचायत राज एक्ट में हुए बदलाव के बाद लागू हुआ था। रिपोर्ट में इस्तेमाल हुए फंड और पूरे हुए कामों को मापा गया है। इसमें यह नहीं मापा गया है कि उन 29,342 महिलाओं में से कितनी ने अपने फैसले खुद लिए। ठ्ऋर-5 के डेटा से पता चलता है कि यूपी में, 57 परसेंट शादीशुदा महिलाएं बताती हैं कि उनके हेल्थकेयर के बारे में फैसले सिर्फ उनके पति ही लेते हैं। पंचायत घर से अलग संस्था है, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं है। सुशीला देवी की रिजर्व सीट अगले चुनाव में रोटेट होगी। वह जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पैड यूनिट उनके प्रधान होने पर निर्भर नहीं करती है रल्ठ्ऋफेडरेशन के पास मशीनरी होती है, पंचायत के पास नहीं। यह व्यवस्था नए प्रधान और नए सेक्रेटरी के बाद भी चलती है या नहीं, यह डेटा में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठ्ऋर अपना अगला सर्वे 2024-26 में करेगा। इसमें 15 से 24 साल की महिलाओं से पूछा जाएगा कि वे अपने पीरियड्स के दौरान क्या इस्तेमाल करती हैं। धर्मपुर में, उनमें से कुछ महिलाओं का जवाब पिछली बार दिए गए जवाब से अलग होगा। यहां हर नंबर का सोर्स ये हैः ठ्ऋर-5 वढ स्टेट फैक्टशीट (मेंस्टुअल हाइजीन 59%, नेशनल 78%, पति के हेल्थकेयर फैसले 57%), वढ पंचायत राज एक्ट 2010 अमेंडमेंट, वढ पंचायती राज डिपार्टमेंट ने पंचायतों की संख्या 58,195 बताई, ठ्ऋर-6 फील्डवर्क विंडो 2024-26। आखिर में यह लाइन इसलिए है क्योंकि यह एक असली सर्वे साइकिल से जुड़ी है यह कोई दिखावटी दिखावा नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है जिसके साथ एक तारीख जुड़ी है।

चिंतन

जीवन-मृत्यु के बीच का नैतिक धर्मसंकट

जीवन की परिभाषा केवल धड़कनों के चलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चेतना और मानवीय गरिमा का होना अनिवार्य है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया यानि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देना, कानून के शुष्क पन्नों से निकलकर मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर लिया गया एक अत्यंत साहसी और ऐतिहासिक फैसला है। पिछले 13 वर्षों से कोमा में पड़े हरीश का मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम विज्ञान के सहारे किसी व्यक्ति को जीवित रख रहे हैं या उसे मरने की अनुमति न देकर उसकी गरिमा का अपमान कर रहे हैं? इस पूरी बहस के केंद्र में माइंड डेड की वह भयावह स्थिति है, जिसे समझना आज के दौर में हर किसी के लिए अनिवार्य हो गया है। चिकित्सा विज्ञान स्पष्ट करता है कि जब मस्तिष्क का वह हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो जाता है जो चेतना और श्वसन को नियंत्रित करता है, तो व्यक्ति केवल एक भौतिक शरीर रह जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज न तो स्पर्श महसूस कर सकता है, न कोई आवाज़ सुन सकता है और न ही किसी प्रकार के दर्द का अनुभव कर सकता है। वह केवल वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट की मशीनी आवाज़ों के बीच एक कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर रह जाता है, जिसे जीवन कहना शायद जीवन शब्द का अपमान होगा। संवेदनाओं और वैज्ञानिक सीमाओं का ऐसा ही एक दौर हाल ही में तब देखने को मिला, जब मेरे एक परिचित परिवार में अत्यंत दुखद घटना घटी। एक महिला अपने कमरे में अचानक संतुलन खोकर गिर गईं और बेड के कोने से सिर के पिछले हिस्से में लगी गहरी चोट ने उनके मस्तिष्क को सदा के लिए शांत कर दिया। दो दिनों तक वह अस्पताल में सघन चिकित्सा और भारी-भरकम मशीनों के सहारे सांसें लेती रहीं, लेकिन डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने परीक्षणों के बाद स्पष्ट कर दिया कि वह माइंड डेड हैं। ऐसी घड़ी में परिवार के सामने खड़ा धर्मसंकट किसी पहाड़ जैसा था। एक तरफ अपनों को खोने का असहनीय गम था, तो दूसरी तरफ मशीनों में जकड़ा हुआ वह बेजान शरीर। अंततः, डॉक्टरों की स्पष्ट राय और परिजनों की आपसी सहमति से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का वह अत्यंत कठिन और हृदयविदारक निर्णय लिया गया। यह फैसला किसी की जान लेने का प्रयास नहीं था, बल्कि उस महिला को एक यंत्रवत और कष्टकारी जीवन से आज़ाद करने की सर्वोच्च करुणा थी। यह उस आत्मा के प्रति सम्मान था, जिसे प्रकृति ने पहले ही बुला लिया था, पर विज्ञान ने मशीनों की बेड़ियों में बाँध रखा था। सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना तर्कसंगत है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु भी जीने के अधिकार का ही एक अनिवार्य विस्तार है। जब चिकित्सा विज्ञान के तमाम प्रयास विफल हो जाएं और सुधार की कोई न्यूनतम गुंजाइश न बचे, तो मशीनों के प्लग के जरिए किसी की धड़कनों को जबरन खींचना उस व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है। एक बेड पर सालों तक निर्जीव शरीर की सेवा करना न केवल आर्थिक रूप से परिवार को खोखला कर देता है, बल्कि मानसिक रूप से भी घर के बाकी सदस्यों के जीवन को खंडित कर देता है। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए बनाए गए कड़े नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि इस कानूनी प्रावधान का कभी कोई दुरुपयोग न हो। एक मेडिकल बोर्ड की निगरानी और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही ऐसा कदम उठाया जाता है, जो यह प्रमाणित करता है कि मरीज अब वापस नहीं लौट सकता। पैसिव यूथेनेशिया का वास्तविक उद्देश्य किसी के जीवन को समय से पूर्व समाप्त करना नहीं है, बल्कि मृत्यु के स्वाभाविक और प्राकृतिक मार्ग में बाधा बनी कृत्रिम दीवारों को हटा देना है। अक्सर समाज में यह तर्क दिया जाता है कि चमत्कार कभी भी हो सकते हैं, लेकिन माइंड डेड की स्थिति में विज्ञान के पास भी कोई उत्तर नहीं होता। ऐसे में करुणा का तकाजा यही है कि हम उस व्यक्ति को शांति से विदा होने दें। हरीश राणा जैसे मामलों में मिली कानूनी अनुमति केवल एक अदालती आदेश नहीं है, बल्कि वर्षों के निशब्द संघर्ष और उस असहनीय पीड़ा का अंत है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन की सार्थकता उसकी गुणवत्ता और चेतना में निहित है, केवल लंबी उम्र में नहीं। हरीश के लिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनके वर्षों के उस लंबे और मौन सफर को अब जाकर अंतिम शांति और सुकून मिला है। उनकी इस गरिमापूर्ण विदाई ने असहनीय पीड़ा की उन तमाम बेड़ियों को हमेशा के लिए काट दिया है, जो उन्हें एक दशक से अधिक समय से जकड़े हुए थीं। अब वह मौन शांत है, वह पीड़ा लुप्त है और वह आत्मा समस्त बंधनों से स्वतंत्र है।

दिलीप कुमार पाठक

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

सेंसेक्स से हवाई किराये तक

पश्चिम एशिया के संकट का असर देश में शेयर बाजार से लेकर हवाई किराये तक पर गहराई से महसूस किया जा रहा है. शेयर बाजार के लिए 2026 अब तक भारी गिरावट वाला साल साबित हुआ है. बीते सप्ताह बीएसइ के 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 4,354.98 अंक या 5.51 प्रतिशत नीचे आ गया. जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1299.35 अंक या 5.31 फीसदी नीचे आ गया. निफ्टी में लगभग 1,300 अंकों की भारी गिरावट बताती है कि यह तेजी का दौर नहीं है.

पश्चिम एशिया के संकट का असर देश में शेयर बाजार से लेकर हवाई किराये तक पर गहराई से महसूस किया जा रहा है. फिलहाल जो स्थिति है, उससे लगता नहीं कि तस्वीर जल्दी बदलने वाली है.

निफ्टी का यह पिछले चार साल में बाजार का सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन है. इससे पहले जून, 2022 में निफ्टी में एक सप्ताह के दौरान पांच प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आयी थी. शेयर बाजार में गिरावट की बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष और विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि है. इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है और बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया है. इसके अलावा कॉरपोरेट नतीजों की सुस्ती, वैश्विक व्यापार का तनाव और एआइ सेक्टर में सीमित हिस्सेदारी भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह शेयर बाजार थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन के आंकड़े और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करेगा. भू-राजनीतिक तनावों से देश में हवाई किराये में भी वृद्धि हुई है. बढ़ती तेल कीमतों के बीच एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अकासा एयर ने भी फ्लाइट टिकट पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है, जो 199 रुपये से 1,300 रुपये के बीच होगा. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होने वाला यह सरचार्ज फ्लाइट की दूरी तथा समय के हिसाब से अलग-अलग होगा. दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनावों की वजह से एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) की कीमत में तेज वृद्धि हुई है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ के दाम 5,500 रुपये तक बढ़ा दिये हैं, इसलिए एयरलाइन कंपनियों ने फ्लाइट टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया है. ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पीछे तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में तेल आपूर्ति में आये बड़े व्यवधान को कारण बताया है. एटीएफ एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 40 फीसदी होता है. दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरों में एटीएफ पर उच्च उत्पाद शुल्क और वैट के कारण यह दबाव और बढ़ गया है, जिससे एयरलाइन की ऑपरेटिंग इकोनॉमी पर काफी दबाव पड़ रहा है.

विश्व व्यापार पर ट्रंप टैरिफ का नया दबाव

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो, एमपी-आइडीएसए
anandkmrai@gmail.com

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कई देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की धमकी देकर विश्व व्यापार व्यवस्था में नयी अनिश्चितता पैदा कर दी है. ट्रंप प्रशासन ने व्यापारिक जांचों का रास्ता चुना है. ये जांचें ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 301 के तहत शुरू की गयी हैं, जो अमेरिकी व्यापार नीति में बेहद शक्तिशाली कानूनी प्रावधान माना जाता है. भारत के लिए यह स्थिति असहज करने वाली है, क्योंकि इधर नयी दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में वार्ता चल रही थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दुनिया के कई देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की धमकी देकर विश्व व्यापार व्यवस्था में नयी अनिश्चितता पैदा कर दी है. पिछले कुछ साल में ट्रंप प्रशासन की आर्थिक रणनीति का सबसे प्रमुख उपकरण टैरिफ ही रहा है. यह कदम तब सामने आया है, जब हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाये गये वैश्विक टैरिफ को अवैध करार दिया था. अदालत के इस फैसले ने अमेरिकी सरकार की व्यापारिक रणनीति को झटका दिया और कई देशों के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं की दिशा भी अचानक बदल गयी. कई देश थे, जिन्होंने अमेरिका के साथ नये द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये थे या ऐसे समझौतों पर बातचीत कर रहे थे, ताकि वे ट्रंप द्वारा लगाये जाने वाले संभावित टैरिफ से बच सकें. पर जब अदालत ने इन टैरिफ को अवैध ठहरा दिया, तब यह सवाल खड़ा हो गया कि अमेरिका अब अपने व्यापारिक दबाव को किस तरह बनाये रखेगा. इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप प्रशासन ने एक नयी रणनीति अपनाते हुए व्यापारिक जांचों का रास्ता चुना है. ये जांचें ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 301 के तहत शुरू की गयी हैं, जो अमेरिकी व्यापार नीति में एक बेहद शक्तिशाली कानूनी प्रावधान माना जाता है.

इस कानून के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को अधिकार प्राप्त है कि वह उन देशों के खिलाफ जांच शुरू करे, जिन पर अमेरिका के साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने का आरोप हो. यदि जांच में आरोप सही पाये जाते हैं, तो अमेरिका उन देशों के खिलाफ जवाबी कदम उठाते हुए टैरिफ या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है. इस प्रकार धारा 301 अमेरिकी प्रशासन को कानूनी ढांचे के भीतर रहते हुए अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करती है. ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि जिन देशों के खिलाफ जांच शुरू की गयी है, वे अपनी औद्योगिक नीतियों और उत्पादन ढांचे के माध्यम से वैश्विक बाजार में असंतुलन पैदा कर रहे हैं. जिन देशों को इस जांच के दायरे में लाया गया है, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं. इनमें भारत, चीन और जापान जैसे बड़े औद्योगिक राष्ट्रों के अलावा वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ताइवान आदि शामिल हैं. यह सूची संकेत देती है कि अमेरिका वैश्विक उत्पादन और व्यापार की संरचना को ही चुनौती देने की कोशिश कर रहा है. दिलचस्प यह है कि इस सूची में कनाडा नहीं है, जबकि वह अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में एक है. इसका एक कारण यह हो सकता है कि उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी हद तक एक-दूसरे से जुड़ी है और अमेरिका तथा कनाडा के बीच आपूर्ति शृंखलाएं अत्यंत घनिष्ठ हैं. यह भी संभव है कि अमेरिका उन देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनके साथ उसका व्यापार घाटा अपेक्षाकृत अधिक है. इन जांचों का परिणाम 2026 की गर्मियों तक सामने आ सकता है और उसके बाद नये टैरिफ लगाये जा सकते हैं. अप्रैल तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की जायेंगी और मई के आसपास सुनवाई आयोजित की जायेगी. यदि जांच में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबंधित देशों ने अनुचित व्यापारिक नीतियां अपनाई हैं, तो जुलाई से पहले ही नये टैरिफ लागू किये जा सकते हैं. इस समयसीमा का एक कारण यह भी है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा पहले लगाये गये अस्थायी टैरिफ जल्द ही समाप्त होने वाले हैं.

भारत के लिए यह स्थिति असहज करने वाली है, क्योंकि इधर नयी दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में वार्ता चल रही थी. दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी रहे हैं, जिनमें बाजार पहुंच, कृषि उत्पादों पर शुल्क और औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार से जुड़े सवाल शामिल हैं. यदि अमेरिका इन जांचों के बाद नये टैरिफ लागू करता है, तो इससे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नयी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि पिछले दशकों में वैश्विक व्यापार व्यवस्था ऐसी दिशा में विकसित हुई है जिसमें कई देशों ने अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच तो प्राप्त कर ली, लेकिन अपने घरेलू बाजारों को पर्याप्त रूप से नहीं खोला. ट्रंप प्रशासन के अनुसार इस असंतुलन के कारण अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ता गया और कई अमेरिकी उद्योगों को नुकसान हुआ. इसलिए प्रशासन का मानना है कि टैरिफ या टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल कर ही अन्य देशों को अधिक संतुलित व्यापार व्यवस्था की ओर प्रेरित किया जा सकता है.

हालांकि इस रणनीति के परिणामों को लेकर मतभेद हैं. कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, टैरिफ अल्पकालिक रूप से घरेलू उद्योगों को कुछ राहत दे सकते हैं, पर लंबे समय में वे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा सकते हैं. यदि अन्य देश जवाबी टैरिफ लगाते हैं, तो इससे व्यापार युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका असर विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. इन जांचों की घोषणा ऐसे समय में भी हुई है, जब अमेरिका और चीन के बीच उच्च-स्तरीय वार्ता होने की संभावना जतायी जा रही है. खबर है कि दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही पेरिस में मुलाकात कर सकते हैं, जो आगे चलकर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संभावित शिखर बैठक का मार्ग प्रशस्त कर सकती है. ऐसे में, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये व्यापारिक जांचें कूटनीतिक बातचीत पर दबाव बनाने का एक साधन बनती हैं या फिर वे दोनों देशों के संबंधों में और अधिक तनाव पैदा करती हैं. कुल मिलाकर, ट्रंप प्रशासन की नयी पहल इस बात का संकेत देती है कि अमेरिका वैश्विक व्यापार नीति में अपने हितों की रक्षा के लिए टैरिफ को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा. अदालत के फैसले के बाद भी वाशिंगटन ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है, बल्कि उसने एक नया कानूनी रास्ता अपनाकर दबाव की रणनीति जारी रखी है. आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि इन जांचों का परिणाम क्या निकलता है और क्या वे वास्तव में वैश्विक व्यापार व्यवस्था को किसी नयी दिशा में ले जाते हैं या फिर वे केवल एक और व्यापारिक टकराव का कारण बनते हैं. फिलहाल इतना तय है कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं आने वाले समय में अमेरिकी व्यापार नीति के इस नये चरण पर करीबी नजर बनाये रखेंगी. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

भारत को अपनी डिजिटल संपदा की रक्षा करनी होगी

अशोक गौतम
मैनेजिंग पार्टनर, एएसटी कंसल्टिंग
ashokpundit@gmail.com

इतिहास गवाह है कि जो देश केवल कच्चे माल का निर्यात करते हैं, वे कभी मूल्य शृंखला के शीर्ष पर नहीं पहुंचते. लिहाजा, यदि विदेशी कंपनियां हमारे डेटा से स्वयं को शक्तिशाली बनाकर वही तकनीक हमें बेचती हैं, तो इससे एक गंभीर आर्थिक विषमता पैदा होगी. यह एक प्रकार का 'डिजिटल उपनिवेशवाद' है. इससे पहले कि हमारे हाथों से फिसल जाए, हमें अपनी डिजिटल संपदा की रक्षा करनी होगी.

पिछले कई महीनों से भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर एक शांत, पर खतरनाक पैटर्न उभर रहा है. हमारे प्रमुख पोर्टलों पर अचानक चीनी आइपी एड्रेस से ट्रैफिक में भारी उछाल देखा गया है. यह व्यवहार किसी सामान्य यूजर का नहीं, बल्कि 'ऑटोमेटेड डाटा स्क्रैपिंग' का है. जब इन रास्तों को ब्लॉक किया जाता है, तो यही ट्रैफिक सिंगापुर और अन्य वैश्विक क्लाउड नोड्स के माध्यम से फिर से लौट आता है. यह कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अत्यंत संगठित और औद्योगिक स्तर की डाटा माइनिंग है. यह संकेत है कि भारत का डिजिटल इकोसिस्टम बिना किसी स्पष्ट लाभ के, वैश्विक एआइ की दौड़ को ईंधन दे रहा है. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर टिका है : कंप्यूटिंग शक्ति, प्रतिभा और डाटा. कंप्यूट खरीदा जा सकता है और प्रतिभाओं को काम पर रखा जा सकता है, लेकिन डाटा वह बुनियादी तत्व है, जिसे लगातार 'हार्वेस्ट' करना पड़ता है.

'स्टैनफोर्ड एआइ इंडेक्स रिपोर्ट, 2024' स्पष्ट करती है कि जहां अमेरिका मॉडल बनाने में आगे है, वहीं चीन एआइ पेटेंट में, पर असली युद्ध डाटा के नियंत्रण का है. एआइ मॉडल्स अब स्थिर नहीं हैं, उन्हें हर पल अपडेट किया जाना आवश्यक है. वे नये व्यवहार और भाषाई लहजे को सीख रहे हैं. जो देश इन डाटा पाइपलाइनों को सुरक्षित कर लेते हैं, वे एआइ की रेस में आगे निकल रहे हैं, जबकि विदेशी प्रणालियों पर निर्भर देश रणनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं. भारत इस मामले में दुनिया की सबसे बड़ी 'डाटा रिफाइनरी' है. हमारे पास यूपीआइ के करोड़ों ट्रांजैक्शन, आधार से जुड़ी सेवाएं और ग्रामीण भारत का डिजिटल डाटा है. जितनी डाटा विविधता भारत के पास है, उतनी शायद ही किसी अन्य राष्ट्र के पास हो. हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं एआइ के लिए अतुलनीय खजाना हैं. इसके बावजूद, भारत के पास अभी तक अपना कोई विशाल 'सॉवरेन फ्रंटियर मॉडल' नहीं है. परिणामस्वरूप, हमारी अधिकांश कंपनियां और सरकारी विभाग विदेशी एआइ मॉडलों के भरोसे हैं. यहीं पर अर्थशास्त्र और भू-राजनीति का खतरनाक मेल दिखता है. एआइ की लागत आज सबसे बड़ा कारक है. जहां अमेरिकी कंपनियों के फ्लैगशिप मॉडल महंगे हैं, वहीं चीन की एआइ फर्में, अपने मॉडलों को बहुत ही कम कीमतों पर उतार रही हैं. सार्वजनिक रिपोर्ट बताती हैं कि चीनी एआइ मॉडलों का उपयोग अमेरिकी मॉडलों की तुलना में कई गुना सस्ता है. उभरते बाजारों में कंपनियां केवल तकनीकी श्रेष्ठता नहीं, किफायत देखती हैं. समय के साथ, यह 'सस्ती विदेशी बुद्धि' हमारे पूरे सिस्टम का आधार बन जायेगी.

इस गणना में हम एक रणनीतिक चूक कर रहे हैं. एआइ अब केवल एक सॉफ्टवेयर टूल नहीं, भविष्य का 'कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर' (संज्ञानात्मक बुनियादी ढांचा) है. यह तकनीक क्रेडिट स्कोरिंग, बीमा पॉलिसी, कृषि परामर्श और चिकित्सा निदान तक को नियंत्रित करेगी. यदि इस बुनियादी ढांचे की 'बुद्धि' विदेशी स्वामित्व वाली है, तो हमारे समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले एल्गोरिदम भी विदेशी हितों से प्रभावित होंगे. यह एक प्रकार का 'डिजिटल उपनिवेशवाद' है, जहां भारत अपना कच्चा माल (डाटा) मुफ्त दे रहा है और बदले में तैयार माल (एआइ मॉडल) किराये पर ले रहा है. इतिहास गवाह है कि जो देश केवल कच्चे माल का निर्यात करते हैं, वे कभी मूल्य शृंखला के शीर्ष पर नहीं पहुंचते. यदि विदेशी कंपनियां हमारे डाटा से स्वयं को शक्तिशाली बनाकर वही तकनीक हमें बेचती हैं, तो यह एक गंभीर आर्थिक विषमता पैदा करेगा. भारत की घरेलू क्षमताएं इस निर्भरता के बोझ तले दम तोड़ देंगी. भारत सरकार ने 'इंडिया एआइ मिशन' के माध्यम से इस खतरे को पहचाना है. कंप्यूटिंग शक्ति के लिए फंड का आवंटन सही दिशा में कदम है, परंतु तकनीकी प्रगति की गति घातीय (एक्सपोनेंशियल) है. एआइ इकोसिस्टम बहुत जल्दी 'लॉक-इन' हो जाते हैं. एक बार जब कोई डेवलपर किसी विदेशी एपीआइ के इर्द-गिर्द अपना पूरा वर्कफ्लो तैयार कर लेता है, तो उसे बदलना लगभग असंभव होता है. नेटवर्क प्रभाव स्थापित होने के बाद नये खिलाड़ियों के लिए रास्ता बनाना कठिन होता है.

आज भारत के सामने दो स्पष्ट विकल्प हैं. पहला, अल्पकालिक लागत पर ध्यान दें, विदेशी एआइ का उपभोग जारी रखें और अपनी बुद्धि को आउटसोर्स कर दें. दूसरा, एआइ को एक 'संप्रभु क्षमता' के रूप में देखें. इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर के कंप्यूट क्लस्टर्स बनाने होंगे और डाटा स्क्रैपिंग के लिए कड़े कानून लाने होंगे. हमें स्थानीय संदर्भों में प्रशिक्षित फाउंडेशन मॉडलों के विकास के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सहयोग स्थापित करना होगा. हालिया डाटा माइनिंग की घटनाएं चेतावनी है, वैश्विक ताकतें हमारे डाटा की कीमत हमसे बेहतर समझ रही हैं. आने वाली सदी उन राष्ट्रों की होगी जो डाटा से 'बुद्धि' का निर्माण करते हैं. भारत को अब यह तय करना है कि वह भविष्य के एआइ युग में निर्माता बनेगा या केवल एक ग्राहक. लंबे समय में, जो राष्ट्र अपनी 'बुद्धि' किराये पर लेते हैं, वे अंततः अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी खो देते हैं. इससे पहले कि हमारे हाथों से फिसल जाए, हमें अपनी डिजिटल संपदा की रक्षा करनी होगी. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

मध्य-पूर्व में उपजे संकट की सर्वाधिक कीमत सबसे गरीब व कमजोर लोग चुका रहे हैं

अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर किये गये हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. उपभोक्ता पहले से ही इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति संकट का दर्द महसूस कर रहे हैं, तिस पर ईरान के नये सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने बीते सप्ताह अपने एक बयान में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहेगा. यह गलियारा वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अब तक के सबसे बड़ा तेल भंडार जारी करने से तेल की कीमतों में जो राहत मिली थी, वह अल्पकालिक साबित हुई, जैसे ही अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमले तेज किये, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिये. परंतु इसका प्रभाव समान रूप से महसूस नहीं हो रहा है. एशिया में, जो कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए मध्य-पूर्व पर अत्यधिक निर्भर है, इसका प्रभाव अधिक महसूस हो रहा है. बांग्लादेश ने ईंधन की कमी के कारण अपने सभी विश्वविद्यालय और पाकिस्तान ने अपने कुछ स्कूल बंद कर दिये हैं. देखा जाये, तो इस युद्ध की कीमत दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोग कहीं अधिक चुका रहे हैं. इस युद्ध ने एक नया मानवीय संकट भी उत्पन्न किया है- ईरान और लेबनान में लाखों लोग विस्थापित हो गये हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, और हजारों आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गये हैं. उधर कई देशों को प्रवासी कामगारों से मिलने वाली धनराशि में कमी का सामना करना पड़ रहा है. मध्य-पूर्व संकट से उपजे आर्थिक संकट का अर्थ लाखों लोगों के लिए सिर्फ तंगहाल परिस्थितियां ही नहीं, जीवन-मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है. भले ही संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन होर्मुज जलडमरूमध्य से मानवीय सहायता काफिलों की सुरक्षित आवाजाही और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के बीच आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता देने के लिए दबाव डाल रहे हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरत इस युद्ध को समाप्त करने की है.

बोधि वृक्ष

परचाताप की भावना

पश्चाताप सुखद अहसास नहीं है, पर इस भावना का भी अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है. यदि आपके भीतर यह भावना विकसित होती है, तो निश्चित तौर पर यह आपको अपना और दूसरों का नुकसान करने से रोकेगी. जब कभी समान स्थितियां उपस्थित होंगी, तब पश्चाताप या गिल्ट की भावना ही आपको दोबारा वैसा करने से रोकेगी. पश्चाताप होना सकारात्मक है, पर यह केवल उसी क्षण तक होना चाहिए, जब इसे दिमाग और जेहन में रखकर आगे बढ़ा जाता है, तो यह एक दीमक की भांति आपको अंदर तक खोखला बना सकता है. आपको पश्चाताप की भावना से बाहर निकलने में निपुण होने के साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने भीतर से उसे पूरी तरह हटा न दें. ऐसा तभी होगा जब आप समझेंगे कि आपके द्वारा किये गये कार्यों के लिए केवल आप ही जिम्मेदार नहीं हैं. कुछ हद तक अपने भीतर पश्चाताप की भावना रखनी है, क्योंकि यह आपके संबंधों को बनाये रखती है. यह भावना आपको पूर्व में किये गये गलत कार्यों में दोबारा शामिल होने से रोकती है.

गलती ऐसी चीज है जो आपको हर समय चुभती है. यह भावना आपकी चेतना तक पहुंचकर उस गलती को दोबारा होने से रोकती है. आपको अपने भीतर वह चुभन रखनी चाहिए, ताकि पश्चाताप की भावना परेशान न करे. जब आप ऐसा कर पाने में सफल हो जायेंगे, तब बौद्धिक क्षमता की परिपक्वता जाहिर होगी, अन्यथा आप कभी अपने कृत्यों की गंभीरता को समझ नहीं पायेंगे. जिस व्यक्ति ने वह गलती की थी, उसने अपना बैग पैक कर लिया है और वह यहां से जा चुका है. अब आपके भीतर एक नया मनुष्य है, जिसे अपनी भूल का अहसास है. वर्तमान क्षण की सुंदरता का आदर करें. श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था, 'मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ. इसके बाद यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे उन पापों के लिए क्या करता हूं. चिंता मत करो, जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है उसे बाहर निकाल दो- तुम्हारा धर्म भी. जो चीजें तुम्हें बांधकर रखती हैं उससे मुक्त हो जाओ, उन्हें छोड़कर मेरे पास आ जाओ.'

-श्री श्री रवि शंकर

प्रबंध सूत्र

गेम में बने रहना भी सफलता है

संजू सैमसन भारतीय टीम के टी-20 फॉर्मेट के अनिवार्य खिलाड़ी बन जायेंगे, यह बात दो महीने पहले तक कोई मानने को तैयार न था. पर अब सब मानते हैं. संजू सैमसन की कामयाबी के कुछ ऐसे सबक हैं, जो हम सबको सीखने चाहिए. गेम में आप तभी कामयाब होंगे, जब आप गेम में होंगे.

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

भारतीय क्रिकेट में अभी प्रतिभा का विस्फोट काल है. बेहतरीन खिलाड़ियों को भी ग्यारह की टीम में जगह मिले, यह जरूरी नहीं है. जिन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली, वे आइपीएल खेलें, राज्यों की टीमों में खेलें, रणजी ट्रॉफी खेलें. मूल बात है गेम में बने रहना. गेम से ही बाहर हो गये, तो कामयाबी की कोई संभावना नहीं है. इसलिए बड़े खिलाड़ी भी रणजी ट्रॉफी खेलते दिख जाते हैं. संजू सैमसन भी ऐसे ही कहीं न कहीं खेलते रहे. वरना यह अहंकार आना बहुत आसान होता है कि एक बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाला राज्य स्तर के टूर्नामेंट में क्यों शरीक हो?

ऐसे लोग हैं, जो कुछ समय कहानी लिखते हैं, पर छोड़ देते हैं, फिर कविता पर जोर आजमाइश करते हैं, छोड़ देते हैं. फिर उपन्यास पर जाते हैं, छोड़ देते हैं. फिर उन्हें एक दिन पता लगता है कि कई दशक निकल गये, न तो कहानीकार बने, न कवि. भारतीय क्रिकेट के हालिया दौर में संजू सैमसन की कहानी हमें गहरा सबक देती है. कभी चयन हुआ, कभी बाहर कर दिये गये, पर उन्होंने हार नहीं मानी. वह रणजी ट्रॉफी, आइपीएल और घरेलू टूर्नामेंटों में लगातार खेलते रहे. यही निरंतरता उन्हें आज टी-20 टीम का अहम हिस्सा बना चुकी है. सफलता का पहला नियम है-गेम में बने रहना. जो भी कर रहे हैं, उसमें निरंतरता चाहिए. कई बार खिलाड़ी या लेखक सोच लेते हैं कि मैं राष्ट्रीय स्तर का हूं, हर मंच पर क्यों जाऊं. यही सोच उन्हें धीरे-धीरे खेल से बाहर कर देती है. संजू सैमसन ने इस अहंकार को अपने पास फटकने नहीं दिया. परिणाम आज सबके सामने है.

लेखन और कला में भी यही सूत्र लागू होता है. कहानी लिखना शुरू किया, फिर बीच में छोड़ दिया. फिर कविता की ओर गये और छोड़ दिया. फिर उपन्यास की ओर गये और छोड़ दिया. ऐसे में, अंत में कुछ भी नहीं बन पायेंगे. नौकरी में उतार-चढ़ाव आयेंगे, लेकिन टिके रहना जरूरी है. व्यवसाय में घाटा हो सकता है, पर निरंतरता ही उसे लाभ तक ले जाती है. जीवन का हर क्षेत्र एक 'गेम' है. इसमें बने रहना ही जीत की संभावना को जीवित रखता है. बाहर हो गये, तो अवसर खत्म. संजू सैमसन की कहानी यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आयें, गेम में बने रहना ही सफलता का पहला और अंतिम सूत्र है.

आपके पत्र

सही समय पर उठाया गया कदम

खाड़ी युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित गैस किल्लत को रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है, जो दूरदर्शी कदम है. माना जा रहा है कि सरकार ने पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए यह निर्णय लिया है. यह कदम सुनिश्चित करता है कि संकट के समय व्यापारी मनमाने दाम न वसूलें, जिससे आम आदमी की थाली और परिवहन बजट पर बोझ न बढ़े. सरकार का यह निर्णय देश की ऊर्जा सुरक्षा बनाये रखने के लिए समय पर उठाया गया कदम है.

युगल किशोर राही, छपरा

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं

देश के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा अंतर है. जहां शहरों में आधुनिक सुविधाओं से संपन्न कई बड़े व मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र ऐसी सुविधाओं व अस्पतालों से वंचित हैं. वहां आम तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व छोटे अस्पताल ही होते हैं, जिनमें कई बार जरूरी दवाइयां और टीके भी उपलब्ध नहीं होते. सरकार से आग्रह है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को परेशानी न हो.

हेमलता रानी, गढ़वा

मार्केट कैप एसबीआइ ₹89,306.22 करोड़ | एचडीएफसी बैंक ₹61,715.32 करोड़ | बजाज फाइनेंस ₹59,082.49 करोड़ | टीसीएस ₹53,312.52 करोड़

prabhatkhabar.com

क्विक बाइट्स

ईस्ट कोस्ट रेलवे एक साल में 500 मिलियन टन माल ढुलाई वाला पहला जोन

भुवनेश्वर. ईस्ट कोस्ट रेलवे ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. यह भारतीय रेलवे के इतिहास में एक ही वर्ष में 500 मिलियन टन माल संभालने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है. इस वर्ष के दौरान, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 262.9 मिलियन टन लोडिंग की, जिसमें 10.4% की वृद्धि दर्ज की गयी. वहीं, अनलोडिंग 237.6 मिलियन टन तक पहुंच गयी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दिखाती है. इस रिकॉर्ड लोडिंग में कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे थोक सामानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

रत्न एवं आभूषण निर्यात 3.86% बढ़कर 268.07 करोड़ डॉलर पर पहुंचा

मुंबई. भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात फरवरी में सालाना आधार पर 3.86 प्रतिशत बढ़कर 268.07 करोड़ डॉलर (24,340.05 करोड़ रुपये) हो गया. उद्योग संगठन रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेइपीसी) के अनुसार अन्य बाजारों में विस्तार के कारण निर्यात में यह बढ़ोतरी दर्ज की गयी. आंकड़ों के अनुसार, एक वर्ष पहले इसी महीने में कुल निर्यात 258.10 करोड़ डॉलर (22,460.13 करोड़ रुपये) रहा था. अप्रैल, 2025 से फरवरी, 2026 के दौरान कुल रत्न एवं आभूषण निर्यात लगभग स्थिर रहा और यह 2,593.37 करोड़ डॉलर रहा. जबकि इससे एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 2,591.58 करोड़ डॉलर था.

संसदीय समिति की रिपोर्ट. मुकदमे कम होंगे, तो करदाताओं को मिलेगी राहत

आयकर संबंधी मुकदमों में कमी लाने के लिए बदलाव की सिफारिश

एजेंसियां, नयी दिल्ली

भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा नीति में कुछ बड़े बदलाव की सिफारिश की है, जिन्हें अगर मान लिया गया, तो देश के लाखों करदाताओं को राहत की सांस मिल सकती है. समिति ने आंकड़े सामने रखते हुए बताया कि साल 2024-25 में हाईकोर्ट में आयकर विभाग को सिर्फ 12% मामले में ही जीत मिली है. वहीं ट्रिब्यूनल में विभाग की जीत का प्रतिशत सिर्फ 14.5% रहा. इसका मतलब है कि विभाग जो भी मामला अदालत में ले जा रहा है, उनमें से लगभग 85% से 88% मामलों में वह हार रहा है. समिति ने कहा है कि विभाग को हर मामले में बिना किसी ठोस वजह के अपील नहीं करनी चाहिए. इसके बजाय एक विशेषज्ञों की टीम बनायी जाए. ये टीम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मामले की अच्छे से जांच करे कि क्या केस जीतने लायक है भी या नहीं.

हर मामले में नहीं करनी चाहिए अपील

समिति का कहना है कि विभाग को मशीन की तरह हर मामले में अपील नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले ये देखना चाहिए कि केस कितना मजबूत है. आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 तक आईटीएटी के पास 3.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विवादित राशि वाले 23,230 मामले पेंडिंग हैं. इसी तरह उच्च न्यायालय में 5.65 लाख करोड़ रुपये के 41,321 मामले और उच्चतम न्यायालय में 25,403 करोड़ रुपये की मांग वाले 6,880 मामले ऐसे हैं, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है.

मुकदमेबाजी के प्रति बदलना होगा रवैया

समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि आयकर विभाग को मुकदमेबाजी के प्रति अपना रवैया बदलना होगा. फिजूल के केस लड़ने से न केवल सरकारी पैसा और समय बर्बाद होता है, बल्कि करदाताओं को भी बिना वजह परेशानी झेलनी पड़ती है. समिति ने कहा कि अधिकारी अक्सर सिर्फ इसलिए अदालतों में अपील कर देते हैं जिससे बाद में उन पर यह आरोप न लगे कि उन्होंने टैक्स वसूलने में ढिलाई की है. वे अपनी जिम्मेदारी या विजिलेंस जांच के डर से बचने के लिए बस केस फाइल कर देते हैं, चाहे उस केस में दम हो या ना हो.

एयर इंडिया ने ट्रैवल पॉलिसी के दुरुपयोग पर 4,000 से अधिक कर्मियों पर की कार्रवाई

एजेंसियां, नयी दिल्ली/मुंबई

एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित अवकाश यात्रा नीति (इएलटी) के उपयोग में बड़े पैमाने पर विसंगतियां पायी हैं. सूत्रों के अनुसार, इस मामले में 4,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं और एयरलाइन ने दोषी कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने सहित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस समय एयरलाइन एक महत्वाकांक्षी परिवर्तन योजना को लागू कर रही है. एयर इंडिया में कुल 24,000 से अधिक कर्मचारी हैं. मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया की इएलटी नीति के उपयोग में बड़ी गड़बड़ियों का पता एक विस्तृत आंतरिक जांच के बाद चला. इएलटी नीति के तहत कर्मचारियों और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों (जैसे जीवनसाथी और माता-पिता) को एक निश्चित संख्या में मुफ्त हवाई टिकट दिये जाते हैं. यह सुविधा कुछ शर्तों के अधीन होती है. सूत्रों ने बताया कि कई कर्मचारियों ने उन लोगों को अपना रिश्तेदार बताकर इस नीति का दुरुपयोग किया, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था. कुछ मामलों में तो कर्मचारियों ने मुफ्त टिकट लेकर उन्हें ऊंचे दामों पर बाहरी लोगों को बेच दिया.

एक अप्रैल से महंगा हो जायेगा फास्टैग वार्षिक पास

नयी दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने फास्टैग वार्षिक पास के लिए लागू शुल्क में संशोधन करने का निर्णय लिया है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह शुल्क 3000 रुपये से बढ़ कर 3075 रुपये कर दिया जायेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यह नया शुल्क ढांचा 01 अप्रैल,2026 से प्रभावी होगा. अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक यह पास 3000 रुपये में ही खरीदा जा सकता है. जो लोग इसके बाद यानी 01 अप्रैल से फास्टैग वार्षिक पास खरीदेंगे, उन्हें 75 रुपये अधिक देना होगा.

पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए रिफाइनरी कीमतों पर रोक की तैयारी

एजेंसियां, नयी दिल्ली

सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां (ओएमसी) ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करने की वजह से उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के लिए रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयातित दरों से कम कीमत देने पर विचार कर रही हैं. इस कदम से एमआरपीएल, सीपीसीएल और एचएमएल जैसी एकल रिफाइनरी कंपनियों पर बुरा असर पड़ सकता है. पश्चिम एशिया संकट से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थीं, जो अब बढ़कर 100 डॉलर के पार पहुंच गयी हैं. हालांकि, भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे पेट्रोलियम कंपनियों को इस बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है. मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ओएमसी अब रिफाइनरी हस्तांतरण शुल्क (आरटीपी) पर रोक लगाने या उस पर छूट तय करने के विकल्प पर विचार कर रही हैं. इस कदम का मकसद रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयात-समता लागत से कम भुगतान करना है. सूत्रों ने यह भी कहा कि यदि आरटीपी पर रोक या छूट निजी रिफाइनरियों पर भी लागू की जाती है, तो नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे रिफाइनरी कंपनियां भी प्रभावित होंगी.

रिफाइनरियां नहीं बढ़ा पायेंगी कीमत

पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक बना रहता है और इसके साथ-साथ यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो इस प्रस्तावित कदम से रिफाइनरियां कच्चे तेल की बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ आरटीपी के जरिये आगे नहीं बढ़ा पायेंगी और उन्हें इस प्रभाव का एक हिस्सा खुद वहन करना होगा. सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी एकीकृत कंपनियां अपने रिफाइनिंग और मार्केटिंग के बीच इस घाटे की भरपाई कर सकती हैं.

कुछ औद्योगिक ग्राहकों के लिए गैस की कीमत घटायी गयी

अदाणी-टोटल गैस

एजेंसियां, नयी दिल्ली

अदाणी टोटल गैस ने कुछ औद्योगिक ग्राहकों को आपूर्ति की जाने वाली अतिरिक्त प्राकृतिक गैस के दाम 119.90 रुपये प्रति मानक घन मीटर से घटाकर 82.95 रुपये प्रति मानक घन मीटर कर दिये हैं. यह बदलाव 16 मार्च की सुबह छह बजे से लागू होगा. संयुक्त उद्यम ने कहा कि यह मूल्य संशोधन उपभोक्ताओं तक कम कीमत का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है. साथ ही यह मौजूदा आपूर्ति प्रतिबंधों के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाये रखने और गैस का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी है. कंपनी ने वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों से कहा था कि वे गैस खपत का केवल 40 प्रतिशत ही उपयोग करें.

बड़े आइपीओ को आसान बनाने के लिए पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों में ढील

एजेंसियां, नयी दिल्ली

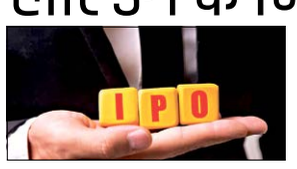

वित्त मंत्रालय ने शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत एक श्रेणीबद्ध ढांचा पेश किया गया है जो बड़ी कंपनियों को उनके आइपीओ ऑफर के समय जनता के लिए शेयरों का एक छोटा हिस्सा पेश करने की सुविधा देता है. संशोधन के अनुसार जिन कंपनियों की निर्गम के बाद की पूंजी 1,600 करोड़ रुपये से अधिक और 5,000 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें तीन साल के भीतर अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर कम से कम 25 प्रतिशत करनी होगी. नियमों में आगे कहा गया है कि निर्गम के बाद की सीमा चाहे कुछ भी हो, सूचीबद्ध होने के समय प्रतिभूतियों के प्रत्येक वर्ग का कम से कम 2.5 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक रूप से पेश किया जाना चाहिए. अगर पूंजी 1,600 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 4,000 करोड़ रुपये से कम है, तो कंपनी को 4,000 करोड़ रुपये के बराबर शेयर पेश करने होंगे.

बिहार

छत का छज्जा भरभराकर गिरा, मलबे में दबने से दो की मौत

ओबरा (औरंगाबाद). स्थानीय थाना क्षेत्र की तेजपुरा पंचायत के मंझियांवा गांव में शनिवार की रात एक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. द्वार पूजा के दौरान एक घर का छज्जा अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि करीब 35 से 40 लोग घायल हो गये. बारात आने के बाद द्वार पूजा की तैयारी के दौरान व्यास यादव के घर के सामने स्थित आमोद सिंह के घर की छत पर काफी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण जमा हो गये. छत के नीचे भी कई लोग इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक छज्जा भरभराकर गिर पड़ा.

20 अप्रैल को बसपा से अलग हुए नेताओं का पटना में जुटान

पटना. बिहार में बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए नेताओं के एक गुट ने पार्टी के बिहार प्रदेश के पूर्व प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में नये सामाजिक-राजनीतिक मंच 'बहुजन शोषित संघर्ष समिति (बीएस-चार)' और 'बहुजन सेना' के गठन की घोषणा की. इस पहल का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने किया. उन्होंने बताया कि यह संगठन बहुजन, दलित, पिछड़े और वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा. साथ ही 20 अप्रैल को पटना में एक बड़े महाजुटान का आयोजन करने की घोषणा भी की गयी है.

आज लोजपा का इफ्तार चिराग भी होंगे शामिल

पटना. लोजपा (रा) की ओर से सोमवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम मे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मौजूद रहेंगे. प्रदेश मीडिया प्रभारी कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री समेत एनडीए घटक दल के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है.

ट्रक और कार की भिड़ंत में दो युवकों की मौत

आरा. बिहिया-बिहटा स्टेट हाइवे पर जिले के पीरो थाना क्षेत्र के तिवारीडीह मोड़ के समीप शनिवार की रात ट्रक एवं कार की सीधी भिड़ंत हो गयी. हादसे में दो युवकों की मौत हो गयी. एक ने घटनास्थल एवं दूसरे ने सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया. वहीं, कार पर सवार छह लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये.

...पहले पेज से

टाटीसिलवे हादसा : जानलेवा कार का...

घटना के 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी दोषी कार चालक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार को मालिक के ही परिवार का एक सदस्य चला रहा था. पुलिस ने उनको थाना बुलाया है. मामले में मृतका रीमा कुमारी की बहन प्रियंका कुमारी की शिकायत पर टाटीसिलवे थाना में आरोपी कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

मृतकों का हुआ अंतिम संस्कार, घायलों का चल रहा इलाज : दोनों मृतकों भोला शर्मा और रीमा कुमारी के शव पोस्टमार्टम के बाद रविवार की दोपहर डेढ़ बजे उनके घर पहुंचाये गये. शव के पहुंचते कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. दोना का अंतिम संस्कार टाटीसिलवे मुरली पुल स्थित स्वर्णरेखा नदी के मुक्तिधाम में परिजनों ने किया.

होर्मुज से होकर 46,000 मीट्रिक टन...

फोन की घंटी लगातार बज रही थी. हर कोई अंश की कुशलता जानना चाहता है. **पलकें बिछाए बैठी है पत्नी, बेटा तनय कर रहा पापा का इंतजार :** अंश की पत्नी चंदा मिश्रा त्रिपाठी (टाटा स्टील में चार्टर्ड अकाउंटेंट) पति के घर आने का पलकें बिछाकर इंतजार कर रही हैं. दो वर्ष के बेटे तनय को भी पापा के घर आने का इंतजार है. पत्नी कहती हैं कि संपर्क पूरी तरह कटा हुआ था. अब सुकून है कि वे देश के लिए अपना कर्तव्य निभाकर सुरक्षित लौट रहे हैं.

रास चुनाव. सुबह नौ बजे से वोटिंग, छह बजे तक आयेगा रिजल्ट

चार सीटों पर एनडीए की जीत तय पांचवीं पर सस्पेंस अब भी बरकरार

संवाददाता, पटना

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा. इसे लेकर रविवार को दिनभर सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के नेताओं की लगातार बैठकें होती रहीं. दोनों पक्ष पांचवीं सीट पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि चार सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है. ऐसे में सबसे ज्यादा नजर पांचवीं सीट पर टिकी हुई है. मतदान से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा उम्मीदवार नितिन नवीन देर रात चार्टर विमान से पटना पहुंचे. वहीं, जदयू विधायक अनंत सिंह भी अनुमति मिलने के बाद जेल से मतदान करने विधानसभा पहुंचेंगे. रविवार सुबह से ही दोनों खेमों ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया था. सोमवार को सुबह नौ बजे से मतदान शुरू होगा, जो अपराह्न चार बजे तक चलेगा. इसके बाद शाम पांच बजे से मतों की गिनती शुरू होगी और शाम छह बजे तक परिणाम आने की संभावना है.

एनडीए से नीतीश, नितिन, शिवेश, रामनाथ व उपेंद्र और राजद से अमरेंद्र प्रत्याशी

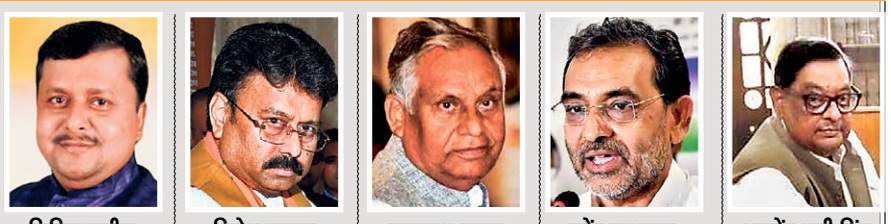

नितिन नवीन	शिवेश कुमार	रामनाथ ठाकुर	उपेंद्र कुशवाहा	अमरेंद्र धारी सिंह
भाजपा	भाजपा	जदयू	रालोमो	राजद

एनडीए की तैयारी : करायी गयी मॉक पोलिंग

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री मदन सहनी और मंत्री लेशी सिंह के आवास पर जदयू विधानमंडल दल की बैठक हुई. इन बैठकों की अध्यक्षता जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने की. इसके बाद संजय कुमार झा के आवास पर भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक हर्ष मल्होत्रा और विजय शर्मा समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक हुई. देर शाम मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर एनडीए विधायकों की रणनीतिक बैठक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे. बैठक में सभी विधायकों से एकजुट होकर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की रणनीति तय की गयी.

महागठबंधन की तैयारी : विधायक होटल में बंद

राजद विधायकों की बैठक रविवार सुबह तेजस्वी यादव के आवास पर हुई. इसके बाद राजद और कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें पटना के आर ब्लॉक स्थित होटल पनाश में ठहराया गया.

एआइएमआइएम देगा महागठबंधन को वोट : एआइएमआइएम की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी पहुंचे, जहां विधायक अख्तरूल इमान ने उनका स्वागत किया. दोनों ने कहा कि एआइएमआइएम के पांचों विधायक महागठबंधन उम्मीदवार को वोट देंगे. हालांकि, बसपा के एकमात्र विधायक ने पत्ते नहीं खोले हैं. कांग्रेस ने कहा कि उसके सभी विधायक महागठबंधन उम्मीदवार को ही मतदान करेंगे.

राजस्व अधिकारी अड़े, कहा मांगें पूरी होने तक हड़ताल

संवाददाता, पटना

राज्य के राजस्व अधिकारियों ने अपनी मांगें सरकार द्वारा लिखित रूप से माने जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है. इससे राज्य के सभी 537 अंचलों में करीब 20 प्रकार के कामकाज बाधित हैं. इस संबंध में रविवार को पटना के अधिवेशन भवन में राजस्व अधिकारियों के संघ बिरसा और बिरसा यूनाइटेड की तरफ से बैठक हुई. इसमें हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया. इस बैठक में सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी सहित राजस्व सेवा के सभी अधिकारी शामिल हुये. दूसरी तरफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल पर रविवार को संयुक्त मोर्चा और विभाग के आला अधिकारियों के बीच बैठक हुई. इसमें सकारात्मक चर्चा हुई. सोमवार को फिर औपचारिक बैठक होगी. इन सबके बीच फिलहाल संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है.

क्या है मामला : राजस्व अधिकारियों के दोनों संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बिहार राजस्व सेवा नियमावली में इसके गठन के समय डीसीएलआर, डीएलएओ सहित अन्य पदों पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी. बाद में बिहार राजस्व सेवा नियमावली को बदल दिया गया. साथ ही डीसीएलआर और डीएलएओ के पदों पर बासा के अधिकारियों के लिए संरक्षित कर दिया गया. दोनों संघों की मांग पर पांच फरवरी 2026 को उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में मौखिक सहमति बनी, लेकिन उसे अब तक लिखित रूप नहीं दिया गया है.

24 घंटे में लौटने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने वाले अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायेगी. उनकी दोनों हड़ताल अवधि का समायोजन कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि मार्च का महीना राजस्व विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई जनहितकारी अभियान इस समय चल रहे हैं. इस अवधि में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा, राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त लगभग 46 लाख आवेदनों का निष्पादन तथा मुख्यमंत्री के निर्देश पर ई-मापी अभियान भी चल रहा है. दोनों काम सीधे जनता से जुड़े हैं और 31 मार्च तक पूरा करना लक्ष्य है. ऐसे में प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सरकार ने संवाद और समन्वय का रास्ता चुना है.

ट्रैक्टर ने सिविल कोर्ट परीक्षा के दो अभ्यर्थियों को कुचला, मौत

भोजपुर और मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे मृतक

मुख्य संवाददाता, गया जी

गया जी शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर के पास रविवार की सुबह एक अनियंत्रित और बेकाबू ट्रैक्टर ने कहर बरपा दिया. इस सड़क हादसे में सिविल कोर्ट की चतुर्थ वर्गीय परीक्षा देने आये दो अभ्यर्थियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. हादसे के वक्त ट्रैक्टर चालक नशे में था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने शनि मंदिर के बगल में स्थित गुमटी और ठेले को जोरदार टक्कर मारी और रेलवे की चहारदीवारी से टकराकर रुक गया. इस घटना में वहां मौजूद कई अन्य परीक्षार्थियों की जान बाल-बाल बच गयी. कुछ अन्य परीक्षार्थियों को हल्की चोटें आयी हैं. लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी. मृतकों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के रमेश कुमार साह (35 वर्ष) और आशुतोष कुमार सिंह (24 वर्ष) के रूप में हुई है.

राज्य की सभी 8053 पंचायतों में बनेंगे आधुनिक 'मुक्तिधाम'

पटना. राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह या मुक्तिधाम का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह निर्माण को लेकर निर्देश दिया है. जिलाधिकारियों को भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में शामिल कराया जाये. इस राशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग के मद से प्राप्त होनेवाली राशि से किया जायेगा.

नेपाल के गोरखा में खाई में पलटी इवी सात भारतीय नागरिकों की गयी जान

प्रतिनिधि, रक्सौल

नेपाल के गोरखा जिले के शहीद लखन गांव पालिका के समीप चाइनीज इवी गाड़ी पलट जाने के कारण सात भारतीय नागरिकों की मौत हो गयी. इस हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं. घायलों में सात भारतीय व दो नेपाली नागरिक शामिल हैं.

जिला पुलिस कार्यालय गोरखा के प्रवक्ता पुलिस निरीक्षक राजन लम्साल ने बताया कि शनिवार को देर रात सूचना मिली थी कि एक गाड़ी शहीद लखन गांव पालिका के वार्ड नंबर तीन करनाटार-अबुखैरनी सड़क पर अनियंत्रित होकर सड़क से 200 मीटर नीचे खाई में गिर गयी है. पुलिस व नेपाली सेना के रुद्रध्वजगण की रेस्क्यू टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. गाड़ी में सवार सभी 16 को रेस्क्यू कर तनहु अस्पताल लाया गया. वहां चिकित्सकों ने सात लोगों को मृत घोषित कर दिया. नौ को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है. मृतकों में तमिलनाडु के ही मुतु कुमार (57), अनामलिक (47), मिनाक्षी (59), शिवगामी (53), बिजनाल (57), मीना (57) व तमिलाशी (60) शामिल हैं.

Stay Ahead Of Competition
Join The Aspirants Community.

✅ Receive Earliest Newspapers updates from 5 AM with All Editions

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ **International Newspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ **Editorials [English & Hindi]**

[National + International Editorials]

युद्धों की कीमत युद्ध के समय नहीं चुकाई जाती, उसका भुगतान तो बाद में होता है।
-बेंजामिन फ्रैंकलिन

जिन चार राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने की है, उनमें किस पार्टी का जादू सिर चढ़कर बोलेगा, इसका पता तो चार मई को ही चलेगा। साथ ही चुनावी नतीजों से विभिन्न मुद्दों पर देश के 17.4 करोड़ मतदाताओं के रुख की भी जानकारी मिलेगी।

सियासी जंग का आगाज

चार राज्यों-असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल और एक केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की जो घोषणा की गई है, वह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मात्र तीन चरणों में इन सभी राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न करा लिया जाएगा। असम, केरल और पुदुचेरी में जहां 9 अप्रैल को मतदान होंगे, वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल एवं पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर एवं दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार दो चरणों में चुनाव संपन्न कराने की घोषणा के साथ चुनाव आयोग ने यह संदेश भी दिया है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी राज्यों में मतगणना चार मई को संपन्न होगी। भर्ती घोटालों व भ्रष्टाचार के मामलों और डेढ़ दशक की सत्ता विरोधी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता बचाने के लिए जूझ रहीं ममता बनर्जी, जिन्हें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुनने को मिली थी, ने चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा से ठीक पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए बकाया डीए भुगतान एवं पुरोहितों व मुअज्जिनों के वेतन में 500 रुपये बढ़ोतरी की दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। केरल में स्थानीय चुनावों में यूडीएफ की जीत ने कांग्रेस के लिए उम्मीदें बढ़ाई हैं, तो तिरुवनंतपुर नगर निगम में एनडीए के सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरने से मिले झटके के बाद राज्य में वाम मोर्चे के सामने देश भर में केरल की इकलौती सत्ता बचाने की परीक्षा है। तमिलनाडु में स्टालिन की द्रमुक मजबूत दावेदार है, पर तथ्य यह भी है कि 1971 के बाद से द्रमुक लगातार दूसरी बार कभी सत्ता में नहीं लौटी है। इसके अतिरिक्त, अभिनेता विजय की टीवीके ने समीकरण जटिल कर दिए हैं, जिसका दक्षिणी तमिलनाडु व युवाओं में खासा असर दिख रहा है। असम में हेमंत विस्व

सरमा के नेतृत्व में भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर पर उठाए गए सवालों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 100 फीसदी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था कर चुनावों की निष्पक्षता व पारदर्शिता बनाए रखने की भरसक कोशिश की है, ताकि संदेह की गुंजाइश न रहे। अब यह तो चार मई को ही पता चलेगा कि मतदाताओं का समर्थन किस पार्टी या गठबंधन को मिलेगा, पर इन चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के साथ पूर्वी और दक्षिण भारत में राजनीति की दिशा व दशा तो तय करेंगे ही।

इस युद्ध का अंत कैसे होगा

ईरानी नेताओं के खुद को अभेद्य समझने का दौर अब खत्म हो चुका है। आपसी कलह या फिर जन-विद्रोह के चलते जल्द ही ईरानी शासन में बदलाव आ सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे यथार्थवादी रास्ता यही है कि ईरान को धमकाते हुए युद्ध को अंत की तरफ पहुंचाया जाए।

ईरान युद्ध के संदर्भ में यदि आधुनिक युद्ध इतिहास का सबसे मशहूर सवाल पूछा जाए कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा, तो मोटे तौर पर चार संभावित परिदृश्य हैं। सत्ता परिवर्तन सबसे आशावादी संभावना है। कुछ लोगों का मानना है कि फिर से वैसे ही बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का दौर शुरू होगा-जिन्हें जनवरी में ईरानी सत्ता ने बेरहमी से कुचल दिया था-लाखों ईरानी दर्जनों शहरों में मार्च करेंगे, जिनमें पुलिस अधिकारी, सैनिक और नियमित सेना के कमांडर भी शामिल होंगे; अमेरिकी और इस्राइली हवाई समर्थन से उत्साहित वे अपने शासकों के कमजोर पड़ चुके दमनकारी तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए उठ खड़े होंगे। किसी को भी इस स्थिति को कम करके नहीं आंकना चाहिए-खास तौर पर तब, जब ईरान को सैन्य और राजनीतिक, दोनों ही मोर्चों पर लगातार झटके लग रहे हों, और शायद उसे अपने नेतृत्व के और भी अहम पदों पर बैठे लोगों को खोना पड़े। पर किसी को भी इस बात पर पूरी तरह निर्भर भी नहीं रहना चाहिए-कम से कम, निकट भविष्य में तो बिल्कुल भी नहीं।

ब्रेट स्टीफेंस
द न्यूयॉर्क टाइम्स

भले ही ईरानी शासन अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में कितना भी अक्षम क्यों न हो, पर अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने में यह अब भी सक्षम है। सत्ता पर काबिज रहने के लिए इसके पास हर मुमकिन वजह मौजूद है। शासन में सुधार-यानी, एक ऐसा शासन, जो सत्ता में तो बना रहे, लेकिन अमेरिका और इस्राइल के निर्देशों का पालन करे-यह एक और आशावादी परिदृश्य है। इसकी संभावना कम ही है कि नए सर्वोच्च नेता, मोजतबा खामनेई, ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को छोड़ने और हिजबुल्ला जैसे क्षेत्रीय प्रॉक्सी को समर्थन देना बंद करने पर सहमत होंगे। पर नए खामनेई का शासन बहुत छोटा हो सकता है। और जो कोई भी इसके बाद शासन की बागडोर संभालेगा, उसे सत्ता की कमजोरी और अलगाव का सामना करना पड़ेगा। यह अलगाव तब और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा, जब अमेरिकी सेनाएं फारस की खाड़ी में ईरानी तट से 15 या

16 मील दूर स्थित खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेंगी-जो ईरान के लगभग 90 प्रतिशत तेल निर्यात के लिए टर्मिनल का काम करता है। इससे शासन के सबसे कट्टरपंथी तत्वों को भी यह समझने में मदद मिल सकती है कि क्या यूरेनियम संवर्धन, या लेबनान में हिजबुल्ला को और अधिक गोला-बारूद भेजना (जिसे इस्राइल नष्ट कर देगा) वास्तव में फायदेमंद है। लेकिन शायद ईरानी शासन झुकने से इन्कार कर दे और युद्ध अगले दो या तीन हफ्तों तक जारी रहे, जिसके बाद किसी तरह की युद्धविराम की घोषणा हो-संभवतः 31 मार्च को बीजिंग में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावित यात्रा से पहले। ऐसे में, सभी पक्ष अपनी-अपनी जीत की घोषणा करेंगे, पर उनमें से कोई भी इस पर पूरी तरह यकीन नहीं करेगा।

ट्रंप को ईरान का 'बेशर्त समर्पण' जैसी कोई चीज तो हासिल नहीं ही होगी, शासन के अगले नेता को चुनने में उनकी कोई भूमिका दूर की कौड़ी है। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुल्लाओं को सत्ता से हटाने के अपने दशकों पुराने सपने को साकार करने में नाकाम रहेंगे। और ईरान के नेता डींग हांकेंगे कि जिस 'प्रतिरोध' का वे कथित तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, वह 'महान शैतान' और 'छोटे शैतान'-दोनों के संयुक्त ताकत से भी अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। हालांकि हकीकत सामने आ ही जाएगी। वे प्रतिबंध, जिन्होंने पहले ही ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है, हटाए नहीं जाएंगे।

यह कल्पना करना कठिन है कि अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान के शेष परमाणु स्थलों पर हमला किए जाने से पहले यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। ईरान द्वारा बड़े आतंकवादी हमले करने, या होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने का कोई भी प्रयास एक और युद्ध का कारण बनेगा।

ईरानी नेताओं के खुद को अभेद्य समझने का दौर अब खत्म हो चुका है। यह बताता है कि ईरानी शासन केवल एक बेजान अवस्था में ही टिक पाएगा। नतीजतन, कुछ ही वर्षों में शासन में बदलाव आ सकता है-संभवतः नेतृत्व के भीतर आपसी कलह के कारण, या फिर किसी अन्य जन-विद्रोह के चलते। दोनों ही स्थितियों में, इस शासन के दिन अब गिने-चुने ही रह गए हैं। इसका एक बदसूरत पहलू भी है: शासन परिवर्तन नहीं, बल्कि राज्य का पतन। इसका जो सबसे चिंताजनक रूप सामने आ सकता है, वह सीरिया के 13 साल लंबे गृहयुद्ध जैसा होगा; जिसमें ईरान के कुछ इलाकों में तो मौजूदा शासन बचा रहेगा, लेकिन अन्य इलाकों में उसका पतन हो जाएगा, जिससे विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होगा। इसके साथ-साथ पूरे पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक शरणार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। हैरानी नहीं है कि ट्रंप ने इराक में मौजूद कुर्दिश सेनाओं को ईरान में जाने से रोका। लेकिन अगर ईरान की कमजोर होती सरकार अपनी सीमा में अशांत कुर्दों का नरसंहार शुरू कर देती है, तो ये सेनाएं चुपचाप नहीं बैठेंगी।

कुछ ऐसी ही स्थिति दक्षिण-पूर्व में ईरान के बलूच अल्पसंख्यक और दक्षिण-पश्चिम में ईरानी अरबों के साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि इस्राइलियों को यह बुरा न लगे, इस सोच के साथ कि एक टूटा हुआ ईरान किसी और की समस्या है। पर अमेरिका और उसके अरब सहयोगियों के लिए ईरान में लंबे समय तक चलने वाली आपसी कलह से भले ही परमाणु खतरे का अंत हो जाए, लेकिन इससे पश्चिम एशिया के संकट से कोई राहत नहीं मिलेगी। तो फिर, ट्रंप प्रशासन को क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव है: खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लें।

ईरान के बाकी बचे बंदरगाहों में बारूदी सुरंगें बिछा दें या उनकी घेराबंदी कर दें। अगले एक-दो हफ्तों में ईरान की जितनी हो सके, उतनी सैन्य क्षमता नष्ट कर दें, जिसमें 'मिडनाइट हैमर' ऑपरेशन का दूसरा चरण भी शामिल है, ताकि ईरान की बची-खुची परमाणु क्षमता और तकनीकी जानकारी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। और ईरानी शासन को धमकी दें कि अगर वह अपने ही नागरिकों का नरसंहार करता है, विदेशों में आतंकी हमले करता है, या फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करता है, तो उस पर और बमबारी की जाएगी। यह जीत का सबसे यथार्थवादी रास्ता है, जिसमें जान-माल, जोखिम और पैसे का नुकसान सबसे कम होने की संभावना है। तमाम खतरों के बावजूद, यह ईरान के लोगों को अपनी आजादी पाने का सबसे बेहतरीन मौका देता है। एक महीने की इस जंग के लिए यह नतीजा बुरा नहीं है-जिसके आलोचकों ने चेतावनी दी थी कि यह 'एक और इराक' साबित होगा।

©The New York Times 2026

जीवन धारा

हेनरी थॉमस हैंब्लिन

सही मार्ग यह है कि हम अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और निःस्वार्थ बनाएं। जब हमारे विचार बदलते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब दृष्टिकोण बदलता है, तो हमारा व्यवहार बदलता है।

दृष्टिकोण बदलने पर ही व्यवहार बदलता है

मनुष्य के भीतर अपार मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां छिपी होती हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन शक्तियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आम व्यक्ति अपने विचारों की गलत दिशा के कारण समस्याएं तो झेलता है, पर उसे इन शक्तियों का जानबूझकर गलत उपयोग करने का खतरा कम होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन आंतरिक शक्तियों का उपयोग करना सीख लेता है, उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि इन शक्तियों का गलत उपयोग किया जाए तो यह परिणामों में विस्फोटक पदार्थ से भी अधिक विनाशकारी हो सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य स्वयं को तुरंत नष्ट कर लेगा, बल्कि यह कि वह अपने जीवन को कठिन बना सकता है और अपनी आत्मिक प्रगति को लंबे समय तक पीछे धकेल सकता है। मन की शक्ति का उपयोग यदि दूसरों को नियंत्रित करने या अपने स्वार्थ के लिए उन्हें प्रभावित करने में किया जाए, तो यह अंततः उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए ही हानिकारक साबित होता है। यह भी सही नहीं है कि हम इन शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के नाम पर ही क्यों न करें। हर आत्मा को अपने जीवन के अनुभवों से सीखने का अधिकार है। जीवन का उद्देश्य ही यह है कि मनुष्य अपने निर्णयों, गलतियों और अनुभवों से बुद्धिमत्ता प्राप्त करे। यदि हम किसी को मानसिक रूप से प्रभावित करके उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, तो हम उसके विकास के प्राकृतिक मार्ग में बाधा डालते हैं। कई लोग यह मानते हैं कि मन की शक्ति से वे दूसरों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि यह परिवर्तन केवल बाहरी सुझावों के माध्यम से हो, तो वह स्थायी नहीं होता। जब तक सुझाव मिलता रहता है, तब तक प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह समाप्त होता है, व्यक्ति फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने लगता है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने विचारों को सकारात्मक बनाए और आत्म-सुझाव के माध्यम से अपनी शक्ति को जागृत करे। मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली तरीका यह है कि वह अपने भीतर के मौन को खोजे। जब हम शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें उस दिव्य शक्ति का अनुभव होता है जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती है। यह आंतरिक शांति हमें सही दिशा में सोचने और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल धन, सुख या भौतिक इच्छाओं को जबर्दस्ती पाने के लिए करता है, तो वह जीवन के संतुलन को बिगाड़ देता है। प्रकृति का अपना नियम और लय होती है। जब हम अपनी इच्छा से उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो अंततः हमें निराशा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सही मार्ग यह है कि हम अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और निःस्वार्थ बनाएं। जब हमारे विचार बदलते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब दृष्टिकोण बदलता है, तो हमारा व्यवहार बदलता है।

-विद इन यू इज द पावर के अनूदित अंश

स्वयं को पहचानें

सूत्र

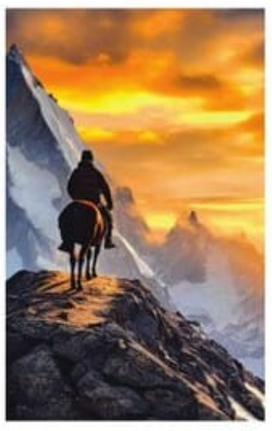

मनुष्य के भीतर अनंत मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और निस्वार्थ बनाते हैं, तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और सुधारने में है। शांत मन में ही दिव्य मार्गदर्शन मिलता है।

दूसरा पहलू

दुनिया भर में चुनाव अक्सर शोर और आरोप-प्रत्यारोप से घिरे रहते हैं। वहीं तिब्बती समुदाय के सरकार गठन की प्रक्रिया काफी अनोखी है।

निर्वासित तिब्बतियों का अनूठा लोकतंत्र

ऐसे समय में जब, दुनिया भर में चुनाव अक्सर शोर, आरोप-प्रत्यारोप, ध्रुवीकरण और प्रतिस्पर्धा का पर्याय बन चुके हैं, तिब्बती समुदाय के चुनावी मॉडल में न प्रचार का कोलाहल है, न दलगत राजनीति का टकराव और न ही सत्ता के लिए मोल-भाव। 27 देशों में फैले निर्वासित तिब्बती समुदाय के बीच सरकार गठन की यह प्रक्रिया सादगी, अनुशासन और नैतिकता का अनोखा उदाहरण है। इसका केंद्र हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज है, जहां से दुनिया भर में फैले निर्वासित तिब्बतियों का केंद्रीय प्रशासन संचालित होता है।

2011 में दलाई लामा ने औपचारिक रूप से अपनी सभी राजनीतिक शक्तियां निर्वाचित नेतृत्व को सौंप दीं।

वर्ष 1959 में तिब्बत से पलायन के बाद आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के भारत में शरण लेने के साथ ही निर्वासन में एक राजनीतिक व सामाजिक संरचना खड़ी करने की आवश्यकता सामने आई। 1960 में बोधगया से इसकी नींव पड़ी और धर्मशाला निर्वासित तिब्बती प्रशासन का केंद्र बन गया। शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अधिकार धर्मगुरु दलाई लामा के पास ही रहे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। 2001 में पहली बार निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख सिक्योंग का पद अस्तित्व में आया, जो प्रधानमंत्री के बराबर का पद है। 2011 में दलाई लामा ने औपचारिक रूप से अपनी सभी राजनीतिक शक्तियां निर्वाचित नेतृत्व को सौंप दीं।

इस साल 90 हजार पंजीकृत मतदाताओं में से 51,140 तिब्बती लोगों ने पहले चरण के लिए फरवरी में बैलेट पेपर से मतदान किया। इसमें पेंपा सेरिंग दूसरी बार सिक्योंग बने हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त लोबसांग येशी बताते हैं कि निर्वासित तिब्बती हर पांच वर्ष में सिक्योंग और निर्वासित संसद के 45 सदस्यों का चुनाव करते हैं। 30 सांसद भारत, नेपाल व भूटान से, 10 सांसद बौद्ध भिक्षुओं से और पांच अन्य देशों से निर्वाचित होते हैं। इस साल 90 हजार पंजीकृत मतदाताओं में से 51,140 तिब्बती लोगों ने पहले चरण के लिए फरवरी में बैलेट पेपर से मतदान किया। इसमें पेंपा सेरिंग 60 फीसदी से अधिक मतों के साथ दूसरी बार सिक्योंग बने हैं। अब अप्रैल में दूसरे चरण के चुनाव में 45 सांसद चुने जाएंगे। यही सांसद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सात विभागों के मंत्रियों का चुनाव करेंगे।

इस चुनावी व्यवस्था की सबसे अहम विशेषता दलीय राजनीति से दूरी है। उम्मीदवार व्यक्तिगत आधार पर मैदान में उतरते हैं। चुनाव आचार संहिता धार्मिक प्रतीकों, विशेषकर धर्मगुरु दलाई लामा की छवि के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाती है। निर्वासित सांसदों को कोई वेतन-भत्ता या विशेष सुविधा नहीं मिलती। दरअसल, यह चुनाव उस सामूहिक स्मृति, संघर्ष और उम्मीद को जीवित रखने का प्रयास है, जो अपने देश लौटने के सपने से जुड़ी है। यह बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल सत्ता परिवर्तन में नहीं, बल्कि सामुदायिक जिम्मेदारी, अनुशासन और नैतिक प्रतिबद्धता में निहित होती है। -मदन मोहन लखेड़ा

आंकड़े

सबसे सस्ती मेट्रो

दिल्ली मेट्रो में यात्रा करना दुनिया की बाकी मेट्रो के लिहाज से सबसे सस्ता है। वहीं भूमिगत यूके मेट्रो का न्यूनतम किराया 390 रुपये है।

दिल्ली मेट्रो, भारत	11
शंघाई मेट्रो, चीन	35
सियोल मेट्रो	84
मैड्रिड मेट्रो, स्पेन	134
न्यूयॉर्क सबवे	250

आंकड़े विभिन्न देशों की मेट्रो के न्यूनतम किराये के, रुपये में | स्रोत : News Reports

तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया, तो गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दे दिया। पर बाद में माफी मांगने पर गणेश जी ने कहा कि विष्णु पूजा में तुम्हारा विशेष महत्व होगा।

गणेश-तुलसी विवाद

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन देवी तुलसी गंगा तट पर घूम रही थीं। उसी समय उन्होंने भगवान गणेश को गहरे ध्यान में लीन देखा। गणेश जी तप में बैठे थे और उनका मन पूर्ण रूप से ईश्वर चिंतन में लगा हुआ था। तुलसी देवी ने गणेश जी के तेज और सौंदर्य को देखकर मन ही मन उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा कर ली।

तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु गणेश जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। उन्होंने तुलसी से कहा कि वे विवाह नहीं करना चाहते और उनका जीवन तप तथा धर्म के मार्ग के लिए समर्पित है। यह सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह अवश्य होगा।

तुलसी के इस व्यवहार से गणेश जी भी दुखी हुए। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसी श्राप के कारण तुलसी का विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हुआ। बाद में तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी।

अंतर्यात्रा
संकलित

तब गणेश जी ने कहा कि तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी और उनकी पूजा में तुम्हारा विशेष महत्व होगा। साथ ही गणेश जी ने यह भी कहा कि मेरी पूजा में तुलसी पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व माना जाता है, जबकि गणेश पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 16 मार्च, 1953

चांदी व सोने के भाव गिर रहे हैं, जबकि रुई व तेल के चढ़ रहे हैं

चांदी, सोने व चीनी के भाव गिरे रहे, रुई व तेल के चढ़े रहे

इस हफ्ते चांदी, सोने और चीनी के भावों में गिरावट रही, जबकि रुई, कपड़ा व धोतियों में काफी तेजी रही। इस वर्ष देश में मूंगफली व उसके तेल के भाव तेज रहेंगे। यदि सरकार ने उसके निर्यात पर रोक लगा दी, तो भाव और गिर सकते हैं।

क्या बदलेगा दीदी का रवैया

सुप्रीम कोर्ट की फटकार व चेतावनी का संकेत समझ ममता ने धरना तो स्थगित कर दिया, पर क्या उनके रवैये में सुधार होगा?

विमल राय | **मुद्दा**

चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान कराने की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो लोक-लुभावन घोषणाएं कीं, जो भले ही आचार संहिता के खिलाफ न हो, लेकिन उनके रवैये को दर्शाता है। वह शायद देश की इकलौती मुख्यमंत्री हैं, जो पद पर रहते हुए भी धरना प्रदर्शन करती रहती हैं। मतदाता सूची से अवैध व बांग्लादेशी वोटरों को हटाने पर केंद्रित एसआईआर की न्यायिक अफसरों की जांच का ही वह विरोध करने बैठ गई थीं, लेकिन 10 मार्च को एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि न्यायिक अधिकारियों के काम पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सख्त हिदायत के बाद ममता ने उसी दिन शाम को धरना खत्म कर दिया, मगर अस्थायी रूप से। इसके पहले, एसआईआर रोकने की ममता की गुहार ठुकरा कर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को न्यायिक अधिकारियों के जरिये 'तार्किक विसंगति' दूर करने का

काम पूरा करने को कहा था। अदालत ने संभवतः चुनावी कार्य में पहली बार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत 'असाधारण परिस्थितियों' में दखल दिया। न्यायिक अफसरों की कमी के चलते झारखंड और ओडिशा के और सौ-सौ जज काम में लगे थे, जिससे तीन राज्यों में लंबित मामलों का बोझ बढ़ा ही होगा। सवाल है कि चुनाव कार्य में लगे सारे बीएलओ व अन्य अधिकारी राज्य सरकार के ही कर्मचारी थे, तो जिंदा/मुर्दा या दूसरी तरह की गलतियों के लिए कोई दूसरा कैसे जिम्मेदार था? तो क्या हंगामा करवाने के लिए जानबूझकर ये गलतियां करवाई गईं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तृणमूल के वकीलों को फटकारा। न्यायिक अधिकारियों के काम में लगते ही 24 फरवरी से लगातार तीन दिनों तक कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट समेत सात जिला अदालतों को बम से उड़ाने के मेल आते रहे। इसे भी 60 लाख अवैध, बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं के नाम नहीं काटने की अप्रत्यक्ष चेतावनी के रूप में देखा गया। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग हाशिये पर ही था, तो क्या ममता का धरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था? ममता जिन बातों का विरोध कर रही थीं, विपक्ष में रहते हुए उनका पुरजोर समर्थन किया था। 13 साल पहले 4 अगस्त, 2005 को लोकसभा में अपननी पार्टी की इकलौती सांसद ममता ने बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ व वोटर लिस्ट में उनके नाम होने के मुद्दे पर अवैध घुसपैठियों के आंकड़ों वाला दस्तावेज सभापति की टेबल पर फेंक दिया था।

लोकसभा के रिकार्ड में दर्ज है कि ममता ने 14 बार अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री के रवैये से साफ लगा कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा व अहंकार के दायरे को इतना बड़ा बना लिया है कि संघवाद, अदालतें, नैतिकता, कानून सब कुछ उन्हें छोटा लगने लगा है। संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद धरने पर बैठ जाए, तो यह बहुत 'खतरनाक' है। अवमानना बहुतों की हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, चुनाव आयुक्त और यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति जैसे प्रथम नागरिक को भी राज्य में अपमानित होना पड़ रहा है। बंगाल की अदालतों पर पहले से ही लंबित मामलों का बोझ है। जो ममता एसआईआर की लाइनों में लगे बंगालियों के कष्ट से द्रवित थीं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए था कि जजों के एसआईआर के काम में लगने से कितने लोगों के लिए न्याय का इंतजार और लंबा हो जाएगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक, कलकत्ता हाईकोर्ट में 2,185 मामले ऐसे हैं, जो पिछले 50 साल या उससे ज्यादा समय से लंबित हैं। एसआईआर के काम में फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोक्सो कोर्ट के जज भी लगे थे।

बंगाल में लोकतंत्र की बात करना ही बेमानी है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या, उत्पीड़न, पुलिस के जरिये गांजा रखने या इसी तरह के 'झूठे' मामलों में फंसाकर जेल भेजना तो दीदी ने वाम शासन से सीखा है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सभाएं करने के लिए 104 बार हाईकोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी। बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा भी अदालत के आदेश से ही निकल पाई। उसके प्रचार वाहनों पर पथराव को तृणमूल की बदनामी के लिए भाजपा का ही षड्यंत्र बताया गया।

प्रधानमंत्री मोदी अगर बंकिम दा बोल देते हैं, तो माफी की मांग की जाती है, लेकिन ममता ने कितनी बार वक्तव्य के दौरान गलत व अशोभनीय बातें कही हैं, इसकी गिनती नहीं है। अपनी गलतियां नहीं स्वीकारेंगे या सुधारेंगे, पर 'बाहर' के लोग अगर कोई भूल कर दें, तो बंगाली अस्मिता फन उठा लेती है।

बंगाल के राजनीतिक माहौल में थोड़ा रहस्य-रोमांच भी आया है। राज्यपाल आनंद बोस की अचानक विदाई और उनकी जगह 11 मार्च को आर एन रवि को राज्य का अतिरिक्त प्रभार संभालने से 'कुछ तो पक रहा है' की षड्यंत्र कथा फैलाई गई। भय राष्ट्रपति शासन का था, लेकिन भाजपा का थिंक टैंक 'सेल्फ गोल' के पक्ष में नहीं था। ममता सरकार अपनी करतूतों से खुद पतन के रास्ते की ओर बढ़ती दिख रही हैं।

Job Alert अमर उजाला
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

दक्षिण मध्य रेलवे ने जारी किया विज्ञापन
अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन

2801 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 11 अप्रैल, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 15 वर्ष व अधिकतम आयु 24 वर्ष
यहां आवेदन करें : scr.indianrailways.gov.in

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में करें आवेदन ■ 143 पद
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2026
पात्रताएं
पोस्ट-ग्रेजुएशन, पीएचडी व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
bujhansi.ac.in

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ■ 58 पद
शिक्षक संवर्ग के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष
यहां आवेदन करें
upsssc.gov.in

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ■ 731 पद
इंजीनियर, जूनियर कार्यकारी सहायक आदि पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 25 मार्च, 2026
पात्रताएं : ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : hindustanpetroleum.com

एम्स, देवघर में रोजगार के अवसर ■ 18 पद
जूनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि 08 अप्रैल, 2026
योग्यताएं
ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
aiimsdeoghar.edu.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना ■ 10 पद
एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर करें आवेदन
वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि 24 मार्च, 2026
वेतनमान
रुपये 78,800 प्रतिमाह निर्धारित
यहां आवेदन करें
esic.gov.in

यहां भी रोजगार के अवसर...
- राइट्स लिमिटेड, गुरुग्राम : असिस्टेंट मैनेजर आदि के पदों पर रिक्तियां।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 27 अप्रैल, 2026
- rites.com
- राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र : प्रोजेक्ट अनुसंधान वैज्ञानिक का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2026
- nbrc.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

बेवजह के कामों में उलझने से बचें

नेतृत्व का अर्थ यह नहीं कि हर काम खुद किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए

लुइस वेलास्केज
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

जब किसी संगठन में नेतृत्व बदलता है या प्रक्रियाओं में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो अक्सर टीम का सबसे सक्षम कर्मी हर समस्या को संभालने लगता है। शुरुआत में यह स्थिति भरोसे और दक्षता का संकेत लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह भरोसा निर्भरता में बदल जाता है। परिणामस्वरूप, वह व्यक्ति लगातार बढ़ते काम के दबाव और जिम्मेदारियों की वजह से थकान और मानसिक दबाव महसूस करने लगता है, जबकि संगठन की उस पर निर्भरता और अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए आवश्यक है कि जिम्मेदारियों का उचित वितरण किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट रूप से तय की जाए, ताकि कार्यप्रणाली संतुलित, सक्षम और सही ढंग से चल सके।

Harvard Business Review

■ समस्या को पहचानें
कार्यस्थल पर हर समस्या को अकेले सुलझाना सही रणनीति नहीं है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या समस्या को तुरंत हल करने की जरूरत है और क्या यह आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर हम दूसरों का काम भी अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है। अगर आप हर चीज खुद सुलझाएंगे, तो टीम के सदस्य जिम्मेदारी लेना छोड़ देंगे। इसलिए काम शुरू करने से पहले सोचें कि यह काम किसका है। यह आदत हमें बेवजह के बोझ से बचाती है।

■ जिम्मेदारी को स्पष्ट करें
जब काम की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होती, तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोग यह नहीं समझ पाते कि निर्णय कौन लेगा और किसे जवाबदेह माना जाएगा। ऐसे में अक्सर सबसे जिम्मेदार व्यक्ति ही सारा काम अपने ऊपर ले लेता है। सही तरीका यह है कि काम शुरू करने से पहले तय कर लिया जाए कि कौन निर्णय लेगा, कौन जिम्मेदार होगा, किससे सलाह ली जाएगी और किसे जानकारी दी जाएगी। इससे टीम में स्पष्टता आती है, और काम सुगमता से होने लगता है।

■ टीम को जिम्मेदार बनाएं
अनजाने में हर समस्या को खुद हल करने से टीम के अन्य सदस्य जिम्मेदारी लेना नहीं सीख पाते। इसलिए हर समस्या को सही व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। यदि कोई समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो साफ बताएं कि यह काम किसका है और आप किस तरह मदद कर सकते हैं। इस तरह आप केवल समस्या हल नहीं करते, बल्कि पूरी टीम को जिम्मेदार बनाना भी सिखाते हैं।

■ नजरिया बदलें
सही नेतृत्व का मतलब यह नहीं कि हर काम खुद किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए। इससे लीडर खुद पर अनावश्यक दबाव कम करते हैं, टीम जिम्मेदार बनती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। यही सच्चा और प्रभावी नेतृत्व है।

खुद को परखें

1. क्षुद्रग्रह 2024 YR4 की खोज किस दूरबीन द्वारा की गई थी?
   (a) हबल अंतरिक्ष दूरबीन
   (b) क्षुद्रग्रह स्थलीय-प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली दूरबीन
   (c) जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन
   (d) जायंट मैगेलन दूरबीन

2. संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) के अनुसार, वर्ष 2025 में कौन-सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका को सूती उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया?
   (a) चीन (b) वियतनाम
   (c) भारत (d) बांग्लादेश

3. मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है?
   (a) ओडिशा
   (b) झारखंड
   (c) बिहार
   (d) छत्तीसगढ़

उत्तर-1.b, 2.c, 3.d

सामान्य ज्ञान

जोहा राइस

- **क्या है**
  यह असम की एक स्वदेशी सुगंधित चावल की किस्म है, जो अपनी विशिष्ट सुगंध, महीन दानेदार बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है।
- **चर्चा में क्यों?**
  हाल ही में भारत ने असम के जीआई-टैग वाले जोहा चावल के 25 मीट्रिक टन के निर्यात को यूनाइटेड किंगडम और इटली तक पहुंचाने में उपलब्धि हासिल की है।
- **प्रमुख जोहा किस्में**
  इसकी खेती साली/खरीफ के मौसम में की जाती है। इसमें शामिल प्रमुख जोहा किस्में कोला जोहा, बोकुल जोहा और कुनकुनी जोहा हैं।
- **विशेषताएं**
  यह चावल कई एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड और फेनोलिक्स से भी भरपूर है। चावल की इस किस्म में दो असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं अर्थात लिनोलिक अम्ल (ओमेगा-6) और लिनोलेनिक अम्ल (ओमेगा-3)। ये आवश्यक फैटी एसिड्स विभिन्न शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

एनआईटी कालीकट समर इंटर्नशिप प्रोग्राम

इंटर्नशिप प्रोग्राम

एनआईटी कालीकट में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के लिए छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह इंटर्नशिप 60 दिनों की अवधि के लिए ऑफलाइन तथा ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में 30 दिनों के लिए उपलब्ध होगी। दो महीने की इंटर्नशिप का विकल्प चुनने वाले छात्रों को 4 से 15 मई, 2026 के बीच रिपोर्ट करना होगा और इंटर्नशिप 15 जुलाई, 2026 तक पूरी करनी होगी। एक महीने की इंटर्नशिप का विकल्प चुनने वाले छात्रों को 15 जून, 2026 को या उससे पहले रिपोर्ट करना होगा। स्नातक, स्नातकोत्तर व उसके समकक्ष डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र आवेदन के पात्र हैं। इसके अलावा आवेदक नियमित पूर्णकालिक छात्र होने चाहिए और पिछले सेमेस्टर में न्यूनतम सीजीपीए 6.5 (10 में से) या 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। आवेदक आधिकारिक लिंक tinyurl.com/3uhz6k3e पर जाकर 23 मार्च, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

28वें अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव की प्रतियोगिता

आवेदन आमंत्रित

सोरिया, स्पेन की स्थानीय सरकार की युवा परिषद ने 28वें अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव की प्रतियोगिता 'स्यूदाद डी सोरिया' के लिए पोस्टर जमा करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। विजेता पोस्टर को 28वें अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव की प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा।

■ इच्छुक प्रतियोगी लें भाग
यह प्रतियोगिता विश्व भर के सभी डिजाइनरों, कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुली है। जो भी इसमें भाग लेने के इच्छुक हों, चाहे टीम के रूप में या व्यक्तिगत लेखक के रूप में, वे भाग ले सकते हैं। प्रत्येक लेखक अधिकतम एक पोस्टर प्रस्तुत कर सकता है।

■ पुरस्कार
इस प्रतियोगिता के विजेता को 1000 यूरो का एकमुश्त पुरस्कार दिया जाएगा।

■ यहां आवेदन करें
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जून, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यताओं की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक tinyurl.com/488netzs पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट हफ्ते की परीक्षाएं

बैंक ऑफ बड़ौदा कार्यालय सहायक मुख्य परीक्षा
- परीक्षा की तिथि : 22 मार्च, 2026
- इस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता, प्रारंभिक अंकगणित व तर्कशक्ति से 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 80 मिनट का समय दिया जाएगा।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें
  tinyurl.com/yze2hfap

यूपीपीएससी एपीओ परीक्षा 2025
- परीक्षा की तिथि : 22 मार्च, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, समसामयिक घटनाएं, भारतीय संविधान, यूपी पुलिस अधिनियम और विनियम आदि से 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित है।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें
  tinyurl.com/28ubpy28

नोट: 14 मार्च को प्रकाशित एग्जाम अलर्ट में सीबीएसई टियर-II परीक्षा की तिथि 19 मार्च के बजाय 19 अप्रैल, 2026 पढ़ें।

रोशनी यहां है

इस बार : जय चौधरी
क्यों : एक गांव से उठी वैश्विक सफलता की कहानी

एक छोटे-से गांव से निकलकर जय चौधरी ने अपने संकल्प और दूरदृष्टि के दम पर अरबपति सीईओ बनने तक का सफर तय किया। आईआईटी, बीएचयू और अमेरिका से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने कई तकनीकी कंपनियां स्थापित कीं, जिनमें जस्केलर भी शामिल है, जो आज क्लाउड सुरक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है।

संघर्ष में बीता बचपन, प्रतिभा और इनोवेशन के दम पर खड़ा किया करोड़ों का कारोबार

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक साधारण गांव से निकलकर वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले जय चौधरी की कहानी संघर्ष, मेहनत और बड़े सपनों की मिसाल है। एक किसान परिवार में जन्मे जय चौधरी ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। आगे चलकर उन्होंने साइबर सुरक्षा कंपनी जस्केलर की स्थापना की, जो आज दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। आज उनकी संपत्ति लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये आंकी जाती है और वे दुनिया के सबसे समृद्ध आईआईटी पूर्व छात्रों में गिने जाते हैं। उनकी प्रेरक यात्रा यह बताती है कि मजबूत इरादे और लगातार मेहनत से साधारण शुरुआत भी असाधारण उपलब्धियों में बदल सकती है।

साधारण परिस्थितियों में बीता बचपन

जय चौधरी का जन्म 1958 में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के छोटे से गांव पनोह में हुआ था। उनका बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता, जहां बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन इतनी मजबूत थी कि वे रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे और बिजली न होने के कारण अक्सर दिन के उजाले में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। स्कूल में जब लंच होता था, तब बाकी बच्चे खेलते थे, लेकिन जय उस समय अपने शिक्षक से कुछ नया सीखने में लगे रहते थे। वे अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल स्थान पर रहे। इन्हीं संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा की मजबूत नींव रखी। आगे चलकर उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय की।

छात्रवृत्ति से अमेरिका में की पढ़ाई

पढ़ाई में मेधावी रहे जय चौधरी ने अपनी प्रतिभा के दम पर विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त किया। उन्हें अमेरिका के सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में एमबीए करने के लिए छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा सके। बताया जाता है कि उनकी पढ़ाई में टाटा ग्रुप की ओर से भी आर्थिक सहयोग मिला था। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने कॅरिअर की शुरुआत प्रतिष्ठित तकनीकी कंपनियों आईबीएम और यूनिसिस में काम करके की। इसके बाद उद्यमिता की राह चुनते हुए उन्होंने 1996 में अपनी पहली साइबर सुरक्षा कंपनी सिक्योरआईटी की स्थापना की। आगे चलकर उन्होंने सिफरट्रस्ट, कोरहार्बर और एयरडिफेंस जैसी कई सफल कंपनियां खड़ी कीं, जिसने उन्हें टेक्नोलॉजी जगत में एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित कर दिया।

जस्केलर की स्थापना

2007 में जय चौधरी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जस्केलर की स्थापना की। उस समय तकनीकी दुनिया तेजी से बदल रही थी और बढ़ते साइबर खतरों के सामने पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियां पर्याप्त साबित नहीं हो रही थीं। प्रौद्योगिकी और नवाचार की गहरी समझ रखते हुए जय चौधरी ने महसूस किया कि कंपनियों को अधिक उन्नत और लचीले सुरक्षा समाधान की जरूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने क्लाउड आधारित सुरक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिसने संगठनों को अपने नेटवर्क और डाटा को सुरक्षित रखने का एक नया तरीका सिखाया। जस्केलर का यह क्लाउड-आधारित मॉडल जल्द ही लोकप्रिय हो गया और अलग-अलग क्षेत्रों की कई कंपनियों ने अपने डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए इसे अपनाना शुरू कर दिया।

क्लाउड सुरक्षा में बड़ी पहचान

जय चौधरी के नेतृत्व में जस्केलर ने तेजी से विकास किया और कुछ ही वर्षों में क्लाउड आधारित साइबर सुरक्षा समाधानों की अग्रणी कंपनियों में शामिल हो गई। आज जस्केलर वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित साइबर सुरक्षा कंपनियों में गिनी जाती है। यह कंपनी आज 25 अरब डॉलर (लगभग 2308.49 रुपये) से अधिक की वैल्यू वाली साइबर सिक्योरिटी लीडर बन चुकी है। फोर्ब्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, जय की कुल संपत्ति लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये है। इसके ग्राहक दुनिया भर में फैले हुए हैं और इनमें वित्त, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी सहित कई महत्वपूर्ण उद्योगों की संस्थाएं शामिल हैं।

युवाओं को सीख

- बड़े सपने देखने वाले ही बड़ी सफलता हासिल करते हैं।
- समय का सही उपयोग ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
- लक्ष्य स्पष्ट हो, तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं।

16 मार्च,1926

आज का दिन

अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट एच. गोडार्ड ने पहला तरल ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया था। इसने 2.5 सेकंड तक 60 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा की। इस रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा के सपनों को नए पंख मिले थे।

- 1802 : संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य अकादमी वेस्ट प्वाइंट की स्थापना हुई थी।
- 1850 : अमेरिकी लेखक नाथेनियल हॉथोर्न की पुस्तक 'द स्कार्लेट लेटर' प्रकाशित हुई थी।
- 1926 : अमेरिकी हास्य अभिनेता जेरी लुईस का जन्म हुआ था।
- 1970 : अमेरिकी गायिका टैमी टेरेल का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : चैत्र कृष्ण पक्ष द्वादशी।
कल : रंग तेरस, वसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक।

कल का पंचांग

सूर्योदय : 06.33
सूर्यास्त : 18.27
(भारतीय मानक समयानुसार)

विक्रमी संवत 2082, 26 फाल्गुन मास शक 1947, चैत्र मास 04 प्रविष्टे, 27 रमजान हिजरी 1447, चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 09.22 तक उपरांत चतुर्दशी, शतभिषा नक्षत्र 30.08 तक उपरांत पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र,सिद्ध योग 08.14 तक उपरांत साध्य योग 30.21 तक तदोपरांत शुभ योग, वणिज करण 09.22 तक उपरांत विष्टि (भद्रा) करण, चंद्रमा कुंभ राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

पं. विनोद त्यागी

मेष : राजकाज में सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति हो सकती है। व्यावसायिक धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा।

वृष : मानसिक तनाव से बचें। नौकरी में नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यवसाय में आय व्यय सम रहेंगे।

मिथुन : नौकरी में कुशल प्रबंधन का लाभ मिल सकता है। व्यवसाय में जोखिम जमानत से बचें।

कर्क : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में नई चुनौतियां आएंगी। व्यावसायिक लाभ से संतुष्ट रहेंगे।

सिंह : नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। कार्यविशेष में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

कन्या : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

तुला : दिनमान श्रम साध्य रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा।

वृश्चिक : व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। कार्यक्षेत्र में सावधानी से निर्णय लें। व्यवसाय में लाभ हो सकता है।

धनु : मानसिक तनाव से बचें। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। नई व्यावसायिक योजना बन सकती है।

मकर : दिनमान सामान्य रहेगा। नौकरी में श्रम के बल पर दबदबा बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

कुंभ : मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

मीन : सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। मित्र सहायक रहेंगे। अटका धन मिलेगा। व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे।

जन्मदिन

राजपाल यादव, अभिनेता

इस वर्ष मनोत्साह बना रहेगा। परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। जमीन-जायदाद के अटके कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। भवन निर्माण पर व्यय हो सकता है। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। साझेदारी में किसी नए व्यवसाय का प्रारंभ हो सकता है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

सुडोकू

4	8			9	5			
			4				6	5
		2		6				
1			2			6		
6	2						4	9
		7			6			1
				3		7		
2	5				4			
			8	5			1	3

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

4	8	6	1	9	5	2	3	7
9	3	1	4	2	7	8	6	5
5	7	2	3	6	8	1	9	4
1	9	5	2	4	3	6	7	8
6	2	8	5	7	1	3	4	9
3	4	7	9	8	6	5	2	1
8	1	4	6	3	9	7	5	2
2	5	3	7	1	4	9	8	6
7	6	9	8	5	2	4	1	3

डेली हेल्थ कैप्सूल

औषधि का काम करता है लहसुन तेल

एंटी-बायोटिक, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल गुणों से भरपूर लहसुन का तेल कई बीमारियों में लाभप्रद है।

लहसुन की कलियों से प्राप्त तेल कई स्वास्थ्य लाभों से युक्त होता है। इसमें एलिसिन, डायलील डाइसल्फाइड और डायलील ट्राइसल्फाइड जैसे यौगिक होते हैं, जो स्वास्थ्य समस्याओं में लाभ पहुंचाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, लहसुन में ही 200 से अधिक ऐसे रसायन पाए जाते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को

मजबूत करने और शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन के तेल में एलिसिन जैसे ऑर्गेनोसल्फर यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और रक्त संचार में सुधार करने में सहायक होते हैं। इससे दिल सेहतमंद रहता है। लहसुन का तेल सल्फर यौगिकों, विटामिन सी और बी6 तथा आवश्यक खनिजों से भरपूर है, जो बालों के रोमों को पोषण देते है और नए बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। लहसुन में मौजूद सूजनरोधी तत्व जोड़ों के दर्द और अकड़न से राहत दिलाते हैं। लहसुन के तेल में जीवाणुरोधी, फफूंदरोधी गुण पाए जाते हैं, जो मुंहासे, त्वचा के संक्रमण और दाद जैसी छोटी-मोटी फफूंद के इलाज में मददगार हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

यदि आपको एसिडिटी या शरीर में बहुत गर्मी रहती है, तो लहसुन के तेल के अत्यधिक उपयोग से बचें। संवेदनशील त्वचा पर इसे तिल के तेल या नारियल तेल में मिलाकर लगाना बेहतर होता है।

-डॉ. नवीन चंद्र जोशी
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

चुनाव की घोषणा

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। अपने देश में फिलहाल जैसी राजनीतिक स्थिति है, उसमें ये पांचों क्षेत्र चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से दो जगह – असम राज्य और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश में भाजपा सरकार में है, जबकि अन्य तीन राज्यों - तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में भाजपा की विरोधी सरकारें हैं। खास यह है कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को ही मतदान है, मतलब इन राज्यों में अब ज्यादा समय नहीं है। हालांकि, इन सभी जगहों पर चुनावी बिगुल बीते एक महीने से बज रहा है, अतः यह कहना सही नहीं होगा कि दलों को चुनाव प्रचार का समय नहीं मिला। हां, पहले के दौर में प्रचार के लिए कुछ ज्यादा समय मिलता था, अब उतना समय नहीं मिलता है। यह एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही, आचार संहिता लागू हो जाती है और बड़े सरकारी काम ठप्प हो जाते हैं। ऐसे में, चुनाव आचार संहिता के समय को कम करना प्रशंसनीय है।

यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि जब राज्य सरकारों को काम के लिए ज्यादा समय मिल रहा है, तो उन्हें लोकलुभावन घोषणाओं के लिए भी ज्यादा समय मिल रहा है। मिसाल के लिए, चुनाव की घोषणा से ठीक पहले, एलपीजी की कमी के मद्देनजर तमिलनाडु की सरकार ने होटलों और क्लाउड किचन के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी की घोषणा की है। उधर, आचार संहिता लागू होने से कुछ ही घंटे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू और मुस्लिम पुजारियों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। अब उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे। इस चुनाव में शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी, जो सांप्रदायिक समूहों को लुभाने की कोशिश न कर रही हो। असम और केरल में भी ऐसी घोषणाएं हुई हैं। लोगों को रिझाने में कोई दल पीछे नहीं है। आज राज्य सरकारों के पास धन बढ़ा है, तो उन्हें अपने हिसाब से बांटने का हक है। हां, लोकलुभावन चुनावी घोषणाओं की निंदा होती है, पर इससे लोगों को सीधे लाभ भी होता है। हालांकि, ऐसी राजनीति में वोट खरीदने का आरोप किसी भी राजनीतिक दल का पीछा नहीं छोड़ता है। हां, यह सकारात्मक बात है कि चुनावी वादे अब अधिकाधिक पूरे होने लगे हैं और जनता के सभी वर्ग को कुछ न कुछ सीधे लाभ हो रहा है।

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में चुनावी तिथियों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। यह चुनाव आयोग के लिए परीक्षा की घड़ी है।

निस्संदेह, राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे खास है, जहां इस बार केवल दो चरणों में मतदान होने हैं। यहां चुनाव आयोग तारीफ का हकदार है। पिछली बार यहां आठ चरणों में मतदान हुए थे और आपराधिक तत्वों को ज्यादा मौके मिले थे। उम्मीद है, यहां चुनावी हिंसा कम होगी। यह चुनाव ममता बनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह चौथे कार्यकाल के लिए लालायित हैं। इस बार सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर होगी। उधर, असम में लगातार दो बार से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है और इस बार भी वह कमजोर नहीं दिख रही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक बहुत मजबूत है, तो केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चा तीसरे कार्यकाल के लिए जोर लगा रहा है। वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे की राह आसान नहीं है। खैर, अगली सरकारों का चेहरा 4 मई को मतगणना के दिन सामने आ जाएगा। इस बार टक्कर तगड़ी है और चुनाव आयोग को ऐसी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम देना है, ताकि किसी को शिकायत का कोई मौका न मिले।

गैस का इंतजाम एक बड़ा इम्तिहान

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

यूरोप से लेकर एशिया तक ज्यादातर देश ईरान युद्ध के संकट का ताप झेलने लगे हैं। कहीं गैस की कमी है, तो कहीं तेल की किल्लत और महंगाई का डर भी सताने लगा है।

लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में
यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।

मशहूर शायर राहत इंदौरी का यह शेर किसी मोहल्ले, गांव, शहर या कह सकते हैं कि किसी पूरे देश को नजर में रखकर लिखा गया होगा और यह उसी रोशनी में सुना व सुनाया जाता रहा है। वैसे, आज शायद यह शेर पूरी दुनिया के लिए सही साबित होता दिख रहा है।

अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के पहले शायद ही किसी ने सोचा था कि इसकी आंच इतनी जल्दी इतनी दूर तक फैल जाएगी। अब तस्वीर साफ है। यूरोप से लेकर एशिया तक तमाम देश इस युद्ध से उपजे संकट का ताप झेल रहे हैं। कहीं गैस की कमी है, तो कहीं तेल की किल्लत और महंगाई का डर सता रहा है।

भारत के लिए यह बड़ी मुसीबत है, क्योंकि होर्मुज जलमार्ग बाधित होने या बंद होने का सबसे खराब असर भारत पर पड़ना तय था। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के रास्ते अरब सागर से जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण जलमार्ग पूरी दुनिया के ऊर्जा-व्यापार की जीवनरेखा है। दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की कुल आपूर्ति का लगभग 20 से 25 फीसदी हिस्सा इसी रास्ते से गुजरकर मंजिल तक पहुंचता है। हर रोज इस रास्ते से औसतन 138 जहाज या टैंकर फारस की खाड़ी से अरब सागर तक का सफर तय करते हैं, जिनमें लगभग 1.40 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 29 करोड़ घनमीटर तरल प्राकृतिक गैस या एलएनजी ढोई जाती है। पिछले दो हफ्तों में इस रास्ते से कुछ ही टैंकर निकल पाए हैं, इधर कुछ और टैंकरों को भी निकाला जा रहा है, पर टैंकरों की आवाजाही घटने का ही असर तेल और गैस के बढ़ते दामों पर दिख रहा है।

पूरी दुनिया में हर रोज करीब 10.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। इसमें से दो करोड़ बैरल सिर्फ पश्चिम एशिया से आता है। इसका बड़ा हिस्सा होर्मुज के रास्ते निकलता है और करीब 60 लाख बैरल पाइपलाइन के रास्ते लाल सागर जाता है। लड़ाई की वजह से दोनों ही रास्तों पर असर पड़ा है और दुनिया को हर रोज दो करोड़ बैरल तेल कम मिल रहा है। अब तक का मोटा अनुमान यही है कि करीब 20 से 25 करोड़ बैरल तेल अटक गया है, जिसका बड़ा हिस्सा उन्हीं देशों के स्टोरेज टैंकरों में आ चुका था। चूंकि अब वे भी भरने लगे हैं, इसलिए ये देश अब कुओं से तेल निकालना ही बंद कर रहे हैं।

भारत की तेल-आपूर्ति का लगभग आधा हिस्सा यहीं से आता है। हालांकि, इससे भी बड़ी परेशानी है एलएनजी या प्राकृतिक गैस। हम गाड़ियों में सीएनजी या घरों में पीएनजी के नाम से जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, वे यही हैं। भारत 84 प्रतिशत एलएनजी पांच देशों से मंगाता है- कतर, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, अंगोला और ओमान, लेकिन इसका 60 फीसदी हिस्सा पश्चिम एशिया के उन्हीं इलाकों से आता है, जिनकी आपूर्ति होर्मुज जलमार्ग से गुजरती है।

तेल के मुकाबले गैस का बाजार बहुत विकट है। तेल तो कहीं से भी कम या ज्यादा मात्रा में खरीदा जा सकता है, पर गैस की आपूर्ति में लंबे समय के करार करने पड़ते हैं। इसीलिए भारत कतर पर काफी हद तक निर्भर है। कतर एनर्जी इस इलाके में एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, पर उसके रस लफान कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले के बाद से उसने एलएनजी उत्पादन बंद कर रखा था। इसी परिस्थिति में दुनिया के दिग्गज विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि यदि होर्मुज का रास्ता दो महीने से ज्यादा बंद रहा, तो एलएनजी का दाम दोगुना होने का डर है। इस वक्त भी इसका दाम 15 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पहुंच चुका है, जो जंग शुरू होने से पहले सात डॉलर पर था। तेल के दाम प्रति बैरल 150 से 200 डॉलर तक पहुंचने की चेतावनियां पहले ही आ चुकी हैं। मान लें कि यह लड़ाई आज ही खत्म हो जाए, तब भी स्थिति सुधरने और आपूर्ति के वापस पटरी पर आने में कम से कम एक महीने का वक्त लग ही जाएगा। हालांकि, इस समय ज्यादा जानकार भविष्यवाणी करने से कतरा रहे हैं, पर तीन तरह के अनुमान लग रहे हैं।

अगर युद्ध तुरंत रुक जाए और दोनों पक्ष शांति के लिए राजी हो जाएं, तो इस इलाके से तेल और गैस आना फिर शुरू होगा। तीन-चार हफ्ते में उत्पादन भी शुरू हो सकता है। फिर भी, हालात सामान्य होने में एक से दो महीने का वक्त लग सकता है।

हालांकि, यदि यह लड़ाई एक-दो महीने तक खिंचती है और होर्मुज की नाकाबंदी जारी रहती है, तब तेल के दाम फिर चढ़ेंगे और 150 डॉलर के ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसे में, सऊदी अरब और यूएई को अपना उत्पादन बंद करना पड़ेगा। गैस की भारी किल्लत हो जाएगी, जिससे खाद कारखानों और प्राकृतिक गैस पर निर्भर दूसरे उद्योगों को झटका लगेगा। शहरों में पाइप लाइन गैस की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है और यातायात महंगा हो सकता है। भारत का तेल आयात खर्च तेजी से बढ़ने का डर है, जिसकी वजह से रुपया भी कमजोर होगा और काफी समय से काबू में दिख रही महंगाई के भी बेलगाम होने का डर पैदा होगा। युद्ध रुकने के बाद भी संकट से उबरने में समय लग सकता है।

तीसरी तस्वीर और भी डरावनी है। अगर वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह ईरान का मोर्चा भी अमेरिका के लिए एक लंबी लड़ाई का मैदान बन जाता है और होर्मुज जलमार्ग को बंद रखने में ईरान कामयाब रहता है, तब कच्चे तेल का दाम 200 डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकता है। दुनिया के तमाम देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। तमाम चीजों की किल्लत देखने को मिल सकती है। महंगाई तेजी से बढ़ी, तो केंद्रीय बैंकों को ब्याज बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसका असर आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा। ऐसे में अनेक देश मंदी की चपेट में भी जा सकते हैं। भारत भी इन सबसे अछूता नहीं रह सकेगा।

अभी भारत और ईरान के बीच बातचीत से उम्मीद बनती है कि होर्मुज का रास्ता शायद भारत के लिए पूरी तरह बंद नहीं होगा, इसलिए अभी परिस्थिति उतनी बिगड़ती नहीं दिखती। अगर तटस्थ होकर देखना है, तो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के प्रमुख की यह चेतावनी याद रखनी चाहिए कि यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, दुनिया के तेल कारोबार के लिए उसके नतीजे उतने ही हाहाकारी होंगे।

भारत सरकार पूरे प्रयास में लगी है कि उसे किसी तरह से तेल मिलता रहे। ईरान को मनाने में कुछ सफलता भी मिली है। हालांकि, अपनी जरूरत भर का तेल लाने के लिए भारत सरकार को अभी और प्रयास करने की जरूरत है। ध्यान रहे, हर गुजरता दिन दुनिया को भी महंगा पड़ रहा है और भारत को भी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

टीकों पर लोगों का भरोसा बढ़ाएगी मुआवजा नीति

यहां स्कैन करें

चंद्रकांत लहारिया | स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ

पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के बाद होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं के लिए 'नो-फॉल्ट मुआवजा नीति' तैयार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि टीकाकरण अभियान सरकार के माध्यम से संचालित होते हैं और इसलिए उनके साथ जवाबदेही और मुआवजे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह नागरिकों और सरकार के बीच मौजूद 'सामाजिक अनुबंध' का हिस्सा है।

निस्संदेह, टीके हर वर्ष लाखों लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में वे गंभीर दुष्प्रभाव भी दिखा सकते हैं। एक परिपक्व स्वास्थ्य व्यवस्था इस आशंका को स्वीकार करती है, प्रभावित लोगों को भरपाई करती है और टीकाकरण के प्रति समाज के भरोसे को अधिक मजबूत बनाती है। यही वह संदर्भ है, जहां 'नो-फॉल्ट मुआवजा प्रणाली' की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। पारंपरिक कानूनी प्रक्रिया में पीड़ित व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि किसी की लापरवाही या गलती के कारण नुकसान हुआ है। इसके विपरीत, 'नो-फॉल्ट' व्यवस्था यह मानती है कि मानकों और नियामक सुरक्षा के बावजूद कभी-कभी प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकते हैं। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को समय पर आर्थिक सहायता देना है, जिन्होंने सार्वजनिक हित के लिए चलाए गए कार्यक्रम में भाग लेते हुए दुर्लभ और गंभीर नुकसान झेला है।

प्रस्तावित 'नो-फॉल्ट मुआवजा' नीति भारत में टीकों के प्रति भरोसे की नींव को और मजबूत कर सकती है, हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

यह विश्वास तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब नए टीकों की शुरुआत की जाती है। हाल ही में भारत ने किशोरियों के लिए 'ह्यूमन पैपिलोमा वायरस' (एचपीवी) टीका उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। फिर भी, कई क्षेत्रों में इसकी स्वीकार्यता अभी सीमित है। वैश्विक वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद, पूर्व की कुछ विवादित घटनाओं और गलत सूचनाओं के कारण लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। इस स्थिति में पारदर्शी नीतियां टीकों के प्रति भरोसा बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

हालांकि, इस तरह की नीति के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। आज के समय में जब सूचना बहुत तेजी से फैलती है और सोशल मीडिया अफवाहों को बढ़ावा देता है, टीकों से जुड़े जोखिमों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। यदि संवाद सावधानीपूर्वक न किया जाए, तो मुआवजा नीति को कुछ लोग इस रूप में भी देख सकते हैं कि टीके असुरक्षित होते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी नीति के साथ स्पष्ट और जिम्मेदार संवाद अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

इस नीति को लागू करते समय कई बातें ध्यान में रखनी होंगी। प्रतिकूल घटनाओं के कारणों की पड़ताल वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीकों से होनी चाहिए। चिकित्सा विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों और कानूनी विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल को प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रक्रिया सरल और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। संभव हो, तो इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कोष या टीका खरीद से जुड़े छोटे वित्तीय योगदान जैसे मॉडल अपनाए जाएं, जैसा कई देशों में होता है।

कोविड-19 महामारी ने यह दिखाया कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान प्रभावकारी, पर जटिल भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने टीकों को संभव बनाया, पर उनकी सफलता अंततः लोगों के विश्वास और भागीदारी पर निर्भर रही। प्रस्तावित 'नो-फॉल्ट मुआवजा' नीति भारत में टीकों के प्रति भरोसे की नींव को और मजबूत कर सकती है, बशर्ते इसे सोच-समझकर तैयार किया जाए। दुर्लभ प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को सहारा देने से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ सकती है। ऐसे समय में, जब गलत सूचनाएं अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों की तुलना में तेजी से फैलती हैं, यह नीति एक महत्वपूर्ण संदेश दे सकती है कि जब नागरिक सामूहिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तब राज्य भी उनके साथ न्याय, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ खड़ा रहता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मन की उम्र बढ़ती रहे

लोग बड़े हो जाते हैं, पर सिर्फ शरीर से, मन उनका बच्चा ही रहता है। बचपन में बचपना सुंदर लगता है, पर बड़े लोग जब बच्चों जैसे आचरण करते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। रिश्तों की गुत्थी सुलझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई कोशिशें कीं।

20वीं सदी में अमेरिका में एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक हुए डॉ एरिक बर्न। उन्होंने सैकड़ों मरीजों का उपचार किया और फिर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान एक अखंड व्यक्तित्व नहीं है। उसके अंदर कई केंद्र होते हैं, जो तरह-तरह के चेहरे बनकर उभरते हैं। अपने अनुभवों की बुनियाद पर उन्होंने एक किताब लिखी- *गेम्स पीपुल प्ले,* यानी खेल जो लोग खेलते हैं।

डॉ बर्न एक वकील का इलाज कर रहे थे, जो कम उम्र में ही एक सफल, प्रसिद्ध और संपन्न वकील बन गया था। एक सत्र के दौरान वह बोला, मैं वकील नहीं हूं, एक छोटा बच्चा हूं। फिर अगले सत्रों में कई बार वकील ने डॉ बर्न से पूछा, आप वकील से बोल रहे हैं या बच्चे से? यह देखकर बर्न में कौतूहल जगा। उन्होंने धीरे-धीरे अपने अन्य मरीजों के विश्लेषण के दौरान भी पाया कि एक व्यक्ति में कम-से-कम तीन लोग बसते हैं- बच्चा, मां-बाप और वयस्क। और, ये तीन लोग क्रमशः बदलते रहते हैं। कब बच्चा उभरता है और कब मां-बाप बोलने लगते हैं, यह कहा नहीं जा सकता। यह बदलाव सिर्फ शब्दों में प्रकट नहीं होता, बल्कि शब्दों से तो बहुत कम कहा जाता है; चेहरे के हाव-भाव, देह-भाषा, शरीर का तापमान और अन्य कई निःशब्द इशारों से उस व्यक्ति की मंशा का पता चलता है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई इंसान बोलता है, तो केवल सात प्रतिशत संप्रेषण उसके शब्दों से होता है, बाकी 38 प्रतिशत स्वर के उतार-चढ़ाव, शब्दों पर आघात इत्यादि से होता है; और देह-भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज द्वारा 55 प्रतिशत संप्रेषण होता है।

हम बचपन में अपने से बड़ों के विचार, भाव और आचरण का अनुकरण कर रहे होते हैं। भारतीयों में यह आदत गहरी होती है, क्योंकि यहां बच्चों पर मां-बाप का असर होता है। यह देखना हमारे विकास में सहयोगी होगा कि जो हमारे विचार या भाव हैं, उनमें कितने सचमुच हमारे हैं और कितने हम मां-बाप के ही दोहरा रहे हैं।

यह देखना हमारे विकास के लिए बहुत सहयोगी होगा कि जो हमारे विचार या भाव आ रहे हैं, उनमें कितने सचमुच हमारे अपने हैं और कितने हम मां-बाप के ही दोहरा रहे हैं।

आदमी वयस्क तब होता है, जब जीवन का सीधा सामना करता है- अभी और यहीं, जब वह भूतकाल के प्रभाव को मिटा देता है। जिसका यह केंद्र विकसित होता है, वह व्यक्ति सहज स्फूर्त और सतर्क होता है। वह अपने फैसले खुद ले सकता है और बचकानी हरकतें नहीं करता। बचपन की इच्छाएं बड़े होने के बाद वयस्क होनी चाहिए। शरीर की उम्र के साथ मन की उम्र भी बढ़ती जाए, तो संतुलन बना रहता है।

अमृत साधना

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी आपूर्ति शृंखलाएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं और इस अनिश्चितता के दौर में आपूर्ति शृंखला में बाधा से बचने का एकमात्र उपाय 'आत्मनिर्भरता' है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 16 मार्च, 1951

भविष्य की चिन्ता

बजट की बहस में हुई आलोचनाओं के बाद प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री के जो भाषण हुए, उनमें निराशा के बजाय आशा और स्थिति की गंभीरता को न छिपाते हुए भी दृढ़ता के साथ उसमें से रास्ता निकालने की चेष्टा की ऐसी छाप पड़ती है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। नेहरूजी तथा देशमुख दोनों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि आज हमारे देश की स्थिति चिन्ताजनक है। देश में फैले हुए भ्रष्टाचार तथा अन्य दोषों की भी किसी ने उपेक्षा नहीं की, परन्तु यह सोचने पर जोर दिया कि 'किस हद तक इनका कारण हमारी अपनी त्रुटियां हैं और किस हद तक संसार की परिस्थितियां। और जो समस्याएं हैं, उन्हें 'क्रियात्मक ढंग से, निश्चित एवं नपा-तुला कदम उठाकर' हल करने की प्रेरणा की। साथ ही अपने को आज में ही न भुलाकर कल यानी भविष्य की भी सुध लेने पर जोर दिया। 'जहांतक मेरा संबंध है, मैं आज की अपेक्षा कल को कुछ ज्यादा महत्व देता हूं।' यह बताते हुए दूरन्देश की तरह प्रधानमंत्री नेहरूजी ने कहा कि 'अगर हमें देश की उन्नति करनी है, तो उस आनेवाले कल के लिए बुनियाद डालनी होगी और वह भी मजबूत बुनियाद, चाहे प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां ही क्यों न हों।' और वित्तमंत्री देशमुख ने भी विकास यानी भावी उत्थान के लिए अपनी संतति के हितार्थ अपने पर अंकुश लगाने का ही प्रतिपादन किया है। इस प्रकार, उन्होंने बताया, बजट को आज की दृष्टि से नहीं, बल्कि कल की दृष्टि से देखा जाना चाहिए- और, इस रूप में, उन्होंने कहा, वह निराशाजनक के बजाय आशाप्रद ही है।

बजट पर बोलनेवालों की मुख्य-मुख्य आलोचनाओं का अपने-अपने ढंग से दोनों ने जवाब दिया और बताया कि प्रत्यक्ष करों द्वारा आय की गुंजाइश अधिक नहीं है, अनिवार्य बचत के साथ ऋण या स्वेच्छया बचत के परम्परागत तरीके नहीं चल सकते, कुछ लोगों के खराब होने के कारण सभी कर्मचारियों को खराब कहने से लाभ के बदले यह हानि ही संभव है कि अच्छे भी बुरे बन जाएं, इसलिए आलोचना विध्वंसक के बजाय रचनात्मक होनी चाहिए, साथ ही प्रयत्न अधिक उत्पादन द्वारा श्रीवृद्धि का होना चाहिए। अगर तरक्की अभीष्ट है, नेहरूजी ने कहा, तो कोई भी शासन-प्रणाली क्यों न हो, देश को पैसा तो बचाना ही होगा।

बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता

रसोई गैस को लेकर मचे हाहाकार और उससे जुड़ी परेशानियों को लेकर प्रशासन की तरफ से दोहरी बात क्यों कही जा रही है? एक ओर, दावा किया जाता है कि देश में गैस-तेल की कोई कमी नहीं, वहीं दूसरी ओर, गैस बुकिंग को लेकर गांव में 45 दिन और शहरों में 25 दिन निर्धारित कर दिए जाते हैं। ऐसे में, जनता आखिर क्या करे? जब बुकिंग की हालत पूर्व जैसी होती, तो शायद अभी जो गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वह नहीं मचता। अगर यह दावा सच है कि गैस-तेल की किल्लत नहीं है, तो फिर गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव क्यों किया गया है? बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। लोगों में उलझन और चिंता इन्हीं वजहों से अधिक है। स्थिति को पहले की भांति करने के लिए सरकार लोगों में भरोसा पैदा करे। इसके लिए उनको सबसे पहले सच बताना चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण देश में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता का माहौल बन गया है। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में भोजन सेवा अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी, वहीं अयोध्या में निःशुल्क भोजन कराने वाली 'राम रसोई' को भी गैस की अनिश्चित उपलब्धता के कारण बंद करना पड़ा। रेलवे की खानपान सेवा भी प्रभावित हुई है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने कैटरिंग इकाइयों को माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का कांच उद्योग गैस आपूर्ति में बाधा के कारण उत्पादन कम करने को मजबूर हुआ है। कई कारखानों में 30 से 40 प्रतिशत तक उत्पादन घटा दिया गया है। इसी तरह, पंजाब में गैस संकट का मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया है और व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग ठप होने से उद्योग व व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर उर्वरक उत्पादन करने वाले संयंत्रों में गैस की कमी से यूरिया उत्पादन रुक गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में गैस एजेंसियों के सामने लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इंदौर और भोपाल में बुकिंग प्रणाली बाधित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय संकट लंबे समय तक चलता है, तो ऊर्जा के अन्य साधनों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। लिहाजा, मौजूदा परिस्थिति हमें यह सबक भी दे रही है कि हमें अपने ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

गैस संकट

विपक्ष द्वारा फैलाई अफवाह से बढ़ा संकट

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। युद्ध जैसे हालात तो और भी ज्यादा। इसीलिए सभी राष्ट्र अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनाते हैं, जिसका समर्थन प्रत्येक नागरिक द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक भी है कि युद्ध के समय हर राजनीतिक दल व नागरिक तमाम मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र की नीतियों का स्वागत करें और अपने देश के साथ दृढ़ता से खड़े रहें। भारत का दुर्भाग्य है कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के कारण सत्ता से बेदखल किए गए राजनीतिक दल सरकार को बदनाम करने और देश में अराजकता फैलाने का कोई अवसर नहीं चूकना चाहते। वे साथ देने के बजाय सरकार को अस्थिर करने का ही प्रयास करते रहते हैं और अपने शासनकाल की अव्यवस्थाओं को भूलकर अफवाह फैलाने में जुट जाते हैं। इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में आए व्यवधान को देश का विपक्ष आपदा में अवसर समझ रहा है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा न होता, तो अचानक एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी की अफवाह फैलाकर लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर कतार में न खड़ा कराया जाता; विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार-विरोधी विमर्श का प्रसार न करता। हालांकि, मुद्दा सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों व गैस की कथित किल्लत को बढ़ा-चढ़ाकर जनता को भ्रमित करने तक सीमित नहीं है। मुद्दा यह भी है कि जब एकजुट होकर अप्रत्याशित आपदा का सामना करने का समय हो, तब विपक्ष द्वारा देश में अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाना कितना उचित है?

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध के कारण हमारे देश में कच्चे तेल सहित कई जरूरी सामग्रियों की आवाजाही बाधित हो रही है। ऐसे में, सरकार का साथ देने के बजाय संसद में विपक्ष बार-बार आलोचना में जुटा है। जब सरकार गैस, तेल व अन्य आवश्यक सामग्रियों की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात प्रयास कर रही हो, तब इस तरह लोगों को भ्रमित करना उचित नहीं। देश में किसी को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने जरूरी कदम भी उठाए हैं। इसलिए विपक्ष को सहयोग करना चाहिए और लोगों तक राहत पहुंचाने में सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देश और जनता की भलाई की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष, दोनों की है। मात्र आलोचना करना विपक्ष का काम नहीं, बल्कि संकट के समय उसे सत्ता का सहयोग भी करना चाहिए।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष के चलते 150 डॉलर प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर तक उछल सकते हैं क्रूड के दाम

कच्चा तेल निवेश के हर मोर्चे पर तेज झटका देगा

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से निवेशकों को हर मोर्चे पर बुरी तरह झटका लगा है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब सभी निवेश विकल्पों (एसेट क्लास) में एक साथ गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण कच्चे तेल के बेतहाशा चढ़ते दाम हैं। यदि कच्चा तेल 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा तो निवेशकों का जोखिम और बढ़ सकता है।

मध्य-पूर्व में जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल के दाम चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। संघर्ष शुरू होने के समय यह 72.48 डॉलर प्रति बैरल था, जो नौ मार्च को 65 फीसदी उछलकर 119.40 डॉलर पहुंच गया था। हालांकि, बाद में कीमतों में कुछ गिरावट आई लेकिन यह एक बार फिर 100 डॉलर के पार निकल गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि होर्मुज जलमार्ग पर आपूर्ति चार से आठ सप्ताह तक बाधित रहती है तो तेल की कीमत 110 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए शेयर बाजार में भारी गिरावट जारी रहने और महंगाई उछलने का दोहरा संकट खड़ा हो सकता है।

निवेश जोखिम बढ़ा : मध्य-पूर्व और अन्य क्षेत्रों में बढ़े संघर्ष ने कई वित्तीय निवेश विकल्पों में उतार-चढ़ाव बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय निवेशकों को तेज झटका लग रहा है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, कच्चे तेल से जुड़े क्षेत्र, मुद्रा बाजार, बॉन्ड और कुछ कमोडिटी में युद्ध की वजह से जोखिम काफी अधिक बढ़ गया है। सबसे बड़ा असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। जब भी वैश्विक स्तर पर युद्ध या तनाव बढ़ता है तो निवेशक जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। इसके कारण शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ जाती है। आंकड़ों के अनुसार, इस महीने विदेशी संस्थागत निवेशक (एफपीआई) भारतीय बाजार में करीब 52,704 करोड़ रुपये की बिकवाली कर चुके हैं। उभरते बाजारों की तुलना में भारत से कमजोर रिटर्न की वजह से भी एफपीआई की दिलचस्पी कम हुई है।

किस पर कितना व्यापक असर

1 शेयर बाजार
मार्च में अब तक घरेलू बाजार आठ फीसदी तक लुढ़क गए हैं। पिछले हफ्ते पांच फीसदी से अधिक की गिरावट आई थी। कई सालों बाद किसी एक हफ्ते में बाजार इतना गिरा है। इससे पहले 2020 में कोविड की शुरुआत में तेज गिरावट आई थी। विशेष रूप से ऑटो, बैंकिंग, मेटल और कंज्यूमर सेक्टर के शेयरों पर ज्यादा बिकवाली हुई है।
आगे की संभावना : यदि होर्मुज जलमार्ग अगले 10 दिनों तक बंद रहता है, तो कच्चा तेल 150 डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में भारत समेत वैश्विक शेयर बाजारों में करीब 10% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है।

2 म्यूचुअल फंड संघर्ष का सीधा असर म्यूचुअल फंड पर भी दिख रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में करीब 65.7 लाख नए एसआईपी खाते खुले, लेकिन लगभग 49.7 लाख बंद भी हो गए। इससे एसआईपी स्टॉपेज अनुपात बढ़कर करीब 76% तक पहुंच गया है।
आगे की संभावना : इक्विटी फंड में तेज उतार-चढ़ाव के कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो का निवेश घट सकता है।

3 सोना-चांदी
पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बावजूद सोने-चांदी की कीमतें गिर गई हैं। फरवरी के आखिर से अब तक सोना करीब छह फीसदी और चांदी नौ फीसदी तक टूट चुकी है। इसका प्रमुख कारण डॉलर में आई मजबूती है। कच्चे तेल का कारोबार ज्यादातर डॉलर में होता है, इसलिए इसके दाम उछलने से डॉलर की मांग बढ़ जाती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ता है।
आगे की संभावना : फिलहाल बाजार का पैसा डॉलर, बॉन्ड और तेल से जुड़े निवेश विकल्प में ज्यादा जा रहा है। हालात बिगड़ने पर सोने-चांदी में तेज उतार-चढ़ाव आ सकता है।

दुनियाभर के बाजार टूटे

ईरान पर हमले के बाद से दुनिया के बाजार में भारी गिरावट का दौर जारी है। पिछले हफ्ते निफ्टी पांच फीसदी से ज्यादा टूटा था।

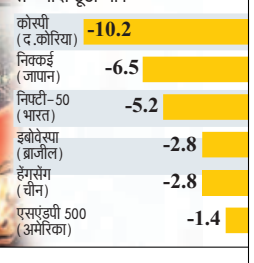

4 कमजोर रुपया
कच्चा तेल उछलने से डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हुआ है। 13 मार्च को यह 92.43 के सबसे निचले स्तर पर आ गया। मार्च में रुपया करीब 1.5 फीसदी कमजोर हो चुका है। अगर क्रूड में तेजी जारी रहती है तो रुपया गिरकर 95 के स्तर तक जा सकता है।
आगे की संभावना : संघर्ष लंबा चला तो अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। आयात महंगा होगा। महंगाई बढ़ सकती है।

5 क्रिप्टोकरेंसी
बीते 15 दिनों में क्रिप्टो बाजार में 2-3 फीसदी गिरावट देखने को मिली है और निवेशकों को करीब दो ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। बिटकाइन 63 हजार डॉलर तक लुढ़का था लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ और यह 72 हजार डॉलर के आसपास बना हुआ है।
आगे की संभावना : यदि कच्चे तेल कीमतें गिरती हैं तो बिटकॉइन फिर तेजी पकड़ सकता है। लेकिन यदि तेल बहुत महंगा हो जाता है तो क्रिप्टो बाजार में फिर से तेज गिरावट देखने को मिल सकती है।

हर बड़े झटके से उबरे

विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले 15 सालों में भारतीय बाजार ने कई बड़े संकट और युद्ध देखे हैं। हर बार बाजार इन संकट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। कोविड संकट के दौरान भारी गिरावट देखने वाले भारतीय बाजारों ने अगले कुछ वर्षों में लगभग 21-22% तक मुनाफा दिया था।

क्या करें निवेशक

लंबी अवधि में ही लाभ मिलेगा
1 लंबे समय तक शेयर बाजार में बने रहने वाले निवेशकों को लाभ मिलता है। भारतीय बाजार लगभग 74 प्रतिशत मामलों में छह से सात वर्षों में दोगुना हुआ है और लगभग 81 प्रतिशत मामलों में दस से ग्यारह वर्षों में तीन गुना हुआ है।

जल्द निकलने पर नुकसान
2 यदि कोई निवेशक 2001 से 2025 के बीच पूरे समय बाजार में निवेशित रहा तो उसे निफ्टी-500 से औसतन 17.3% का रिटर्न मिला। लेकिन उसने केवल 10 सबसे अच्छे दिन छोड़ दिए तो रिटर्न घटकर लगभग 13.7% रह गया।

mint

बाजार 30s

रत्न-आभूषण निर्यात 3.86% बढ़ा

मुंबई। भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात फरवरी में सालाना आधार पर 3.86 प्रतिशत बढ़कर 268.07 करोड़ डॉलर (24,340.05 करोड़ रुपये) हो गया। उद्योग संगठन रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अनुसार अन्य बाजारों में विस्तार के कारण निर्यात में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई। परिषद के आंकड़ों के अनुसार, एक वर्ष पहले इसी महीने में कुल निर्यात 258.10 करोड़ डॉलर (22,460.13 करोड़ रुपये) रहा था। अप्रैल, 2025 से फरवरी, 2026 के दौरान कुल रत्न एवं आभूषण निर्यात लगभग स्थिर रहा।

अमेरिकी जांच में चीन पर होगी कड़ी नजर

नई दिल्ली। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) का मानना है कि अमेरिका द्वारा 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ शुरू की गई जबरिया मजदूरी के व्यवहार की दूसरी 'व्यापार जांच' में चीन पर खास नजर रखी जाएगी। इन देशों में चीन के अलावा भारत भी शामिल है। जीटीआरआई ने कहा कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र में कथित रूप से जबरिया मजदूरी कराए जाने के आरोप लगे हैं।

नई श्रम संहिताओं से रोजगार बढ़ेगा : रिपोर्ट

नई दिल्ली। लगभग 75 प्रतिशत कंपनियों को उम्मीद है कि नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद निश्चित अवधि वाले रोजगार में वृद्धि होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह बदलाव कार्यबल के औपचारिककरण की दिशा में एक बड़ा संकेत है। मानव संसाधन समाधान प्रदाता जीनियस एचआरटेक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यबल के औपचारिककरण की ओर झुकाव स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है।

वेदांता लिमिटेड 2,575 करोड़ रुपये जुटाएगी

नई दिल्ली। वेदांता लिमिटेड संस्थागत निवेशकों की ओर से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) निर्गम के जरिये करीब 2,575 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जैसे संस्थागत निवेशकों की ओर से जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है।

आईपीओ के नियमों में संशोधन किया

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कंपनियों के न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम से संबंधित नियमों में संशोधन किया है और इसे निर्गम के बाद की पूंजी से जोड़ दिया है। प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 के अनुसार, जिन कंपनियों की निर्गम के बाद की पूंजी ₹1,600 करोड़ से अधिक और ₹5,000 करोड़ से कम है, उन्हें तीन साल के भीतर सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत करनी होगी।

अनचाही रोबोटिक कॉल आने पर जुर्माना लगेगा

प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। मोबाइल पर आने वाली अनचाही कॉल और एसएमएस की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि अगर किसी टेलीकॉम नेटवर्क से बड़ी संख्या में स्पैम कॉल या रोबोटिक कॉल की जाती हैं, तो उस नेटवर्क के ऑपरेटर से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

ट्राई के अनुसार तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ स्पैम कॉल और मैसेज की समस्या तेजी से बढ़ी है। कई कंपनियां बड़ी संख्या में स्वचालित प्रचार कॉल (रोबोटिक कॉल) का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे मोबाइल उपभोक्ताओं को बार-बार अनचाही कॉल मिलती हैं।

दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई का यह भी कहना है कि अगर किसी कंपनी के नेटवर्क से 1400 या 1600 सीरीज के अलावा अन्य नंबरों से बड़े पैमाने पर प्रचार कॉल या रोबोकॉल की जाती हैं तो उस कॉल के लिए संबंधित ऑपरेटर को प्रति मिनट पांच पैसे का टर्मिनेशन चार्ज देना होगा। वर्तमान में देश में घरेलू वॉइस कॉल पर कोई टर्मिनेशन शुल्क नहीं लिया जाता है। नियामक ने यह भी कहा है कि अगर कोई कंपनी प्रमोशनल एसएमएस के लिए गलत हेडर या कंटेंट टेम्पलेट का पंजीकरण करती है तो उस पर दंड लगाया जा सकता है।

एआई से होगी पहचान

ट्राई ने स्पैम कॉल की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। अभी कंपनियां एआई के जरिए ग्राहकों को संदिग्ध स्पैम कॉल के बारे में चेतावनी देती हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत ऐसे मामलों में कंपनियों को स्पैम भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। यदि किसी नंबर को पिछले 10 दिनों में एआई सिस्टम ने संदिग्ध स्पैमर के रूप में चिन्हित किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए अब तीन उपभोक्ता शिकायतें ही पर्याप्त होंगी। पहले इसके लिए पांच शिकायतों की जरूरत होती थी।

लाखों करदाताओं ने रिफंड दावे सुधारे

नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर विभाग की चेतावनी के बाद करीब 50 लाख करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न में सुधार किया है। इसके कारण सरकार को दिए जाने वाले रिफंड दावों में करीब 2,000 करोड़ रुपये की कमी आई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, पिछले साल विभाग ने कई ऐसे मामलों की पहचान की थी, जिनमें करदाताओं ने गलत या फर्जी कटौती (डिडक्शन) का दावा किया था। इसके बाद विभाग ने लोगों को अपने रिटर्न की दोबारा जांच करने का संदेश भेजा।

विदेश से सोना मंगवाना सस्ता हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोने की आयात आधार कीमत में कटौती कर दी है। नई दर के अनुसार अब सोने की आयात आधार कीमत 1664 डॉलर प्रति 10 ग्राम से घटकर 1652 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गई है। सरकार के इस फैसले से ज्वैलर्स, सोना व्यापारियों और ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है।

सोने की कीमतों में पिछले कुछ समय से चल रहे तेज उतार-चढ़ाव के बीच यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। आयात आधार कीमत वह तय मानक होता है, जिसके आधार पर सरकार सोने के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क और अन्य करों की गणना करती है। जब यह कीमत घटाई जाती है तो आयात करने वाले व्यापारियों पर कर का बोझ कुछ कम हो जाता है।

चांदी पर शुल्क बढ़ा : वहीं, सरकार ने चांदी की आयात आधार कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। यह कीमत 20 डॉलर प्रति किलो बढ़ाकर 2,800 डॉलर से 2,820 डॉलर कर दी गई है। इस कदम से आयातित चांदी की लागत बढ़ सकती है। सरकार समय-समय पर यह कीमत बदलती रहती है।

घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है असर

हाल के दिनों में वैश्विक बाजार में कीमतों और रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण सोने का आयात महंगा हो रहा था। कीमत घटने से आयातकों की लागत कम हो सकती है, जिसका असर बाजार में सोने के दाम पर भी पड़ सकता है। ज्वैलर्स और सोना कारोबारी नई कीमत के आधार पर अपने दामों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि इसी कीमत के आधार पर कर तय किया जाता है।

कम मात्रा में सोने का वायदा कारोबार आज से

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) सोमवार से कम मात्रा में सोने में ट्रेडिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कमोडिटी श्रेणी में 10 ग्राम सोने के वायदा अनुबंध (गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट) उपलब्ध होंगे। इस सुविधा से अब छोटे निवेशक भी छोटे आकार के गोल्ड अनुबंध में कारोबार कर सकेंगे।

एक्सचेंज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि निवेशकों के लिए नया उत्पाद तैयार है। इस अनुबंध में सोमवार से शुक्रवार तक कारोबार होगा, जिसका समय सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक रहेगा। इस व्यवस्था के तहत 10 ग्राम सोने की डिलीवरी लेना पूरी तरह अनिवार्य रहेगा। डिलीवरी केंद्र अहमदाबाद में तय क्लियरिंग हाउस सुविधा पर होगा। सोने की गुणवत्ता 99.9% शुद्धता की होगी और यह मान्यता प्राप्त सप्लायर द्वारा दिया जाएगा। अनुबंध की कीमत अहमदाबाद के भाव पर तय होगी, जिसमें सीमा शुल्क तो शामिल होगा, लेकिन जीएसटी का भुगतान अलग से करना होगा। अधिकतम ऑर्डर साइज 10 किलोग्राम तय किया गया है।

एनएसई का यह नया वायदा अनुबंध हर महीने की श्रृंखला में उपलब्ध होगा। इसका कारोबारी चिह्न 'गोल्ड10जी' तय किया गया है। हर महीने के आखिरी कैलेंडर दिन इस अनुबंध की समाप्ति होगी।

छोटे निवेशकों को फायदा

वर्तमान में एमसीएक्स पर सोने के वायदा कारोबार में प्रत्येक लॉट के जरिए एक किलोग्राम और 100 ग्राम की मात्रा (एक लॉट) से ट्रेडिंग की जा सकती है। इसके लिए निवेशकों को मोटा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। इससे कई छोटे निवेशक टेडिंग से वंचित रह जाते हैं। उन्हें राहत देने के लिए 10 ग्राम की मात्रा पेश की गई है।

क्या है वायदा कारोबार

सोने का वायदा कारोबार यानी ऐसा सौदा जिसमें निवेशक उसी दिन ही तय कर लेते हैं कि भविष्य में किसी तय तारीख पर सोना किस कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे। इसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में लोग असल सोना नहीं लेते। वे सिर्फ कीमत के अंतर से फायदा या नुकसान कमाते हैं।

पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (ओएमसी) देश की रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयातित दरों से कम कीमत पर देने पर विचार कर रही हैं। इस कदम का उद्देश्य ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करने की वजह से हो रहे घाटे को कम करना है।

सूत्रों ने बताया कि ओएमसी अब रिफाइनरी हस्तांतरण शुल्क (आरटीपी) पर रोक लगाने या उस पर छूट तय करने के विकल्प पर विचार कर रही हैं। आरटीपी वह आंतरिक कीमत होती है, जिस पर रिफाइनरियां अपने विपणन खंड को ईंधन बेचती हैं। इस कदम का मकसद रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयात-समता लागत से कम भुगतान करना है।

एक अप्रैल से वार्षिक फास्टैग पास 75 रुपये महंगा होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वार्षिक फास्टैग पास योजना की फीस में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पास की कीमत अब 3,075 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि अभी तक इसकी फीस 3,000 रुपये थी।

नई दर 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के तहत इस वार्षिक पास की फीस में हर वर्ष संशोधन किया जा सकता है और इसी प्रक्रिया के अनुसार इस बार मामूली बढ़ोतरी की गई है। फास्टैग वार्षिक पास देश के लगभग 1,150 टोल नाकों पर मान्य है। इस सुविधा के अंतर्गत निजी वाहन मालिक एकमुश्त राशि जमा कर एक वर्ष की अवधि या 200 बार टोल पार करने तक बिना बार-बार फास्टैग रिजार्च किए टोल का भुगतान कर सकते हैं। यह पास केवल गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है। इस पास को 'राजमार्ग यात्रा' ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खरीदा जा सकता है।

- **वित्त वर्ष 2026-27 में पास 3,075 रुपये में मिलेगा, अभी यह तीन हजार में मिल रहा है**

जेन-जी पीढ़ी सबसे अधिक खर्च करेगी

रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में जेन-जी पीढ़ी आने वाले वर्षों में देश के उपभोक्ता बाजार को तेजी से बदल सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक यह पीढ़ी देश की आबादी का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा होगी और करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 108 लाख करोड़ रुपये) का खर्च करेगी।

बाजार शोध संस्था रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग जेन-जेड पीढ़ी में आते हैं। यह पीढ़ी खरीदारी करते समय नए अनुभव, स्टाइल, सुविधा और डिजिटल सेवाओं को ज्यादा महत्व देती है। इनकी खास दिलचस्पी सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में है।

अनुमान है कि 2030 तक इस क्षेत्र में जेन-जी का बाजार लगभग 19 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। हर दो में से एक जेन-जी महिला अपनी आय का 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा ब्यूटी और पर्सनल केयर उत्पादों पर खर्च करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि युवा पुरुष भी अपनी देखभाल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पिछले पांच साल में पुरुषों की स्किन केयर रूटीन से जुड़ी इंटरनेट खोज में 850 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।

फैशन बाजार पर भी असर

जेन-जी का असर फैशन उद्योग पर भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक फैशन बाजार का करीब आधा हिस्सा इसी पीढ़ी से प्रभावित होगा। हालांकि यह पीढ़ी महंगे ब्रांड की बजाय 1,000 रुपये से कम कीमत वाले फैशन उत्पाद ज्यादा पसंद करती है। ऑनलाइन फैशन वेबसाइटों पर जेन-जेड सबसे बड़ा ग्राहक समूह बन चुकी है।

फिटनेस और स्वस्थ खानपान की ओर झुकाव

जेन-जी में फिटनेस का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस पीढ़ी के करीब एक-तिहाई लोग अपनी आय का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा फिटनेस और खेल गतिविधियों पर खर्च करते हैं। वहीं, नियमित व्यायाम करने वाले लगभग 40 प्रतिशत युवा वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों को अपनाना पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2025 के बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोटीन सप्लीमेंट की बिक्री में 230 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कारोबारी चर्चा

कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव

बीएसई और एनएसई के मेनबोर्ड पर सूचीबद्ध हुआ इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड(INA Solar) का शेयर

सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड (INA Solar) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपने 1 रुपये अंकित मूल्य के 22,03,94,625 इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के मेनबोर्ड पर सफलतापूर्वक सूचीबद्ध कर लिया। कंपनी के शेयर दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर कारोबार के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इस अवसर पर जयपुर में आयोजित

समारोह में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि, जयपुर के पूर्व सांसद श्री रामचरण बोहरा विशिष्ट अतिथि तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ मैनेजर श्री जसवंत जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कृष्णा'ज हर्बल एंड आयुर्वेदा ने शुरू किया एक सशक्त जागरुकता अभियान - She Needs Care

महिला दिवस के अवसर पर, कृष्णा'ज हर्बल एंड आयुर्वेदा ने गर्व के साथ अपना भावनात्मक जागरुकता अभियान "She Needs Care" लॉन्च किया है। यह पहल विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कड़े इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना है जब महिलाएं सभी का ख्याल रखती हैं, तो उनका ख्याल कौन रखता है? हार्मोनल असंतुलन, अनियमित पीरियड्स, बालों का झड़ना। लगातार पिंपल्स, 35 के बाद कम ऊर्जा, मूड स्विंग्स, इन समस्याओं को अक्सर 'सामान्य' कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। महिलाओं को यह सिखा दिया जाता है कि असुविधा सहना, थकान को सामान्य मान लेना और अपनी सेहत को टालना ही उनकी ताकत है। "She Needs Care" अभियान इसी सोच को चुनौती देता है।

The Kerala Files फिल्म 2250 स्टाफ के लोगों को आचार्य मनीष जी द्वारा दिखाई गई

समाज में जागरुकता फैलाने और बच्चों के भविष्य को लेकर सही सोच विकसित करने के उद्देश्य से Jeena Sikho कंपनी के संस्थापक आचार्य मनीष के द्वारा फिल्म "The Kerala Files 2" कंपनी के सभी स्टाफ को निःशुल्क दिखाई गई इस दौरान फिल्म देखने आए सभी कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था आचार्य मनीष जी की ओर से की गई। फिल्म के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि माता-पिता और समाज को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सजग रहना कितना

आवश्यक है। यह फिल्म Cosmo Mall, Zirakpur में दिखाई गई। इसके लिए 3 दिनों के लिए पूरा थिएटर Jeena Sikho कंपनी द्वारा बुक किया गया है, जहां लगभग 2250 स्टाफ को यह फिल्म दिखाई गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्नलिखित राज्य सरकार ने कुल ₹58,420/- करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए, नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री करने का प्रस्ताव किया है।

अ क्र.	राज्य/ के.प्र.	अधिसूचित राशि (₹ करोड़)	अतिरिक्त ऋण (ग्रीनशु) विकल्प राशि (₹ करोड़)	अवधि (वर्षों में)	नीलामी का प्रकार
1.	असम	900	–	06	प्रतिफल आधारित
2.	छत्तीसगढ़	1,000	–	26 नवंबर 2025 को जारी 7.19% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2035 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		1,000	–	18	प्रतिफल आधारित
3.	गोवा	100	–	11	प्रतिफल आधारित
4.	गुजरात	1,000	500	08	प्रतिफल आधारित
		1,000	500	09 वर्ष और 06 महीने	प्रतिफल आधारित
5.	हरियाणा	1,000	–	16	प्रतिफल आधारित
		1,000	–	19	प्रतिफल आधारित
6.	जम्मू और कश्मीर	1,000	–	20	प्रतिफल आधारित
7.	झारखंड	1,000	–	06	प्रतिफल आधारित
		1,000	–	10	प्रतिफल आधारित
		1,000	–	14	प्रतिफल आधारित
8.	कर्नाटक	2,000	–	27 मार्च 2024 को जारी 7.44% कर्नाटक एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		2,000	–	13 मार्च 2024 को जारी 7.36% कर्नाटक एसजीएस 2034 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		2,000	–	06 मार्च 2024 को जारी 7.42% कर्नाटक एसजीएस 2035 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		2,000	–	11 मार्च 2026 को जारी 7.44% कर्नाटक एसजीएस 2036 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		2,000	–	04 मार्च 2026 को जारी 7.54% कर्नाटक एसजीएस 2039 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
9.	केरल	2,000	–	22	प्रतिफल आधारित
		1,500	–	27	प्रतिफल आधारित
10.	मध्य प्रदेश	2,100	–	09	प्रतिफल आधारित
		2,000	–	15	प्रतिफल आधारित
11.	महाराष्ट्र	1,500	500	04	प्रतिफल आधारित
		2,000	500	03 दिसंबर 2025 को जारी 7.43% महाराष्ट्र एसजीएस 2040 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		1,000	–	04 मार्च 2026 को जारी 7.66% महाराष्ट्र एसजीएस 2047 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		1,000	–	04 मार्च 2026 को जारी 7.66% महाराष्ट्र एसजीएस 2052 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
12.	नागालैंड	600	–	04	प्रतिफल आधारित
13.	पुडुचेरी	150	–	15	प्रतिफल आधारित
14.	राजस्थान	1,200	–	10	प्रतिफल आधारित
15.	सिक्किम	250	–	10	प्रतिफल आधारित
16.	तमिलनाडु	2,000	–	05 वर्ष और 06 महीने	प्रतिफल आधारित
		1,000	–	07	प्रतिफल आधारित
		2,000	–	09	प्रतिफल आधारित
		1,000	–	11 मार्च 2026 को जारी 7.41% तमिलनाडु एसजीएस 2036 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		2,000	–	12	प्रतिफल आधारित
17.	तेलंगाना	540	–	19	प्रतिफल आधारित
		1,000	–	28	प्रतिफल आधारित
		1,000	–	30	प्रतिफल आधारित
18.	त्रिपुरा	580	–	15	प्रतिफल आधारित
19.	उत्तर प्रदेश	1,500	–	12	प्रतिफल आधारित
		1,000	–	11 फरवरी 2026 को जारी 7.81% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2041 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
		1,500	–	18	मूल्य आधारित
		1,000	–	25 फरवरी 2026 को जारी 7.71% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2046 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
20.	उत्तराखंड	2,000	–	18 फरवरी 2026 को जारी 7.58% उत्तराखंड एसजीएस 2038 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
21.	पश्चिम बंगाल	2,000	–	19	प्रतिफल आधारित
		2,000	–	23	प्रतिफल आधारित
	कुल	58,420			

यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) पर एकाधिक मूल्य पद्धति में **17 मार्च 2026 (मंगलवार)** को आयोजित की जाएगी। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल **(https://rbiretaildirect.org.in)** के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट **(wwww.rbi.org.in)** पर **13 मार्च 2026 (शुक्रवार)** की प्रेस प्रकाशनी देखें।

''पैसे का वादा करने वाले ई-मेल/एसएमएस/कॉल द्वारा धोखा न खाएं''

संपादकीय जागरण

सोमवार, 16 मार्च, 2026 : चैत्र कृष्ण - 12 वि. 2082

संकल्प का विकल्प नहीं होता

चुनावी बिगुल

चार राज्यों-असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही यह प्रश्न सतह पर आ गया कि इन राज्यों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को क्या दशा-दिशा प्रदान करेंगे? इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव यह भी बताएंगे कि अपने-अपने राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान प्रभावी साबित होगा या नहीं? यह बहुत कुछ राज्य सरकारों के कामकाज के प्रति आम जनता के रवैये पर निर्भर करेगा। आम तौर पर सभी सरकारों को कुछ न कुछ सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो सरकारें लंबे समय तक सत्ता में रहती हैं, उनके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान के प्रभावी होने के आसार बढ़ जाते हैं। इस दृष्टि से तीसरा कार्यकाल पूरा कर रही बंगाल की तृणमूल सरकार और अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहीं केरल की वाम मोर्चा सरकार और असम की भाजपा सरकार प्रमुख हैं। इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भी परीक्षा लेंगे। इनमें प्रमुख हैं भाजपा एवं कांग्रेस। वैसे तो केरल में वाम मोर्चे की सरकार का नेतृत्व कर रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, लेकिन उसकी हैसियत क्षेत्रीय दल सरीखी रह गई है।

यदि असम में भाजपा के सत्ता में पुनः आने की संभावना है तो केरल में कांग्रेस के लिए भी कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस राज्य में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। वह गुटबाजी से भी ग्रस्त है। कांग्रेस असम में भी भाजपा को चुनौती देने का प्रयत्न करेगी, लेकिन यहां भी उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं। अभी हाल में उसके एक प्रमुख नेता भाजपा में शामिल हो गए। तमिलनाडु में भी कांग्रेस कुल मिलाकर सत्तारूढ़ डीएमके के रहमोकरम पर ही है। डीएमके उसे 25-30 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं। तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में गठबंधन सरकार है, जिसमें भाजपा भी शामिल है। फिलहाल उसके समक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं, लेकिन चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि यहां किसकी सरकार बनती है। राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे ही अधिक प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी अपना असर दिखाते हैं। एसआइआर का मुद्दा सभी गैर-भाजपा शासित राज्यों में गर्म हो सकता है। बंगाल में तो इसे तृणमूल कांग्रेस की ओर से विशेष रूप से उभारा जाएगा। इसके जवाब में भाजपा यहां घुसपैठियों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी, लेकिन यह समय ही बताएगा कि वह वांछित सफलता हासिल कर पाएगी या नहीं? इन चुनावों की एक अच्छी बात यह है कि बंगाल में दो चरणों में और अन्य सभी में एक चरण में मतदान होगा।

स्वागतयोग्य पहल

यमुनापार के तीन प्रमुख अस्पतालों को मिलकर एम्स जैसा एक स्वायत्त संस्थान बनाने संबंधी दिल्ली सरकार का निर्णय स्वागतयोग्य है। इसे एक सार्थक पहल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जीटीबी अस्पताल और दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट पर मरीजों का भारी दबाव है, वहीं राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि इन तीनों अस्पतालों का एकीकरण करने से इन अस्पतालों में मौजूद संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाओं के साथ अच्छा इलाज भी मिल सकेगा।

> अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम हो और उनके संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, ताकि दिल्ली में मरीजों को बेहतर इलाज मिले

दिल्ली में ऐसे कई अस्पताल हैं, जिनके संसाधनों पर मरीजों का खासा दबाव है। वहीं, कई अस्पताल ऐसे भी हैं जिनमें संसाधन तो हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से इनमें मरीजों की संख्या कम है। ऐसे में दिल्ली सरकार की ये पहल इन अस्पतालों के संसाधनों के समुचित इस्तेमाल की उम्मीद जगाती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसके अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्ता वाला इलाज मिलना ही चाहिए। ये तभी संभव है, जब अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम हो और उनके संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या होर्मुज से भारतीय जहाजों का निकलना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है?

आज का सवाल

क्या पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर दिखाएंगे?

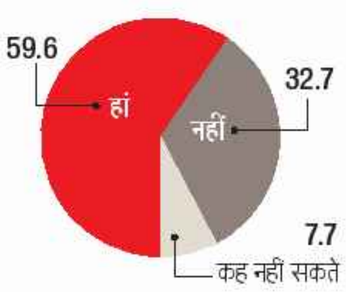

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

ईरान की अडिग रहने की रणनीति

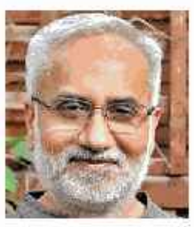

शिवकांत शर्मा

ईरान का इरादा लड़ाई को जितना ले सके, उतना फैलाना और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का गला दबाना है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि यह सोचते थे कि शीर्ष नेतृत्व के खत्म हो जाने और पंद्रह दिनों की भीषण बमबारी झेलने के बाद ईरान हाथ खड़े कर देगा तो वह शायद उनकी भूल थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मिसाइल हमले में मारे जाने के बाद उनकी गद्दी पर बैठे उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले ही संदेश में खून का बदला खून से लेने का एलान करते हुए पड़ोस के खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि वे अपने यहां बने अमेरिकी अड्डों को बंद करें। हालांकि उनके संदेश की जिस बात ने पूरी दुनिया के बाजारों और कारोबारों में हड़कंप मचाया वह दुश्मनों को मात देने के लिए होर्मुज जलमार्ग का हथियार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में था। दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस इसी मार्ग से होकर जाता है, जिसका 60 प्रतिशत से अधिक चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और हिंदचीन के देशों को जाता है।

हड़कंप को शांत करने के लिए ट्रंप ने लड़ाई के लगभग पूरा हो जाने की बातें कीं। ईरान को धमकी दी कि होर्मुज बंद किया तो बीस गुना भीषण हमले झेलने होंगे। कभी होर्मुज से जाने वाले जहाजों का बीमा करने की बात उछाली। कभी जहाजों के अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा देने की बातें कीं। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने आपात रिजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की घोषणा की। साथ में ट्रंप ने रूस के जहाजों पर लदे करीब 35-40 करोड़ बैरल तेल की बिक्री से एक महीने के लिए प्रतिबंध हटा लिए, लेकिन जहाजों पर ईरान के छिटपुट हमलों और उसकी धमकी से फैले आतंक के सामने किसी घोषणा की एक न चली। होर्मुज से जहाजों का यातायात लगभग ठप रहा और कच्चे तेल के दाम 100 डालर प्रति बैरल पार कर गए।

अमेरिका और इजरायल का दावा है कि उन्होंने ईरान की हवाई, नौसैनिक और मिसाइल निर्माण एवं मारक क्षमता खत्म कर दी है। शीर्ष नेतृत्व मारा जा चुका है, इसलिए देश में कोई व्यवस्था नहीं बची है, मगर उनके ये दावे जमीनी हकीकत पर खरे नहीं उतरते। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की संख्या घटी जरूर है, पर हमले जारी हैं और इजरायल, अमेरिका एवं खाड़ी के देशों के सुरक्षा कवचों को भेद भी रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अराघची के बयानों और हावभाव में किसी तरह की घबराहट या चिंता दिखाई नहीं दे रहीं। मोजतबा खामेनेई के चुनाव को लेकर अवश्य 88 मुजाहिदों की मजलिस-ए-रहबरी के बीच कुछ विवाद होने की खबरें हैं, क्योंकि इस्लामी क्रांति का मकसद

अवधेश राजपूत

वंशवादी राजशाही को हटाकर ऐसी मुल्लाशाही स्थापना करना था जिसके नेता का चुनाव योग्यता के आधार हो। मोजतबा खामेनेई का चुना जाना वंशवाद का ही प्रतीक है। इसलिए चर्चा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लरिजानी मोजतबा के चुनाव से खुश नहीं हैं। मोजतबा आइआरजीसी या रेवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और गरमपंथी माने जाते हैं। इसलिए लगता है कि एक तो आइआरजीसी ने उनके चुनाव का समर्थन किया और दूसरे 28 फरवरी के हमले में घायल होने के कारण उन्हें रमजान युद्ध के योद्धा के रूप में भी पेश किया गया।

ईरानी मुल्लाशाही ने व्यवस्था का गठन इस तरह किया है कि सत्ता इस्लाम और फलस्तीनी संघर्ष में निष्ठा रखने वाले लोगों के हाथों में ही रहे। साथ ही शीर्ष नेतृत्व का सफाया हो जाने पर भी दुश्मन का प्रतिरोध और व्यवस्था चलती रहे। मोजाइक प्रतिरक्षा या रक्षा-जाल नाम की व्यवस्था का गठन आइआरजीसी के कमांडर मोहम्मद अली जफारी ने किया था। सेना की कमान को देश के तीस प्रांतों की स्वायत्त टुकड़ियों में बांट दिया गया है जो संकट की स्थिति में पहले से तय कमान के आधार पर स्वायत्त होकर अपनी-अपनी कार्रवाई करती रहती हैं। यह व्यवस्था अमेरिका और इजरायल के हमलों में केंद्रीय कमान के खत्म हो जाने पर लड़ाई और देश की व्यवस्था जारी रखने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस रणनीति को ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने हमला शुरू होने के बाद के एक इंटरव्यू में उजागर किया था।

ईरान की रणनीति लड़ाई को जितना हो सके उतना फैलाना है। साथ ही, होर्मुज जलमार्ग को हमलों के आतंक से बंद करके अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का गला दबाना है, ताकि अमेरिका और उसके मित्रों को अधिक से अधिक आर्थिक चोट पहुंचे और वे उस पर इस तरह की भूल दोबारा न करने का दबाव डालें। इसके लिए उसने सस्ते और मारक ड्रोनों और मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रखा है। उसमें से अधिकांश को नष्ट कर देने पर भी उसके पास इतनी क्षमता है कि वह कई महीनों तक छिटपुट हमले जारी रखकर आतंक बनाए रख सकता है। होर्मुज के अलावा उसके पास हूतियों की मदद से लाल सागर जलमार्ग को बंद करने का विकल्प बाकी है, जिसके जरिये वह इस युद्ध की आर्थिक चोट को और बढ़ा सकता है।

इसके विपरीत ट्रंप की रणनीति हवाई और नौसैनिक हमलों से आनन-फानन में ईरानी सेना की हवाई और नौसैनिक शक्ति, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और शीर्ष नेतृत्व को खत्म करके सत्ता परिवर्तन करने या ईरान को पश्चिम एशिया के लिए निरापद बनाकर लौट जाने की थी। उनके निरंतर बदलते वक्तव्यों को सुनकर लगता है कि यह लड़ाई उनके अनुमान से कहीं लंबी खिंच चुकी है, जिसे लेकर वे तिलमिलाए हुए हैं। लगता है ईरान ने 'चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं' के अंदाज में अपने सीमित साधनों से होर्मुज को बंद करके और खाड़ी देशों का तेल उत्पादन और यातायात ठप करके ट्रंप की दुखती रग पकड़ ली है। यदि खाड़ी का तेल उत्पादन जल्दी बहाल नहीं हुआ और होर्मुज नहीं खुला तो तेल एवं गैस के दाम और चढ़ सकते हैं। उसका असर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरें घटनी बंद हो जाएंगी, बजट बिगड़ेंगे और दैनिक खर्च की मार से नाराज लोग नवंबर के कांग्रेस और सीनेट के चुनाव में ट्रंप की पार्टी को हरा सकते हैं। कांग्रेस और सीनेट में बहुमत खोने पर ट्रंप को महाभियोगों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो न हो, पर आर्थिक संकट की वजह से अमेरिका और यूरोप के देशों में जरूर हो सकता है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

एलपीजी का विकल्प बने बायोगैस

विशाल खालदे

जैविक कचरा गैस आपूर्ति का एक घरेलू आधार बन सकता है, जिसे अवसर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है

वैश्विक तनाव से बढ़ा घरेलू आपूर्ति पर दबाव ● फाइल

दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव अब ऊर्जा बाजारों पर भी असर डाल रहा है। एलपीजी की आपूर्ति को लेकर हो रही चर्चाओं ने फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या देश को ईंधन के मोर्चे पर कुछ और घरेलू स्रोतों को मजबूत करना चाहिए? दरअसल भारत के पास पहले से ही एक ऐसा संसाधन है जिसे अक्सर केवल कचरा समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही संसाधन भविष्य में गैस आपूर्ति का एक घरेलू आधार बन सकता है। यह संसाधन है जैविक कचरा, जो खेतों से लेकर शहरों की रसोइयों तक हर जगह मौजूद है। हर साल भारत में बड़ी मात्रा में जैविक कचरा उत्पन्न होता है। इसमें खेतों से निकलने वाला फसल अवशेष, पशुओं का गोबर, शहरों का गीला कचरा और बाजारों से निकलने वाला खाद्य कचरा शामिल है। इन सबका उपयोग बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए किया जा सकता है। इस गैस का उपयोग खाना पकाने, बिजली बनाने या वाहनों को चलाने में किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवड्र्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (एसएटीएटी) योजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करना और जैविक कचरे को ईंधन में बदलना है। पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसे कई संयंत्र स्थापित किए गए हैं और उनसे गैस का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। यदि इस व्यवस्था को विस्तार दिया जाए, तो इसका प्रभाव केवल शहरों की रसोइयों तक सीमित नहीं रहेगा। यह कृषि, शहरी प्रबंधन, उद्योग और परिवहन सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है।

भारत के खेतों से हर साल लाखों टन फसल अवशेष और पशुओं का गोबर निकलता है। इन सामग्रियों को संसाधित करने के लिए बड़े बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। यदि ऐसे संयंत्र गांवों और सहकारी समितियों के माध्यम से विकसित किए जाएं, तो हर साल पर्याप्त मात्रा में गैस का उत्पादन किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकता है। गोबर और कृषि अवशेष से गैस बनाने के कुछ प्रयोग पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहले ही शुरू हो चुके हैं। किसान अपने पशुओं का गोबर या खेत का अवशेष गैस संयंत्रों तक पहुंचाते हैं और बदले में उन्हें भुगतान मिलता है। संयंत्र में बनने वाली गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि अवशेष जैविक खाद के रूप में फिर खेतों में लौट जाता है। इससे एक चक्र बनता है-कचरा खेत से निकलता है और खाद बनकर फिर खेत में लौटता है।

ऐसी संभावना शहरों में भी मौजूद है। भारतीय शहरों से सालाना छह करोड़ टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें आधे से अधिक जैविक होता है। यदि इस कचरे को अलग करके बायोगैस संयंत्रों तक पहुंचाया जाए तो काफी मात्रा में गैस तैयार की जा सकती है। इंदौर ने बेहतर कचरा प्रबंधन के साथ बायोगैस परियोजनाओं पर काम किया है, जहां गीले कचरे से ऊर्जा बनाने की पहल हुई है। जमशेदपुर में भी खाद्य कचरे को बायोगैस में बदलने के प्रयोग किए गए हैं। यदि नगर निकाय बाजारों, होटलों और घरों से गीला कचरा व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा कर उसे बायोगैस संयंत्रों तक भेजें, तो शहरों को दो लाभ मिल सकते हैं। एक तरफ कचरे की मात्रा कम होगी और दूसरी तरफ गैस का एक स्थानीय स्रोत तैयार होगा। उद्योग क्षेत्र में भी बायोगैस की भूमिका बढ़ सकती है। खाद्य प्रसंस्करण, डेरी या कपड़ा उद्योग जैसे कई छोटे और मध्यम उद्योग जैविक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। यदि ऐसे उद्योग अपने परिसर में छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित करें, तो वे अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक हिस्सा स्वयं पूरा कर सकते हैं। इससे एलपीजी या अन्य ईंधनों पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है। परिवहन क्षेत्र में भी कंप्रेस्ड बायोगैस का उपयोग बढ़ रहा है। देश में सीएनजी पर चलने वाले वाहन मौजूद हैं और उसी ढांचे में बायोगैस आधारित ईंधन का उपयोग भी किया जा सकता है। कुछ शहरों में आटो-रिक्शा और छोटे ट्रक ऐसे ईंधन का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं।

हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि बायोगैस अचानक भारत की पूरी ऊर्जा जरूरतों को बदल देगी। देश की कुल गैस मांग बहुत बड़ी है, लेकिन यदि कृषि, शहरों, उद्योगों और परिवहन में छोटे-छोटे प्रयास जुड़ते जाएं, तो उनका प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई दे सकता है। उत्साहजनक बात यह है कि अब कई छोटे, विकेंद्रीकृत और आसानी से स्थापित किए जा सकने वाले बायोगैस सिस्टम उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्लग-एंड-प्ले माड्यूलर तकनीकों के रूप में आते हैं, जो होटल, बाजार, हाउसिंग सोसायटी या छोटे उद्योगों के स्तर पर ही जैविक कचरे को गैस में बदलने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पादन का माडल धीरे-धीरे बड़े केंद्रीकृत संयंत्रों से हटकर अधिक स्थानीय प्रणालियों की ओर बढ़ सकता है। वर्तमान में भारत में जैविक कचरे का बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। खेतों में फसल अवशेष जला दिए जाते हैं, शहरों में गीला कचरा लैंडफिल में जमा हो जाता है और रसोई का कचरा शहरों के बाहर डाला जाता है, लेकिन यदि इसी कचरे को एक संसाधन के रूप में देखा जाए, तो तस्वीर काफी अलग हो सकती है। संभव है कि वही कचरा, जिसे आज समस्या माना जाता है, आने वाले समय में भारत के लिए ईंधन का एक छोटा, लेकिन स्थिर स्रोत बन जाए।

(लेखक ब्लू प्लैनेट बायोफ्यूल के संस्थापक एवं सीईओ हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

निरंतरता

जीवन की गति का सही दिशा में होने जितना ही महत्वपूर्ण है उसमें निरंतरता का होना। बिना किसी अवरोध के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास करते रहना ही सकारात्मक गति को जन्म देता है। वास्तव में निरंतरता ही वह धुरी है, जिस पर सृष्टि का चक्र टिका है। वृक्षों का फल देना, नदियों का अनवरत प्रवाह और सूर्य का निर्बाध प्रकाश-ये सभी प्रकृति की इसी निरंतरता के जीवंत प्रमाण हैं। मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाली बाधाओं के वेग को केवल निरंतरता के बल पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। चोटी पर विजय पताका फहराने के लिए आत्म-केंद्रित होना और निरंतरता का हाथ थामे रखना अनिवार्य है। लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत थोड़ा विश्राम कर पुनः अगली मंजिल का सफर तय करना ही जीवन को सच्चे अर्थों में गतिमान बनाता है, अन्यथा अवरोधों का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता।

खाली दिमाग शैतान का घर होता है और धीरे-धीरे यह खंडहर में बदल जाता है, जहां जीवनोपयोगी कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं। जिस प्रकार रुका हुआ पानी दुर्गंध पैदा करने लगता है, उसी प्रकार जीवन में आया ठहराव मनुष्य को गर्त की ओर ले जाता है। पानी की रवानी और जिंदगी की कहानी तभी सुंदर बनती है जब वे निरंतर सुखद अनुभवों के साथ प्रवाहित होती रहें। हम जिस कार्य को निरंतरता के साथ करते हैं, वह समय के साथ हमारा संघर्ष न रहकर हमारी आदत बन जाता है। हमारे शरीर के भीतर भी अनेक जैविक प्रक्रियाएं निरंतर चल रही हैं, और इसी सतत गुण के कारण हम जीवित हैं। यह निर्बाध गति ही विकास को रेखांकित करती है।

जिस तरह वर्षों से बंद ताले में जंग लग जाती है, उसी तरह रुकी हुई जिंदगी भी निष्काम और व्यर्थ हो जाती है। जब तक जीवन है, तब तक 'कर्म रूपी तेल' जिंदगी की गाड़ी में डालते रहना अनिवार्य है। तभी यह अपनी पटरी पर दौड़ते हुए हमें हमारे मोक्ष स्थल तक पहुंचा पाएगी।

पारूल हर्ष वंसल

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

जमाखोरी की आदत

'मुनाफाखोरी की बीमारी' संपादकीय में देश में एलपीजी संकट को लेकर मुनाफाखोरी तंत्र के सक्रिय हो जाने को लेकर सटीक विवेचना की गई है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है, उसका सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ता है। ऐसे समय में देश के भीतर रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी का बढ़ जाना इस बात का संकेत है कि संकट की घड़ी में कुछ लोग केवल मुनाफा कमाने के अवसर तलाशते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इससे आम जनता की परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं। हाल में विभिन्न शहरों में प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी में बड़ी मात्रा में रसोई गैस सिलिंडरों की अवैध जमाखोरी पकड़ी गई। कई लोगों ने अपने गोदामों और घरों में दर्जनों सिलिंडर छिपाकर रखे थे, ताकि बाद में उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। चिंताजनक बात यह है कि इन मामलों में कुछ प्रभावशाली लोग और स्थानीय स्तर के नेता भी शामिल पाए गए। समस्या के समाधान के लिए सरकार को निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना होगा। गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने, डिजिटल ट्रैकिंग लागू करने और शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी करने की जरूरत है। साथ ही दोषी अधिकारियों और मुनाफाखोरों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है। जब तक कानून का सख्ती से पालन नहीं होगा और समाज में नैतिक जिम्मेदारी की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक ऐसी आपात स्थितियों में जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

आर्थिक आपदा बनता युद्ध

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'आर्थिक आपदा बनता युद्ध' में सही कहा है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यह एक गंभीर वैश्विक चिंता है। राजनयिक स्तर पर दुनिया भर के देश हालिया दिनों में बातचीत के जरिए इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यदि यह युद्ध दो-तीन महीने से अधिक खिंचता है, तो दुनिया 'स्टैगफ्लेशन' (रुकी हुई विकास दर और उच्च महंगाई) की चपेट में आ सकती है। होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद होने से दुनिया की 20 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति रुक गई है। खाड़ी देशों ने अपने उत्पादन में लगभग एक करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती की है, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा "सप्लाई व्यवधान" माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 100 से 120 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस की कीमतों में 50 प्रतिशत तक की उछाल आई है, जिससे यूरोप और एशिया में बिजली और परिवहन महंगा हो गया है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़ा निर्यातक है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

असफलता का भय

दिल्ली के आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में छात्र की आत्महत्या की घटना देश को झकझोर देने वाली है। उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और कोचिंग केंद्रों से छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबरें सामने आती रही हैं। प्रतिस्पर्धी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है एवं परिवार की उम्मीदें, बेहतर प्रदर्शन की होड़, असफलता का भय, भविष्य की अनिश्चितता छात्रों को मानसिक रूप से कमजोर करती है। पढ़ाई का दबाव, घर से दूर रहना, असफलता का डर और तुलना की मानसिकता कई छात्रों को अंदर से तोड़ देती है और कुछ छात्र इस मानसिक संघर्ष को झेल नहीं पाते। इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों में मनोवैज्ञानिकों व मनोचिकित्सकों की नियुक्ति अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि छात्रों को समय-समय पर काउंसलिंग मिल सके और वे अपने मानसिक तनाव को साझा कर सकें।, शिक्षण संस्थानों में ऐसा माहौल बनाया जाए, जहां छात्र बिना डर और संकोच के अपनी समस्याएं व्यक्त कर सकें। परिवारों को भी यह समझना होगा कि हर छात्र की क्षमता अलग-अलग होती है। अत्यधिक अपेक्षाएं कई बार बच्चों के लिए बोझ बन जाती हैं। सरकारों, विश्वविद्यालय प्रशासन और समाज सभी को मिलकर ऐसी नीतियां और व्यवस्थाएं बनानी होंगी, जिनसे छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव कम हो और उन्हें सहायक एवं सकारात्मक वातावरण मिल सके।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पोस्ट

कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर की भूमिका वही है, जो भारतीय क्रिकेट टीम में जसप्रीत बुमराह की है।

सुमित@sumitsaurabh

बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव आठ चरणों में हुए थे और इस बार के चुनाव दो चरणों में होंगे। यह भी एक बड़ा बदलाव है।

वसुधा वेणुगोपाल@Vasudha156

विंस्टन चर्चिल ने सही कहा था कि जब आप मुक्त बाजार पर आघात करते हैं तो असल में आप कालाबाजारी के लिए आधार तैयार करते हैं। आरके विज@ipsvijrk

दुनिया में युद्ध है। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। हम पर कोई असर न पड़े, यह हो नहीं सकता। युद्ध इसलिए ही निंदित है। यदि युद्ध से सब बढ़िया ही चलता रहे तो फिर क्या चिंता? कुमार श्याम@thekumarshyam

आज भारत अनुसंधान और विकास की तुलना में मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) पर 27 गुना अधिक खर्च कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप विश्वस्तरीय नवाचार और पेटेंट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

किरण कुमार एस@KiranKS

जनपथ

चलिए, अब तो हो गया है चुनाव एलान,
ममता जी इस बार तो लड़ा दीजिए जान।
लड़ा दीजिए जान बचानी है यदि गद्दी,
दिखता फंसा चुनाव गले में बनकर हड्डी।
झूठा शोर मचाय स्वयं को ही ना छलिए,
सोच-समझकर आप चुनावी चालें चलिए!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक- संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा -201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 240

कर्जमाफी या इनकम सपोर्ट

किसानों के लिए कर्जमाफी की स्कीमों का सिलसिला जारी है। अब महाराष्ट्र ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए किसानों का कर्ज माफ करने वाली स्कीम की घोषणा की है। भारत में किसान कर्जमाफी का लंबा इतिहास है और इसने राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को कमजोर करने के अलावा किसानों की आर्थिक हैसियत में कोई सुधार नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने चेताया है कि अलग-अलग राज्यों में चुनावी वादे के तौर पर आने वाली कर्जमाफी की स्कीमों ने कृषि के क्षेत्र में क्रेडिट कल्चर को बरबाद किया है। इससे किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि वह कर्ज न चुकाएं और कर्जमाफी स्कीमों का इंतजार करें। वहीं, इस तरह की स्कीमों को देखते हुए बैंक भी किसानों को कर्ज देने से कतराते हैं। दशकों का अनुभव यह बताता है कि कर्जमाफी स्कीमों से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। जरूरत किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मुहैया कराने की है। कृषि सुधारों में डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात कही गई है। केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया करा रही है लेकिन रकम बहुत कम है। ऐसे में सवाल है कि कर्जमाफी स्कीमों के बजाय केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को नियमित वित्तीय मदद देने वाली योजनाएं क्यों नहीं लाती हैं, जिससे किसान आधुनिक खेती को अपना कर अपनी माली हालत को बेहतर बना सकें...

कृषि ऋण माफी योजनाओं पर खर्च हुए 3 लाख करोड़ रुपये

2014-15 के बाद से कृषि ऋणमाफी योजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, 1990 के बाद से केंद्र सरकार ने केवल दो राष्ट्रीय स्तर की कर्ज माफी योजनाएं शुरू की हैं। अधिकांश योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा घोषित की गई हैं। पिछले 35 वर्षों में केंद्र और राज्यों ने मिलकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपये कृषि ऋणमाफी योजनाओं पर खर्च किए हैं। इन स्कीमों के प्रभाव और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए वैकल्पिक उपायों का अवलोकन कर रहे हैं महेन्द्र सिंह...

ऋणमाफी और चुनावी राजनीति

अक्सर कृषि ऋणमाफी योजनाएं चुनावों के आसपास घोषित की जाती हैं।

आरबीआइ के 2019 के इंटरनल वर्किंग ग्रुप के अनुसार: 1990 और 2008 की राष्ट्रीय ऋणमाफी योजनाएं तथा 2014 के बाद कई राज्यों में योजनाएं चुनावों के समय घोषित की गई थीं।

₹10,000 करोड़ लगभग थी लागत 1990 की योजना में (2016-17 की कीमतों पर लगभग 50,600 करोड़)।

₹52,500 करोड़ लगभग थी लागत 2008 की योजना में (2016-17 की कीमतों पर लगभग 81,200 करोड़)।

कृषि ऋण पर प्रभाव

- ऋण माफी के बाद कुछ समय के लिए कृषि ऋण वृद्धि धीमी हो जाती है
- बाद में ऋण वितरण धीरे-धीरे सामान्य हो जाता है

आरबीआइ की राय

- आरबीआइ बार-बार कृषि ऋण माफी का विरोध करता रहा है
- उसका तर्क है कि इससे क्रेडिट अनुशासन कमजोर होता है
- किसान भविष्य में माफी की उम्मीद में ऋण चुकाने में देरी कर सकते हैं
- इससे किसानों की क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है
- भविष्य में नया ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है

सरकारों पर वित्तीय दबाव

- ऋणमाफी योजनाएं सरकारी वित्त पर बड़ा दबाव डालती हैं
- राज्यों के राजस्व व्यय में लगभग 5 आधार अंक की वृद्धि ऋणमाफी के कारण हुई

आरबीआइ वर्किंग ग्रुप के अनुसार

- ऋणमाफी पर खर्च होने वाला पैसा यदि कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास में लगाया जाए तो अधिक लाभकारी हो सकता है
- ऋणमाफी का बहुत सीमित और अल्पकालिक प्रभाव होता है

केंद्र सरकार की कृषि ऋणमाफी योजनाएं

1 कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990: यह पहली बड़ी राष्ट्रीय कृषि ऋणमाफी योजना थी। इसमें 2 अक्टूबर 1989 तक के अल्पकालिक ऋण और अवधि ऋण की बकाया किश्तें शामिल थीं। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों पर लागू थी। प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये तक की राहत दी गई। इसमें भूमि के आकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था।

2 कृषि ऋणमाफी और ऋण राहत योजना, 2008: योजना का दायरा और बढ़ाया गया। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों (5 एकड़ तक भूमि) को बड़े किसानों की तुलना में अधिक लाभ दिया गया। इसकी वित्तीय लागत 52,500 करोड़ रुपये थी।

एसबीआइ की एक रिपोर्ट के अनुसार

- 2014 के बाद लगभग 3.7 करोड़ पात्र किसानों में से मार्च 2022 तक केवल लगभग 50 प्रतिशत को ही ऋणमाफी का लाभ मिला
- इससे योजना की प्रभावशीलता सीमित हो गई
- ऋणमाफी किसानों की समस्याओं को पूरी तरह हल नहीं कर पाई
- कुछ क्षेत्रों में क्रेडिट अनुशासन कमजोर हुआ

राज्यों की कृषि ऋणमाफी योजनाएं

राज्य	योजना का नाम	वर्ष	मुख्य लाभ
महाराष्ट्र	महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना	2019	किसानों के फसल ऋण में लगभग 2 लाख तक की माफी
तेलंगाना	तेलंगाना किसान ऋण माफी योजना	2024	किसानों के कृषि ऋण 2 लाख तक माफ
उत्तर प्रदेश	यूपी फसल ऋण मोचन योजना	2017	छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के ऋण माफ
पंजाब	पंजाब कृषि ऋणमाफी योजना	2017	छोटे किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ
कर्नाटक	कर्नाटक किसान ऋणमाफी योजना	2018	सहकारी व वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए 2 लाख तक के ऋण माफ
राजस्थान	राजस्थान किसान ऋणमाफी योजना	2017	किसानों के 50,000 तक के फसल ऋण माफ
मध्य प्रदेश	जय किसान फसल ऋणमाफी योजना	2018	किसानों के 2 लाख तक के फसल ऋण माफ
छत्तीसगढ़	कृषि ऋणमाफी योजना	2018	अल्पकालीन कृषि ऋण माफ
तमिलनाडु	सहकारी बैंक कृषि ऋणमाफी योजना	2016	सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण पूरी तरह माफ
आंध्र प्रदेश	एपी फसल ऋणमाफी योजना	2014	किसानों के 1.5 लाख तक के ऋण माफ

किसानों के लिए वैकल्पिक समाधान

- एसबीआइ की रिपोर्ट के अनुसार, इनकम सपोर्ट स्कीमें बेहतर विकल्प हो सकती हैं
- इससे अधिक किसानों को लाभ मिल सकता है और उन्हें स्थिर आर्थिक सहायता मिल सकती है

रिपोर्ट का निष्कर्ष

- कृषि ऋणमाफी दीर्घकालिक समाधान नहीं है
- नीतियों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की इनकम सपोर्ट स्कीमें अधिक प्रभावी हो सकती हैं

आय बढ़ाने के स्थायी उपायों पर हो काम

प्रो. आरएस देशपांडे
एफआइएसएई, एफकेएसटीए

करीब तीन दशक के अनुभव से यह साबित हो चुका है कि कृषि ऋणमाफी योजनाएं किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही हैं। इसके बजाय सरकारों को किसानों के लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीमें लाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार के लिए किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी

भारतीय कृषि व्यवस्था में किसान प्रायः मूल्य ग्रहणकर्ता के रूप में कार्य करता है। जब वह बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई या बिजली जैसे कृषि इनपुट खरीदता है, तब उनके दाम विक्रेता तय करते हैं। इसी प्रकार जब किसान अपनी उपज बेचता है, तब कीमतें अक्सर व्यापारी या खरीदार समूह द्वारा निर्धारित होती हैं। परिणामस्वरूप किसान के पास बाजार में कीमतों को प्रभावित करने की बहुत सीमित क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश किसानों की आय नियमित नहीं होती। उन्हें आमतौर पर फसल कटाई के बाद ही आय प्राप्त होती है। इस कारण वे अक्सर ऋण बाजार पर निर्भर रहते हैं।

इतिहास में ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों ने ऋण को फसल बिक्री से जोड़ दिया था, जिससे किसान अपनी उपज केवल उसी को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। ये साहूकार अक्सर कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) में एजेंट के रूप में भी कार्य करते थे। पिछले लगभग पचास वर्षों में संस्थागत ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि गैर-संस्थागत स्रोतों से कर्ज कुछ कम हुआ है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका महत्व बना हुआ है। किसानों को ऋण की आवश्यकता मुख्यतः आय की अनियमितता और प्राकृतिक आपदाओं- जैसे सूखा, बाढ़ या फसल खराब होने के कारण होती है। जब ऐसी परिस्थितियों में किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तब सरकारें अक्सर ऋण माफी योजनाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करती हैं।

शुरुआत में ऋण माफी योजनाओं को किसानों को अस्थायी राहत देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ यह एक नियमित सरकारी नीति और कई बार राजनीतिक साधन भी बन गई है। कई बार सरकारें इन योजनाओं की घोषणा चुनावों के आसपास करती हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि ऋण माफी का उपयोग किसानों को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक रणनीति के रूप में किया जाता है। भारत में कृषि परिवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह एक प्रभावशाली मतदाता वर्ग है। हालांकि ऐसी घोषणाएं किसानों को तात्कालिक राहत देती हैं, लेकिन इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है और कई विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। साथ ही यह कृषि उत्पादकता में दीर्घकालिक सुधार नहीं कर पाती। इसके बावजूद ऋण माफी के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। जब किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं, तब वे मानसिक तनाव का सामना करते हैं और कई बार यह स्थिति आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं तक पहुंच जाती है। किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता और उससे जुड़े सामाजिक तनाव को देखते हुए कई राज्यों ने 2014 से 2019 के बीच ऋण माफी योजनाएं लागू कीं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में भी इन्हें शामिल किया। ऐसी योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं या बाजार में अचानक आई गिरावट के कारण प्रभावित किसानों को तात्कालिक राहत देती हैं और ग्रामीण समाज में अस्थिरता को कम करने में मदद करती हैं। हालांकि अनेक शोध अध्ययनों में इन योजनाओं की सीमाएं भी बताई गई हैं। पहली समस्या यह है कि बार-बार ऋण माफी से बैंकिंग प्रणाली में क्रेडिट अनुशासन कमजोर हो सकता है, क्योंकि किसानों में भविष्य में भी ऋण माफी की उम्मीद बन जाती है। दूसरी समस्या यह है कि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है, जिससे अन्य विकास योजनाओं के लिए संसाधन कम हो जाते हैं। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की कुछ रिपोर्टों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में त्रुटियों की ओर भी संकेत किया गया है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि ऋण माफी के स्थान पर अधिक स्थायी उपायों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी इनकम सपोर्ट स्कीमें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और कृषि विस्तार सेवाएं किसानों की स्थिति को अधिक स्थायी रूप से सुधार सकती हैं। ऋण माफी योजनाएं किसानों को तात्कालिक राहत प्रदान करती हैं, लेकिन वे कृषि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हैं। यदि इनका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में और सही लक्षित समूह के लिए किया जाए तो यह उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन बार-बार और राजनीतिक उद्देश्य से की गई घोषणाएं न केवल वित्तीय बोझ बढ़ाती हैं बल्कि कृषि विकास की दीर्घकालिक संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र के स्थायी विकास के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो किसानों की आय, उत्पादकता और जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाएं।

आपकी आवाज

किसान कर्ज माफी योजनाएं राज्यों में चुनाव जीतने का मंत्र बन गई हैं। राज्य सरकारें चुनाव से कुछ महीने पहले किसानों से कर्ज माफी का वादा करती हैं और चुनाव जीत कर सरकार बनाने के बाद आधा अधूरा वादा पूरा करके हाथ खड़ा कर लेती हैं। पिछले एक दशक में राज्यों में कर्ज माफी चलन जोर पकड़ रहा है। इस तरह की योजनाओं से वे किसान ठगा हुआ महसूस करते हैं जो समय पर कर्ज चुका होते हैं। जाहिर है कि ऐसी योजनाओं से किसानों का कोई भला नहीं हो रहा है उलटा राज्य का विकास जरूर प्रभावित होता है। **मोहन वर्मा**

राजनीतिक दलों ने कर्ज माफी की योजनाओं को किसानों का आक्रोश शांत करने का एक हथियार बना लिया है। कर्ज माफी के बजाए जरूरत है कि किसानों को आधुनिक तकनीक और वित्तीय सहायता मिले। इससे वह खेती में पैदावार बढ़ा कर बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं लेकिन इस दिशा में राज्य और केंद्र सरकारें उदासीन हैं। केंद्र सरकार भी हर साल फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा कर अपनी पीठ थपथपाती है लेकिन देश के ज्यादातर किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। **सनातन पाराशर**

केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों का कर्ज माफ करने के बजाए कृषि क्षेत्र में शोध एवं टेक्नोलाजी को बढ़ावा देना चाहिए। इससे लंबी अवधि में किसानों की आय में इजाफा होगा और देश की जीडीपी में कृषि का योगदान भी बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में शोध के मामले में हम विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। यही कारण है कि इन देशों की तुलना में हमारे यहां प्रति हेक्टेयर उपज काफी कम है। **मुरली मिश्र**

कृषि क्षेत्र में टेक्नोलाजी और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दें सरकारें

प्रो. रमेश चंद
सदस्य, नीति आयोग

कृषि क्षेत्र में कीमतों को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ की रणनीति पर काम ले रहा है। सब्सिडी पर भी सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है लेकिन इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती नहीं मिल रही है। इसके बजाए टेक्नोलाजी और प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए

समय समय पर अलग अलग राज्यों द्वारा लाई जा रही कृषि ऋण माफी वाली योजनाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक की चिंता जायज है। इससे सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगता है जो समय पर कर्ज चुका देते हैं। उनको लगता है कि हमने कानून का पालन किया तो हमें इसका दंड मिला अगर हम भी कर्ज न चुकाते तो हमको फायदा मिलता। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में जैसे बहुत बड़ा सूखा आ गया या दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आ गईं, ऐसी स्थिति में कई बार किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो ऐसे में तो कृषि ऋण माफी की योजनाओं का औचित्य बनता है। लेकिन जब कृषि क्षेत्र का ग्रोथ पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छा चल रहा है तो ऐसे में इस तरह की योजनाओं का कोई खास मतलब नहीं बनता है।

दूसरी अहम बात यह है कि कृषि क्षेत्र में जो सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश हो रहा है, चाहे वह शोध में हो या मृदा संरक्षण में हो या कृषि क्षेत्र के लिए बुनियादी संरचनाओं पर हो, यह बहुत कम है। भारत में यह निवेश अगर केंद्र और राज्यों का मिला कर देखें तो यह कृषि जीडीपी का दो प्रतिशत है, जबकि कई अध्ययनों में कहा गया है कि निवेश कम से कम चार प्रतिशत होना चाहिए इससे आगे की ग्रोथ के लिए कृषि क्षेत्र की नींव मजबूत होती है। ऐसे में अगर किसी राज्य के पास पैसा है तो उसे ढांचागत सुविधाओं पर निवेश करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र है जहां विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की दिक्कत अक्सर आती है। आप वहां कर्ज माफ करके एक साल के लिए किसानों को तात्कालिक राहत दे सकते हैं। लेकिन अगर यही पैसा पानी के लिए ढांचागत सुविधाएं बनाने पर खर्च किया जाए तो इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि लंबी अवधि में किसानों की आय भी बढ़ेगी। इस तरह से राज्य किसानों के हित में पैसे का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालात यह हैं कि आप किसी भी राज्य में जाइये वहां राज्य कहते हैं कि हमारे पास कृषि क्षेत्र में शोध के लिए पैसे नहीं हैं।

कृषि राज्यों का विषय है और केंद्र का तो आइसीएआर है। सारे विश्वविद्यालय कहते हैं कि हमें शोध के लिए आइसीएआर पैसा दे। हमारे पास तो किसान नेता आते हैं हम उनसे कहते हैं कि एपीएमसी मंडियों में पैसा देते हैं तो उनसे कहिए कि वह इस पैसे का एक हिस्सा शोध के लिए दें या आप ही आधा प्रतिशत अधिक दे सकते हैं, शोध के क्षेत्र में काम आए। कृषि के क्षेत्र में शोध को मजबूत करना जरूरी है। कृषि क्षेत्र में ग्रोथ टेक्नोलाजी से आती है। मक्की में टेक्नोलाजी आई तो उसमें छह सात प्रतिशत की ग्रोथ आ रही है। सरसों में टेक्नोलाजी नहीं आई तो उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और हमें खाने का तेल बाहर से आयात करना पड़ता है। मेरा मानना है कि प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में निवेश पर होना चाहिए।

एक और चीज कृषि क्षेत्र में गलत हो रही है वह है कि हम कीमतों के आधार पर ग्रोथ लाने की नीति पर काम कर रहे हैं। इसमें सब्सिडी भी शामिल है। वहीं टेक्नालाजी व उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह तरीका ठीक नहीं है क्योंकि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ रहा है लेकिन इससे किसानों को खास फायदा नहीं मिल रहा है। इसके बजाय हमें टेक्नोलाजी और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।

जाति, पंथ और संप्रदाय की आस्था में अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं : योगी

राज्य ब्यूरो, जागरण. लखनऊ: उप्र में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में आपत्तिजनक या विवादित सवालों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि प्रश्नपत्र बनाते समय किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय की मर्यादा व आस्था से जुड़े विषयों पर अमर्यादित टिप्पणी किसी भी स्थिति में शामिल न की जाए। यह भी कहा कि सभी प्रश्नपत्र तैयार करने वालों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए ताकि प्रश्नपत्रों में संवेदनशीलता बनी रहे।

उप्र पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। परीक्षा में एक बहु विकल्पीय प्रश्न पूछा गया-'अवसर के अनुसार

योगी आदित्यनाथ ● फाइल फोटो

बदलने वाला।' परीक्षार्थियों को इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो विकल्प दिए गए, उसमें एक है-'पंडित'। भाजपा के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने इस पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि यदि कोई पेपर तैयार करने वाला बार-बार ऐसी गलती करता है तो उसे आदतन उल्लंघन करने वाला मानते हुए प्रतिबंधित किया जाए।

अब यूपी पुलिस की पोस्ट ने 'पंडित' शब्द विवाद को दिया तूल

जासं, प्रयागराज: प्रश्नपत्र में 'पंडित' शब्द पर विवाद को यूपी पुलिस के संदेश ने और भड़का दिया। पुलिस ने 'एक्स' पर संदेश जारी कर परीक्षा के प्रश्नपत्रों या उनके कंटेंट पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार को प्रतिबंधित बताते हुए चेताया है। संदेश में कहा गया कि ऐसा करने पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस के संदेश को प्रतियोगी छात्र सीनाजोरी बताते हुए इसे डिलीट करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा के प्रश्नों पर चर्चा व विश्लेषण प्रतियोगी संस्कृति का सामान्य हिस्सा है।

'आयकर से जुड़े मुकदमे कम करने व समीक्षा के लिए बनाएं विशेषज्ञ समिति'

- संसदीय समिति ने कहा- हाईकोर्ट व आइटीएटी में मुकदमों की सफलता दर बहुत कम
- 2024-25 में साढ़े तीन लाख करोड़ से जुड़े 23 हजार मुकदमे आइटीएटी में लंबित

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमेबाजी के प्रति दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का सुझाव दिया है। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह संसद में पेश रिपोर्ट में विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में अपील से पहले मामलों की समीक्षा के लिए 'विशेषज्ञ मुकदमेबाजी समिति' गठित की जानी चाहिए।

समिति ने वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट के स्तर पर आयकर विभाग की मुकदमेबाजी में सफलता दर महज 12.07% और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) के स्तर पर 14.50% रही है। प्रतिकूल परिणाम 'प्रणालीगत कमजोरियों' की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट में कहा है, केवल इसलिए यांत्रिक तरीके से अपील दायर करने की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है क्योंकि विवादित राशि तय मौद्रिक सीमा से अधिक है। ऐसा व्यक्तिगत जिम्मेदारी या जांच से बचने को किया जाता है। तीन वर्षों में विभाग की सफलता दर गिरी है। समिति का मानना है कि अस्थिर अपीलों को जारी रखने से मुकदमेबाजी का खर्च, न्यायिक ढांचे पर बोझ पड़ता है। करदाताओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

प्रोफेशनल केयरगिवर्स तैयार करने को बनेंगे रीजनल ट्रेनिंग क्लस्टर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: एकल परिवारों और अन्य परिस्थितियों के कारण बच्चों, वृद्धों और बीमारों की देखभाल के लिए केयरगिवर्स के रूप में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर अन्य देशों में केयरगिवर्स की बेहद मांग है। मोदी सरकार ने इसी अवसर को भुनाने के लिए बजट में घोषणा की कि डेढ़ लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस घोषणा को लागू करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने अन्य संबंधित मंत्रालयों से विमर्श कर रोडमैप पर काम शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों ने सहमति दी है कि प्रोफेशनल केयरगिवर्स तैयार करने को रीजनल ट्रेनिंग क्लस्टर बनाए जाएं। सूत्रों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के साथ बैठकें हो चुकी हैं।

एक अप्रैल से 75 रुपये महंगा होगा फास्टैग का सालाना पास

- एनएचएआइ ने कहा-3000 वाला पास अब 3075 रुपये में
- 56 लाख वाहन चालक इस्तेमाल कर रहे यह सालाना पास

नई दिल्ली, प्रेट्र: अपनी कार या निजी वाहन से फास्टैग के जरिये नेशनल हाईवे पर सफर करना अब महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास की कीमत में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत फास्टैग का सालाना पास वर्तमान 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नई शुल्क संरचना एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 2025 को वार्षिक पास सुविधा शुरू की गई थी। निजी वाहन मालिकों के बीच फास्टैग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में 56 लाख से ज्यादा वाहन चालक इस वार्षिक पास का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वार्षिक पास का विकल्प चुनने से वाहन चालकों को बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह प्रणाली एक बार के शुल्क भुगतान पर आधारित है, जो पूरे एक वर्ष या कुल 200 टोल प्लाजा पार करने की वैधता प्रदान करती है। यह पास सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। राजमार्ग यात्रा एप या एनएचएआइ की वेबसाइट से शुल्क भुगतान के बाद वार्षिक पास वाहन से जुड़े फास्टैग पर सक्रिय हो जाता है।